राष्ट्रीय संस्करण

पुतिन इसी साल आएंगे भारत, द्विपक्षीय संबंधों का नया एजेंडा होगा तय
>>3

वर्ष 8 अंक 289

दैनिक जागरण

मूल्य ₹8.00 नई दिल्ली, शुक्रवार, 28 मार्च, 2025

www.jagran.com

पृष्ठ 14

जागरण विशेष

खिलाड़ियों को चोटिल होने से बचाएगा खास फैब्रिक

गाजियाबाद : खिलाड़ियों को खेलते समय गेंद से लगने वाली चोट से बचाने के लिए निटरा के विज्ञानियों ने एक खास फैब्रिक तैयार किया है। • पेज 7

संपादकीय

भाजपा को रोकने के लिए भ्रम की राजनीति : स्टालिन केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव बढ़ाकर अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों में राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। **डा. एके वर्मा** का आलेख।

पाठ्यपुस्तकों में गुम असली नायक : भारत ने अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए कितना कुछ भोगा, यह हमें विस्तार से बताया जाना चाहिए था। **प्रणय कुमार** का दृष्टिकोण। • पेज 8

विमर्श

साइबर ठगों पर प्रभावी अंकुश से ही बनेगी बात : संचार के विभिन्न माध्यमों से साइबर ठगों से सावधान रहने के लिए निरंतर किए जा रहे प्रचार के बावजूद देश में साइबर ठगों पर प्रभावी अंकुश लगता नहीं दिख रहा है। **लोकमित्र** का आलेख।

वैदिक परंपरा के प्राचीन साक्ष्य : उत्तर प्रदेश के सिनौली से हाल ही में मिले पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में पहले से ही वैदिक मान्यताओं का अनुसरण करने वाले लोग रहा करते थे और वे इसी क्षेत्र के मूलनिवासी थे। **शुभम केवलिया** का दृष्टिकोण। • पेज-9

दैनिक जागरण सप्तरंग

मनोरंजन की दुनिया का

नाम के लिए संघर्ष

गजगामिनी की कहानी : अदिति राव हैदरी

• पेज-13

अपने नौनिहालों का जीवन कैसे बचाया जाए, भारत से सीखे दुनिया

जेएनएन, नई दिल्ली

- बाल मृत्युदर में 70% कमी लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने भारत को सराहा
- कहा-आयुष्मान भारत जैसी पहल से स्वास्थ्य प्रणाली में रणनीतिक निवेश के जरिये भारत ने लाखों जीवन बचाए
- स्वास्थ्य कवरेज बढ़ाने, मौजूदा स्थिति को सुधारने और स्वास्थ्य ढांचे विकसित करने के लिए किए गए उपाय

संयुक्त राष्ट्र ने आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य पहल का उदाहरण देते हुए बाल मृत्युदर में कमी लाने के लिए भारत के प्रयासों और प्रगति की सराहना की है। विश्व निकाय ने कहा है कि देश ने अपनी स्वास्थ्य प्रणाली में रणनीतिक निवेश के माध्यम से लाखों लोगों का जीवन बचाया है। इसने दिखाया है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, साक्ष्य-आधारित रणनीतियों और निरंतर निवेश से मृत्युदर में पर्याप्त कमी लाई जा सकती है।

मंगलवार को जारी संयुक्त राष्ट्र अंतर-एजेंसी समूह की बाल मृत्युदर आकलन रिपोर्ट में भारत, नेपाल, सेनेगल, घाना और बुरुंडी का उदाहरण दिया गया तथा बाल मृत्युदर रोकने में हुई प्रगति में अहम भूमिका निभाने वाली विभिन्न रणनीतियों पर प्रकाश डाला गया है।

भारत के बारे में रिपोर्ट में कहा गया कि देश ने स्वास्थ्य प्रणाली में निवेश के माध्यम से स्थिति को बेहतर किया है। अपनी स्वास्थ्य प्रणाली में रणनीतिक निवेश के माध्यम से भारत पहले ही लाखों लोगों का जीवन बचा चुका है और लाखों अन्य लोगों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त किया है। वर्ष 2000 से भारत ने पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्युदर में 70 प्रतिशत की कमी तथा नवजात शिशुओं की मृत्युदर में 61 प्रतिशत की कमी हासिल की है। स्वास्थ्य कवरेज बढ़ाने, मौजूदा स्थिति को सुधारने और स्वास्थ्य ढांचे तथा मानव संसाधन विकसित करने के लिए किए गए उपायों के कारण ऐसा संभव हुआ है। आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो प्रति वर्ष प्रति परिवार को पांच लाख रुपये की वार्षिक कवरेज प्रदान करता है।

2020 में भारत में शिशु मृत्युदर (प्रति 1,000 जन्म के समय) 29.85 थी।

2025 में भारत में शिशु मृत्युदर (प्रति 1,000 जन्म के समय) 24.98 होगी

2000 में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में खसरे से होने वाली मृत्युदर में भारत सबसे आगे था। खसरे से 1.89 लाख शिशुओं की मृत्यु हुई थी

2023 तक शिशुओं में खसरे से पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्युदर 97 प्रतिशत घटकर 5,200 रह गई थी

तेज होती किलकारियों की सराहना। प्रतीकात्मक

टीकाकरण, पोषण, सुरक्षित जल और स्वच्छता तक पहुंच के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता के कारण आज लाखों बच्चे जीवित हैं। बाल मृत्युदर को निम्न स्तर पर लाना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। लेकिन, सही नीतिगत विकल्पों के बिना लाखों और बच्चे मर जाते हैं। हम ऐसा होने नहीं दे सकते। -**कैथरीन रसेल, यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक**

इन उपायों से बची लाखों बच्चों की जिंदगी

- रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रत्येक गर्भवती महिला मुफ्त प्रसव की हकदार है और शिशु देखभाल संस्थानों में मुफ्त परिवहन, दवाएं, निदान और आहार इसमें सहायता प्रदान करती है।
- स्वास्थ्य सेवाओं के लिए व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए भारत ने प्रसूति प्रतीक्षा गृहों, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग, बीमार नवजात की देखभाल, मातृ देखभाल और जन्म दोष जांच के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है।
- इससे हर साल लाखों स्वस्थ गर्भधारण और जीवित बच्चों का जन्म सुनिश्चित होता है। भारत ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए दाइयों और कुशल प्रसव सहायकों के प्रशिक्षण तथा तैनाती को भी प्राथमिकता दी है।

एमएसपी से कम पर फसलों की खरीदारी नहीं करें राज्य : केंद्र

नई दिल्ली : किसान हित में केंद्र ने सभी राज्य सरकारों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम पर फसलों की खरीदारी नहीं करने का आग्रह किया है। सरकार का सबसे अधिक जोर दलहन खरीद पर है, क्योंकि दाल का बफर स्टाक न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है। अगले चार वर्षों में दलहन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य आसान नहीं है। (पेज-3)

ओडिशा विधानसभा के बाहर हंगामा, पुलिस पर हमला

भुवनेश्वर : ओडिशा विधानसभा के बाहर महात्मा गांधी मार्ग पर गुरुवार को जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामे के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पत्थर, कुर्सी एवं अंडों से हमला किया, जवाबी कार्रवाई में पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी और अश्रु गैस छोड़े। इससे एक दर्जन पुलिसकर्मी व 20 कांग्रेस कार्यकर्ता घायल हो गए। इनमें से कुछ को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। (पेज-4)

जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने के फैसले पर पुनर्विचार कर सकती है कोलेजियम

दावा ▸ छह बार एसोसिएशन के अध्यक्षों की मांग पर सीजेआइ ने दिया सकारात्मक संकेत

बार एसोसिएशन के अध्यक्षों ने सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम से मिलकर रखी मांगें

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सरकारी आवास से कथित तौर पर भारी मात्रा में नकदी मिलने के मामले में जांच का सामना कर रहे दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस भेजने के फैसले पर कोलेजियम पुनर्विचार कर सकती है। गुरुवार को छह हाई कोर्टों के बार एसोसिएशनों के अध्यक्षों ने प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना सहित कोलेजियम के पांच न्यायाधीशों से मुलाकात कर जस्टिस वर्मा को भेजने की सिफारिश वापस लेने का आग्रह किया। सीजेआइ ने उन्हें मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया।

जिन छह हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और प्रतिनिधि सीजेआइ से मिले हैं, उनमें इलाहाबाद, गुजरात, केरल, जबलपुर, कर्नाटक और लखनऊ हाई कोर्टों की बार एसोसिएशनों के अध्यक्ष शामिल थे। इसके अलावा 18 अन्य हाई कोर्ट की बार एसोसिएशनों का भी समर्थन उन्हें प्राप्त है। कुल 25 हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन उनके साथ हैं।

इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने गुरुवार को बताया कि प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना सहित कोलेजियम के पांच न्यायाधीशों से मुलाकात कर जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश वापस लेने का आग्रह किया गया है। सीजेआइ ने उन्हें मांग पर विचार करने का भरोसा दिलाया है। सीजेआइ के भरोसा दिलाने के बाद बार एसोसिएशन जस्टिस वर्मा को भेजने की सिफारिश के विरोध में जारी हड़ताल वापस लेने पर विचार कर सकती है।

बार एसोसिएशनों ने ज्ञापन में जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में सीजेआइ द्वारा उठाए गए कदम और दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की रिपोर्ट सहित सारे दस्तावेज वेबसाइट पर सार्वजनिक कर पारदर्शिता को बढ़ावा देने की सराहना की है। ज्ञापन में तीन आग्रह किए गए हैं। पहला अनुरोध है कि सीजेआइ और कोलेजियम जस्टिस यशवंत वर्मा को भेजने की सिफारिश वापस ले। जस्टिस वर्मा से न्यायिक कार्य के अलावा सभी तरह का प्रशासनिक काम भी वापस लिया जाए। जिस तरह किसी भी सरकारी कर्मचारी के मामले में आपराधिक कानून के प्रविधान लागू होते हैं, वैसे ही इस मामले में भी आपराधिक कानून लागू किया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की रिपोर्ट के मुताबिक किसी ने 15 मार्च को परिसर से सामान हटाया है। ऐसे में आपराधिक कानून को काम करने दिया जाना चाहिए, ताकि साक्ष्य नष्ट न हों। बार एसोसिएशनों ने कोलेजियम से यह भी आग्रह किया है कि उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की जवाबदेही का मानक तय होना चाहिए और मौजूदा आंतरिक जांच व्यवस्था का पुनः आकलन किया जाना चाहिए।

मालूम हो कि गत 14 मार्च को न्यायाधीश यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास में आग लगने की सूचना मिलने पर जब अग्निशमन दस्ता आग बुझाने पहुंचा तो कथित तौर पर वहां भारी मात्रा में जले हुए नोट मिले थे। इस मामले में सीजेआइ ने जांच के लिए जजों की तीन सदस्यीय कमेटी बनाई है।

जस्टिस वर्मा से न्यायिक कार्य के अलावा प्रशासनिक काम भी वापस लिया जाए

नई दिल्ली में सीजेआइ संजीव खन्ना से भेंट के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी (दाएं) एवं अन्य। प्रेट्र

प्राथमिकी दर्ज करने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई आज

प्रेट्र के अनुसार, जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से कथित तौर पर अधजले नोट मिलने को लेकर दिल्ली पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत की वाद सूची के अनुसार, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। वकील मैथ्यूज जे नेदुम्परा और तीन अन्य ने रविवार को याचिका दायर कर दिल्ली पुलिस को मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।

भारत कोई धर्मशाला नहीं, रहेगी कड़ी निगरानी : शाह

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- आप्रवास और विदेशियों से संबंधित विधेयक पर चर्चा के जवाब में गृह मंत्री ने विपक्ष को सुनाई खरी-खरी
- बोले -अब तक देश में विदेशी संसद में बना कानून, मोदी सरकार ने बनाई है स्वदेशी नीति
- इमिग्रेशन एंड फारनर्स बिल, 2025 लोस में ध्वनिमत से पारित

लोकसभा में आप्रवास और विदेशियों से संबंधित विधेयक, 2025 पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों को निशाने पर लेते हुए विपक्ष को भी खूब खरी-खरी सुनाई। कहा कि देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रवासियों से जुड़े मामलों के लिए अब तक जो कानून थे, वे विदेशी संसद में बने थे। गृह मंत्रालय ने तीन वर्षों तक विचार कर यह नया विधेयक तैयार किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह देश कोई धर्मशाला नहीं है और जो लोग देश की सुरक्षा को खतरे में डालेंगे, उन पर कड़ी नजर रखी जाएगी। गृह मंत्री के जवाब के बाद इस विधेयक को सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया।

गृह मंत्री ने कहा कि प्रवासन कोई अलग-थलग मुद्दा नहीं है। देश के कई मुद्दे इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। यह जानना जरूरी है कि हमारे देश की सीमा में कौन आता है, कब आता है, कितनी अवधि तक रहता है और किस उद्देश्य से आता है। यह जानकारी देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कोई नया विचार नहीं है, बल्कि कई सालों से यह अलग-अलग कानूनों में पड़े थे। हमने उन्हें एकीकृत रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इमिग्रेशन एंड फारनर्स बिल, 2025 के पारित होने के बाद भारत आने वाले हर विदेशी का व्यवस्थित व अद्यतन लेखा-जोखा रखा जाएगा। जो लोग देश को विकसित करने, व्यापार या शिक्षा के लिए आते हैं, उनका स्वागत है, लेकिन जो सुरक्षा को खतरे में डालेंगे, उन पर हमारी कड़ी नजर होगी।

गुरुवार को लोकसभा में बोलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। वीडियोग्रेब/प्रेट्र

रोहिंग्या या बांग्लादेशी अशांति फैलाने आएंगे, तो होगी कठोर कार्रवाई पेज>>3

सड़क पर नमाज पढ़ी तो केस व रद होगा पासपोर्ट

जागरण संवाददाता, मेरठ

- मेरठ पुलिस का फरमान, गत वर्ष दर्ज मुकदमों में आरोपितों के पासपोर्ट निरस्तीकरण की भेजी जा रही रिपोर्ट
- सड़क पर नमाज अदा करने वाले मुस्लिम नहीं कर सकेंगे हज यात्रा

ईद-उल-फितर की नमाज सड़क पर पढ़ने वालों के खिलाफ इस बार मेरठ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया है। एफआइआर के साथ आरोपितों के पासपोर्ट रद किए जाएंगे। गत वर्ष दर्ज केसों में आरोपितों के पासपोर्ट निरस्तीकरण की रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। इससे हज यात्रा नहीं कर सकेंगे।

एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने कहा कि ईद की नमाज सड़क पर नहीं पढ़ने दी जाएगी। पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने अपील की है कि ईदगाह के अलावा लोग अपने आसपास की मस्जिदों में नमाज पढ़ें। एसएसपी विपिन ताडा ने बताया कि ड्रोन और वीडियो कैमरों से निगरानी होगी। सड़क पर नमाज पढ़ने वालों पर एफआइआर कर उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी।

इस बीच, रालोद अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्यमंत्री जयन्त चौधरी ने मेरठ की पुलिस इस चेतावनी पर एक्स पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे 'आरवेलियन 1984 की ओर पुलिसिंग' बताया है। 'आरवेलियन' उस अन्यायपूर्ण व अधिनायकवादी स्थिति को कहते हैं, जो एक खुले समाज के लिए विनाशकारी हो।

संभल में छतों पर भी नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध

जासं, संभल : संभल में सड़क के साथ ही छतों पर भी नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का कहना है छतों पर नमाज पढ़ने से हादसे का खतरा रहता है। लोगों से छत पर नमाज न पढ़ने की अपील की गई है। एसडीएम वंदना मिश्रा ने कहा कि शांति समिति की बैठकों में मुस्लिमों ने सड़क और छतों पर नमाज नहीं पढ़ने पर सहमति जताई है।

हरियाणा में ईद का राजपत्रित अवकाश हुआ वैकल्पिक, लेनी होगी छुट्टी पेज>>7

जितनी उम्र लिखी है, उतनी लिखी है : सलमान खान

मुंबई : कुख्यात गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई गिरोह से मिली धमकियों और कड़ी सुरक्षा के कारण गतिविधियों पर प्रतिबंध को लेकर अभिनेता सलमान खान ने बुधवार रात मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि जितनी उम्र लिखी है, उतनी लिखी है। बस यही है। (पेज-7)

अमेरिका ने भारत में रद किए दो हजार वीजा अपाइंटमेंट

नई दिल्ली : भारत में अमेरिकी दूतावास ने करीब दो हजार वीजा अपाइंटमेंट को रद कर दिया है। वीजा आवेदन में कुछ गड़बड़ियों की शिकायत मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है। दूतावास ने यह भी कहा कि उसकी शेड्यूलिंग नीतियों का उल्लंघन करने वाले एजेंटों और फिक्सरों की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। (पेज-10)

कठुआ में तीन जवान बलिदान, तीन आतंकी ढेर

जागरण संवाददाता, कठुआ

- हीरानगर क्षेत्र में सुबह से सुरक्षाबल और आतंकियों के बीच रुक-रुक कर गोलीबारी जारी
- मुठभेड़ में डीएसपी सहित पांच सुरक्षाकर्मी घायल, आतंकियों की पांच दिन से हो रही थी तलाश

जम्मू संभाग के कठुआ जिले में गुरुवार सुबह सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच भीषण मुठभेड़ में तीन जवान बलिदान और पुलिस के डीएसपी सहित पांच सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। इनमें एक पैरा कमांडो भी शामिल है। तीनों बलिदानी जम्मू के बताए जा रहे हैं। मुठभेड़ में तीन आतंकियों को भी मार गिराया गया है। सुबह से देर शाम तक रुक-रुक कर दोनों तरफ से गोलीबारी जारी रही। अंधेरा होते ही अभियान रोका गया है। पूरे इलाके को सुरक्षाबलों ने घेरा हुआ है और अंतिम प्रहार के लिए सुबह का इंतजार किया जा रहा है। बताया जा रहा कि ये वही आतंकी हैं, जिन्होंने गत रविवार को जिले के हीरानगर में घुसपैठ की थी। सेना, बीएसएफ, पुलिस व सीआरपीएफ के जवान आपरेशन में जुटे हैं।

सुबह पौने नौ बजे हीरानगर के राजबाग क्षेत्र के जुथाना के अंबानाल में एक ग्रामीण ने हथियारों से लैस पांच आतंकियों को देख पुलिस को जानकारी दी। ये आतंकी बिलावर की तरफ निकल रहे थे। कुछ ही देर में सुरक्षाबल मौके पर पहुंच गए और क्षेत्र की घेराबंदी कर ली। करीब आधे घंटे बाद तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने खुद को घिरा हुआ देख गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षाबलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। डेढ़ तक चली मुठभेड़ के बाद अचानक गोलीबारी बंद हो गई। मुठभेड़ में तीन आतंकी मारे गए हैं। आतंकियों के शव जंगल में ही पड़े हैं।

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में गुरुवार को आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान मोर्चा संभाल रहे जवान। जागरण

सेना के हेलीकाप्टर से आतंकियों के छिपे स्थान की निगरानी पेज>>5

परंपरा से जुड़ाव

शिक्षा मंत्रालय ने देश के सभी हिस्सों से 75 से अधिक प्राचीन भारतीय खेलों को किया चिह्नित, नई पीढ़ी में पढ़ाई के साथ रोपे जाएंगे इन खेलों के भी बीज, देशभर से खोजे जा रहे इनके प्रशिक्षक

गिल्ली-डंडा और कंचे जैसे खेल भरेंगे बच्चों में नए रंग

अरविंद पांडेय • जागरण

नई दिल्ली : यदि आपके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और अब तक गिल्ली-डंडा, कंचे, कबड्डी, गुट्टी व राजा मंत्री-चोर सिपाही जैसे खेलों से परिचित नहीं हैं तो जल्द ही उन्हें इन परंपरागत प्राचीन भारतीय खेलों से परिचित होने का मौका मिल सकता है। आधुनिकता और तकनीक के इस दौर में तेजी से लुप्त हो रहे इन परंपरागत भारतीय खेलों को बचाने को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने एक नई मुहिम शुरू की है। जिसमें देश की नई पीढ़ी को इन भारतीय खेलों से स्कूली स्तर पर ही जोड़ा जाएगा। इनमें ऐसे परंपरागत खेलों को अधिक अहमियत दी जाएगी, जो समूहों में खेले जाते हैं। माना जा रहा है कि इससे बच्चों में सामाजिक जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद मिलेगी।

देश के अलग-अलग हिस्सों में प्राचीन समय से खेले जाने वाले करीब 75 भारतीय खेलों को अब तक इस पहल के तहत चिह्नित किया गया है। इनमें खो-खो, कबड्डी व गिल्ली-डंडा जैसे ऐसे खेल भी शामिल हैं, जो अलग-अलग नामों से देश के कई हिस्सों में और दुनिया के दूसरे देशों में खेले जाते हैं।

मंत्रालय फिलहाल कबड्डी की तर्ज पर इन खेलों के लिए एक स्टैंडर्ड नियम-कायदे बनाने में जुटा है। इसमें इन खेलों से जुड़े विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। अब तक कबड्डी, गिल्ली-डंडा, खो-खो और लगोरी या पिट्ठू जैसे खेलों के नियम कायदे और इसे खेलते हुए वीडियो अपलोड भी किए जा चुके हैं। बाकी खेलों को लेकर भी ऐसी तैयारी चल रही है।

मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, इस पहल के पीछे का उद्देश्य बच्चों को इन खेलों के जरिये भारतीय जड़ों से परिचित कराना है। इसका एक ढांचा तैयार किया जा रहा है। इन खेलों से जुड़े देशभर के प्रतिभाशाली लोगों की पहचान की जा रही है। स्कूलों में तैनात खेल तथा व्यायाम शिक्षकों को इसका प्रशिक्षण देने की तैयारी भी की जा रही है।

यह भी बताया गया है कि स्कूलों से इसका ब्योरा मांगा गया है। इसके साथ ही इन खेलों के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए देशभर में इससे जुड़ी प्रतियोगिताएं आयोजित करने जैसी पहल शामिल है। शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में की गई पहल को इससे जोड़कर देखा जा रहा है।

- आधुनिकता और तकनीक के इस दौर में तेजी से लुप्त होते जा रहे भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े हैं ये परंपरागत खेल

प्रतीकात्मक

यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पीथमपुर में ही जलेगा

जबलपुर : भोपाल में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री के जहरीले कचरे को पीथमपुर में जलाकर निष्पादित करने के ट्रायल रन (परीक्षण) में किसी तरह का नुकसान सामने नहीं आया है। यह बात मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में राज्य शासन की ओर से गुरुवार को प्रस्तुत स्टेटस रिपोर्ट में कही गई। कोर्ट को बताया गया कि ट्रायल रन सभी नियमों का पालन करते हुए किया गया था। तीनों आशा के अनुरूप सफल रहे। इनमें 10-10 टन कचरा जलाया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार 72 दिनों में पूरे जहरीले कचरे को जलाकर नष्ट किया जाएगा। (पेज-6)

धूम धड़ाका

आज का मैच (आइपीएल)

चेन्नई सुपरकिंग्स VS रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु

शाम 7:30 बजे | स्थान : चेन्नई

प्रसारण : स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क/ जियोहाटस्टार

लद्दाख को स्थायी तौर पर मिलेगी सेना की एक और डिवीजन

राज्य ब्यूरो, जागरण • जम्मू

- चीन से सुधरते रिश्तों के बावजूद अपनी रणनीतिक तैयारियों में ढिलाई नहीं बरत रही सेना
- सेना की 72 डिवीजन पूर्वी लद्दाख में होगी तैनात, उत्तरी कमान के अधीन करेगी कार्य

चीन से सुधरते रिश्तों के बीच भारतीय सेना लद्दाख में अपनी रक्षा तैयारियों में कोई ढिलाई नहीं बरतना चाह रही है। यही वजह है कि पर्वतीय क्षेत्र में युद्धकौशल में पारंगत सेना की विशेष डिवीजन को स्थायी तौर पर लद्दाख में तैनात रखने का निर्णय लिया गया है। फिलहाल इस नई डिवीजन के गठन की प्रक्रिया जारी है और इसका कार्यालय क्रियाशील हो चुका है। इसका मुख्यालय लेह में रहेगा। यहां बता दें कि लद्दाख में पहले से ही सेना की तीन डिवीजन तैनात हैं।

अलबत्ता, यह डिवीजन पहले लिए गए निर्णयानुसार, मांउटेन स्ट्राइक कोर के अधीन नहीं रहेगी। संबंधित सूत्रों ने बताया कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी की सुरक्षा का जिम्मा संभालने के लिए विशेष रूप से 72 डिवीजन के गठन का प्रस्ताव गलवन के बाद उपजे हालात व चीन की चालबाजियों से निपटने को आया था। योजना थी कि 72 डिवीजन पूर्वी लद्दाख के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी चीन से सटी सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगी। चीन से बढ़े गतिरोध के बीच सेना ने योजना में बदलाव करते हुए 72 डिवीजन को उत्तरी कमान के अधीन रखने का प्रस्ताव तैयार किया। इस पर रक्षा मंत्रालय ने भी मुहर लगा दी।

72 डिवीजन में होंगी तीन ब्रिगेड पेज>>7

****

3.8 डिग्री अधिक सामान्य से अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस गुरुवार को दर्ज किया गया। पीतमपुरा दिल्ली का सबसे गर्म इलाका रहा। यहां का तापमान 38.1 डिग्री रहा।

आज का मौसम

आसमान साफ रहेगा। 10 से 20 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी।

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
28 मार्च	34.0	18.0
29 मार्च	33.0	17.0
नोएडा		
28 मार्च	36.0	17.0
29 मार्च	35.0	16.0
गुरुग्राम		
28 मार्च	35.0	18.0
29 मार्च	35.0	16.0

डिग्री सेल्सियस में

न्यूज गैलरी

डूटा का विभिन्न मांगों के लिए धरना, दो घंटे नहीं लगी कक्षाएं

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (डूटा) ने गुरुवार को विभिन्न कालेजों में शिक्षक अधिकारों व समस्याओं के तत्काल निदान की मांग को लेकर धरने सभी कालेजों में धरना दिया। डूटा के आह्वान पर हुए धरने में डीयू के सभी कालेजों के शिक्षक शामिल हुए। इस दौरान मार्निंग कालेजों में सुबह 11 से एक बजे तक और ईवनिंग कालेजों में शाम चार से छह बजे तक कक्षाएं बाधित रहीं। हालांकि, धरने से पहले और बाद में कक्षाओं का संचालन हुआ। (जासं)

सतीश उपाध्याय के चुनाव को सोमनाथ भारती ने दी चुनौती

नई दिल्ली: मालवीय नगर से विधानसभा चुनाव में भाजपा नेता सतीश उपाध्याय की जीत को आप नेता सोमनाथ भारती ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में सतीश उपाध्याय पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया है। यह भी दावा किया गया है कि उनके खिलाफ एक आपराधिक शिकायत लंबित है। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने सोमनाथ भारती को सतीश उपाध्याय के खिलाफ लंबित मामले के दावे पर कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश देते हुए सुनवाई आठ अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। (जासं)

'विधानसभा में नहीं हो सकती कानून व्यवस्था पर चर्चा'

नई दिल्ली: विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी के पत्र का जवाब देते हुए सदन में कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था पर विधानसभा में चर्चा नहीं हो सकती। गुप्ता ने आतिशी के पत्र का जवाब देते हुए कहा कि विशेष उल्लेख नोटिस दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र के विषयों से संबंधित होने चाहिए। गुप्ता ने कहा कि कानून और व्यवस्था दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। इसलिए इस पर विधानसभा के अंदर चर्चा नहीं की जा सकती।। (जासं)

दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाने में बड़ा कदम है बजट

चर्चा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोलीं ▶ फिर से बनेगा यमुनापार विकास बोर्ड, वित्तीय लीकेज पर अंकुश लगाएगा प्रशासन

दिल्ली की मंडियों की दशा सुधारने का भी बजट में जोड़ा जाएगा प्रस्ताव

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा में बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने द्वारा सदन में रखे गए बजट को दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया। इसके साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। बजट के लिए एक लाख करोड़ जुटाए जाने के स्रोत के बारे में विपक्ष के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए विपक्ष को चिंता करने की जरूरत नहीं है। डबल इंजन की सरकार बजट भी जुटाएगी और काम भी करेगी। इसके साथ मुख्यमंत्री ने तर्क दिया कि प्रशासन इस तरह के वित्तीय लीकेज पर अंकुश लगाएगा ताकि दिल्ली के फंड का प्रभावी ढंग से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके, जिससे केंद्र पर निर्भर हुए बिना भी बजट लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार स्वयं भी एक लाख करोड़ जुटाने में सक्षम होगी।

इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष की नेता की मौजूदगी में पूर्व की आप की सरकार को भी लपेटा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पिछली आप सरकार ने पैसे की बर्बादी और भ्रष्टाचार किया है। अब यही पैसा दिल्ली के विकास पर खर्च होगा।उन्होंने आप सरकार की विभिन्न योजनाओं का जिक्र कर योजनाओं के नाम पर पैसे की बर्बादी वाली योजनाओं को गिनाया। जिसमें उन्होंने कोरोना महामारी से लेकर कुछ माह पिछले तक दिल्ली में रही आप सरकार की बखिया उधेड़ी। सीएम ने कहा कि इस लोगों ने पैसे की ही नहीं, लोगों के समय और बच्चों के भविष्य की भी चोरी की है। मुख्यमंत्री गुप्ता ने आप पर मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के आधिकारिक इंटरनेट मीडिया हैंडल को भी चुराने का आरोप लगाया। इसके साथ मुख्यमंत्री ने विधायकों द्वारा आए सुझावों को भी बजट में शामिल करने की घोषणा की है।जिसमें लक्ष्मीनगर से विधायक अभय वर्मा आदि द्वारा यमुनापार विकास बोर्ड के पुनर्गठन की मांग और दिल्ली की सभी मंडियों की दशा सुधारने की योजना शामिल है।

कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने कहा कि मुख्यमंत्री ने एक विकसित दिल्ली के संकल्प पत्र के क्रियावयन को शुरू करने लिए संकल्प के साथ इस बजट को दिल्ली की जनता को समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की दीदी रेखा जब सदन में वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश कर रही थीं तो उन्होंने बताया कि पिछली सरकार में कैसे तीन चौथाई बजट हर साल स्कीम में क्रियावयन की जगह प्रचार पर खर्च किया जाता था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का बजट दिल्ली को पुनर्जीवित करने वाला बजट है। यह बजट हमारी पार्टी के संकल्प पत्र को मूर्तरूप देने की गारंटी है। कहा कि हमारी पार्टी को लेकर इसी सदन में बहुत बातें की गई हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी को अनपढ़-गंवारों की पार्टी तक कहा गया। मंत्री सूद ने कहा कि आप बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, मगर दूसरे को कम आंकना और बोलना शालीनता नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बजट को बनाने की रूपरेखा ऐसे निराशाजनक माहौल में 33 दिन पहले ही शुरू हो गई थी, जब जनता के बीच जाने पर लोग हमसे यह नहीं कह रहे थे कि मेरे बच्चों के लिए बढ़िया कालेज बना देना। लोग कहते थे मेरा सीवर ठीक करा देना तो कोई कहता था कि मेरी सड़क ठीक करा देना।

इस बीच, विपक्ष की नेता आतिशी ने बजट की कड़ी आलोचना की और इसे आर्थिक सर्वेक्षण की अनुपस्थिति के कारण इसे खोखला अनुमान बताया। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली का राजकोषीय घाटा 13,000 करोड़ रुपये से अधिक के रिकार्ड पर पहुंच जाएगा। उन्होंने भाजपा सरकार पर राजस्व अनुमानों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया। बजट पर चर्चा में बजट पर चर्चा में सत्तापक्ष के सदस्य ओम प्रकाश शर्मा, मोहन सिंह बिष्ट, राजकुमार भाटिया, कुलदीप सोलंकी, अशोक गोयल, विपक्ष के सदस्य गोपाल राय, जरनैल सिंह, कुलदीप कुमार आदि ने भी बात रखी।

दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सदन में बोलती मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। सौजन्य :दिल्ली सरकार

हर राज्य का स्थापना दिवस मनाएगी दिल्ली सरकार

राज्य ब्यूरो, जागरण, नई दिल्ली: दिल्ली में हर राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत एक अप्रैल से होने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को घोषणा की कि हर राज्य का स्थापना दिवस राष्ट्रीय राजधानी में मनाया जाएगा, क्योंकि यहां सभी राज्यों के लोग रहते हैं। सभी राज्यों के लोग दिल्ली को अपना मानते हैं, ऐसे में उनकी भावनाओं को देखते हुए इस बारे में फैसला लिया गया है। दिल्ली विधानसभा में बजट चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्थापना दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। इसमें सबसे पहले एक अप्रैल को ओडिशा दिवस मनाया जाएगा। देश में राज्य 28 हैं। बाकी आठ केंद्र शाषित प्रदेश हैं, हालांकि अभी तक दिल्ली अपना स्थापना दिवस नहीं मनाती है।

बिजली वितरण कंपनियों की विनियामक परिसंपत्ति की हो जांच : आरडब्ल्यूए

राज्य ब्यूरो, जागरण, नई दिल्ली: दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने पिछले दिनों विधानसभा में बताया था कि बिजली वितरण कंपनियों (डिस्काम) की विनियामक परिसंपत्ति 27,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। इसके लिए उन्होंने पूर्व की आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि पूर्व सरकार की नाकामी से दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं पर यह बोझ बढ़ा है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के सदस्य भी डीईआरसी के सामने उठाते रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से इसकी कैग से जांच कराने की मांग की है।

बिजली की दरें घोषित करने के लिए डीईआरसी ने गुरुवार से दो दिवसीय जनसुनवाई शुरू की है। नार्थ दिल्ली रेजिडेंट वेलफेयर फेडरेशन के अध्यक्ष अशोक भसीन इसमें शामिल होकर बिजली कनेक्शन पर लागू स्थायी शुल्क व अन्य शुल्क में कमी करने, डिस्काम के खातों की जांच कराने की मांग की। आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने ईस्ट दिल्ली आरडब्ल्यूए ज्वाइंट फ्रंट के अध्यक्ष बीएस वोहरा, यूनाइटेड रेजिडेंट आफ दिल्ली (यूआरडी) के महासचिव सौरभ गांधी ने कहा कि भौतिक रूप से जनसुनवाई में उपस्थित होने के लिए उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई। आनलाइन का उन्होंने विरोध किया।

सड़कों पर अतिक्रमण हुआ तो अधिकारी जिम्मेदार

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

▶ लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने निर्धारित समय सीमा में एसटीएफ को कार्रवाई करने के दिए निर्देश

लोक निर्माण (पीडब्ल्यूडी) मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि पूरी दिल्ली में सारी सड़कों पर ही अतिक्रमण है। चाहे निगम की हो या पीडब्ल्यूडी की हो। हर जगह रेहड़ी-पटरी वालों ने कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा कि जिस विभाग की सड़क है यदि वो शिकायत करता है तो समय सीमा में एसटीएफ एक्शन ले, हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। एसटीएफ में निगम, जिला प्रशासन, पुलिस यातायात सभी विभाग रहते हैं। ताकि सामंजस्य से काम कर सकें।

उन्होंने कहा कि इसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होगी। अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। दोबारा अतिक्रमण होता है तो जिम्मेदारी जरूर किसी अधिकारी की होगी। सभी अतिक्रमण लिखित में दें और जब भी कार्रवाई हो तो वहां पर खड़े होकर साथ दें। एक सवाल के जवाब में प्रवेश वर्मा ने यह भी बताया कि इस साल भाजपा सरकार ने छठ पर्व का बजट 25 करोड़ से बढ़ा कर 55 करोड़ कर दिया है। यानी इस साल यह पर्व और भी धूमधाम से मनाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि चाहे छठ पूजा हो, कांवड़ सेवा, चाहे उर्स हो या फूल वालों की सैर हो। हर में सरकार पैसा देती है। यह हेड 1994 में शुरू हुआ था, उस समय भाजपा सरकार थी और मदनलाल खुराना मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि 1995 में इसका नाम बदलकर तीर्थ यात्रा विकास समिति कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सभी धार्मिक कार्यक्रमों का हेड भाजपा की सरकार ने शुरू किया था।

सदन में हंगामा : उधर दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के चौथे दिन उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब मंत्री प्रवेश वर्मा ने भाई शब्द का इस्तेमाल किया। सदन में प्रवेश वर्मा द्वारा 'कहां से लाए हो भाई' कहते ही आप नेता आक्रमक हो गए। उन्होंने सदन में खासा व्यवधान उत्पन्न किया। आप ने आरोप लगाया कि प्रवेश वर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को कहा कि कहां से लाते हो भाई। व्यवधान इतना बढ़ गया कि विधानसभा अध्यक्ष ने आप के कुलदीप कुमार एवं विशेष रवि को मार्शल के जरिए से सदन से बाहर निकलवा दिया।

अवैध मीट विक्रेताओं पर होगी कार्रवाई : प्रवेश वर्मा : मंत्री प्रवेश वर्मा ने नवरात्र शुरू से पहले गुरुवार को 'अवैध' मीट विक्रेताओं पर कार्रवाई की घोषणा की। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान, भाजपा विधायक करनैल सिंह ने नौ दिवसीय पर्व से पहले फुटपाथों और दुकानों में खुलेआम मीट बेचे जाने पर चिंता जताई। इस पर जवाब देते हुए वर्मा ने कहा, निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई कहीं अवैध रूप से बैठा है, तो हटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने विधायकों से अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अतिक्रमण की सूचना देने का आग्रह किया और आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को हल करने के लिए अभियान शुरू किया जाएगा।

मंत्री प्रवेश वर्मा गुरुवार को दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बोलते हुए। एएनआइ

दिल्ली की सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए सड़कों पर उतरेंगे अधिकारी

राज्य ब्यूरो, जागरण, नई दिल्ली:: दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने पर इस वर्ष हिंदू नववर्ष को भव्य तरीके से मनाने की तैयारी है। इसे ध्यान में रखकर 28 व 29 मार्च को पूरी दिल्ली में विशेष अभियान चलाया जाएगा। सफाई व्यवस्था खराब न हो इसके लिए मुख्यमंत्री ने नगर निगम के आयुक्त से लेकर जूनियर इंजीनियर तक को फील्ड में रहने और प्रत्येक दिन किसी वार्ड का निरीक्षण करने और साप्ताहिक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।

स्वच्छता एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने, बेसहारा पशुओं, सड़कों पर गड्ढे व धूल और सीवर जाम की समस्या हल करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शहरी विकास विभाग, नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली शहरी आश्रय विकास बोर्ड के अधिकारी के साथ बैठक की। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने हिंदू नववर्ष से पहले मंदिरों के आसपास सफाई का विशेष अभियान चलाने के साथ ही पूरी दिल्ली को साफ करने का निर्देश दिया। विधायक भी इसमें योगदान देंगे।

विधानसभा में अवैध हुक्काबार और बैंक्वेट हालों का मुद्दा गरमाया

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

▶ सदस्यों ने कहा, बैंक्वेट हाल के चलते लग रहा यातायात जाम, हुक्का बार की अवैध गतिविधियों पर उठे सवाल

दिल्ली के विभिन्न स्थानों में बैंक्वेट हालों के चलते लगने वाले यातायात जाम एवं औद्योगिक क्षेत्रों में छतों के ऊपर अवैध रूप से चल रहे हुक्काबार का मुद्दा भी बृहस्पतिवार को विधानसभा में गूंजा। सदन में जब सत्तापक्ष एवं विपक्ष के कई सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाया तो विधानसभा अध्यक्ष ने भी इस पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह समस्या दिल्ली के हर इलाके में है। इस गंभीर समस्या के समाधान को लेकर सरकार द्वारा जरुरी कार्रवाई की जानी चाहिए।

इसके बाद कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मामले की जांच कराने व पूरी रिपोर्ट सदन के समक्ष रखने की बात कही। हालांकि इस मुद्दे को लेकर आप विधायक जरनैल सिंह व मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के बीच बहस भी हुई। प्रश्नकाल के दौरान विश्वास नगर से भाजपा विधायक ओपी शर्मा ने शाहदरा व पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में बैंक्वेट हाल के चलते लगने वाले यातायात जाम व इनमें व्याप्त भारी अनियमितताओं का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि विवेक विहार, कडकडडूमा व आनंद विहार इलाके में कई बैंक्वेट चल रहे हैं। रिठाला से विधायक कुलवंत राणा ने भी अपने क्षेत्र में अवैध बैंक्वेट हाल के कारण जाम की समस्या को उठाया। विधायक मनोज शौकीन ने नांगलोई जाट में अवैध बैंक्वेट हालों के साथ साथ हुक्काबार चलने का मुद्दा उठाया। वहीं तिलक नगर से आप विधायक जरनैल सिंह ने दिल्ली के कई औद्योगिक इलाकों में अवैध रूप हुक्का बार चलने की बात कही। उन्होंने कहा कि मायापुरी, कर्मपुरा सहित कई अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में छतों के उपर हुक्काबार चल रहे हैं। इस पर मंत्री सिरसा ने कहा कि हुक्काबार व बैंक्वेट हालों की यह समस्या एक दम से पैदा नहीं हो गई है। यह समस्या पिछले दस सालों से हैं। सिरसा ने कहा कि यह भाजपा की सरकार है, हर समस्या को खत्म कर देगी। उन्होंने सदन को विश्वास दिलाते हुए कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी।

दंगे में हत्या कर शव नाले में फेंकने के मामले में 12 बरी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे के दौरान गोकलपुरी इलाके में एक युवक की हत्या कर शव नाले में फेंकने के मामले में कोर्ट ने 12 लोगों को बरी कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचल के कोर्ट ने पाया कि अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्ष्य और गवाहों के बयानों से इन पर आरोप साबित नहीं होते।

दंगे के दौरान 26 फरवरी 2020 में गोकलपुरी इलाके में दंगाइयों ने मेरठ के लखीपुरा स्थित शाहजहां कालोनी निवासी हमजा की हत्या कर शव को भागीरथी विहार नाले में फेंक दिया गया था। घटना के पांच दिन बाद शव नाले से बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर 13 घाव पाए गए थे। वह रेहड़ी पर खाने-पीने का सामान बेचता था। इस मामले में पुलिस ने लोकेश सोलंकी, पंकज शर्मा, सुमित चौधरी उर्फ बादशाह, अंकित चौधरी उर्फ फौजी, प्रिंस उर्फ डीजे वाला, ऋषभ चौधरी उर्फ तापस, जतिन शर्मा उर्फ रोहित, विवेक पांचाल उर्फ नंदू, हिमांशु आदि को आरोपित बनाया था।

अधिकारियों के खिलाफ लंबित मामलों पर नहीं होगी कोई कार्रवाई

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

▶ दिल्ली विस ने अधिकारियों से जुड़े सभी मामलों पर आगे कार्रवाई न करने का प्रस्ताव पास किया

आम आदमी पार्टी की सरकार में वरिष्ठ आइएएस से जुड़े मामलों में अब कोई कार्रवाई नहीं होगी। दिल्ली विधानसभा ने अधिकारियों से जुड़े सभी मामलों पर आगे कार्रवाई न करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। इस प्रस्ताव में दिल्ली के मुख्य सचिव एमएम कुट्टी सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों के मामले शामिल हैं। अधिकारियों से जुड़े मामलों में छठी और सातवीं विधानसभा की तीन समितियों (विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति और प्रश्न एवं संदर्भ समिति) को जांच करनी थी। सातवीं विधानसभा के भंग होने पर जांच आठवीं विधानसभा को सौंपी गई थी। आठवी विधानसभा में दिल्ली विधानसभा में मुख्य सचेतक अभय वर्मा के प्रस्ताव को पास कर लंबित मामलों पर आगे जांच करने पर रोक लगा दी गई है।

विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि नियम-183 के अंतर्गत प्रविधान का उपयोग बहुत कम और केवल महत्वपूर्ण मामलों में किया जाता है, जहां समिति सदन के भंग होने से पहले काम पूरा नहीं कर सकती। जबकि अधिकांश लंबित मामलों की या तो समितियों द्वारा जांच ही नहीं की गई या उन्हें कई वर्षों तक कोई रिपोर्ट प्रस्तुत किए बिना लंबित रखा गया। जबकि दिल्ली सरकार के अधिकारियों से जुड़े कुछ मामलों के कारण दिल्ली उच्च न्यायालय में केस भी दायर हुए थे। विधानसभाध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि छठी विधानसभा के 59 मामले और सातवीं विधानसभा के 69 मामले विशेषाधिकार समिति द्वारा लंबित रखे गए थे।

विजेंद्र गुप्ता। फाइल

अमेजन और फ्लिपकार्ट के गोदामों में छापेमारी, कम गुणवत्ता वाले सामान जब्त

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) की दिल्ली शाखा ने ई-कामर्स कंपनियों अमेजन व फ्लिपकार्ट के गोदामों पर छापेमारी कर कम गुणवत्ता वाले या नकली आइएसआइ मार्क का इस्तेमाल हुए 76 लाख रुपये के सामान को जब्त किया है। 19 मार्च को मोहन कोआपरेटिव औद्योगिक क्षेत्र में स्थित अमेजन के गोदामों में 15 घंटे से अधिक का तलाशी और जब्ती अभियान चला। जहां बिना आइएसआइ मार्क वाले व नकली आइएसआइ लेबल वाले 3,500 से अधिक उत्पाद जब्त किए गए। जब्त उत्पादों जैसे गीजर, फूड मिक्सर और अन्य बिजली के उपकरणों की कुल अनुमानित कीमत लगभग 70 लाख है।

बीआइएस के एक अधिकारी के अनुसार, इसी तरह त्रिनगर में स्थित फ्लिपकार्ट की सहायक कंपनी इंस्टाकार्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर की गई एक अन्य छापेमारी में बिना आइएसआई मार्क वाले स्पोर्ट्स फुटवियर का स्टाक बरामद हुआ। इस कार्रवाई के दौरान करीब छह लाख रुपये की कीमत के करीब 590 जोड़ी स्पोर्ट्स फुटवियर जब्त किए गए।

आप सरकार में कागजों से आगे नहीं बढ़ीं अनुसूचित जाति से जुड़ी योजनाएं

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

▶ कांग्रेस ने आप पर लगाया अनुसूचित जाति विरोधी होने का आरोप

▶ ज्यादातर योजनाओं में 50 प्रतिशत भी खर्च नहीं हो पाया आवंटित फंड

पूर्ववर्ती आप सरकार के कार्यकाल में अनुसूचित जाति से जुड़ी ज्यादातर योजनाएं कागजों से आगे नहीं बढ़ सकीं। समाज कल्याण विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार आप सरकार के आखिरी कार्यकाल वर्ष 2020-24 में स्लम बस्तियों में उत्थान के लिए 260 करोड़ रुपये आवंटन किए, लेकिन खर्च सिर्फ 120.58 करोड़ ही हुए। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना में चार वर्षों में 461 करोड़ आवंटित किए जबकि खर्च सिर्फ 32.21 करोड़ हुए। 2020-21 में 150 करोड़ बजट में एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ।

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत 2020-24 चार वर्षों में 180 करोड़ आवंटित हुए, लेकिन खर्च मात्र 4.40 करोड़ ही किए गए। वर्ष 22-23 में 70 करोड़ आवंटित बजट में से एक पैसा भी खर्च नहीं किया और 23-24 में बजट में 50 करोड़ की कटौती कर 20 करोड़ आवंटित हुए, जिसमें से सिर्फ एक लाख ही खर्च हुआ। ओबीसी और ईडब्लूएस छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के अंतर्गत चार वर्षों में 250 करोड़ बजट आवंटन में मात्र 4.21 करोड़ ही खर्च हुआ और यह राशि सिर्फ 21-22 में 70 करोड़ बजट आवंटन में एक वर्ष में खर्च हुए बाकी तीन वर्षों एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया। 2022-23 में अल्पसंख्यक एवं पिछड़े गरीबों के साथ बड़ा धोखा हुआ। 90 करोड़ का आकर्षक बजट आवंटन हुआ पर खर्च हुआ शून्य। केजरीवाल सरकार ने 2020-21 से 2023-24 के बीच अल्पसंख्यक, पिछड़ों एवं गरीबों के लिए रूपए 250 करोड़ का आकर्षक बजट किया पर धोखा देते हुए खर्चे सिर्फ रूपए 4.2 करोड़।

आम आदमी पार्टी अनुसूचित जाति की विरोधी है। पिछले 10 वर्षों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के कल्याण- उत्थान की योजनाओं को सिर्फ दस्तावेजों में चलाया। वादों को पूरा करने के नाम पर दिल्ली वासियों को भ्रमित करना का काम किया।

– देवेंद्र यादव, अध्यक्ष, दिल्ली कांग्रेस

आम आदमी पार्टी एवं अरविंद केजरीवाल ने अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग को योजनाओं के नाम पर गुमराह किया है। प्रचार पर भारी राशि खर्च की गई, लेकिन अनुसूचित जाति के लोगों को इसका लाभ नहीं दिया गया। – वीरेंद्र सचदेवा, अध्यक्ष, दिल्ली भाजपा

सर्वाधिक अंगदान होने के बाद भी ब्रेन डेड घोषित करने में सुस्ती अभियान में बाधक

चेतावनी

ब्रेन डेड मरीजों की रिपोर्ट नहीं भेज रहे अस्पताल, नोटो ने दी जुर्माना लगाने की चेतावनी, पिछले वर्ष ब्रेन डेड हुए 1,128 मरीजों के अंगदान से 3,236 मरीजों को हुई प्रत्यारोपण सर्जरी, आबादी के अनुपात में अंगदान की दर है कम

रणविजय सिंह ● जागरण

नई दिल्ली : देश में पिछले एक वर्ष में अब तक का सर्वाधिक अंगदान हुआ। इससे रिकार्ड अंग प्रत्यारोपण सर्जरी भी हुई। फिर भी अभी आबादी के अनुपात में अंगदान की दर बहुत कम है। ब्रेन डेड हुए मरीजों को मृत घोषित कर अंगदान कराने में अस्पतालों की सुस्ती इस अभियान में बाधक बन रही है।

इसके मद्देनजर सफदरजंग अस्पताल के परिसर में स्थित केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नोटो (राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन) ने एक बार फिर सभी राज्यों के स्वास्थ्य विभाग और सोटो (राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण) को पत्र लिखकर अस्पतालों के आइसीयू में ब्रेन डेड घोषित किए जाने वाले मरीजों की हर महीने रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। इसका पालन नहीं होने पर अस्पतालों पर जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। दिल्ली एनसीआर में ब्रेन डेड डोनर के अंगदान से 143 मरीजों को लिवर, किडनी, हृदय, फेफड़ा इत्यादि प्रत्यारोपित किया गया। लेकिन इसे और बढ़ाया जा सकता है। कैडेवर डोनर, जिसे मृत दाता भी कहा जाता है, वह व्यक्ति होता है जो ब्रेन डेड होने के बाद अपने अंगों को दान करता है। अंग प्रत्यारोपण, रिट्रीवल के लिए नोटो में कुल 966 अस्पताल पंजीकृत हैं। नोटो ने इन अस्पतालों को भी यह पत्र भेजा है। नोटो के निदेशक डा. अनिल कुमार द्वारा लिखे इस पत्र में कहा गया है कि मानव अंग ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम के तहत आइसीयू में ब्रेन डेड हुए मरीजों की पहचान और उनके अंगदान के लिए परिजनों को प्रेरित करना आवश्यक है। चिंता का विषय यह है कि बार-बार कहने के बावजूद ब्रेन डेथ की रिपोर्ट नहीं भेजी जा रही है। इससे अंगदान बढ़ाने के प्रयास प्रभावित हो रहे हैं। मौजूदा समय में देश में दस लाख की आबादी पर एक से भी कम अंगदान हो पाता है।

डा. अनिल कुमार ने कहा कि नोटो सीधे तौर पर अस्पतालों को आदेश जारी नहीं कर सकता। इसलिए राज्यों के स्वास्थ्य विभाग को अस्पतालों में ब्रेन डेड होने वालों की रिपोर्ट की सख्ती से निगरानी करने और पंजीकृत अस्पतालों से रिपोर्ट लेकर सोटो के माध्यम से हर महीने की सात तारीख को नोटो को भेजने के लिए कहा है। बहरहाल, नोटो को उम्मीद है कि इस पहल से अंगदान बढ़ाने में मदद मिलेगी। देश में सड़क हादसे में हर वर्ष करीब एक लाख लोगों की मौत होती है। इसके अलावा स्ट्रोक से हर वर्ष करीब साढ़े सात लाख लोगों की मौत होती है। लेकिन बहुत कम अस्पताल अंगदान करा पाते हैं। इस मामले में दिल्ली में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है।

प्रतीकात्मक

अंगदान और अंग प्रत्यारोपण के आकड़े

वर्ष	कैडेवर डोनर	कैडेवर डोनर प्रत्यारोपण	लाइव डोनर प्रत्यारोपण	कुल प्रत्यारोपण
2024	1,128	3,236	15,475	18,711
2023	1,099	2,935	15,443	18,378
बढ़ा	29	301	32	333

ट्रांसजेंडर व अंगदान करने वालों को आरएमएल में मिलेगा निशुल्क इलाज

राज्य ब्यूरो, जागरण, नई दिल्ली : वैसे तो सरकारी अस्पतालों में इलाज निशुल्क होता है, लेकिन विभिन्न बीमारियों की सर्जरी और प्रोसीजर में इस्तेमाल होने वाले इंप्लांट का खर्च बीपीएल श्रेणी के मरीजों को छोड़कर अन्य मरीजों को भुगतान करना पड़ता है। सीटी स्कैन, एमआरआइ जैसे रेडियोलाजी जांच का शुल्क भी निर्धारित होता है, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आरएमएल अस्पताल ने बुधवार को एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है, इसके तहत 13 श्रेणियों के मरीजों को अस्पताल में पूरी तरह निशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रेस की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : मीडिया के लेख को हटाने की मांग वाली एक कंपनी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला है। पत्रकारों को कानूनी प्रतिशोध के डर के बिना पेशेवर निर्णय का प्रयोग करने के लिए कुछ हद तक स्वतंत्रता की आवश्यकता है। अदालत की उक्त टिप्पणी एक कंपनी की उस याचिका पर आई जिसमें एक मीडिया फर्म द्वारा अपमानजनक लेख को हटाने की मांग की गई थी।

कंपनी ने दावा किया कि लेख अपमानजनक था और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। न्यायालय ने दावे को खारिज करते हुए कहा कि कंपनी और उसके संस्थापकों ने लेख के प्रकाशन के एक साल बाद रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था।

****

669 एशियाई शेरों की मौत पिछले पांच वर्षों में हुई है, लेकिन शिकार के कारण कोई मौत दर्ज नहीं की गई। गुजरात में गीर का जंगल एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है।

पुतिन इसी साल आएंगे भारत, द्विपक्षीय संबंधों का नया एजेंडा होगा तय

- प्रधानमंत्री मोदी के आमंत्रण को रूसी राष्ट्रपति ने किया स्वीकार
- भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पुतिन
- रूसी विदेश मंत्री लावरोव बोले- अब हमारी बारी है

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। वह इस वर्ष के अंत में नई दिल्ली में होने वाले रूस-भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आएंगे। यह जानकारी रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने 'भारत-रूस : एक नए द्विपक्षीय एजेंडे की ओर' विषय पर आयोजित सेमिनार में दी। इस कार्यक्रम में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए।

लावरोव और जयशंकर ने संकेत दिया कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों के नए एजेंडे पर कार्य कर रहे हैं, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हर वर्ष भारत और रूस के बीच शीर्षस्तरीय सम्मेलन आयोजित होते हैं। दिसंबर 2021 में पुतिन भारत आए थे, जबकि जुलाई 2024 में पीएम मोदी रूस गए थे।

लावरोव ने कहा- 'पीएम मोदी के आमंत्रण को राष्ट्रपति पुतिन ने स्वीकार कर लिया है और उनकी यात्रा की तैयारियां चल रही हैं।' लावरोव ने यह भी बताया कि पिछले साल फिर से प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेन्द्र मोदी ने पहली विदेश यात्रा रूस की ही की थी। उन्होंने कहा- अब हमारी बारी है।

व्लादिमीर पुतिन। फाइल/रायटर

फरवरी 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध की शुरू होने के बाद भारत ने जिस तरह से इस मुद्दे पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है, उसकी लावरोव ने भी काफी सराहना की।

उन्होंने भारत को रूस की कूटनीति के लिए एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बताया और कहा कि दोनों देशों के रिश्ते धरातल पर काफी मजबूत हैं। द्विपक्षीय कारोबार का आकार 60 अरब डालर को पार कर गया है, जो कि ऐतिहासिक है। हम बहुध्रुवीय व्यवस्था का समर्थन करते हैं

विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत रूस के साथ अपने संबंधों का बहुत सम्मान करता है और दोनों देश एक-दूसरे के मुख्य हितों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि भारत इन संबंधों को और आगे बढ़ाना चाहता है और सहयोग के नए क्षेत्रों को शामिल करने की इच्छा रखता है। दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय कारोबार को 100 अरब डालर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। बता दें कि रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से भारत ने दोनों पक्षों से बराबर स्तर पर संपर्क बनाए रखा है।

भारत आएंगे चिली के राष्ट्रपति, लीथियम आपूर्ति पर समझौता संभव

- दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम उत्पादक देश है चिली
- अपने कुल लिथियम उत्पादन का 80% अभी चीन को करता है निर्यात

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

दक्षिण अमेरिकी देश चिली के युवा राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट एक अप्रैल से पांच अप्रैल तक भारत का दौरा करेंगे। यह चिली के किसी राष्ट्रपति का 16 वर्षों बाद भारत दौरा होगा। इसको लेकर भारत सरकार बेहद उत्साहित है। भारत की खास तौर पर नजर चिली के लीथियम भंडारों पर है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी है। भारत इस संदर्भ में चिली के साथ आधिकारिक समझौता करने के लिए उत्सुक है।

चिली विश्व का सबसे बड़ा लीथियम उत्पादक (वैश्विक भंडार का 52 प्रतिशत) देश है। यह अपने कुल लीथियम उत्पादन का 80 प्रतिशत चीन को निर्यात करता है। यह ध्यान देने योग्य है कि चिली जैसे लैटिन अमेरिकी देशों के साथ संबंध मजबूत करने में चीन भारत से काफी आगे है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि राष्ट्रपति फोंट की आगामी यात्रा भारत की क्रिटिकल मिनिरल्स की खोज में कितनी सहायक होती है। चिली के राष्ट्रपति की यह यात्रा भारत की दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ संबंधों को नए आयाम देने की कोशिश के रूप में भी देखी जा रही है। यह संभावना है कि चिली के साथ एफटीए पर भी सहमति बने।

गैब्रियल बोरिक फोंट। फाइल

दक्षिण अमेरिकी देशों में पैठ बनाने में काफी आगे है चीन

वैसे चीन ने पहले ही इन देशों की आर्थिक संभावनाओं को भांप लिया है। उदाहरण के लिए, चीन और चिली के बीच 2023 में 57 अरब डालर का द्विपक्षीय कारोबार हुआ, जबकि भारत और चिली के बीच यह आंकड़ा एक अरब डालर से भी कम है। चिली ने 2023 में कुल 7.72 अरब डालर का लीथियम निर्यात किया, जिसमें से 6.02 अरब डालर केवल चीन को गया। चिली और भारत के बीच द्विपक्षीय कारोबार 2020 की तुलना में 2024 में 1545 करोड़ रुपये से बढ़कर 3843 करोड़ रुपये हो गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आमंत्रण पर चिली के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं। उनके साथ एक उच्चस्तरीय दल होगा, जिसमें चिली सरकार के प्रमुख मंत्री, सांसद, निजी उद्यमी और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। यह बोरिक फोंट की पहली भारत यात्रा होगी। एक अप्रैल को फोंट की पीएम मोदी से द्विपक्षीय वार्ता होगी। बता दें कि चिली के साथ भारत के संबंध काफी पुराने हैं और यह दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश है जिसने 15 अगस्त, 1947 को अपने प्रतिनिधि को भेजा था।

दो वर्षों में प्राथमिक स्कूलों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या आठ प्रतिशत घटी

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने गुरुवार को लोकसभा को बताया कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में वर्ष 2023-24 में स्कूलों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या में चिंताजनक गिरावट दर्ज की गई है। खासकर प्राथमिक स्तर पर, जहां 2021-22 की तुलना में इस संख्या में लगभग आठ प्रतिशत की गिरावट आई है।

उइके ने बताया कि प्राथमिक स्तर पर आदिवासी छात्रों का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 2021-22 में 103.4 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 97.1 प्रतिशत हो गया है। इसकी तुलना में, सभी समुदायों के छात्रों का जीईआर 2021-22 में 100.13% से घटकर 2023-24 में 91.7% हो गया। आंकड़ों से पता चला है कि माध्यमिक स्तर (कक्षा 9-10) पर आदिवासी छात्रों का जीईआर 2021-22 में 78.1% से घटकर 2023-24 में 76.9 प्रतिशत हो गया। सभी समुदायों के छात्रों के लिए माध्यमिक स्तर पर जीईआर 2021-22 में 79.56 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 77.4 प्रतिशत हो गया।

एमएसपी से कम पर फसलों की खरीदारी नहीं करें राज्य : केंद्र

दालों का बफर स्टाक न्यूनतम स्तर पर पहुंचा, स्टाक बढ़ाने का प्रयास

बफर स्टाक में कम से कम 35 लाख टन दाल होना है बेहद जरूरी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

किसान हित में केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से किसी भी हाल में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम कीमत पर फसलों की खरीदारी नहीं करने का आग्रह किया है। सरकार का सबसे अधिक जोर दलहन खरीद पर है, क्योंकि दाल का बफर स्टाक अभी न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है और ऐसी स्थिति में अगले चार वर्षों के भीतर दलहन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य आसान नहीं है। कीमतों पर नियंत्रण रखते हुए देश की विशाल आबादी को दाल की आपूर्ति के लिए बफर स्टाक में कम से कम 35 लाख टन दाल होनी चाहिए, ताकि दाम बढ़ने पर बाजार में हस्तक्षेप किया जा सके। मगर बफर स्टाक में मानक से अभी आधी मात्रा में ही दाल उपलब्ध है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि केंद्र सरकार किसानों के साथ उपभोक्ताओं की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है।

शिवराज सिंह चौहान। फाइल

दालों का घरेलू उत्पादन बढ़ाने, किसानों को अत्यधिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने एवं दलहन आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत राज्यों के उत्पादन के सौ प्रतिशत अरहर, उड़द और मसूर खरीद को मंजूरी दी है। बजट में भी अपनी आवश्यकता के अनुसार दलहन उत्पादन का संकल्प जताया जा चुका है। इसके लिए अगले चार वर्षों तक इन तीन तरह की दालों की सारी उपज की खरीदारी की जाएगी। चालू खरीफ मौसम में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं तेलंगाना में अरहर खरीद को मंजूरी दी गई है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश में अरहर की कीमत अभी एमएसपी से अधिक चल रही है। इसलिए यहां खरीदारी की रफ्तार सुस्त है। कर्नाटक में खरीद की अवधि को 90 दिनों से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं तेलंगाना में नेफेड एवं एनसीसीएफ के जरिये अभी तक 2.46 लाख टन अरहर खरीदी जा चुकी है।

कृषि मंत्री ने बताया कि दाल भंडार को समृद्ध करने के लिए रबी मौसम के दौरान चना खरीद को भी मंजूरी दी गई है। पीएम-आशा योजना को 2025-26 तक बढ़ाया गया है। इसके तहत किसानों से एमएसपी पर दालों एवं तिलहनों की खरीद होती रहेगी। चालू रबी मौसम में चने की खरीदारी के लिए कुल स्वीकृत मात्रा 27.99 लाख टन है। तिलहन की कमी को देखते हुए 28.28 लाख टन सरसों की भी खरीदारी होगी। दाल उत्पादक प्रमुख राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात शामिल हैं। मसूर की कुल स्वीकृत मात्रा 9.40 लाख टन है। सरकार ने किसानों को पंजीकरण और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नेफेड और एनसीसीएफ पोर्टलों का उपयोग सुनिश्चित किया है।

धनखड़ ने शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस खारिज किया

नई दिल्ली, प्रेट्र: राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस गुरुवार को खारिज कर दिया। शाह ने अपने बयान को प्रमाणित करने के लिए 1948 की एक सरकारी विज्ञप्ति का हवाला दिया था कि कांग्रेस के एक नेता प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के प्रबंधन का हिस्सा थे। धनखड़ ने विशेषाधिकार हनन नोटिस को खारिज करते हुए कहा कि मैंने इसे ध्यानपूर्वक पढ़ा है। मुझे लगता है कि इसमें कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के विशेषाधिकार हनन नोटिस पर अपनी व्यवस्था में धनखड़ ने कहा कि शाह ने कोई उल्लंघन नहीं किया है और इस सप्ताह की शुरुआत में एक बहस के दौरान उनके बयान सत्य का पूर्ण अनुपालन कर रहे थे। सभापति ने आगे कहा कि मीडिया में चर्चा पाने के लिए विशेषाधिकार हनन का जल्दबाजी में हवाला दिया गया। साथ ही सभापति ने सदन की आचार समिति से कहा कि वह आसन के साथ संवाद जारी करने या नोटिस जारी करने जैसे मुद्दों पर सांसदों के आचरण पर नए दिशानिर्देश बनाए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी पर आक्षेप लगाने का आरोप लगाते हुए शाह के खिलाफ नोटिस दिया था।

अमेरिका की टैरिफ धमकियों पर विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना, मांगा स्पष्टीकरण

- राज्यसभा में की सरकार से देश का रुख स्पष्ट करने की मांग
- ट्रेड वार से निर्यात में गिरावट, एफडीआइ में कमी के प्रति चेताया
- उच्च सदन ने वित्त विधेयक लोस को लौटाया, बजट की प्रक्रिया हुई पूरी

कांग्रेस सांसद पी. चिदंबरम गुरुवार को राज्यसभा में बोलते हुए। एएनआइ

नई दिल्ली, प्रेट्र : राज्यसभा में वित्त विधेयक, 2025 पर चर्चा के दौरान गुरुवार को विपक्षी सदस्यों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों पर चिंता व्यक्त की और सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने सरकार से देश का रुख स्पष्ट करने की मांग की और कहा कि इस मुद्दे पर न तो संसद में कोई चर्चा हुई और न ही विपक्षी पार्टियों से कोई विचार-विमर्श किया गया। राज्यसभा ने गुरुवार को 35 सरकारी संशोधनों के साथ वित्त विधेयक, 2025 लोकसभा को लौटा दिया और इसी के साथ एक फरवरी को शुरू हुई 2025-26 की बजट प्रक्रिया पूरी हो गई।

राज्यसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए चिदंबरम ने सचेत किया कि ट्रेड वार से निर्यात में गिरावट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कमी, उच्च मुद्रास्फीति व मुद्रा का अवमूल्यन होगा। उन्होंने कहा कि भारत को कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी व जापान जैसे देशों के साथ खड़ा होना चाहिए और टैरिफ एवं ट्रेड वार से बचने के लिए हर सामूहिक प्रयास करना चाहिए।

दो अप्रैल से लागू होने वाले ट्रंप टैरिफ का जिक्र करते हुए पूर्व वित्त मंत्री ने कहा, 'सरकार का जवाब क्या है? भारत का जवाब क्या है? नीति पर कोई बयान नहीं दिया गया है, संसद में कोई चर्चा नहीं हुई और विपक्षी पार्टियों के साथ कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया। सरकार ने अपने सभी पत्ते छिपाकर रखे हैं, अगर कोई हैं।'

बता दें कि अमेरिका ने भारत समेत कई देशों पर पारस्परिक टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इससे दुनियाभर में कारोबार प्रभावित होने की आशंका है। कई देशों ने अमेरिकी घोषणा खिलाफ अपने हित में जबावी कार्रवाई की घोषणा की है। लेकिन भारत की ओर से अभी इस दिशा में ठोस कार्रवाई होना शेष है।

चिदंबरम ने कहा, 'टैरिफ वार से ट्रेड वार छिड़ेगा। इससे पूरी दुनिया को नुकसान होगा।' उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप के दबाव में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 में विभिन्न वस्तुओं पर सीमा शुल्क घटा दिया जिनमें मोटर वाहन, यात्री कारें, वस्तुएं, मालवाहक वाहन, मोटरसाइकिलें, साइकिलें और यहां तक कि खिलौने भी शामिल हैं। तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष ने कहा कि दो अप्रैल को सुनामी आ रही है जो भारत की निर्यात से आय के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। उन्होंने हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर नकदी मिलने को नोटबंदी की विफलता करार दिया। चर्चा में आप के राघव चड्ढा, राजद के एडी सिंह, वाईएसआरसीपी के अयोध्या रामी रेड्डी, आइयूएमएल के अब्दुल वहाब, राकांपा के प्रफुल्ल पटेल ने भी हिस्सा लिया।

रोहिंग्या या बांग्लादेशी अशांति फैलाने आएंगे तो होगी कठोर कार्रवाई : शाह

प्रथम पृष्ठ से आगे

शाह ने बताया कि भारत का डायसपोरा 146 देशों में फैला हुआ है। प्रवासियों के भ्रमण का देशों की आर्थिक मजबूती से सीधा संबंध नहीं है। वे विश्व की संस्कृति, शिक्षा और विज्ञान में योगदान देना चाहते हैं। हमारे लगभग 1.72 करोड़ एनआरआइ हैं। उनके सुचारू आवागमन और चिंताओं के निराकरण के लिए यह विधेयक लाया गया है। चूंकि, पूरी दुनिया के अर्थतंत्र में भारत ब्राइट स्पाट बनकर उभरा है। भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने जा रहा है, इसलिए विश्वभर के लोगों का भारत आना स्वाभाविक है।

गृह मंत्री ने चिंता जताते हुए कहा कि हमारे इमिग्रेशन का स्केल और साइज बहुत बड़ा है, और इसी तरह देश में शरण लेकर इसे असुरक्षित करने वालों की संख्या भी बड़ी है। इन दोनों को संतुलित करना आवश्यक है। यदि रोहिंग्या या बांग्लादेशी यहां अशांति फैलाने आएंगे तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा विधेयक की धारा 3 में प्रवेश निषेध के प्रविधान का विरोध करने पर शाह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो खतरा पाया जाएगा, उसे प्रवेश की अनुमति कतई नहीं दी जाएगी।

बंगाल सरकार नहीं दे रही फेंसिंग के लिए जमीन, इसलिए आ रहे घुसपैठिए : सांसद सुखदेव भगत द्वारा बंगाल में घुसपैठ रोकने में बीएसएफ की नाकामी का आरोप लगाए जाने पर शाह ने टीएमसी सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि हमारी बांग्लादेश से सटी हुई सीमा 2216 किलोमीटर है। 563 किमी सीमा खुली है। 450 किलोमीटर बार्डर क्षेत्र में फेंसिंग के लिए बंगाल सरकार भूमि नहीं दे रही। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी सरकार को दस रिमाइंडर लिखे गए हैं। गृह सचिव ने बंगाल के मुख्य सचिव के साथ सात बैठकें कीं, लेकिन राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही। वहां फेंसिंग लगाने जाएं तो सत्ताधारी दल का कैडर हुड़दंग मचाता है। घुसपैठियों और बांग्लादेशियों के दिल्ली तक आ जाने के आरोप पर शाह ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, तब असम से आते थे लेकि घुसपैठिये बंगाल से आते हैं।

चीन की ब्रह्मपुत्र बांध परियोजना पर नजर रख रही सरकार : कीर्ति वर्धन

नई दिल्ली, प्रेट्र : विदेश राज्यमंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सरकार ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित सभी घटनाक्रमों पर सावधानीपूर्वक नजर रख रही है, जिसमें चीन द्वारा जलविद्युत परियोजना बनाने की योजना भी शामिल है। सरकार देश के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

सिंह ने कहा कि भारत सरकार अपने हितों की रक्षा के लिए सीमा पार नदियों के मुद्दे पर चीन के साथ संपर्क में बनी हुई है। ब्रह्मपुत्र के निचले इलाकों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए 'निवारक और सुधारात्मक उपाय' किए जा रहे हैं।

गौरतलब है कि विदेश मंत्रालय से पूछा गया था कि क्या यह सच है कि चीन ने यारलुंग सांगपो पर एक मेगा जलविद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जबकि भारत ने इसके निचले इलाकों में जल प्रवाह और पारिस्थितिकी स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चिंता जताई है।

राहुल पर टिप्पणी मामले में विपक्ष गोलबंद, स्पीकर से की शिकायत

- आइएनडीआइए के नेताओं ने नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देने से लेकर बिरला की टिप्पणी का राजनीतिकरण किए जाने का उठाया मुद्दा
- डिप्टी स्पीकर पद खाली होने, विपक्षी सांसदों के माइक बंद किए जाने, स्थगन प्रस्ताव को निष्क्रिय बनाने जैसे आठ मुद्दों पर जाहिर की चिंता

लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई गुरुवार को संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए। एएनआइ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की टिप्पणियों का सत्तापक्ष की ओर से राजनीतिकरण करने पर गंभीर सवाल उठाते हुए बिरला से मुलाकात की। गुरुवार को हुई इस मुलाकात में विपक्षी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने सदन में राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिए जाने पर क्षोभ जाहिर करते हुए एक पत्र भी सौंपा। विपक्षी दलों ने इस पत्र में नेता प्रतिपक्ष को बोलने का अवसर नहीं देने, लोकसभा डिप्टी स्पीकर का अब तक चुनाव नहीं कराए जाने से लेकर विपक्षी सांसदों के माइक बंद करने जैसे आठ मुद्दे उठाए हैं।

विपक्ष की ओर से स्पीकर को सौंपे गए पत्र में कार्य मंत्रणा समिति के निर्णयों की अनदेखी, स्थगन प्रस्ताव नोटिस को पूरी तरह निष्क्रिय बना दिए जाने, सदस्यों के निजी विधेयकों व प्रस्तावों की उपेक्षा, बजट एवं अनुदान मांगों पर चर्चा में प्रमुख मंत्रालयों को शामिल नहीं करना, नियम-193 के तहत बेहद कम चर्चाएं करना और सदन में मामले उठाने के दौरान विपक्षी सदस्यों के माइक्रोफोन बंद कर दिए जाने जैसे विषय उठाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि जब भी विपक्षी सांसद कोई मुद्दा उठाते हैं तो उनके माइक्रोफोन बंद कर दिए जाते हैं। इसके विपरीत सत्तारूढ़ पार्टी के मंत्री या सांसद जब भी बोलना चाहते हैं तो उन्हें तुरंत बोलने की अनुमति मिल जाती है। विपक्ष के अनुसार, सदन में यह एकतरफा नियंत्रण लोकतांत्रिक बहस की भावना को कमजोर करता है।

स्पीकर से इस मुलाकात में लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई, द्रमुक के ए. राजा, तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव, शिवसेना (यूबीटी) के नेता अरविंद सावंत, एनसीपी (एसपी) की सुप्रिया सुले के साथ राजद, आइयूएमएल, एमडीएमके और आरएसपी के भी नेता शामिल थे। गौरव गोगोई ने प्रतिनिधिमंडल की स्पीकर से मुलाकात के बाद कहा कि विपक्षी नेताओं के संयुक्त हस्ताक्षर का एक पत्र बिरला को सौंपा गया है, जिसमें सदन के संचालन में नियमों-परंपराओं की धज्जियां उड़ाए जाने पर अपनी सामूहिक चिंता और निराशा व्यक्त की है।

स्पीकर की ओर से नियम-349 का संदर्भ लेकर नेता विपक्ष पर टिप्पणी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि वह किस विशिष्ट घटना का उल्लेख कर रहे थे, यह स्पष्ट नहीं है। साथ ही हमने स्पीकर का ध्यान आकृष्ट किया कि किस तरह उनकी टिप्पणी का इस्तेमाल कर दुष्प्रचार और राजनीति की जा रही है।

विपक्षी नेताओं के पत्र में परंपरा का हवाला देते हुए कहा गया है कि जब भी नेता प्रतिपक्ष खड़े होते हैं तो उन्हें बोलने की अनुमति दी जाती रही है। मगर मौजूदा सरकार बार-बार विपक्ष के नेता को बोलने का अवसर देने से इन्कार कर रही है। यह पिछली प्रथाओं से अलग है, जब टकराव की स्थिति में भी विपक्ष के नेता की बात सुनी जाती थी। लोकसभा डिप्टी स्पीकर का पद 2019 से ही रिक्त होने को अभूतपूर्व बताते हुए कहा गया है कि सदन की तटस्थता और कामकाज में उपाध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, फिर भी सरकार चुनाव कराने में विफल रही है। स्थगन प्रस्ताव के संबंध में शिकायत की गई है कि इसे अब पूरी तरह नजरअंदाज या सरसरी तौर पर खारिज कर विपक्षी सांसदों को तत्काल सार्वजनिक मुद्दे उठाने से वंचित किया जा रहा है।

कार्यशाला

अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला के लिए भारत आए कई देशों के प्रतिनिधियों ने साझा की चुनौतियां, कई देशों के प्रतिनिधियों ने इस योजना से सीख लेकर अपने यहां लागू करने की जताई इच्छा

भारत की भूमि स्वामित्व योजना ने विकासशील देशों का खींचा ध्यान

जितेंद्र शर्मा • जागरण

नई दिल्ली : भूमि के स्वामित्व की चुनौती सिर्फ भारत के सामने ही नहीं है, बल्कि दुनिया के कई विकासशील देशों के सामने यही संकट है। लिबेरिया, सिएरा लियोन और टोगो जैसे कई देश हैं, जो इस मामले में भूमि स्वामित्व के पुराने ढर्रे, भ्रष्टाचार व राजनीतिक हस्तक्षेप जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। अब उन्हें भारत की स्वामित्व योजना में समाधान दिखाई दे रहा है। यह तथ्य कई बार सामने आ चुका है कि न्यायपालिका पर एक बहुत बड़ा बोझ भूमि विवाद के मुकदमों का भी है। चुनौती बड़ी है, लेकिन इससे निपटने की दिशा में भारत सरकार ने भूमि दस्तावेजों के डिजिटलीकरण और सेटेलाइट सर्वे जैसे कदम उठाए हैं। खासतौर पर पंचायतीराज मंत्रालय की स्वामित्व योजना कारगर साबित हो रही है। तंजानिया की भूमि प्रशासन की सहायक आयुक्त हेलेन नजाऊ ने विशेष रूप से भूमि विवादों को हल करने और भूमि प्रबंधन में सुधार करने के लिए भारत की तकनीक से सीखने में रुचि दिखाई है।

भूमि स्वामित्व योजना की बढ़ रही वैश्विक स्वीकार्यता। प्रतीकात्मक

पंचायतीराज मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा 'भूमि प्रशासन' पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला में शामिल होने के लिए अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के 22 देशों के 44 वरिष्ठ अधिकारी आए हैं। कार्यशाला के कुल छह दिन हैं। गुरुग्राम स्थित हरियाणा इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दो दिन के अकादमिक सत्रों में वह भारत की स्वामित्व योजना के बारे में जान-समझ चुके हैं। गांवों का दौरा कर स्वामित्व योजना के तहत होने वाले ड्रोन सर्वे व अन्य तकनीकी-विधायी प्रक्रिया का व्यावहारिक ज्ञान ले चुके हैं। इसके साथ ही कुछ देशों के प्रतिनिधियों ने भूमि प्रशासन संबंधी उन चुनौतियों को सभी के साथ साझा भी किया, जिनका सामना उनके देश कर रहे हैं। जैसे कि लिबेरिया से आए लिबेरिया लैंड अथारिटी के आयुक्त महमूद सोलोमन और निदेशक एन. सिलवेस्टर एन. बुंदू ने अपने प्रस्तुतीकरण में बताया कि उनके देश में संसाधनों की सीमित क्षमता है। उनकी तुलना में भूमि संबंधी विवाद कहीं अधिक हैं। इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप भी उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है।

सिएरा लियोन की मिनिस्ट्री आफ लैंड, हाउसिंग एंड कंट्री प्लानिंग के प्रोफेशनल हेड ताम्बा एस. दाऊद और निदेशक राष्ट्रीय नियोजन साहर एम. कनावा ने विस्तार से अपने देश की परिस्थितियों के बारे में बताया कि 2015 की राष्ट्रीय भूमि नीति और 2022 के अधिनियमों से पहले सिएरा लियोन में भूमि प्रशासन को लेकर बिल्कुल स्पष्टता नहीं थी।

टोगो गणराज्य से शहरी नियोजन, आवासन एवं भूमि सुधार मंत्रालय के महानिदेशक डा. एफो बिजो और नियोजक अबू एदोमी ने अपने देश के हालात साझा किए। बताया कि देश के बड़े हिस्से में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रथागत अधिकार अभी भी प्रचलित है। वैश्विक चुनौतियों की इन चर्चा के बीच स्वामित्व योजना की सफलता ने सभी को प्रभावित किया है। कई देशों के प्रतिनिधियों ने इस योजना से सीख लेने और इन तकनीकी विधियों को अपने यहां लागू कराने की इच्छा जाहिर की है। लेसोथो के प्रतिनिधि और भूमि सर्वेक्षक लेबित्सा बेन लेबित्सा ने बताया कि लेसोथो में ड्रोन सर्वेक्षण का उपयोग केवल टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण के लिए किया गया है न कि कैडस्ट्रल सर्वेक्षणों के लिए। वह अब भारत से प्रेरित होकर अपने देश में कैडस्ट्रल सर्वे के लिए ड्रोन को अपनाने पर विचार कर रहे हैं।

****

कह कर रहेंगे माधव जोशी

11 हजार किलो बारूद रखा गया था गोवा में विस्फोट प्रभावित फैक्ट्री के गोदाम में। पिछले सप्ताह गोला-बारूद की फैक्ट्री के गोदाम में हुए विस्फोट की जांच से यह जानकारी मिली है।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 28 मार्च, 2025

भाषा विवाद पर योगी का बयान राजनीतिक ब्लैक कामेडी : स्टालिन

पलटवार ▶ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने परिसीमन पर भी उत्तर प्रदेश के सीएम की टिप्पणियों की तीखी आलोचना की

कहा, किसी भाषा का नहीं, उसे थोपने और अंधराष्ट्रवाद का विरोध किया जा रहा

एमके स्टालिन।

चेन्नई, प्रेट्र : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने परिसीमन और त्रि-भाषा नीति विवाद पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हालिया टिप्पणियों की तीखी आलोचना की है। अपने समकक्ष पर निशाना साधते हुए स्टालिन ने उनकी टिप्पणी को ''राजनीतिक ब्लैक कामेडी'' करार दिया और कहा कि उनका राज्य किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहा है, बल्कि उसे ''थोपने और अंधराष्ट्रवाद'' का विरोध कर रहा है। उधर, द्रमुक सांसद कनिमोरी ने भी योगी पर कटाक्ष करते हुए उनकी 'विभाजनकारी राजनीति'' वाली टिप्पणी पर कहा कि जब भाजपा का कोई व्यक्ति, खासकर यूपी के सीएम विभाजनकारी राजनीति की बात कर रहे हों तो यह दुनिया का ''सबसे बड़ा मजाक'' है।

बहरहाल, स्टालिन उत्तर प्रदेश के सीएम के उन कथित आरोपों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे कि द्रमुक सरकार भाषा के मुद्दे का उपयोग करके विभाजनकारी रणनीति में लिप्त है। स्टालिन ने अपने एक्स पोस्ट पर दावा किया कि दो भाषा नीति और निष्पक्ष परिसीमन पर तमिलनाडु की निष्पक्ष और दृढ़ आवाज ''पूरे देश में गूंज रही है और भाजपा इससे स्पष्ट रूप से घबरा गई है। और, अब माननीय योगी आदित्यनाथ हमें नफरत पर व्याख्यान देना चाहते हैं? कृपया हमें छोड़ दें। यह विडंबना नहीं है - यह सबसे काली राजनीतिक कामेडी है। हम किसी भाषा का विरोध नहीं करते; हम इसे थोपने और अंधराष्ट्रवाद का विरोध करते हैं। यह वोट के लिए दंगा करने की राजनीति नहीं है। यह सम्मान और न्याय की लड़ाई है।''

एक न्यूज एजेंसी को दिए गए साक्षात्कार में सीएम योगी ने कहा कि स्टालिन क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका वोट बैंक खतरे में है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भाषा को लोगों को एकजुट करना चाहिए, न कि विभाजित करना चाहिए। उन्होंने बताया कि तमिल भारत की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है, जिसका इतिहास और विरासत समृद्ध है। कोई भी भाषा विभाजित करने का काम नहीं करती, यह एकजुट करने का काम करती है। एकता और समावेशिता के महत्व पर जोर देते हुए योगी ने एक व्यापक दृष्टिकोण की वकालत की। उन्होंने कहा, 'मेरा मानना है कि यह संदेश हमारे राष्ट्रगान से भी मिलता है। यह केवल संकीर्ण राजनीति है। जब इन लोगों को लगता है कि उनका वोट बैंक खतरे में है तो वे क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभाजन पैदा करने की कोशिश करते हैं। देश के लोगों को हमेशा ऐसी विभाजनकारी राजनीति से सावधान रहना चाहिए और देश की एकता के लिए दृढ़ रहना चाहिए।''

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने दावा किया, ''अब पूरा देश जानता है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के परिवार के पास निजी स्कूल हैं जो तीन या उससे भी अधिक भाषाएं पढ़ाते हैं। लेकिन राज्य के सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए इसी नीति का विरोध करते हैं।'' उन्होंने 'एक्स' पर पोस्ट में कहा, ''तमिलनाडु के सीएम को लगता है कि यहां-वहां उनकी पार्टी के लोगों द्वारा रचा गया नाटक पूरे तमिलनाडु की आवाज को दर्शाता है। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपको यह एहसास ही नहीं हुआ कि लोगों का ध्यान महत्वहीन मामलों से हटाने के आपके प्रयासों का पर्दाफाश हो गया है। आप अपनी अज्ञानता की दुनिया में रहिए।

भाषा विवाद में सांस्कृतिक जुड़ाव का सेतु बनेगी वीरांगना की गाथा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ भाजपा महिला मोर्चा हिंदी में कराएगा वीरांगना रानी वेलू नचियार पर आधारित नाटक का मंचन

▶ नाटक का मंचन स्वतंत्रता संग्राम में उनके बहुमूल्य योगदान और महान संघर्ष को करेगा जीवंत

दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु में आजकल भाषा विवाद कुछ ज्यादा ही गरमाया हुआ है। तमिलनाडु सरकार कभी नई शिक्षा नीति के बहाने तो कभी हिंदी भाषा थोपने का आरोप लगा रही है। इस बीच भाजपा महिला मोर्चा ने दक्षिण भारत की वीरांगना रानी वेलू नचियार की गाथा को उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव का सेतु बनाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। मोर्चा ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने वाली पहली रानी वीरांगना रानी वेलु नचियार पर आधारित नाटक का हिंदी में मंचन कराने जा रहा है। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया था, यह बात उत्तर भारत के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन लक्ष्मीबाई से पहले अंग्रेजों को धूल चटाने वाली रानी वेलु नचियार की गाथा से यहां के लोग ज्यादा परिचित नहीं हैं। ऐसे में हिंदी में रानी वेलु नचियार पर आधारित नाटक का मंचन स्वतंत्रता संग्राम में उनके बहुमूल्य योगदान और महान संघर्ष को जीवंत करेगा। रानी वेलु नचियार पर आधारित नाटक का मंचन 29 मार्च को शाम चार बजे यहां केदारनाथ साहनी आडिटोरियम सिविक सेंटर में होगा।

कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि होंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी और ओडिशा की उप मुख्यमंत्री पार्वती परिदा विशिष्ट अतिथि होंगी। इसके अलावा कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष वनाथी श्रीनिवासन व अन्य विशिष्ट जन शामिल होंगे। मंचन में रानी वेलु नचियार के जीवन का वर्णन किया जाएगा और आजादी के लिए प्राण न्योछावर करने वाली 75 महिला स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को लेकर एक पुस्तक का भी अनावरण किया जाएगा।

वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विस से प्रस्ताव पास

चेन्नई, प्रेट्र : वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ तमिलनाडु विधानसभा ने गुरुवार को प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में कहा गया है कि केंद्र सरकार इस विधेयक को वापस ले, क्योंकि इससे अल्पसंख्यक मुसलमानों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। भाजपा सदस्यों के विरोध और वाकआउट के बीच पारित प्रस्ताव को मुख्य विपक्षी दल अन्नाद्रमुक और भाजपा की सहयोगी पीएमके सहित अन्य सभी दलों का समर्थन मिला। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा, यह धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। इससे मुस्लिमों की भावनाएं आहत हो रही हैं। उन्होंने दावा किया कि यह अल्पसंख्यकों और उनके संस्थानों के संवैधानिक अधिकारों पर हमला है। हम इसका विरोध जारी रखेंगे। गौरतलब है कि वक्फ (संशोधन) विधेयक में प्रस्तावित बदलावों को केंद्रीय कैबिनेट मंजूरी दे चुकी है। बजट सत्र के दौरान ही विधेयक के पारित होने की संभावना है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू द्वारा लोकसभा में पेश किए जाने के बाद अगस्त 2024 में विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेज दिया गया था। जेपीसी ने 30 जनवरी को अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी थी।

रणनीति के तहत वक्फ संशोधन पर विपक्ष बना रहा माहौल : चिराग

राज्य ब्यूरो, जागरण ● पटना: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री सह लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने गुरुवार को कहा कि एक सोची-समझी रणनीति के तहत विपक्ष की कई पार्टियां ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक मुस्लिमों के खिलाफ है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने यह बात कही।

चिराग पासवान।

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग ने कहा कि यह विधेयक अभी संसद में चर्चा के लिए आया भी नहीं है। लेकिन, आशंका में ही विपक्ष के नेताओं ने जनता के बीच गलत संदेश फैलाना शुरू कर दिया है।

बिहार विधानसभा के बाहर बुधवार को विपक्षी विधायकों का विरोध प्रदर्शन राजनीतिक उद्देश्य से किया गया है। चुनाव आने वाला है, इसलिए अब उन्हें मुस्लिमों की याद आ रही है। चिराग ने कहा कि मुझे मुस्लिम धार्मिक संगठनों से भी समस्या है जो उन लोगों से सवाल नहीं कर रहे, जो मुस्लिमों के शुभचिंतक होने का दिखावा कर रहे हैं। उन लोगों ने मुस्लिमों को लूटने और उनके वोट बैंक का शोषण करने के अलावा कुछ भी नहीं किया।

अन्नाद्रमुक समान विचारों वाले दल से गठबंधन को तैयार : पलानीसामी

▶ शाह से मुलाकात के बाद अन्नाद्रमुक-भाजपा के गठजोड़ की अटकलें

इदाप्पडी के.पलानीसामी।

तुतिकोरिन (तमिलनाडु), प्रेट्र : अन्नाद्रमुक के प्रमुख इदाप्पडी के.पलानीसामी ने भाजपा की ओर कदम बढ़ाने के संकेत देते हुए कहा कि उनका अकेला शत्रु द्रमुक है। और वह भविष्य में अपने दल जैसे विचारों वाले किसी राजनीतिक दल से गठबंधन करने के लिए तैयार हैं।

पलानीसामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के अगले ही दिन गुरुवार को संवाददाताओं से कहा कि यह चुनावी गठबंधन आगामी चुनावों के बाद ही संभव है। गौरतलब है कि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने में मात्र 11 महीने रह गए हैं। वैसे भी पलानीसामी और अमित शाह की मुलाकात के बाद से अन्नाद्रमुक और भाजपा के बीच गठबंधन होने की अटकलें जोर पकड़ने लगी हैं। गठबंधन के संबंध में विपक्ष के नेता पलानीसामी ने कहा कि अगले साल चुनाव होने हैं और जब भी गठबंधन बनेगा मीडिया को अवश्य जानकारी दी जाएगी। जहां तक अन्नाद्रमुक का सवाल है, उसका अकेला बड़ा दुश्मन सत्तारूढ़ द्रमुक ही है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में अमित शाह से हुई मुलाकात के दौरान उन्होंने तमिलनाडु के मुद्दे उठाए थे, जैसे- मनरेगा समेत केंद्रीय कोष जारी करना आदि। उन्होंने द्वि भाषा नीति का मुद्दा भी उठाया था। उनका कहना है कि द्रविड़वादी नेता सीएन अन्नादुरई व दिवंगत अन्नाद्रमुक नेता एमजी रामचंद्रन और जयललिता ने शुरुआत से यही रुख अपनाया था। उन्होंने शाह से आग्रह किया कि तमिलनाडु में द्वि भाषा नीति कायम रहनी चाहिए। उन्होंने बर्खास्त अन्नाद्रमुक नेता ओ.पनीरसेलवम की पार्टी में वापसी संबंधी बयान पर संवाददाताओं को जवाब देते हुए कहा कि उनके पूर्व सहयोगी के लिए पार्टी में अब जगह नहीं है।

ओडिशा विस के बाहर हंगामा, पुलिस पर हमला

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर

▶ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया पत्थर, कुर्सी एवं अंडा से पुलिस पर हमला

▶ पुलिस ने भांजीं लाठियां, पानी की बौछार व दागे आंसू गैस के गोले

ओडिशा विधानसभा के सामने हंगामा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार करती पुलिस। जागरण

ओडिशा विधानसभा के बाहर महात्मा गांधी मार्ग पर गुरुवार को जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामे के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पत्थर, कुर्सी एवं अंडा से हमला किया, जवाबी कार्रवाई में पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी और आंसू गैसे के गोले दागने पड़े। इससे एक दर्जन पुलिसकर्मी व लगभग 20 कांग्रेस कार्यकर्ता घायल हो गए, कुछ कार्यकर्ताओं के बेहोश हो जाने से उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। मालूम हो कि विधानसभा के बाहर कांग्रेस की तरफ से महिला अत्याचार एवं कांग्रेस विधायकों को निलंबित किए जाने के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था।

इस बीच पुलिस द्वारा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास, प्रभारी अजय कुमार लल्लू, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जयदेव जेना, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक तारा प्रसाद वाहिनीपति एवं अन्य विधायक व वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर स्थिति को संभालने का प्रयास किया गया, परंतु कार्यकर्ता शांत नहीं हुए। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों पर दोबारा हमला बोलते हुए विधानसभा के सामने मौजूद आखिरी बैरिकेड को तोड़ने का प्रयास किया। ऐसे में पुलिस को भी दोबारा सख्ती दिखानी पड़ी। तब भीड़ तितर-बितर हुई।

बताते चलें कि कि महिला सुरक्षा को लेकर हंगामा कर रहे कांग्रेस के विधायकों को अनुशासनहीनता के आरोप में मंगलवार को सात दिनों के लिए निष्कासित कर दिया गया था। निलंबित किए जाने के बावजूद विधानसभा में ही जमे रहने पर मार्शलों ने रात लगभग दो बजे उन्हें बलपूर्वक बाहर निकाल दिया था। इसके बाद कांग्रेस के विधायकों समेत, नेता एवं कार्यकर्ता विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए थे। इसके बाद बुधवार को जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेसियों ने चार बैरिकेडिंग तोड़ते हुए अंदर घुसने का प्रयास किया, जिसे मौके पर भारी संख्या में तैनात पुलिसकर्मियों ने विफल कर दिया था।

खरगे बोले, सत्ता के बिना लागू नहीं की जा सकती विचारधारा

▶ कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी जिला अध्यक्षों की बैठक को किया संबोधित

▶ राज्यों में चुनाव जीतने को एकजुटता से काम करने की अपील की

नई दिल्ली, प्रेट्र: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार को कहा कि संगठन की विचारधारा मजबूत है, लेकिन इसको सत्ता के बगैर देश में लागू नहीं किया जा सकता है। उन्होंने पार्टी की जिला इकाई प्रमुखों से राज्यों में चुनाव जीतने के लिए दीर्घकालिक रणनीति के साथ एकजुट होकर काम करने की अपील की।

खरगे ने जिला कांग्रेस अध्यक्षों की तीन बैठकों में से पहली को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आइएनडीआइए में शामिल पार्टियों ने भाजपा और उसके सहयोगी दलों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ी, जिससे भाजपा 240 सीटों तक सीमित होकर रह गई। अगर कांग्रेस को 20-30 सीटें और मिलतीं तो एक वैकल्पिक सरकार बन जाती। जिला कांग्रेस अध्यक्षों की तीन दिनों में अलग-अलग चरणों में बैठक हो रही है। गुरुवार की बैठक में 13 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के जिला कांग्रेस कमेटियों (डीसीसी) के अध्यक्ष शामिल हुए।

खरगे ने यहां कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में डीसीसी अध्यक्षों से कहा, 'हमारे संविधान बचाओ अभियान ने संविधान को बदलने की भाजपा-आरएसएस की गोपनीय मंशा को उजागर किया है। आज भाजपा के पास बहुमत नहीं है और वह दो घटक दलों पर निर्भर है। एक प्रधानमंत्री ने अहंकारपूर्वक दावा किया था कि वह 400 सीटें जीतेंगे, लेकिन उन्हें हमने बड़ा झटका दिया।' उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस के खिलाफ कांग्रेस की लड़ाई संसद के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर जारी है। खरगे ने राहुल गांधी और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में कहा, 'राहुल गांधी और मैंने आपके साथ सीधे संवाद की आवश्यकता को पहचाना है।' उन्होंने दावा किया कि सांप्रदायिक मुद्दे लोगों के बजाय भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर मीडिया में गढ़े जाते हैं।

भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार विधानसभा परिसर में प्रदर्शन

राज्य ब्यूरो, जागरण ● पटना: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो गया है। गुरुवार को विधानसभा परिसर में विपक्ष ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्षी नेता अपने हाथों में पोस्टर लेकर नारे बुलंद करते दिखे। वे आरोप लगा रहे थे- बिहार में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हैं और नौकरशाह ही इसके प्रहरी हैं। गुरुवार को विधानसभा के बजट सत्र का समापन होना था। समापन के पूर्व विधायी कार्य शुरू हो, इसके पहले ही संयुक्त विपक्ष ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध नीतीश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व राष्ट्रीय जनता दल (राजद) कर रहा था। विधानसभा पोर्टिको में इकट्ठा हुए विपक्ष के नेता अपने हाथों में प्ले-कार्ड और पोस्टर लिए हुए थे, जिस पर तरह-तरह के नारे लिखे हुए थे। विपक्ष के नेताओं ने अपने हाथों में तिरंगा भी उठा रखा था। साथ ही यह नारे बुलंद कर रहे थे - बिहार की जनता करें पुकार, बंद करो अब भ्रष्टाचार। विपक्ष का यह प्रदर्शन करीब 10 मिनट तक चला।

भारत में काम करने वाले व्यक्ति को पाकिस्तान से मिला वेतन : हिमंत

हिमंत विस्वा सरमा

गौरव गोगोई की पत्नी का आइएसआइ से संबंध पर असम के सीएम का बयान

गुवाहाटी, प्रेट्र: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को आरोप लगाया कि पाकिस्तान के अली तौकीर शेख और भारत में उसके सहयोगियों के बीच संबंधों की जांच कर रही एसआईटी ने पाया है कि इस देश में काम करने वाले एक व्यक्ति को तीन साल तक पाकिस्तान से वेतन मिला।

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न के आइएसआइ संबंधों को लेकर उठे विवाद के बीच असम पुलिस ने पिछले महीने एक प्राथमिकी दर्ज की थी और भारत के आंतरिक मामलों पर शेख की इंटरनेट मीडिया टिप्पणियों की जांच के लिए एसआइटी का गठन किया था। पाकिस्तान योजना आयोग के सलाहकार और कोलबर्न के पूर्व सहयोगी शेख पर बीएनएस और यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि एसआइटी को पिछले दो महीनों में कई दस्तावेज मिले हैं, जो स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि एक व्यक्ति को पाकिस्तान से भुगतान मिला था।

मुंबई में 17, केरल में एक घुसपैठिया गिरफ्तार

मुंबई, एएनआइ: महाराष्ट्र पुलिस ने मुंबई में 17 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। उधर केरल के पेरुंबवूर में एक बांग्लादेशी घुसपैठिये को जाली करेंसी के साथ गिरफ्तार किया गया है। मुंबई शिवाजीनगर और आरसीएफ पुलिस ने भारतीय नागरिकता का सुबूत प्रस्तुत करने में विफल रहने के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार कर लिया। गुप्त सूचना पर शिवाजीनगर थाना की टीम ने 24 मार्च को एक अभियान में आठ संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। आरसीएफ पुलिस ने 25 मार्च को पांच महिलाओं समेत नौ और लोगों को हिरासत में लिया।

अखिलेश बोले- गोशालाओं से आ रही भ्रष्टाचार की दुर्गंध

राज्य ब्यूरो, जागरण ● लखनऊ

▶ उपमुख्यमंत्री का पटलवार, कहा-सुगंध और दुर्गंध का फर्क भूल गए अखिलेश, मांगें माफी

▶ आरोप लगाया था कि गोशालाओं के नाम पर बजट भाजपा नेताओं और समर्थकों की जेब में जा रहा

अखिलेश यादव। फाइल

केशव प्रसाद मौर्य। फाइल

गोशालाओं को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के दिए गए बयान पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। सपा मुखिया ने कहा था कि भाजपा सरकार में गोशालाओं को सेवाभाव से नहीं चलाया जा रहा है। गोशालाओं में भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार की दुर्गंध है। कमीशनखोरी चरम पर है। इसी बयान पर उपमुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा-सत्ता हाथ से क्या गई, सुगंध और दुर्गंध में फर्क भूल गए। जिस गोमाता के चरणों में देवी-देवताओं का वास हो, उसी पर तंज कसना अधर्म नहीं तो और क्या है?

सपा प्रमुख ने आरोप लगाया था कि गोशालाओं के नाम पर सरकारी बजट भाजपा नेताओं और समर्थकों की जेब में जा रहा है। गोशालाओं में साफ-सफाई नहीं है। गायों के खाने-पीने की व्यवस्था नहीं है। आए दिन गायों की भूख और बीमारी से मरने की खबरें आती हैं। भाजपा सरकार में गोशालाओं और गायों के नाम पर पैसों की बंदरबांट हो रही है। भाजपा सरकार गायों की भूख, बीमारी और मौतों के पाप की भागीदार है। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस आरोप के जवाब में उपमुख्यमंत्री ने लिखा कि जो गोधन को बोझ समझे, वह गोपाल भगवान श्रीकृष्ण और राधारानी के चरणों की भक्ति का अलौकिक आनंद क्या जाने। जिनके लिए सत्ता का सिंहासन ही सर्वस्व हो वे गाय, गंगा और गीता की महिमा पर सवाल उठाएंगे ही। अखिलेश यादव जी अगर विरासत में केवल सियासत नहीं संस्कार भी मिले होते तो सियासत के साथ सपरिवार गोसेवा भी करते। आपकी कठोर वाणी ने करोड़ों गो-भक्तों को आहत किया है। इसके लिए तत्काल माफी मागें, अन्यथा सपा का पूर्ण सफाया होगा।

ऐसे लोग राजनीति के लिए दूसरा देश तलाशें : संबित पात्रा

प्रेट्र के अनुसार भाजपा ने गुरुवार को अखिलेश यादव की 'गौशालाओं की दुर्गंध' वाले बयान पर आलोचना की और कहा कि ऐसे लोगों को अपनी राजनीति करने के लिए दूसरा देश तलाशना चाहिए, क्योंकि भारत सनातन धर्म का कोई 'अपमान' बर्दाश्त नहीं करेगा। भाजपा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस के मध्य प्रदेश विधायक राजेंद्र कुमार सिंह द्वारा साधुओं की तुलना बैल से करने संबंधी मीडिया रिपोर्ट पर भी कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि उनके बयान से साफ पता चलता है कि कांग्रेस नेता सनातन विरोधी हैं। कांग्रेस विधायक सिंह ने बुधवार को सतना में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कथित तौर पर "साधु-संन्यासी और महामंडलेश्वर" की तुलना 'सांड' से की और आरोप लगाया कि भाजपा ने "हिंदुत्व का प्रचार करने और भगवा पार्टी को बढ़ावा देने के लिए उन्हें लोगों के बीच छोड़ दिया है"। यादव की टिप्पणी को "भड़काऊ" बताते हुए पात्रा ने कहा कि भारत सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, "एक तरफ अखिलेश यादव को गौशाला में 'दुर्गंध' मिलती है, दूसरी तरफ राहुल गांधी के मित्र और कांग्रेस विधायक को 'साधु-संतों' में सांड दिखते हैं। उन्होंने कहा कि इसी कांग्रेस विधायक ने महाकुंभ के खिलाफ भी टिप्पणी की थी।"

राष्ट्रीय फलक

अनंत नारायण को आदेश, काशी नरेश की बेटी को प्रताड़ित न करें

जागरण संवाददाता, वाराणसी

अदालत ने गुरुवार को काशिराज परिवार के अनंत नारायण सिंह और उनकी पत्नी अनामिका सिंह को निर्देश दिया कि काशी नरेश विभूति नारायण सिंह की बेटी विष्णुप्रिया को प्रताड़ित न करें। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) साकेत मिश्रा ने आदेश में कहा कि विष्णुप्रिया को संरक्षण प्रदान करना आवश्यक है। अनंत नारायण व विष्णुप्रिया के जीवन में हस्तक्षेप न करें और उन्हें आर्थिक, मानसिकरूप से प्रताड़ित न करें।

विष्णुप्रिया ने अदालत में प्रार्थनापत्र देकर आरोप लगाया है कि अनंत नारायण और उनकी पत्नी प्रताड़ित कर उन्हें रामनगर किला में स्थित उनके निवास स्थान से जबरन निकालना चाहते हैं। उनकी संपत्ति पर कब्जा करने की धमकी देते हैं। उन्हें अपनी संपत्ति दोनों के नाम करने के लिए मजबूर किया। विष्णुप्रिया ने अदालत से उन्हें अनुतोष दिलाने का निवेदन भी किया है। उनके प्रार्थना-पत्र पर सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) ने अनंत नारायण सिंह और उनकी पत्नी को यह भी आदेश दिया कि विष्णुप्रिया के परिचितों, अतिथियों, रखरखाव और दैनिक कार्य के लिए आने वाले लोगों को रोकने का प्रयास न करें। बिना किसी विधिक प्रक्रिया को अपनाए संपत्ति से बेदखल न करें। विष्णुप्रिया के कब्जे वाले हिस्से में किसी प्रकार का कोई निर्माण या ध्वस्तीकरण आदि न करें।

बोर्ड परीक्षा से रोके जा सकते हैं डमी स्कूलों के छात्र

▶ इंजीनियरिंग-मेडिकल प्रवेश की तैयारी में लगे कई छात्र लेते हैं इनमें प्रवेश

▶ डमी स्कूलों में प्रवेश लेने की पूरी जिम्मेदारी अभिभावकों-छात्रों की

नई दिल्ली, प्रेट्र: इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेजों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले ऐसे छात्र जो हाजिरी से बचने के लिए डमी स्कूलों में प्रवेश ले लेते हैं, उन्हें बोर्ड परीक्षा में शामिल होने से रोका जा सकता है। सीबीएसई ने साफ कहा है कि डमी स्कूलों में प्रवेश लेने की पूरी जिम्मेदारी अभिभावकों-छात्रों की है।

डमी स्कूलों पर लगाम लगाने की कड़ी में सीबीएसई परीक्षा से जुड़े उपनियमों में संशोधन का विचार कर रही है ताकि ऐसे स्कूलों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को परीक्षा देने से रोका जा सके। इन छात्रों को नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ओपन स्कूलिंग (एनआइओएस) परीक्षा देनी होगी। बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ''बोर्ड द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान अगर छात्र स्कूलों में गैरहाजिर मिले या पता चला कि वे नहीं आते हैं, तो ऐसे छात्रों को बोर्ड परीक्षा में शामिल होने से रोका जा सकते है।''

उन्होंने कहा डमी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले या छात्रों की गैर-हाजिरी को प्रायोजित करने वाले स्कूलों के खिलाफ बोर्ड की संबद्धता और परीक्षा उपनियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इस मुद्दे को सीबीएसई की गवर्निंग बोर्ड बैठक में भी उठाया गया, जहां इस फैसले को अकादमिक सत्र 2025-26 से लागू करने की सिफारिश की गई। जबकि परीक्षा समिति में इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि न्यूनतम अनिवार्य 75 प्रतिशत हाजिरी ना होने पर बोर्ड परीक्षा में नहीं दे सकेंगे। केवल स्कूल में नामांकन से बोर्ड परीक्षा में शामिल होना सुनिश्चित नहीं हो जाता।

अधिकारी ने कहा कि अगर ऐसे छात्रों को सीबीएसई अनुमति नहीं देता है तो वे परीक्षा के लिए एनआइओएस के पास जा सकते हैं। बोर्ड इस प्रस्ताव को एनआइओस के पास भी ले जा सकता है और अगले सत्र के लिए दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

गौरतलब है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश में राज्यों के विशेष कोटा का फायदा उठाने के लिए छात्र डमी स्कूल चुनते हैं। जैसे दिल्ली से 12वीं करने वाले छात्र दिल्ली के मेडिकल कालेजों में राज्य कोटा के हकदार हो जाते हैं, जिससे कई अन्य राज्यों के छात्र भी राजधानी के डमी स्कूलों में प्रवेश को वरीयता देते हैं।

****

हिमाचल में 2795.23 करोड़ रुपये कहां खर्चे, कोई पता नहीं

राज्य ब्यूरो, जागरण ● शिमला

▶ मुख्यमंत्री ने विधानसभा में रखी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट पेश की। इसमें पता चला कि पिछले दो वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च हुए 2795.23 करोड़ रुपये के 2990 उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) जमा नहीं करवाए गए। उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा न होने से यह पता नहीं चला कि इस राशि का उपयोग किन कार्यों के लिए हुआ अथवा हुआ ही नहीं। बजट में बिना प्रविधान किए 94.36 करोड़ रुपये खर्च करने की बात भी रिपोर्ट में सामने आई है। कैग रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2022-23 की अपेक्षा 2023-24 में राजस्व प्राप्तियों में 1083.55 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जबकि राजस्व व्यय में 306.37 करोड़ रुपये की ही वृद्धि हुई। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान 1,744.60 करोड़ रुपये 1,342 यूसी जो देय थे, जो संबंधित निकायों और प्राधिकरणों द्वारा प्रदान ही नहीं किए गए। इसके अतिरिक्त 1,050.63 करोड़ की कुल राशि के 1,648 यूसी वर्ष 2022-23 तक प्रस्तुत करने हेतु देय थे और इन्हें 31 मार्च 2024 तक जमा ही नहीं करवाया गया।

23 वर्ष बाद साक्ष्य के अभाव में अदालत ने झारखंड के हजारीबाग में आतंकियों को पनाह देने के आरोपित जमालुद्दीन उर्फ नासिर को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष पुख्ता साक्ष्य पेश करने में असफल रहा।

न्यूज गैलरी

भूस्खलन पीड़ितों के पुनर्वास का चल रहा कार्य : प्रियंका

वायनाड : कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को कहा कि वायनाड भूस्खलन के पीड़ितों के लिए प्रस्तावित टाउनशिप का शिलान्यास उनके पुनर्वास की दिशा में पहला कदम है और हर किसी को इसके बारे में सकारात्मक रहना चाहिए। तीन दिन के दौरे पर वायनाड आईं प्रियंका ने पुलपल्ली में श्री सीता देवी लव कुश मंदिर का दौरा करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हर कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयास कर रहा है। कर्नाटक सरकार ने 100 घर बनाने की घोषणा की है। (प्रेट्र)

प्रारंभिक परीक्षा के तुरंत बाद उत्तर कुंजी जारी करे यूपीएससी

नई दिल्ली : एक संसदीय समिति ने गुरुवार को सुझाव दिया कि विश्वसनीयता, निष्पक्षता और अभ्यर्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए यूपीएससी को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के तुरंत बाद उत्तर कुंजी जारी कर देनी चाहिए। यूपीएससी ने संसदीय समिति को सूचित किया कि वह संपूर्ण चयन प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी प्रकाशित करता है। कार्मिक और लोक शिकायत विभाग से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने कहा कि इससे उम्मीदवारों की अगले चरण में आगे बढ़ने से पहले संभावित त्रुटियों को चुनौती देने की क्षमता में देरी होती है। इससे पारदर्शिता और निष्पक्षता कम होती है। इस तरह की प्रक्रिया अभ्यर्थियों का मनोबल गिरा सकती है। बताते चलें, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रति वर्ष तीन चरणों- प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जाती है। इसके माध्यम से भारतीय विदेश सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का चयन किया जाता है। (प्रेट्र)

डिब्रूगढ़ से अफस्पा हटा, असम के सिर्फ तीन जिले में लागू

गुवाहाटी : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को कहा कि सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफस्पा) को डिब्रूगढ़ से हटा लिया गया है। अब राज्य के केवल तीन जिलों में यह लागू है। यह कानून सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने और बिना किसी पूर्व वारंट के किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। सरमा ने कहा कि हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से डिब्रूगढ़ से अशांत क्षेत्रों का टैग हटाने का अनुरोध किया था, क्योंकि हम इसे राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने हमारा अनुरोध सुना और इस संबंध में केंद्र द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है। अफस्पा अब तिनसुकिया, शिवसागर और चराइदेव जिलों में लागू होगा। (प्रेट्र)

शराब की लत छिपाने से स्वास्थ्य बीमा का दावा हो सकता है खारिज : सुप्रीम कोर्ट

महत्वपूर्ण निर्णय ▸ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का मुआवजा देने का आदेश रद

सुप्रीम कोर्ट ने एलआइसी के दावा खारिज करने के निर्णय को उचित माना है

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कोई स्वास्थ्य बीमा लेता है और उसमें साफ साफ शर्त में पूछा गया होता है कि क्या बीमा लेने वाला व्यक्ति शराब, सिगरेट, बीड़ी या किसी भी रूप में तम्बाकू का सेवन करता है और अगर बीमा लेने वाला व्यक्ति शराब पीने की आदत छुपाते हुए उस सवाल का नहीं में जवाब देता है तो बीमा कर्ता कंपनी बाद में उसका स्वास्थ्य बीमा का दावा खारिज कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए अपने एक फैसले में कहा है कि शराब पीने की आदत छिपाना और शराब पीने के कारण हुई बीमारी पर अस्पताल में भर्ती होने वाले का स्वास्थ्य बीमा में चिकित्सा खर्च का दावा खारिज किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) का आदेश खारिज कर दिया है जिसमें एनसीडीआरसी ने उपभोक्ता फोरम के एलआइसी को स्वास्थ्य बीमा मुआवजा देने के आदेश को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने एलआइसी के दावा खारिज करने के निर्णय को उचित माना है। एलआइसी ने जीवन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा लेने वाले पालिसीधारक द्वारा शराब पीने की आदत छुपाए जाने और इस संबंध में गलत जानकारी दिए जाने के आधार पर दावा खारिज कर दिया था। यह फैसला जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की खंडपीठ ने गत तीन मार्च को एनसीडीआरसी के आदेश के खिलाफ दाखिल एलआइसी की अपील स्वीकार करते हुए सुनाया। शीर्ष अदालत ने एनसीडीआरसी का 12 मार्च 2020 का आदेश खारिज कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि बीमाकर्ता की मृत्यु के बाद जो पैसा उसकी पत्नी को दिया जा चुका है, उसकी रिकवरी नहीं की जाएगी।

दावा दाखिल करने वाली पत्नी के पति महिपाल ने 2013 में एलआइसी की जीवन आरोग्य पालिसी ली थी। इस पालिसी में अस्पताल में भर्ती होने पर नकद लाभ दिया जाता था। इसके तहत बीमाधारक के गैर आइसीयू अस्पताल में भर्ती होने पर एक हजार रुपये और आइसीयू अस्पताल में भर्ती होने पर 2000 रुपये रोजाना भुगतान का प्रविधान था। पालिसी लेने के लगभग एक साल बाद पालिसीधारक के पेट में तेज दर्द होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई। पालिसीधारक की मृत्यु होने के बाद उसकी पत्नी ने एलआइसी में दावा दाखिल किया लेकिन एलआइसी ने दावा यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पालिसीधारक ने शराब पीने की पुरानी लत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी बीमा लेते समय छिपाई थी। एलआइसी ने जीवन आरोग्य योजना में लाभ देने से मना करने के खंड सात (11) का हवाला दिया जिसमें साफ तौर पर स्वपीड़ित चोटों या आत्महत्या का प्रयास अथवा किसी दवा या शराब के उपयोग या दुरुपयोग से उत्पन्न जटिलताओं को कवरेज से बाहर रखा गया था। एलआइसी द्वारा दावा खारिज करने के बाद दावेदार ने उपभोक्ता फोरम में याचिका दाखिल की जिस पर उपभोक्ता फोरम ने एलआइसी को चिकित्सा पर आए खर्च की प्रतिपूर्ति करने का आदेश दिया।

एनसीडीआरसी के फैसले को गलत बताया

सुप्रीम कोर्ट ने फोरम के आदेश को सही ठहराने वाले एनसीडीआरसी के फैसले को गलत बताते हुए अपने निर्णय में कहा कि मेडिकल रिकार्ड में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि रोगी का लगातार शराब के सेवन करने का इतिहास रहा है। कोर्ट ने कहा कि पालिसी के प्रस्ताव फार्म में विशेष रूप से एक प्रश्न था कि क्या बीमित व्यक्ति शराब, सिगरेट, बीड़ी या किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन करता है। पालिसीधारक द्वारा इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। कोर्ट ने कहा कि मृतक की शराब पीने की आदत लंबे समय से चली आ रही थी जिसे उसने पालिसी लेते वक्त जानबूझकर छिपाया था। तथ्यों को छिपाने के कारण एलआइसी द्वारा दावे को अस्वीकार करना उचित था।

उच्च स्तरीय जांच कमेटी ने दर्ज किया फायर निदेशक का बयान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▸ कमेटी ने फायर निदेशक गर्ग से बयान से पलटने के बारे में भी ली जानकारी

यशवंत वर्मा। फाइल

दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में स्टोर रूम में आग लगने से बेहिसाब जले नोट मिलने के मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच कमेटी ने दिल्ली अग्निशमन विभाग के निदेशक अतुल गर्ग का बयान दर्ज किया। गर्ग का पहली बार बयान दर्ज किया गया है। माना जा रहा है कि इसके बाद घटना के दौरान आवास पर पहुंचने वाले दोनों अधिकारियों के बयान भी दर्ज किए जा सकते हैं।

जांच कमेटी के निर्देश पर अतुल गर्ग चाणक्यपुरी स्थित हरियाणा गेस्ट हाउस में बने कैंप कार्यालय में तय समय से पहले दोपहर करीब 2:15 बजे पहुंच गए। वहां कमेटी के सदस्य न्यायमूर्ति शील नागू (पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश), न्यायमूर्ति जी एस संधावालिया (हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश) और कर्नाटक हाई कोर्ट की न्यायाधीश अनु शिवरामन के सामने गर्ग का बयान दर्ज किया गया। जांच समिति ने इनसे पूरी घटना की जानकारी प्राप्त करने के अलावा जांच के तौर तरीके के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। कमेटी ने गर्ग से बयान बदलने के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। गर्ग ने मीडिया से बातचीत में आग बुझाने के दौरान जस्टिस वर्मा के स्टोर रूम में बोरियों में रखे नोट जलने व जले हुए नोट बरामद किए जाने से साफ इन्कार कर दिया था, लेकिन कुछ घंटे बाद ही बयान से पलट गए थे।

14 मार्च की रात 11:15 बजे आग लगने की काल मिलने पर चाणक्यपुरी स्थित फायर स्टेशन से असिस्टेंट डिवीजनल आफिसर सुमन कुमार व सफदरजंग फायर स्टेशन से मनोज कुमार मौके पर पहुंचे थे। उनके साथ आठ से दस फायरकर्मी थे। एक अधिकारी के मुताबिक, नियमानुसार आग बुझाने के बाद आवास व दुकान के मालिक अथवा वहां मौजूद सदस्यों से पूछताछ की जाती है कि उनके कौन-कौन से सामान व पैसे जल गए। उनके वैल्यू आदि के बारे में भी पता करने के बाद कंट्रोल रूम को जानकारी दी जाती है। आग कैसे लगी इसकी जांच स्थानीय पुलिस करती है। कंट्रोल रूम में तैनात कर्मचारी घटना में जान माल का नुकसान से संबंधी हर जानकारी आनलाइन सर्वर पर अपलोड कर देते हैं। वहां से स्थानीय पुलिस व पीड़ित रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं।

केरल की मुख्य सचिव ने कहा- काले रंग के कारण सहना पड़ा अपमान

तिरुअनंतपुरम, प्रेट्र : केरल की मुख्य सचिव शारदा मुरलीधरन को काले रंग को लेकर अपमान सहना पड़ा। हाल ही में इंटरनेट मीडिया पर एक टिप्पणी में किसी ने उनकी तुलना उनके पति और पूर्ववर्ती वी. वेणु से करते हुए कहा था कि शारदा उतनी ही काली हैं जितने गोरे उनके पति वेणु हैं। इन टिप्पणियों से आहत शारदा ने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि कैसे सांवला होने के कारण उन्हें बचपन से ही अपमान सहना पड़ा। बाद में अपने बच्चों की मदद से उन्हें अहसास हुआ कि काला रंग ''सुंदर'' होता है।

एक टीवी चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि समाज को अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। शारदा ने कहा कि उनके पति के साथ तुलना ''अप्रत्याशित'' थी। पति ने ही उन्हें अपना फेसबुक पोस्ट डालने के लिए प्रोत्साहित किया था। शारदा ने कहा कि यह ऐसी चीज है जिससे उनकी पहचान और योग्यता पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा, ''हां मैं काली हूं। काला रंग सात गुना सुंदर है।

शारदा ने लिखा, पिछले सात महीनों में, जब से पति का स्थान मुख्य सचिव के रूप में लिया है तुलना किए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्य सचिव ने अपने बचपन की एक याद भी साझा की, जब वह चार साल की थीं और अपनी मां से पूछती थीं कि क्या वह उन्हें वापस गर्भ में रख सकती हैं और उन्हें ''पूरी तरह गोरी बनाकर बाहर ला सकती हैं। बड़ी होने पर महसूस होने लगा कि गोरी नहीं होने के कारण उन्हें कमतर आंका जा रहा है, लेकिन उनके बच्चों ने उनका नजरिया बदल दिया। शारदा मुरलीधरन केरल की मुख्य सचिव हैं, जिन्होंने अपने पति डा. वी. वेणु के सेवानिवृत्त के बाद यह पद संभाला। बाद में एएनआइ से बातचीत में उन्होंने कहा कि काला होना शर्म की बात नहीं है, बल्कि इसका जश्न मनाया जाना चाहिए।

▸ कहा- ब्रह्मांड का सर्वव्यापी सत्य और सात गुना सुंदर है काला रंग

▸ समाज को नजरिया बदलने और पूर्वाग्रहों से उबरने की जरूरत

रांची में भाजपा नेता की हत्या के विरोध में कई जिलों में प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, रांची : रांची में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य अनिल टाइगर की बुधवार को हुई हत्या के विरोध में भाजपा और आजसू द्वारा घोषित रांची बंद का कई जिलों में असर देखने को मिला। भाजपा नेताओं ने जगह-जगह धरना-प्रदर्शन कर घटना की निंदा की। प्रदर्शन कर रहे रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ को पुलिस ने रांची के रातू रोड में आगे बढ़ने से रोक दिया, भाजपा के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया।

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन भाजपा विधायकों ने घटना को लेकर सदन के अंदर और बाहर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से पहली पाली में विधानसभा की कार्यवाही स्थगित रही। रांची के स्कूल और लगभग सभी दुकानें बंद रहीं। रांची समेत राज्य के कई जिलों में हत्याकांड को लेकर जगह-जगह सड़क पर धरना प्रदर्शन किए जाने से जनजीवन अस्त-व्यस्त रहा।

बिना राज्यों की अनुमति सीबीआइ जांच के लिए बने नया कानून : संसदीय समिति

नई दिल्ली, प्रेट्र : एक संसदीय समिति ने गुरुवार को सिफारिश की कि सीबीआइ के लिए एक नया कानून बने ताकि एजेंसी बिना राज्यों की अनुमति के राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता से जुड़े मामलों की जांच कर सके। वहीं, एजेंसी में प्रतिनियुक्ति पर कर्मियों की कमी का मामला उठाते हुए समिति ने विशेषज्ञों के लिए लैटरल एंट्री की सिफारिश की है।

भाजपा के राज्यसभा सदस्य ब्रजलाल के नेतृत्व वाली कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने गुरुवार को संसद में अपनी 145वीं रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में कहा गया है कि सीबीआइ को जांच की ज्यादा ताकत देने के लिए एक अलग या नए कानून की आवश्यकता है, जिससे जरूरत पड़ने पर यह बिना राज्यों की मंजूरी के राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की तुरंत जांच कर सके। इस कानून के लिए राज्यों के विचार लिए जा सकते हैं। कानून में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय भी शामिल होने चाहिए, इससे राज्य सरकारें खुद को शक्तिहीन महसूस नहीं करेंगी। समिति ने बताया कि आठ राज्यों द्वारा सीबीआइ जांच के लिए सहमति वापस ले ली गई, जिससे भ्रष्टाचार और संगठित अपराध की जांच करने की इसकी क्षमता गंभीर रूप से सीमित हुई है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि सीबीआइ में प्रतिनियुक्ति के लिए उचित नामांकन की कमी से परिचालन क्षमता पर असर पड़ रहा है। प्रमुख कारणों में उन विभागों में कर्मियों की कमी है जहां से इसे कर्मचारी मिलते हैं, राज्य पुलिस की अनिच्छा, दस्तावेज बनाने की प्रक्रिया में देरी और कुशल कर्मचारियों की पहचान ना होना शामिल है। इसमें सिफारिश की गई है कि प्रतिनियुक्ति पर निर्भरता कम की जाए और एजेंसी एसएससी, यूपीएससी या केवल अपनी विशेष परीक्षा के जरिये उप पुलिस अधीक्षक, निरीक्षक और उप-निरीक्षक जैसे मुख्य पदों पर सीधी भर्ती की अनुमति देकर स्वतंत्र भर्ती का ढांचा विकसित करे। इसे साइबर अपराध, फोरेंसिक, वित्तीय धोखाधड़ी और कानूनी क्षेत्रों में विशेषज्ञों के लिए लैटरल एंट्री भी शुरू करनी चाहिए।

▸ संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कई सिफारिशें कर एजेंसी की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया

▸ एसएससी, यूपीएससी समेत विशेष परीक्षा आयोजित कर सीबीआइ करे कर्मियों की सीधी भर्ती

प्रतीकात्मक

साल में तीन बार होंगी सीए फाइनल परीक्षाएं

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आइसीएआइ) ने गुरुवार को घोषणा की कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या सीए फाइनल परीक्षाएं 2025 से साल में दो के बजाय तीन बार आयोजित की जाएंगी। पिछले वर्ष आइसीएआइ ने इंटरमीडिएट और फाउंडेशन कोर्स की परीक्षाएं वर्ष में तीन बार आयोजित करने का निर्णय लिया था और अब सीए फाइनल परीक्षाएं भी तीन बार आयोजित की जाएंगी।

आइसीएआइ ने बयान में कहा, छात्रों को अधिक अवसर प्रदान करने के लिए आइसीएआइ की परिषद ने सीए फाइनल परीक्षाएं साल में तीन बार आयोजित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब तीनों स्तरों - सीए फाइनल, इंटरमीडिएट और फाउंडेशन की परीक्षाएं प्रत्येक वर्ष तीन बार होंगी। ये परीक्षाएं जनवरी, मई और सितंबर के महीने में आयोजित की जाएंगी। आइसीएआइ ने कहा कि इन्फार्मेशन सिस्टम्स आडिट में पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स के लिए परीक्षा साल में तीन बार - फरवरी, जून और अक्टूबर में आयोजित की जाएगी।

सपा सांसद के घर पर हुए हमले में दो मुकदमे, करणी सेना का नाम नहीं

राणा सांगा पर टिप्पणी मामला

जागरण संवाददाता, आगरा

मेवाड़ के राजा रहे महाराणा संग्राम सिंह (राणा सांगा) पर टिप्पणी मामले में सपा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर करणी सेना के हमले के मामले में बुधवार देर रात दो मुकदमे दर्ज कराए गए। सांसद के बेटे और दारोगा की ओर से दर्ज कराए मुकदमे में करणी सेना का उल्लेख नहीं है। पुलिस की ओर से दर्ज मुकदमे में ओकेंद्र सिंह राणा को नामजद किया गया है, लेकिन संगठन और पद का नाम नहीं है। गुरुवार को घटना के विरोध में सपा के दो समर्थक स्पीड कलर लैब के सामने मुख्यमंत्री का पुतला फूंककर भाग गए।

राज्यसभा सदस्य रामजीलाल सुमन के बेटे व पूर्व विधायक रणजीत सिंह सुमन की ओर से दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि बुधवार को सैकड़ों लोगों की अनियंत्रित भीड़ ने जान से मारने की धमकी एवं जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मुझ पर और मेरे समर्थकों पर प्राणघातक हमला किया। भीड़ ने गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए फ्लैट से कीमती सामान लूट लिया। समर्थकों को भी चोटें आईं।

▸ एक मुकदमा सांसद के बेटे तो दूसरा ड्यूटी पर तैनात दारोगा ने कराया दर्ज

गुरुवार को रामजीलाल सुमन के आवास पर उनके पुत्र रणजीत से जानकारी लेते सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव। जागरण

शिवपाल यादव ने कहा, झुकेंगे नहीं करेंगे मुकाबला

शिवपाल ने कहा कि हमला भाजपा के इशारे पर हुआ है। भाजपा देश का सौहार्द व सद्भाव बिगाड़ना चाहती है। शासन-प्रशासन के इशारे पर गुंडई की गई, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, मुकाबला करेंगे। हमलावर क्षत्रिय करणी सेना के प्रदर्शनकारी कई किमी चलकर आए, उन्हें रोका भी जा सकता था। पिछड़ा दलित व अल्पसंख्यक विरोधी है।

सुमन की जुबान काटने वाले को देंगे एक करोड़

जासं, मेरठ : अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही ने गुरुवार को कार्यकर्ताओं के साथ मेरठ में कमिश्नरी चौराहे पर सड़क के बीचोबीच बैठकर प्रदर्शन किया। सपा नेता की सदन से सदस्यता रद करने और हिंदू समाज से सपा को वोट न देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सुमन की जुबान काटने वाले को एक करोड़ रुपये इनाम देगा।

सेना के हेलीकाप्टर से आतंकियों के छिपे स्थान की निगरानी

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे

डीएसपी बार्डर धीरज कटोच सहित पांच जवान जख्मी हुए। घायलों में अखनूर निवासी एसपीओ भरत चलोत्रा को जीएमसी जम्मू में, हीरानगर के एसपीओ हैप्पी शर्मा को जीएमसी कठुआ में लाया गया। बाद में उन्हें जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया। डीएसपी बार्डर धीरज कटोच को जीएमसी कठुआ में भर्ती किया। घायल पैरा कमांडो को एयरलिफ्ट कर सैन्य अस्पताल ले जाया गया। सेना के हेलीकाप्टर से आतंकियों के छिपे स्थान की निगरानी की जा रही है।

कठुआ रेलवे स्टेशन को घेरा : मुठभेड़ के दौरान कठुआ रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा बढ़ाते हुए पुलिस जवान तैनात कर दिए गए हैं। यात्रियों के सामान की चेकिंग की गई। पूरे स्टेशन को सुरक्षाबलों ने घेर लिया। इसके पास ही उज्ज दरिया साथ लगता है, वह भी आतंकियों का पहले रूट रहा है। अगर कठुआ स्टेशन पर अचानक बढ़ाई सुरक्षा को देखा जाए तो किड़िया गंडयाल में दो दिन पहले दिखे संदिग्ध इसी रूट पर घुसपैठ हुए यह कहा जा सकता है। बताया जाता है कि मुठभेड़ के दौरान कुछ जवानों के घायल होने पर तुरंत एंबुलेंस बुलाई गई।

राजनेताओं को आमंत्रित करना बंद करे जेयू : कलकत्ता हाई कोर्ट

राज्य ब्यूरो, कोलकाता, कोलकाता

▸ अधिकारियों से गैर-छात्रों को परिसर से हटाने को कहा

कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को कोलकाता स्थित जादवपुर विश्वविद्यालय (जेयू) के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में किसी भी राजनीतिक पदाधिकारी को आमंत्रित न करें। साथ ही यह भी कहा कि परिसर के भीतर होने वाले कार्यक्रमों में केवल शिक्षाविदों की भागीदारी होनी चाहिए। छात्रों को छोड़कर किसी भी बाहरी को अधिकारियों की अनुमति के बिना परिसर में प्रवेश करने या छात्रावास में रहने का अधिकार नहीं है।

हाल में छात्रों के एक समूह और बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु के काफिले में शामिल लोगों के बीच हुई झड़प के मद्देनजर अदालत जादवपुर विश्वविद्यालय में अराजकता और अनुशासनहीनता का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

याचिका में संस्थान में व्यवस्था बहाल करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि कुछ खास राजनीतिक संबद्धता वाले छात्रों के एक गुट उपद्रव कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने विश्वविद्यालय और हास्टल की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पुलिस या केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की थी।

मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगनम व न्यायमूर्ति चैताली चटर्जी (दास) की खंडपीठ ने कहा कि बैठक के लिए विश्वविद्यालय जाने पर मंत्री के वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। अभी विश्वविद्यालय की सुरक्षा निजी एजेंसियों की तरफ से देखी जा रही है, लेकिन कोर्ट ने इस पर संदेह जताया कि क्या ये एजेंसियां पर्याप्त सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं। अदालत ने विश्वविद्यालय को तीन सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, जब मामले की फिर से सुनवाई होगी।

उत्तर प्रदेश में 28,138 पदों पर होगी भर्ती

राज्य ब्यूरो, जागरण ● लखनऊ

उप्र पुलिस में भर्ती होने का सपना देख रहे युवाओं की जल्द बड़ा अवसर मिलेगा। पुलिस व कारागार विभाग के अलग-अलग कुल 28,138 पदों पर भर्ती होगी। आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती के बाद सिपाही के 19,220 और पदों पर भर्ती होगी। दारोगा, बंदी रक्षक, कंप्यूटर आपरेटर व रेडियो सहायक परिचालक के पदों पर भी भर्ती होगी। डीजीपी मुख्यालय ने अलग-अलग पदों पर भर्ती का अधियाचन पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड को भेजा है। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष/डीजी राजीव कृष्ण के अनुसार, अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में भर्तियों से जुड़ी विज्ञप्ति प्रकाशित किए जाने की तैयारी है। साथ ही अभ्यर्थियों के आनलाइन आवेदन की तिथि घोषित की जाएगी। भर्ती बोर्ड ने एक वर्ष में सभी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को पूरा कराने का लक्ष्य रखा है।

उपनिरीक्षक के कुल 4,534 पदों पर भर्ती का अधियाचन प्राप्त हुआ है। इनमें उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के 4,242 पद, उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस (महिला) बदायूं/गोरखपुर/लखनऊ (पीएसी महिला बटालियन) के 106 पद, प्लाटून कमांडर/उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस के 135 पद व उपनिरीक्षक/प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल के 60 पद शामिल हैं। आरक्षी के कुल 19,220 पदों पर भर्ती का अधियाचन भेजा गया है। इनमें आरक्षी पीएसी के 9,837 पद, आरक्षी उप्र विशेष सुरक्षा बल के 1,341 पद, आरक्षी पीएसी महिला बदायूं/गोरखपुर/लखनऊ (महिला बटालियन) के 2,282 पद, आरक्षी नागरिक पुलिस के 3,245 पद, आरक्षी पुलिस/सशस्त्र पुलिस के 2,444 पद व आरक्षी घुड़सवार पुलिस के 71 पद शामिल हैं। इनके अलावा कारागार विभाग में 2,833 पदों पर बंदी रक्षकों की भर्ती भी होगी।

▸ दारोगा के 4,543, सिपाही के 19,220, बंदी रक्षक के 2,833 व कंप्यूटर आपरेटर के 1153 पद शामिल

प्रतीकात्मक

21 अप्रैल से शुरू हो सकता है कुशल खिलाड़ी भर्ती का ट्रायल

पुलिस विभाग में कुशल खिलाड़ी श्रेणी के तहत उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के 91 पदों, आरक्षी नागरिक पुलिस के 372 पदों व आरक्षी पीएसी के 174 पदों पर भर्ती के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। भर्ती बोर्ड अप्रैल के तीसरे सप्ताह में अभिलेखों की जांच व खेल कौशल परीक्षण (ट्रायल) की प्रक्रिया शुरू करने तैयारी में है। कुशल खिलाड़ी भर्ती में 21 अप्रैल से ट्रायल शुरू हो सकता है।

उत्तराखंड में अवैध मदरसों और अतिक्रमण के खिलाफ तेज रहेगी कार्रवाई : धामी

राज्य ब्यूरो, जागरण ● देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में अवैध मदरसों के खिलाफ हो रही कार्रवाई को जायज ठहराया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवैध मदरसे और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में जल्द ही सत्यापन अभियान शुरू किया जाएगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देवभूमि के मूल स्वरूप को बचाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य में अतिक्रमण और अवैध कब्जों के लगभग 160 मामलों में कार्रवाई की गई है। राज्य सरकार की अवैध मदरसों व अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में आने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, लेकिन जो पहचान छिपाकर आएगा उस पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि राज्य में गैरकानूनी काम करने वालों के फंडिंग के स्रोत की भी जांच शुरू की जाएगी।

सीबीआइ ने जब्त किए भूपेश बघेल के तीन फोन, होगी फारेंसिक जांच

▸ एएसपी माहेश्वरी के घर दूसरे दिन भी छापेमारी

▸ तीन पुलिस कर्मियों से सीबीआइ दफ्तर में पूछताछ

राजनंदगांव स्थित एएसपी अभिषेक माहेश्वरी के घर सीबीआइ की टीम ने दबिश दी। फोटो नईदुनिया »

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर

सीबीआइ ने पांच हजार करोड़ के महादेव सट्टेबाजी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तीन फोन जब्त किए हैं। उनकी फारेंसिक जांच की जाएगी। इस मामले में सीबीआइ की कार्रवाई गुरुवार दूसरे दिन भी जारी रही। पहले दिन दोनों जगहों पर कोई नहीं था, इसलिए घर को सील किया गया था। गुरुवार को उनकी उपस्थिति होने पर सीबीआइ उनके तीनों जगह के मकानों की जांच करने दोबारा पहुंची। सीबीआइ ने बुधवार को बघेल के भिलाई स्थित आवास में 15 घंटों तक चली छापेमारी के दौरान फोन जब्त किए थे। जांच एजेंसी ने जेल में बंद उनकी उपसचिव रहीं सौम्या चौरसिया के करीबी माने जाने वाले जगदलपुर में तैनात पुलिसकर्मी सूरज कश्यप, भिलाई क्राइम ब्रांच के तत्कालीन एएसआइ पूर्ण बहादुर टिर्की, एएसआइ सम्मित मिश्रा और भिलाई छावनी थाने में तैनात अमित दुबे को रायपुर सीबीआइ कार्यालय बुलाकर पूछताछ की है।

बिहार में मासूम की मौत का मामला पंचायत ने आठ लाख में निपटाया

जासं, बारसोई (कटिहार) : बिहार के कटिहार जिले में धर्मपुर पंचायत के गोविंदपुर गांव में दो भाइयों के बीच भूमि विवाद में बुधवार को एक बच्चे की हत्या कर दी गई। उसके शव को बिना पोस्टमार्टम के ही दफन कर दिया गया। पुलिस से घटना की शिकायत भी नहीं की गई। मामले में पंचायत बैठी और बच्चे की जान की कीमत आठ लाख रुपये लगाई गई। आरोपित ने अपने चचेरे दामाद और भतीजी के नाम पर आठ लाख रुपये की जमीन की गुरुवार को रजिस्ट्री कर दी। बारसोई के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी मिली है। थानाध्यक्ष को जांचकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार, मु. सलीमुद्दीन का अपने भाई मु. सलाम के साथ भूमि विवाद चल रहा था। सलीमुद्दीन का तीन वर्षीय नाती मु. अयान सलाम के घर चला आया।

5.2 तीव्रता के भूकंप के झटके गुरुवार दोपहर को कश्मीर में महसूस किए गए। इसमें कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोगों में दहशत जरूर फैल गई।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 28 मार्च, 2025

न्यूज गैलरी

बिहार में बालू तस्करों का पुलिस व खनन टीम पथराव

नारदीगंज (नवादा) : बिहार के नवादा जिले में केशौरिया-मधुवन सांगोवर गांव के समीप नदी घाट पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस व खनन विभाग की संयुक्त टीम पर बालू तस्करों ने निकट की पहाड़ी पर चढ़कर पथराव कर दिया। बचने के लिए पुलिस को वाहनों की ओट लेनी पड़ी, फिर भी कई जवान चोटिल हो गए। इसके बाद पुलिस ने अवैध खनन में लगे 12 ट्रैक्टर जब्त कर लिए। थाना अध्यक्ष प्रभा कुमारी ने बताया कि खनन पदाधिकारी की लिखित शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने अवैध खनन व पुलिस पर हमले का आरोप लगा दस लोगों को नामजद किया है। (जासं)

बिल्ली से डरकर भागी बच्ची गर्म दूध के भगोने में गिरी, मौत

जयपुर : राजस्थान में डीग जिले के कामां इलाके में बिल्ली से डर कर भागी तीन साल की बच्ची उबलते दूध में गिर गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल बच्ची की इलाज के दौरान जयपुर में मौत हो गई। बच्ची के पिता जितेंद्र सिंह राष्ट्रीय राइफल में कांस्टेबल हैं। वह जम्मू-कश्मीर में तैनात हैं। ड्यूटी के कारण वह बच्ची के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके। दादा वायुसेना में रहे हैं। जानकारी के अनुसार 25 मार्च की रात को बच्ची सारिका घर की छत पर अकेली थी। छत पर चूल्हा जल रहा था, जिस पर दूध गर्म हो रहा था। बच्ची की मां छत से नीचे रसोई में कुछ सामान लेने चली गई। इस दौरान छत पर अचानक बिल्ली आ गई। बिल्ली से बचने के भागी बच्ची भगोने से टकरा कर उसमें गिर गई, इससे वह 70 फीसदी झुलस गई। (जासं)

बंगाल में मवेशी तस्करों के हमले में जवान घायल

सिलीगुड़ी: बंगाल के दार्जिलिंग जिले में मवेशी तस्करों के हमले में सीमा सुरक्षा बल का एक जवान घायल हो गया है। घटना भारत-बांग्लादेश सीमा पर हुई है। इस दौरान एक तस्कर को दबोच लिया गया। मवेशी तस्करी की कोशिश नाकाम कर दी गई। मवेशियों को भारतीय सीमा क्षेत्र से बांग्लादेश भेजने की कोशिश की जा रही थी। बाद में बीएसएफ के जवानों ने हमला कर भाग रहे तस्करों को खदेड़ा और उसमें से एक को दबोच लिया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया है कि गुप्त सूचना के आधार पर सीमा सुरक्षा बल उत्तर बंगाल फ्रंटियर के सिलीगुड़ी सेक्टर की विशेष टीम ने यह कार्रवाई की। (जासं)

केरल के शराब के साथ पकड़े गए कक्षा 10 के चार छात्र

पतनमथिट्टा : केरल के पतनमथिट्टा जिले में 10वीं कक्षा के चार छात्रों के पास से शराब की बोतलें बरामद हुई है। पुलिस ने गुरुवार को कहा कि इस संबंध में छात्रों की काउंसलिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोझेनचेरी के एक स्कूल में बुधवार को छात्र अपनी अंतिम परीक्षा समाप्त होने का जश्न मनाने के लिए शराब लेकर आए थे। छात्रों की गतिविधियों पर संदेह होने पर शिक्षकों ने उनके बैग की जांच की, उनमें से एक के पास से शराब जब्त की और पुलिस को सूचना दी। (प्रेट्र)

महाराष्ट्र में पचास करोड़ रुपये की ड्रग्स के साथ दो गिरफ्तार

मुंबई : मुंबई में एनसीबी ने एक घर से 50 करोड़ रुपये का प्रतिबंधित पदार्थ जब्त करने के बाद महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में ड्रग्स निर्माण की गुप्त प्रयोगशाला का पर्दाफाश किया है। इस पदार्थ के निर्माता सहित दो को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए दो लोगों में से मादक पदार्थ के एक आपूर्तिकर्ता के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत डीआरआइ द्वारा पहले भी दो मामले दर्ज किए गए थे। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि वह जमानत पर जेल से बाहर था और वह मेफेड्रोन बनाने वाले गिरोह में शामिल था। विशेष सूचना के आधार पर एनसीबी ने शनिवार को मुंबई के भांडुप में एक घर से दो को गिरफ्तार कर 46.8 किलो मेफेड्रोन जब्त की। (प्रेट्र)

यूनियन कार्बाइड का जहरीली कचरा जलाने से नुकसान नहीं, पीथमपुर में ही जलेगा पूरा

स्टेटस रिपोर्ट ▸ कचरा जलाने के तीन ट्रायल रन की स्टेटस रिपोर्ट मप्र हाई कोर्ट में प्रस्तुत

270 किलो प्रति घंटा के हिसाब से 72 दिन में पूरा जहरीला कचरा नष्ट किया जाएगा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर

पीथमपुर में यहीं जलाया जा रहा जहरीला कचरा। फाइल/नईदुनिया

> यूनियन कार्बाइड का 30 टन जहरीला कचरा जलाए जाने के बाद गैस उत्सर्जन में निकले तत्वों की निगरानी की गई। गैस में मौजूद विषैले तत्व तय मात्रा से कम ही रहे।
> – एसएन द्विवेदी, रीजनल आफिसर, मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

भोपाल में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री के जहरीले कचरे को पीथमपुर में जलाकर निष्पादित करने के ट्रायल रन (परीक्षण) में किसी तरह का नुकसान सामने नहीं आया है। यह बात मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में राज्य शासन की ओर से गुरुवार को प्रस्तुत स्टेटस रिपोर्ट में कही गई। कोर्ट को बताया गया कि ट्रायल रन सभी नियमों का पालन करते हुए किया गया था। तीनों आशा के अनुरूप सफल रहे। इनमें 10-10 टन कचरा जलाया गया। इनकी रिपोर्ट सही पाई गई। इस तरह किसी तरह के नुकसान की आशंका निर्मूल साबित हो गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार आगामी 72 दिनों में जहरीले कचरे को जलाकर नष्ट किया जाएगा। कचरा 270 किलो प्रति घंटे के हिसाब से जलाया जाएगा।

बता दें, ट्रायल रन के पहले चरण में 27 फरवरी से 135 किलो कचरा प्रति घंटे जलाया गया। दूसरे चरण में चार मार्च से 180 किलो कचरा प्रति घंटा जलाया गया। तीसरे व अंतिम चरण में 10 मार्च से 270 किलो कचरा प्रति घंटा जलाया गया था। रिपोर्ट के अनुसार करीब 300 टन (कुल 337 टन में से 30 टन जलाया जा चुका है) कचरा जलने पर 900 टन राख निकलेगी, जिसे जमीन में गड्ढा खोदकर दबाया जाएगा। बता दें, कचरे में विषैले तत्वों के नियंत्रण के लिए चूना व अन्य पदार्थ भी मिलाए जा रहे हैं इसलिए अवशेष ज्यादा निकल रहा है। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने इस स्टेटस रिपोर्ट को रिकार्ड पर लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 30 जून को नियत कर दी। कचरा जलने के बाद बनी फ्लू गैस को स्प्रे डायर में भेजकर उस पर पानी का छिड़काव किया जाता है। गैस को तेजी से ठंडा करने से दोबारा हानिकारक तत्व नहीं बनते। इस गैस को मल्टी साइक्लोन मशीन से गुजारा जाता है। इससे भारी कण अलग हो जाते हैं। फिर गैस को ड्राय स्क्रबर से गुजारा जाता है। वहां चूना, एक्टिवेटेड कार्बन व सल्फर के मिश्रण का छिड़काव गैस पर किया जाता है। इस प्रक्रिया में गैस से सभी एसिडिक तत्व जैसे सल्फर डायआक्साइड, सल्फर ट्राइआक्साइड और हाइड्रो क्लोरिक एसिड को खत्म कर दिया जाता है। फिर गैस को 35 मीटर ऊंची चिमनी से वातावरण में छोड़ा जाता है। चिमनी में लगे सेंसर से गैस में हानिकारक तत्वों की लगातार निगरानी की जाती है।

850 से 1100 डिग्री सेल्सियस पर जलाया जाता है कचरा : यूनियन कार्बाइड के 30 टन कचरे को अब तक ट्रायल रन के तहत 12 दिन में जलाकर नष्ट किया गया। पीथमपुर में रि- सस्टेनेबिलिटी कंपनी के भस्मक संयंत्र में 850 से 1100 डिग्री सेल्सियस पर इस कचरे को भस्म किया गया ताकि इसमें मौजूद हानिकारक तत्व पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएं। इस कचरे में यूनियन कार्बाइड परिसर की मिट्टी, रिएक्टर अवशेष, सेविन (कीटनाशक) अवशेष, नेफ्थाल अवशेष हैं।

रोहतक की यूनिवर्सिटी में मिले अफीम के पौधे

- मामला सीएमओ-राजभवन तक पहुंचा तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बनाई जांच कमेटी
- अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज, पता लगाया जा रहा किसने लगाए अफीम के पौधे

यूनिवर्सिटी परिसर में अफीम के पौधों की जांच करती पुलिस। जागरण

जागरण संवाददाता, रोहतक

दादा लखमी चंद राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला यूनिवर्सिटी (डीएलसी सुपवा) में अफीम के 150 पौधे मिले हैं। पौधों से अफीम निकालने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही मामला उच्चतर शिक्षा विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) और राजभवन तक पहुंच गया। बुधवार को जैसे ही विभाग ने रिपोर्ट मांगी तो यूनिवर्सिटी प्रशासन अचंभित रह गया। उसने अपने स्तर पर जांच के लिए पांच सदस्यीय कमेटी गठित की है।

गुरुवार को डीएसपी गुलाब सिंह, अर्बन एस्टेट थाना प्रभारी प्रदीप दहिया, एंटी नारकोटिक सेल और बागवानी विभाग के अधिकारियों की टीम जांच करने पहुंची तो परिसर की नर्सरी और पार्कों में तीन जगह अफीम के 150 पौधे मिले, जिनका वजन करीब सात किलो 480 ग्राम है। करीब चार बजे पुलिस ने सभी पौधे उखाड़कर अपने कब्जे में ले लिए। अर्बन एस्टेट थाने में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पता लगाया जा रहा है कि अफीम के पौधे किसने लगाए हैं।

मालूम हो कि यूनिवर्सिटी परिसर में अफीम के पौधों की कुछ विद्यार्थियों ने वीडियो बनाकर उच्चतर शिक्षा विभाग, सीएमओ और राजभवन भेजी थी। बुधवार शाम को रिपोर्ट मांगी गई तो यूनिवर्सिटी प्रशासन हरकत में आया। जहां-जहां पर अफीम के पौधे उगे मिले वहां सिक्योरिटी गार्ड तैनात कर दिए गए, ताकि पौधों का दुरुपयोग न किया जा सके। जानकारों का कहना है कि अफीम के पौधों को उगाने के लिए अक्टूबर और नवंबर में बिजाई की गई। इसके बाद फरवरी में फूल आने शुरू हुए। मार्च में डोडा बन गया। इसी डोडे में चीरा लगा दिया जाता है और दूध जैसा तरल पदार्थ निकलकर उसी डोडे पर जम जाता है।

'प्रचंड प्रहार' में दिखा भारतीय सेना का पराक्रम

- भारतीय सेना, वायु सेना और सशस्त्र बलों ने अरुणाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्र में किया संयुक्त अभ्यास
- अधिकारी बोले- इस प्रकार का संयुक्त अभ्यास सेनाओं के बीच तालमेल और सामंजस्य बढ़ाता है

नई दिल्ली, आइएएनएस : भारतीय सेना ने संयुक्त परिचालन क्षमता का शक्तिशाली प्रदर्शन करते हुए एक महत्वपूर्ण 'इंटीग्रेटेड मल्टी-डोमेन एक्सरसाइज' की। यह त्रि-सेवा एकीकृत बहु क्षेत्रीय अभ्यास पूर्वी क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र में किया गया। इस दौरान भारतीय सेना का दमदार पराक्रम देखने का मिला।

अधिकारियों के अनुसार इस अभ्यास का नाम 'प्रचंड प्रहार' रखा गया था जोकि 25 से 27 मार्च तक चला। इसमें भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना और भारतीय सशस्त्र बलों ने संयुक्त अभ्यास किया। इसका उद्देश्य भविष्य के युद्ध की परिस्थितियों का सामना करने के लिए एक समन्वित युद्धाभ्यास था। यह अभ्यास न केवल विभिन्न सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि भारतीय सशस्त्र बल किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस प्रकार के संयुक्त अभ्यास से सेनाओं के बीच तालमेल और सामंजस्य बढ़ता है, जो किसी भी संभावित संकट के समय में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस अभ्यास के दौरान आधुनिक तकनीक से लैस प्लेटफार्मों का इस्तेमाल किया गया, जैसे लंबी दूरी के समुद्री निगरानी विमान, सशस्त्र हेलीकाप्टर, यूएवीएस और अंतरिक्ष पर आधारित संसाधन। टारगेट की पहचान के बाद उन्हें लड़ाकू विमानों और अन्य आधुनिक हथियारों के समन्वित हमलों के माध्यम से तेजी से निष्प्रभावित किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रामचंदर तिवारी और एयर मार्शल सूरत सिंह ने इस अभ्यास की समीक्षा की और सैनिकों की उच्च स्तरीय पेशेवरता को सराहा। यह अभ्यास 'पूर्वी प्रहार' की गति पर आधारित था, जो नवंबर 2024 में आयोजित किया गया था।

अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र में 'प्रचंड प्रहार' नामक युद्धाभ्यास किया गया। वीडियोग्रैब/प्रेट्र

टेंडर घोटाले में बिहार के आठ अधिकारियों के यहां ईडी छापे

राज्य ब्यूरो, जागरण ● पटना

- मुख्य अभियंता समेत चार अन्य इंजीनियर और प्रशासनिक सेवा के अफसर निशाने पर

बिहार में टेंडर घोटाले से जुड़े मामले में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने गुरुवार को ताबड़तोड़ छापेमारी की। पटना में सुबह-सुबह एक मुख्य अभियंता (चीफ इंजीनियर), तीन अभियंता और बिहार प्रशासनिक सेवा (बिप्रसे) से जुड़े चार अधिकारियों समेत आठ अधिकारियों के यहां एक साथ ईडी की विभिन्न टीम ने छापे मारे।

जानकारी के अनुसार भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता (उत्तर) तारिणी दास के यहां सबसे पहले ईडी ने अपनी कार्रवाई प्रारंभ की। इसके बाद बुडको (बिहार अरबन डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लिमिटेड) के अभियंता तथा वहां तैनात एक अधिकारी समेत अन्य अधिकारियों के यहां भी जांच टीम पहुंची। छापेमारी जारी है। इस संबंध में ईडी ने आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं बताया। सूत्रों की मानें तो यह पूरा मामला आइएएस अधिकारी संजीव हंस से जुड़ा हुआ है। संजीव हंस मामले की जांच के क्रम में ही ईडी को भवन निर्माण, नगर विकास एवं आवास विभाग, बुडको में टेंडर घोटाले में गड़बड़ी के प्रमाण मिले थे। सूत्रों के अनुसार ईडी ने अपनी प्रारंभिक छापेमारी के दौरान ही तारिणी दास के ठिकाने से करोड़ों की नकदी बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। जो नकदी बरामद की गई है, वह तीन करोड़ के करीब बतायी जा रही है। हालांकि, अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है।

प्रतीकात्मक।

असम का पत्रकार जमानत के बाद दूसरे मामले में गिरफ्तार

गुवाहाटी, प्रेट्र : असम के पत्रकार दिलवर हुसैन मजुमदार को गुरुवार को एक अन्य मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि 25 मार्च को वित्तीय अनियमितताओं को लेकर एक सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक से पूछताछ करने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद उन्हें जमानत दे दी गई थी। वहीं, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दावा किया कि वह पत्रकार नहीं हैं, क्योंकि सरकार केवल प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के लोगों को ही पत्रकार मानती है।

अधिकारियों ने बताया कि डिजिटल पोर्टल 'द क्रास करंट' के मुख्य संवाददाता को मूल्यवान बैंक दस्तावेज चुराने के प्रयास के आरोप में दोबारा गिरफ्तार किया गया है। वह गुवाहाटी प्रेस क्लब के सहायक महासचिव भी हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में असम कोआपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डंबरू सैकिया ने 25 मार्च को शिकायत दर्ज कराई थी, जिस दिन मजुमदार ने उनसे पूछताछ की थी।

अखबार व सब्जी बेच दिलाई पत्नी को नौकरी, प्रेमी संग फरार

जागरण संवाददाता, अररिया : अखबार व सब्जी बेचकर पत्नी को शिक्षिका बनाया। उम्मीद थी कि दोनों बच्चों की परवरिश बेहतर तरीके से हो सकेगी और घर में खुशहाली आएगी। नौकरी मिलने के बाद पत्नी बेवफा निकली। पति व बच्चों को ठुकराकर दूसरे के साथ चली गई। महिला का पति बिहार में पूर्णिया जिले के नगर थाना क्षेत्र स्थित एक गांव का हैं। उनकी पत्नी बौंसी थाना क्षेत्र के एक गांव में पंचायत शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं। स्कूल के समीप गांव में एक किराये के मकान में रहकर स्कूल आती-जाती थी। मंगलवार को वह पड़ोस के सुनील राम के साथ फरार हो गई। पीड़ित पति ने जिला शिक्षा अधिकारी, डीएम व बौंसी थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि शिक्षिका की बरामदगी का प्रयास जारी है। पीड़ित पति के अनुसार, उसकी पत्नी को पड़ोस का सुनील राम बहकाकर ले गया है।

उप्र में कार्बन क्रेडिट से किसानों को मिलेंगे 202 करोड़ रुपये

शोभित श्रीवास्तव ● जागरण

पर्यावरण संरक्षण

- वर्ष 2026 तक 25,140 किसानों को मिलेगा इसका लाभ
- कार्बन क्रेडिट से किसानों को धनराशि देने वाला पहला राज्य बना उप्र

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए हरियाली बढ़ाने के साथ-साथ किसानों की आय भी कार्बन क्रेडिट के जरिये बढ़ाने की कोशिश में जुटी है। प्रदेश के छह मंडलों गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद व सहारनपुर के 25,140 किसानों को वर्ष 2026 तक 202 करोड़ रुपये कार्बन क्रेडिट से मिलने की उम्मीद है। सरकार को इन किसानों के पास 42,19,369 कार्बन क्रेडिट का अनुमान है। प्रत्येक पांच वर्ष में छह अमेरिकी डालर प्रति कार्बन क्रेडिट किसानों को मिलेगा। प्रदेश में कृषि वानिकी को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में कार्बन क्रेडिट योजना महत्वपूर्ण साबित हो रही है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2070 तक भारत को जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनाने की घोषणा की है। इसके तहत किसानों को अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। किसानों को कृषि वानिकी में किए गए पौधरोपण से कार्बन क्रेडिट के माध्यम से उनकी आय भी बढ़ाने की योजना है। किसानों को अधिक से अधिक तीव्र गति से बढ़ने वाले वृक्षों जैसे पापुलर, मीलिया डूबिया व शीशम आदि के पौधों का रोपण करने के लिए कहा जा रहा है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष सुनील चौधरी ने बताया कि कार्बन क्रेडिट के जरिये किसानों की आय में वृद्धि के लिए द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टेरी) के साथ एमओयू किया गया है।

भदोही में जमानत पर छूटे मनबढ़ ने फिर किया कक्षा नौ की छात्रा का अपहरण

जागरण संवाददाता, भदोही : उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में 12 फरवरी को जमानत पर छूटे युवक ने अपने ही गांव की 16 वर्षीय कक्षा नौ की छात्रा का फिर अपहरण कर लिया। इस मामले में पुलिस ने बुधवार की शाम आरोपित युवक आशीष सरोज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। किशोरी की मां ने आरोपित की मां, पिता व ताऊ पर अपहरण में शामिल होने का आरोप लगाया है।

किशोरी की मां ने कहा कि आरोपित पहले भी उनकी बेटी को भगा ले गया था। इसके बाद उस पर पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। युवक इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने पर रिहा हुआ था। आरोपित की गिरफ्तारी व किशोरी की बरामदगी के लिए पुलिस की तीन टीमें बनी हैं। युवक उसका पड़ोसी है। 22 मार्च को किशोरी की मां बाजार गई थीं। पिता भी काम से बाहर गए थे। घर में अकेली किशोरी को युवक भगा ले गया। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि आशीष के खिलाफ अप्रैल में इसी किशोरी के अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने तीन महीने बाद पुणे से किशोरी को मुक्त कराते हुए युवक को गिरफ्तार किया था।

'वसुधैव कुटुंबकम मानने वाले देश में सगे परिवार में एकता नहीं'

नई दिल्ली, प्रेट्र : परिवार संस्था के विघटन से चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में लोग 'वसुधैव कुटुंबकम' यानी पूरे विश्व को एक परिवार मानने में विश्वास करते हैं। लेकिन अपने करीबी रिश्तेदारों से भी निकटता बनाए रखने में विफल हो रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के जिला सुलतानपुर के एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि परिवार की अवधारणा अब 'एक व्यक्ति एक परिवार प्रणाली' से छिन्न-भिन्न हो रही है। हम आज अपने सगे परिवार में भी एकता नहीं बनाए रख पा रहे हैं। परिवार की पूरी अवधारणा ही शिथिल पड़ती जा रही है। हम अब एक व्यक्ति-एक परिवार बनकर ही रह गए हैं। सर्वोच्च अदालत ने यह गंभीर टिप्पणी एक महिला के अपने सबसे बड़े बेटे को घर से निकालने को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के दौरान की है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि उनके बेटे को घर से बाहर करने का कड़ा कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि वरिष्ठ नागरिक कानून के तहत उनका गुजारा भत्ता जारी रहना चाहिए।

अल्लाह के साथ रिश्ते को गहरा करने की कोशिश है रमजान

रमजान एक पवित्र और आध्यात्मिक माह है। इस महीने में, मुसलमान रोजा रखते हैं, जिसमें दिनभर भूखा और प्यासा रहकर उपवास करना होता है। यह महीना मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिसमें वे अपने आध्यात्मिक जीवन को मजबूत करने और अल्लाह के साथ अपने रिश्ते को गहरा करने की कोशिश करते हैं। रमजान के मुबारक महीने की खास इबादत रोजा रखने से, मुसलमान को अपने आप पर नियंत्रण रखने, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने और अपने शरीर को स्वस्थ रखने का अवसर मिलता है। रोजे की हालत में खाने-पीने की पाबंदी के साथ-साथ हर बुराई से रोजा होना होता है। रोजा रखने से मुसलमानों को यह भी सीखने को मिलता है कि कैसे गरीब और जरूरतमंदों की मदद करनी है, इसलिए इस महीने का इनाम अल्लाह की तरफ से उसके खत्म होने पर ईद है और ईद के लिए फितरा है। हर मुसलमान को अपनी बस्ती के गरीब के घर फितरा यानी दान देना लाजमी कर दिया गया है। फितरा लगभग दो किलो आटा या इतनी ही किशमिश या इतनी ही खजूर की कीमत लगा कर घर के हर सदस्य की तरफ से अदा किया जाना होता है।

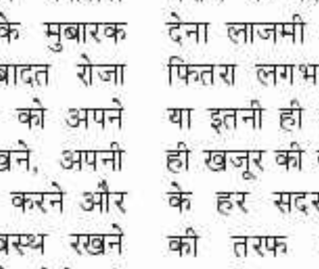

आतिफ रशीद
पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

'छुट्टी लेकर घर जा सकते डल्लेवाल, अवैध हिरासत में नहीं हैं'

राज्य ब्यूरो, जागरण ● चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल अपनी मर्जी से अस्पताल से छुट्टी लेकर घर जा सकते हैं। इसलिए पुलिस की अवैध हिरासत में नहीं हैं।

डल्लेवाल की रिहाई को लेकर दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस मनीषा बत्रा ने याचिकाकर्ता के वकील पूछा कि क्या डल्लेवाल खुद अस्पताल से डिस्चार्ज होना चाहते हैं, तो वकील ने जवाब 'नहीं' में दिया।

इस पर अदालत ने कहा कि डल्लेवाल अपनी मर्जी से अस्पताल से छुट्टी लेकर घर जा सकते हैं, इसलिए इसे अवैध हिरासत नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि डल्लेवाल से अस्पताल में मिलने आने वाले परिवार, मित्रों, रिश्तेदारों या किसी भी अन्य व्यक्ति को कोई रुकावट न हो।

19 अप्रैल को रेलमार्ग से कश्मीर जुड़ जाएगा कन्याकुमारी तक

जागरण संवाददाता, जम्मू

- प्रधानमंत्री मोदी कटड़ा रेलवे स्टेशन से बारामुला के लिए रेलगाड़ी को दिखाएंगे हरी झंडी
- रियासी जिले में दरिया चिनाब पर बने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भी जाएंगे पीएम

19 अप्रैल 2025... यह तिथि भारतीय रेलवे के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। इस तारीख को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के आधार शिविर कटड़ा से बारामुला के लिए पहली रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। इसी के साथ कश्मीर रेलमार्ग के जरिये कन्याकुमारी से भी जुड़ जाएगा। यात्री देश के किसी भी हिस्से से जम्मू और श्रीनगर होते हुए उत्तरी कश्मीर के बारामुला तक रेलगाड़ी की रोमांचपूर्ण यात्रा कर सकेंगे। बारामुला तक रेलगाड़ी शुरू होने की तिथि की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डा. जितेंद्र सिंह ने स्वयं दी है। जितेंद्र सिंह ने बताया कि कटड़ा से बारामुला के बीच रेल यातायात शुरू करने के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद 19 अप्रैल को उक्त रेलखंड में रेल यातायात बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस रेल खंड में कई बार रेलगाड़ी को दौड़ाकर ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री 19 अप्रैल की सुबह विमान से ऊधमपुर सैन्य छावनी पहुंचेंगे। वहां से वह हेलीकाप्टर से कटड़ा पहुंचेंगे। कटड़ा रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाने के बाद कटड़ा में ही एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर बाद वह ऊधमपुर और वहां से दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे।

दिशा के पिता ने कहा-मेरे साथ आदित्य ठाकरे सहित अन्य का भी हो नार्को टेस्ट

मुंबई, प्रेट्र : दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व प्रबंधक दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने कहा है कि मैं आज ही नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं। लेकिन, पुलिस को दी गई मेरी शिकायत में जिन लोगों के नाम हैं, उनका भी नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए। कहा कि इसमें आदित्य ठाकरे का नाम भी शामिल है। बुधवार को शिवसेना (यूबीटी) के लोकसभा सांसद अरविंद सावंत ने सतीश सालियान का नार्को टेस्ट किए जाने की मांग की थी। इसी के जवाब में उन्होंने ये बातें कहीं।

इस बीच, सतीश सालियान ने अपने अधिवक्ताओं के साथ दक्षिण मुंबई स्थित पुलिस आयुक्त कार्यालय में संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) से मुलाकात की। बताया गया है कि उन्होंने अपनी बेटी दिशा सालियान की मौत के मामले में शिवसेना (यूबीटी) के नेता आदित्य ठाकरे और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। इस संबंध में वह पहले ही पुलिस को लिखित शिकायत दे चुके हैं। दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने जून 2020 में रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई अपनी बेटी की मौत की नए सिरे से जांच कराने के लिए बांबे हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि दिशा के साथ दुष्कर्म किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। कुछ प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए राजनीतिक रूप से साजिश रची गई। आदित्य ठाकरे ने पहले कहा था कि वह याचिका में लगाए गए आरोपों का जवाब अदालत में देंगे। दिशा सालियान की मौत आठ जून 2020 को मलाड में एक आवासीय इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने से हुई थी।

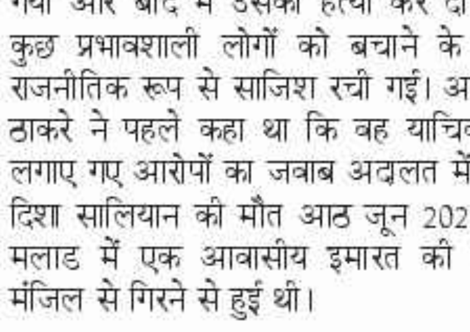

दिशा सालियान और आदित्य ठाकरे। फाइल

****

10 नशेड़ी केरल के मलप्पुरम में राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी की जांच में एचआइवी पाजिटिव मिले हैं। आशंका है कि सभी ने एक ही एचआइवी संक्रमित सीरिंज का इस्तेमाल किया, जिसके कारण उन्हें यह बीमारी हो गई।

दो और संगठनों ने हुर्रियत से तोड़ा नाता

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर साझा की जानकारी, कहा– पूरे कश्मीर में एकता की जीत की गूंज

कश्मीर में प्रतिबंधित जमाते इस्लामी समेत कई संगठनों व नेताओं के दो दर्जन ठिकानों को खंगाला

राज्य ब्यूरो, जागरण • श्रीनगर

अलगाववाद और आतंक के प्रति केंद्र सरकार की शून्य सहिष्णुता और अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण से आए बदलाव से कश्मीर में लोगों का अलगाववाद से मोहभंग हो चुका है।

अस्तित्वहीन हो रही हुर्रियत कान्फ्रेंस से गुरुवार को दो और अलगाववादी संगठन तहरीक-ए-इस्तिकलाल और तहरीक-ए-इस्तिकमात ने भी पीछा छुड़ा लिया। दोनों ने खुद को हुर्रियत कान्फ्रेंस और अलगाववाद से पूरी तरह अलग कर लिया है। पिछले चार दिन में हुर्रियत से पांच संगठनों ने नाता तोड़ा है।

इस बीच, जम्मू-कश्मीर में बचे-खुचे आतंकी और अलगाववादी पारिस्थितिकी तंत्र की जड़ें खोजकर इनका समूल नाश करने के अभियान में पुलिस ने अब और धार लाई है। इसी के तहत कश्मीर के कई इलाकों में प्रतिबंधित जमाते इस्लामी, मुस्लिम कान्फ्रेंस और पीपुल्स लीग समेत विभिन्न संगठनों व नेताओं के दो दर्जन घरों को खंगाला गया। हुर्रियत से जुड़े दो और संगठनों के अलग होने की जानकारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने खुद अपने एक्स हैंडल पर साझा की है। उन्होंने लिखा, 'कश्मीर से एक और बड़ी खुशखबरी। हुर्रियत से जुड़े दो और दलों जेएंडके तहरीक-ए-इस्तिकलाल और तहरीक-ए-इस्तिकमात ने अलगाववाद को त्याग दिया है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा निर्मित नए भारत में अपना विश्वास जताया है। मोदी सरकार के तहत अलगाववाद अपनी अंतिम सांस ले रहा है और पूरे कश्मीर में एकता की जीत की गूंज सुनाई दे रही है।'

जिन दो दर्जन ठिकानों पर तलाशी हुई वह सभी प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े : पुलिस ने कश्मीर में जिन दो दर्जन ठिकानों में तलाशी ली वह सभी प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े हैं। श्रीनगर में पठान कालोनी जकूरा और डाउन-टाउन के नवाकदल में जम्मू-कश्मीर पीपुल्स लीग के तोता गुट के ठिकानों को खंगाला गया। वहीं, शोपियां जिले के त्रेंज, इमामसाहिब, चोटीपोरा और मलडूरा में करीब एक दर्जन जगह पर तलाशी ली गई।

इस बीच बारामुला जिले में पुलिस ने मुस्लिम लीग और जमाते इस्लामी से जुड़े चार लोगों के ठिकानों को खंगाला है। तलाशी में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित संगठनों की प्रचार सामग्री, आतंकी व अलगाववादियों के महिमामंडन करने वाली और भड़काऊ सामग्री वाली पुस्तकें, वित्तीय लेनदेन के दस्तावेज और कुछ पोस्टर बरामद किए गए हैं।

> अलगाववाद और आजादी का नारा पूरी तरह से पाकिस्तानी एजेंडा साबित हुआ है, जबकि हम कश्मीर और कश्मीरियों की भलाई की बात करते हैं। कश्मीरियों को उनके मौलिक व लोकतांत्रिक अधिकार पूरी तरह से नहीं मिल रहे थे, वह मिले हैं, आज हम पूरे हिंदुस्तान के बराबर के नागरिक हैं।
>
> –अहमद, तहरीक-ए-इस्तिकमात के उपप्रधान

> मेरा अब हुर्रियत समेत ऐसे किसी भी संगठन से कोई नाता नहीं है जो भारत की एकता, अखंडता या संप्रभुता के खिलाफ बात करता हो। कश्मीर की आजादी और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा पूरी तरह से गलत है। इस नारे के कारण हम कश्मीरियों के साथ न्याय नहीं कर पाए, हमने कश्मीर और कश्मीरियत को नुकसान पहुंचाया है।
>
> –गुलाम नबी सोफी, तहरीक-ए-इस्तिकलाल के अध्यक्ष

ये संगठन हुर्रियत से हो चुके अलग

मोहम्मद शरीफ सरताज की अगुआई वाले जेएंडके फ्रीडम पार्टी, शाहिद सलीम की जेकेपीएम और एडवोकेट शफी रेशी के संगठन जेकेडीपीएम ने 24 और 25 मार्च को हुर्रियत से अलग होकर भारतीय संविधान में अपनी आस्था जताई थी। उन्होंने हुर्रियत को एजेंडा विहीन संगठन बताते हुए कहा था कि इसकी नीतियों से कश्मीरियों का कभी कोई भला नहीं हुआ। अब तहरीक-ए-इस्तिकलाल और तहरीक-ए-इस्तिकमात संगठन भी इससे अलग हो गए हैं। वहीं हुर्रियत के दो गुट हैं और दोनों गुटों के अधिकांश नेता जेल में हैं। उदारवादी गुट के चेयरमैन मीरवाइज मौलवी उमर फारूक कुछ माह पहले ही नजरबंदी से मुक्त हुए हैं।

राजौरी में बना आतंकी ठिकाना ध्वस्त, सामान बरामद

जागरण संवाददाता, राजौरी : सुरक्षाबलों ने जिले के मनैयाल गली क्षेत्र के जंगलों में बने आतंकी ठिकाने को ध्वस्त करके एक हैंडग्रेनेड, पांच एके राइफल की गोलियां व अन्य सामान बरामद किया। जवानों ने जंगल को घेर तलाशी अभियान तेज कर दिया है। ड्रोन के साथ श्वान की भी मदद ली जा रही है ताकि जल्द से जल्द जंगल के छिपे आतंकियों तक पहुंचाया जा सके।

'आत्महत्या का प्रयास या धमकी क्रूरता और तलाक का आधार'

- मुंबई हाई कोर्ट ने तलाक मंजूर करने के परिवार अदालत के फैसले में हस्तक्षेप से किया इन्कार
- मामले में पत्नी दिया करती थी धमकी, एक बार किया था आत्महत्या करने का प्रयास

मुंबई, प्रेट्र : बांबे हाई कोर्ट ने कहा है कि जीवनसाथी का आत्महत्या का प्रयास करना या आत्महत्या करने की धमकी देना क्रूरता है और यह तलाक का वैध आधार है। हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ के जस्टिस आरएम जोशी ने पिछले महीने अपने आदेश में दंपती के विवाह को खत्म करने के परिवार अदालत के आदेश को बरकरार रखा। महिला ने परिवार अदालत के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। पति ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी ने धमकी दी थी कि वह आत्महत्या करके उसे व उसके परिवार को जेल भिजवा देगी। परिवार अदालत के समक्ष दायर तलाक की याचिका में उसने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के प्रविधानों के तहत यह क्रूरता है।

हाई कोर्ट पीठ ने अपने आदेश में कहा कि पति की ओर से परिवार अदालत में प्रस्तुत साक्ष्य एवं अन्य गवाह यह प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त से अधिक हैं कि उसकी क्रूरता की दलील साबित होती है। अदालत ने कहा कि पति ने न सिर्फ पत्नी द्वारा आत्महत्या की धमकी का आरोप लगाया था बल्कि पत्नी ने एक बार आत्महत्या का प्रयास किया भी था। हाई कोर्ट ने कहा, 'जीवनसाथी की ओर से इस तरह का कृत्य ऐसी क्रूरता मानी जाएगी जो तलाक का आदेश देने का आधार बन जाती है।' पीठ ने तलाक मंजूर करने के परिवार अदालत के आदेश को रद करने से इन्कार कर दिया और कहा कि इसमें कुछ भी प्रतिकूलता नहीं है, लिहाजा किसी तरह के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।

बांबे हाई कोर्ट।

मामले के अनुसार, दंपती का अप्रैल, 2009 में विवाह हुआ था और उनकी एक पुत्री भी है। पति ने दावा किया था कि उसके सास-ससुर अक्सर उसके घर आया करते थे और उनके वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करते थे। 2010 में उसकी पत्नी उसका घर छोड़कर अपने माता-पिता के घर चली गई और लौटने से इन्कार कर दिया।

आयकर अधिकारी बन लूटने वाले सीआइएसएफ के पांच कर्मचारी निलंबित

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) ने नकली आयकर अधिकारी बनकर हाल में कोलकाता के बागुईआटी थाना इलाके में एक दिवंगत रियल एस्टेट प्रमोटर के घर पर तलाशी के नाम पर लूटपाट करने के आरोप में बंगाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अपने पांच कर्मियों को निलंबित कर दिया है और आंतरिक जांच शुरू कर दी है। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। लूटपाट मामले में कोलकाता के विधाननगर कमिश्नरेट की पुलिस ने बीते दो-तीन दिनों के दौरान बल के पांच कर्मियों समेत कुल आठ लोगों को गिरफ्तार किया था।

गिरफ्तार सीआइएसएफ कर्मियों में एक इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल और तीन कांस्टेबल शामिल हैं, जिनमें से एक महिला कांस्टेबल है। 17-18 मार्च की रात में एक गिरोह ने कथित रूप से आयकर अधिकारी बनकर चिनार पार्क इलाके में दिवंगत प्रमोटर के घर छापा मारा था और तलाशी के नाम पर लूटपाट की थी। शक होने पर अगले दिन प्रमोटर की बेटी विनीता सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद सभी की गिरफ्तारी हुई। मृतक प्रमोटर की दूसरी पत्नी आरती सिंह मास्टरमाइंड बताई जा रही है। सौतेली बेटी विनीता सिंह से पैसों को लेकर काफी दिन से विवाद चल रहा था। संपत्ति हड़पने के लिए उसने लूटपाट कराने की साजिश रची।

मणिपुर में प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े पांच उग्रवादी गिरफ्तार

इंफाल, प्रेट्र : मणिपुर में सुरक्षा बलों ने इंफाल पश्चिम और इंफाल पूर्व से पांच उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, ये उग्रवादी घाटी आधारित प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े थे। इसके अलावा, पुलिस ने इंफाल ईस्ट जिले में एक लावारिश वाहन से पांच किलो हेरोइन बरामद की है। प्रतिबंधित संगठन 'पीपुल्स लिबरेशन आर्मी' के दो सक्रिय सदस्यों को बुधवार को इंफाल पश्चिम के डिंगकू रोड इलाके से गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा, इंफाल ईस्ट के टॉप माखा लेईकाई से मंगलवार को प्रतिबंधित संगठन पीआरईपीएके (प्रो) के दो सक्रिय सदस्य गिरफ्तार किए गए थे। बुधवार को इंफाल ईस्ट के ताखेल ममांग लेईकाई इलाके से प्रतिबंधित संगठन कांगलेई यावोल कन्ना लूप के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि इंफाल ईस्ट जिले में एक लावारिस वाहन से करीब चांप किलो संदिग्ध हेरोइन बरामद की गई है। हेरोइन, वाहन में 419 साबुन के डिब्बों में छिपाई गई थी।

जितनी उम्र लिखी है, उतनी लिखी है : सलमान

- लारेंस बिश्नोई से जान के खतरे पर पहली बार बोले बालीवुड अभिनेता
- कहा–सुरक्षा प्रोटोकाल ने मेरी दिनचर्या को प्रभावित किया है

एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई : कुख्यात गैंग्सटर लारेंस बिश्नोई गिरोह से मिली मौत की धमकियों और कड़ी सुरक्षा के कारण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगने को लेकर अभिनेता सलमान खान ने प्रतिक्रिया दी है। 'दबंग' अभिनेता ने बुधवार रात मीडिया के साथ बातचीत में बताया कि सुरक्षा प्रोटोकाल ने उनकी दिनचर्या को प्रभावित किया है।

59 वर्षीय सलमान से सुरक्षा संबंधी सवाल पूछने पर उन्होंने अपनी अंगुली ऊपर उठाई। जब एक पत्रकार ने कहा– अल्लाह, तो उन्होंने कहा कि भगवान, अल्लाह सब बराबर है। जितनी उम्र लिखी है, उतनी लिखी है। बस यही है। कभी-कभी इतने सारे लोगों को साथ लेकर चलने पर समस्या हो जाती है। इस दौरान उन्होंने अपने निजी जीवन और मौत की धमकियों समेत कई मुद्दों पर बात की। कहा कि मैं इसके (सुरक्षा) बारे में कुछ नहीं कर सकता। खल्लास। इसलिए मैं गैलेक्सी (मुंबई स्थित घर का नाम) से शूटिंग के लिए जाता हूं और वापस आता हूं। किसी और रास्ते नहीं जाता।

उल्लेखनीय है कि साल 2018 में बिश्नोई ने काले हिरण शिकार (1998) मामले में अभिनेता की संलिप्तता को लेकर जोधपुर में अदालत में पेशी के दौरान उन्हें खुलेआम जान से मारने की धमकी दी थी। तब से अभिनेता को कई धमकियों का सामना करना पड़ा है। पिछले साल अप्रैल में कथित तौर पर बिश्नोई गिरोह के दो शूटरों ने उनके बांद्रा स्थित आवास के बाहर गोलियां चलाईं। इसके बाद उनकी बालकनी की सुरक्षा बुलेटप्रूफ ग्लास से बढ़ा दी गई और बाहर सड़क पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी गई। इसके दो महीने बाद नवी मुंबई पुलिस ने दावा था किया कि जब वह मुंबई के पास पनवेल में अपने फार्महाउस पर गए थे, तो अभिनेता की हत्या की साजिश का पता चला था। पिछले साल अक्टूबर में राजनेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अभिनेता के आसपास सुरक्षा और कड़ी कर दी गई थी। बता दें कि सिद्दीकी सलमान के करीबी दोस्त माने जाते थे।

सलमान खान।

अपने इर्द-गिर्द तैनात सुरक्षाकर्मियों को लेकर पूछे गए सवाल पर सलमान ने कहा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। इसलिए वे आपके साथ अच्छे हैं। मैं नहीं चाहता कि वे उन लोगों के साथ अच्छे रहें जो अच्छे नहीं हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या यह सुरक्षा आपके लिए अड़चन है? उन्होंने कहा कि ऐसा तब नहीं होता जब मैं प्रेस के साथ होता हूं, बल्कि तब होता है जब मैं प्रेस के बिना होता हूं। यह (सुरक्षा) मेरी शैली को बाधित करती है। सलमान की फिल्म सिकंदर रविवार को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

जेईई–एडवांस, 2025 से जुड़ी याचिका पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर केंद्र सरकार एवं अन्य से जवाब तलब किया है जिसमें वर्ष 2023 में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों ने आइआइटी में प्रवेश की परीक्षा जेईई-एडवांस, 2025 में शामिल होने के लिए अनुमति देने के निर्देश की मांग की है। जस्टिस बीआर गवई एवं जस्टिस अगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने केंद्र सरकार, ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड (जेएबी) एवं अन्य को नोटिस जारी कर उनसे 21 अप्रैल तक जवाब मांगा है। जेईई-एडवांस का आयोजन जेएबी ही करता है। याचिकाकर्ता 18 छात्रों ने कहा है कि वे जेईई-मेंस, 2025 में अंतिम प्रयास के तौर पर शामिल होने के पात्र हैं, लेकिन 18 मई को होने वाली जेईई-एडवांस में शामिल होने के अयोग्य हैं। याचिका के अनुसार, आइआइटी के लिए प्रवेश परीक्षा दो चरणों (जेईई-मेंस व जेईई-एडवांस) में होती है। जेईई-मेंस की नीति में अभ्यर्थियों को लगातार तीन वर्षों तक छह बार परीक्षा में बैठने की अनुमति है, लेकिन जेईई-एडवांस में छात्र सिर्फ दो बार ही परीक्षा में बैठ सकते हैं।

हरियाणा में ईद का राजपत्रित अवकाश वैकल्पिक, कर्मियों को लेनी पड़ेगी छुट्टी

राज्य ब्यूरो, जागरण • चंडीगढ़

- सैनी सरकार ने 31 मार्च को मौजूदा वित्त वर्ष का अंतिम दिन होने को बनाया आधार, विधानसभा में हंगामा

हरियाणा में 31 मार्च को पूर्व घोषित ईद के राजकीय अवकाश को रद कर वैकल्पिक अवकाश में बदल दिया गया है। अब ईद पर सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे। वैकल्पिक अवकाश के चलते जो कर्मचारी ईद पर छुट्टी लेना चाहेंगे, उन्हें सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेश पर गुरुवार को विधानसभा में हंगामा हुआ। नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने कहा कि हमारा एक ही त्योहार होता है। यह पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। राजपत्रित अवकाश को वैकल्पिक अवकाश में बदला जाना गलत है। इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सफाई दी कि 31 मार्च को मौजूदा वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन होने के कारण यह फैसला लिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यह गलत है। पूरे देश में ईद पर राजपत्रित अवकाश है, प्रदेश में इसे रद क्यों किया गया है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे मुद्दा ना बनाया जाए।

यह पहला मौका है जब प्रदेश में ईद के राजपत्रित अवकाश को वैकल्पिक अवकाश में बदला गया है। वैकल्पिक अवकाश का मतलब धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व पर दी जाने वाली छुट्टी से है, जो कर्मचारी के विवेक पर निर्भर करती है। वह चाहे तो छुट्टी ले सकता है अथवा नहीं भी। यह एक तरह का सवेतन अवकाश है और अनिवार्य नहीं है। जारी पत्र में कहा गया है कि 2024-25 की क्लोजिंग के कारण यह छुट्टी रद की गई है। 29 व 30 मार्च को वीकेंड है और 31 को वित्त वर्ष का आखिरी दिन है। सरकारी कैलेंडर में 31 मार्च को राजपत्रित अवकाश घोषित था। जनवरी में जारी अधिसूचना में मार्च में तीन राजपत्रित छुट्टियां दिखाई गई थीं, जिनमें 14 को होली, 23 को शहीदी दिवस और 31 को ईद-उल-फितर की छुट्टी थी। अब ईद पर वैकल्पिक अवकाश कर दिया गया है।

'सब मुझे मार देंगे' कहकर चार बच्चों की गर्दन काटी, खुद फंदे से लटका

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर

'ऐसा लगता है कि सब मुझे मार देंगे...' अक्सर यह दोहराने वाले राजीव कुमार ने मासूमों का नृशंस-सामूहिक हत्याकांड कर डाला। उसने बुधवार रात चारों बच्चों को एक थाली में दाल-चावल खिलाकर सुलाया। इसके बाद गंडासे से चारों की गर्दन काट दी। इनमें पांच वर्ष का बेटा रिषभ भी था। वह राजीव के सीने की ओट में लेटा था। अपनों के खून से हाथ रंगने के बाद राजीव ने पत्नी की साड़ी का फंदा बनाया और खुद भी जान दे दी। खौफनाक इरादे को अंजाम देने के लिए उसने दोपहर में ही झगड़ा कर पत्नी को मायके भगा दिया था। इसके बाद रेगमार से बांका की धार बढ़ाता रहा था।

उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर जिले के मानपुर चचरी गांव के राजीव कुमार के पिता पृथ्वीराज ने बताया कि एक वर्ष पूर्व दुर्घटना में सिर में चोट से बेटे की मानसिक स्थिति खराब हो गई थी। वह अक्सर उग्र हो जाता था। वह कुछ समय से कहने लगा था कि 'आसमान फटता महसूस हो रहा...आग बरस रही है। ऐसा लगता है कि सब मुझे मार देंगे।' 20 नवंबर, 2024 को बरेली के मानसिक अस्पताल में उपचार भी आरंभ कराया। वहां के चिकित्सक ने पर्चे पर उसके दिमाग में आने वाले विचार '...सब मुझे मार देंगे' का उल्लेख भी किया था। यह गंभीर मरीजों की मेडिकल हिस्ट्री जानने के बाद किया जाता है। उसके लिए दवा आती थी, मगर नियमित नहीं खाता था। बुधवार दोपहर उसने पत्नी कौशल्या उर्फ क्रांति देवी से झगड़ा कर उन्हें मायके भगा दिया। क्रांति चारों बच्चों स्मृति (13), कीर्ति (नौ), प्रगति (सात) व रिषभ (पांच) को साथ ले जाना चाहती थीं, मगर राजीव ने मना कर दिया। उन्होंने जाते समय बच्चों को नुकसान पहुंचाए जाने का अंदेशा जताया था।

- शाहजहांपुर में झगड़ा कर पत्नी को मायके भगाया, बच्चे अपने पास रोके

पृथ्वीराज बोले– शाम को चारों बच्चों को पड़ोस में बने अपने घर बुलाकर लिटा लिया था, मगर कुछ देर बाद राजीव उन्हें टाफी दिलाने के बहाने बुलाकर ले गया। उसके उग्र स्वभाव के कारण उसे रोक नहीं सके। रात 12 बजे तक उसके घर के आसपास रहकर आहट लेता रहा, फिर सो गए। गुरुवार सुबह सात बजे तक राजीव के घर में चहलपहल नहीं होने पर दीवार कूदकर अंदर पहुंचे। वहां बरामदे में तीन चारपाइयों पर चारों बच्चों के लहूलुहान शव पड़े थे। राजीव पत्नी की साड़ी से बने फंदे से लटका था। क्रांति ने बताया कि रात 11 बजे कीर्ति ने फोन कर कहा था कि अब सोने जा रहे हैं। पति का उपचार कराने को पट्टे पर मिली चार बीघा भूमि 65 हजार में गिरवी रख दी थी।

72 डिवीजन में होंगी तीन ब्रिगेड

प्रथम पृष्ठ से आगे

सैन्य सूत्रों ने बताया कि 72 डिवीजन में तीन ब्रिगेड होंगी और फिलहाल इसका एक ब्रिगेड मुख्यालय पूर्वी लद्दाख मे क्रियाशील हो चुका है। अन्य ब्रिगेड मुख्यालय और वाहिनियों के गठन की प्रक्रिया जारी है। ब्रिगेड में भी तय नियमों के मुताबिक वाहिनियों के गठन की प्रक्रिया जारी है। 72 डिवीजन को उत्तरी कमान को सौंपे जाने के बदले में माउंटेन स्ट्राइक कोर को एक नई डिवीजन दी जा रही है। इन दोनों नई डिवीजन के लिए अधिकारियों व जवानों की नियुक्ति सेना अपने मौजूदा संसाधनों से ही कर रही है। 72 डिवीजन में तैनात किए जाने वाले जवानों व अधिकारियों को संबंधित सैन्य युद्ध कौशल स्कूलों व संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 72 डिवीजन के पूरी तरह से क्रियाशील होने और पूर्वी लद्दाख में अपनी जिम्मेदारी संभालने के साथ ही वहां राजौरी-पुंछ के अलावा कुपवाड़ा व अनंतनाग से भेजी गई फोर्स वापस अपनी पुरानी जिम्मेदारी संभालेगी। गलवन के बाद इन वाहिनियों को विशेष तौर पर लद्दाख भेजा गया था।

बंगाल में पूर्व भाजपा सांसद के घर के बाहर फायरिंग व बमबाजी

- तृणमूल कांग्रेस की स्थानीय पार्षद के बेटे पर हमले का आरोप
- सांसद अर्जुन सिंह ने कहा– मैं चूड़ी पहनकर बैठने वाला नहीं हूं

राज्य ब्यूरो, कोलकाता: बंगाल में भाजपा के वरिष्ठ नेता व बैरकपुर से पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के उत्तर 24 परगना जिले के भाटपाड़ा स्थित आवास के बाहर अज्ञात बदमाशों द्वारा फिर फायरिंग व बमबाजी की घटना सामने आई है। पुलिस ने बताया कि यह हमला बुधवार देर रात हुआ जिसमें एक युवक घायल हो गया। भाजपा नेता का आरोप है कि रात करीब 10.30 बजे 50 से 60 लोगों के समूह ने हमला किया। देशी बम फेंके गए। अर्जुन सिंह और उनके सहयोगियों ने हमलावरों का पीछा किया लेकिन वे मौके से भागने में सफल रहे।

इधर, हिंसा भड़काने के आरोप में पुलिस ने अर्जुन को गुरुवार को ही दिन में तलब किया, मगर वह थाने नहीं गए। पुलिस ने उनके घर पहुंचकर पूछताछ की। भाजपा नेता ने स्पष्ट कहा कि मैं चूड़ी पहनकर बैठने वाला आदमी नहीं हूं। बैरकपुर के पुलिस आयुक्त अजय ठाकुर ने कहा कि घटना में शामिल लोगों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें कि पिछले साल चार अक्तूबर को भी सिंह के आवास पर हमला हुआ था। तब भी नमित सिंह पर आरोप लगा था। भाजपा नेता ने कहा कि हमले के पीछे तृणमूल कांग्रेस की स्थानीय पार्षद सुनीता सिंह के बेटे नमित सिंह का हाथ है। दावा किया कि उसने पुलिस के सामने अंधाधुंध गोलीबारी और बमबाजी की। पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, इलाके में मेघना जूट मिल में श्रमिकों के दो समूहों के बीच विवाद के बाद हिंसा भड़की। जगदल से तृणमूल के स्थानीय विधायक सोमनाथ श्याम ने अर्जुन सिंह और उनके समर्थकों पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। अशांति की खबर मिलने के बाद नमित घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि इसके तुरंत बाद स्थिति बिगड़ गई और गोलीबारी व बम विस्फोट होने लगे।

बंगाल में सांप्रदायिक तनाव के बाद हिंसा

जासं, मालदा: बंगाल में मालदा जिले के मोथाबाड़ी इलाके में सांप्रदायिक तनाव ने हिंसक रूप ले लिया। गुरुवार को उपद्रवियों ने मोथाबाड़ी थाने का घेराव किया और पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। कई दुकानों और घरों को भी निशाना बनाया। खासकर हिंदुओं की दुकानों और घरों पर हमले किए गए। घटना की सूचना मिलते ही जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार यादव के नेतृत्व में भारी पुलिस टीम मौके पर पहुंची। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठियां भांजी और उपद्रवियों को खदेड़ा। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है।

स्थानीय लोगों के अनुसार सोमवार रात करीब 10 बजे मोथाबाड़ी मोड़ पर मस्जिद के सामने पटाखा फोड़ने की घटना ने विवाद को बढ़ाया। मस्जिद में पटाखे फोड़ने की घटना को लेकर एक बैठक बुलाई गई थी। काफी भीड़ जमा हुई। भीड़ यहां से थाने की ओर निकली और रास्ते में दुकानों और घरों पर हमला शुरू कर दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस पहुंची तो उनकी भी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई।

खिलाड़ियों को बाल से चोटिल नहीं होने देगा खास फैब्रिक

जागरण विशेष निटरा के विज्ञानियों ने थ्रीडी स्पेयर निटेट फैब्रिक को विकसित करने में पाई सफलता

शाहनवाज अली • जागरण

गाजियाबाद: एक खिलाड़ी कभी रुकना नहीं चाहता, लेकिन चोट उसके खेल में एक बाधा बन जाती है। क्रिकेट, हाकी और बेसबाल जैसे खेलों में जहां तेज गति से आती गेंद खिलाड़ियों को गंभीर रूप से घायल कर देती है। इसके समाधान के लिए भारतीय विज्ञानियों ने थ्रीडी स्पेसर निटेड फैब्रिक विकसित किया है, जो खिलाड़ियों को लगने वाली चोट से बचाने में सक्षम होगा। इसे पहनने के बाद खिलाड़ियों को लेग गार्ड, थाई पैड, एलबो गार्ड पहनने की जरूरत नहीं होगी।

राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन (एनटीटीएम) के तहत उत्तर भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (निटरा) के विज्ञानियों ने इस फेब्रिक को डेढ़ वर्ष के शोध के बाद तैयार किया है। इसे खेल जगत के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। विज्ञानियों का मानना है कि यदि इस कपड़े का उपयोग बड़े स्तर पर किया जाता है तो यह पारंपरिक सुरक्षा गियर की जगह ले सकता है। यह खिलाड़ियों के लिए अधिक सुरक्षित व आरामदायक होगा। निटरा के महानिदेशक डा. अरिंदम बसु और विज्ञानी डा. रूपम चौहान के नेतृत्व में सहायक राजकुमार गौतम व रमेश ने इस फैब्रिक को तैयार करने में एक खास शियर थिकनिंग फ्लुइड का उपयोग किया है। यह फ्लुइड एक बेहद गाढ़ा तरल पदार्थ है। इस फैब्रिक को पहने किसी खिलाड़ी को यदि तेज गति की गेंद लगती है तो यह सख्त होकर चोट से बचाव करता है। आसान भाषा में कहें तो यह उसी तरह काम करेगा जैसे टक्कर लगने पर कार में लगा एयर बैग खुल जाता है। इसके अलावा, यह फैब्रिक हल्का और काफी लचीला है। इससे खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी बेहतर होगा। विज्ञानियों का दावा है कि 150 किमी प्रति घंटा गति से आने वाली गेंद से यह फैब्रिक सुरक्षा करेगा। क्रिकेट, हाकी और बेसबाल खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है।

विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें।

उत्पादन के लिए कंपनियों से बातचीत जारी

जहां तक खिलाड़ियों के लिए इसके फैक्रिक के उपयोग की बात है, तो इस नई तकनीक के बने थ्री डी स्पेयर निटेट फैब्रिक का निटरा की ओर से प्रमाणीकरण किया गया है। इसके लिए खेल उपकरण तैयार करने वाली तीन कंपनियों से वार्ता हो रही है। जल्द ही इस फैब्रिक से तैयार उत्पादों को बाजार में उतारा जाएगा। खास बात यह है कि इसकी कीमत प्रयोग होने वाले मौजूदा सुरक्षात्मक उत्पादों के आसपास ही होगी। इससे यह अधिक से अधिक खिलाड़ियों तक पहुंच सकेगा।

निटरा में तैयार थ्री डी स्पेसर निटेड फैब्रिक को दिखातीं विज्ञानी डा. रुपम चौहान • जागरण

पर्यावरण अनुकूल व आरामदायक

इस फैब्रिक की खासियत ये भी है कि यह काटन की तुलना में अधिक स्किन-फ्रेंडली है और शरीर से पसीना व नमी को ज्यादा सोखेगा। नई तकनीक से बना यह फैब्रिक सामान्य काटन के मुकाबले ज्यादा नमी को अवशोषित कर सकता है। इसे रिसाइकल भी किया जा सकेगा। जिससे यह पर्यावरण के अनुकूल भी रहेगा। अब तक क्रिकेट, हाकी और बेसबाल जैसे खेलों में खिलाड़ी भारी और कड़े पैड व सुरक्षा गार्ड पहनकर खेलते आए हैं, लेकिन इस नए थ्री डी स्पेसर निटेड फैब्रिक के आने से खिलाड़ियों को सुरक्षात्मक चीजें पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह हल्का और फ्लेक्सिबल होगा, जिससे खिलाड़ी आसानी से मूवमेंट कर सकेंगे।

> खेलों में खिलाड़ियों की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमने इस फैब्रिक को खास तौर पर खिलाड़ियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही यह तकनीक खेल जगत में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी।
>
> **डा. अरिंदम बसु,** महानिदेशक निटरा

> वास्तव में इस तरह का फैब्रिक खेल और खिलाड़ियों के लिए क्रांति से कम नही है। इससे खिलाड़ी निश्चित ही बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। जैसा कि बताया गया कि ये स्किन फ्रेंडली भी होगा तो काफी देर तक बल्लेबाज और विकेटकीपर आराम भी महसूस करेंगे।
>
> **नलिन मिश्रा,** रणजी प्लेयर उत्तर प्रदेश

अंडमान पुलिस ने 36000 करोड़ के ड्रग्स जब्ती में दाखिल की चार्जशीट

पोर्ट ब्लेयर, प्रेट्र: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस ने गुरुवार को पोर्ट ब्लेयर में विशेष एनडीपीएस कोर्ट में समुद्र के बीच से अब तक की सबसे बड़ी नशीले पदार्थ (ड्रग्स) की खेप के संबंध में चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस ने 36,000 करोड़ रुपये मूल्य की 6,016 किलोग्राम मेथामफेटामाइन बरामद की थी। डीजीपी एचएस धालीवाल ने कहा कि ऐसा संदेह है कि पिछले साल 23 नवंबर को अंडमान सागर में बैरन द्वीप के पास छह म्यांमार के चालक दल के सदस्यों के साथ पाया गया यह प्रतिबंधित ड्रग्स थाईलैंड जा रहा था। चालक दल के सदस्य फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। डीजीपी धालीवाल ने कहा था कि मछली पकड़ने वाले नाव में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी और वह थाईलैंड की ओर जाने के बजाय भारतीय जलक्षेत्र की ओर चला गया।

****

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 28 मार्च, 2025

दैनिक जागरण

वाणी की मिठास व्यक्तित्व की आभा बढ़ा देती है

सेहत का मोर्चा

भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के इस आकलन से अपनी पीठ थपथपा सकती है कि वर्ष 2000 के बाद भारत में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्युदर में 70 प्रतिशत की कमी आई है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की रिपोर्ट में उन योजनाओं और कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है, जिनके चलते शिशुओं की मृत्युदर कम करने में सफलता मिली है। इसका अर्थ है कि बीते कुछ समय में स्वास्थ्य सेवाओं और ढांचे को बेहतर करने के लिए वास्तव में कई उल्लेखनीय कदम उठाए गए हैं। इनमें आयुष्मान भारत योजना भी है। इसका उल्लेख भी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने विशेष रूप से किया है। यह स्वास्थ्य संबंधी विश्व की सबसे बड़ी योजना है। यह निर्धन परिवारों के लिए वरदान सिद्ध हुई है। आश्चर्य नहीं कि संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने कहा कि भारत ने लाखों लोगों के जीवन को बचाने का काम किया है। आयुष्मान भारत योजना की उपयोगिता को देखकर ही हाल में 70 वर्ष की आयु के सभी बुजुर्गों को इस योजना के दायरे में लाया गया है। बीते दिनों एक संसदीय समिति ने जिस तरह 60 वर्ष के ऊपर के सभी नागरिकों को इस योजना के दायरे में लाने की जरूरत जताई, उससे यही इंगित होता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए न केवल केंद्र सरकार को तत्पर रहना चाहिए, बल्कि राज्य सरकारों को भी।

केंद्र और राज्य सरकारों को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्वास्थ्य ढांचा सही स्थिति में नहीं है। छोटे शहरों और गांवों में न केवल डाक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है, बल्कि अस्पतालों और मेडिकल उपकरणों की भी। इसके चलते इन क्षेत्रों के लोग शहरों के बड़े अस्पतालों की ओर दौड़ लगाते हैं, जहां निजी क्षेत्र के अस्पतालों के मुकाबले सरकारी अस्पताल बहुत पीछे नजर आते हैं। यह एक हकीकत है कि एक बड़ी संख्या में लोग सरकारी अस्पतालों में मजबूरी में ही उपचार कराना पसंद करते हैं। यह सही है कि बीते कुछ वर्षों में अनेक नए मेडिकल कालेज खुले हैं, लेकिन इन मेडिकल कालेजों से निकले डाक्टर ग्रामीण इलाकों में सेवाएं देने के लिए तैयार नहीं होते। समय के साथ उपचार महंगा होता जा रहा है। यदि किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को निजी अस्पताल में उपचार कराना पड़ता है तो वह कर्जे में डूब जाता है। इसका एक कारण यह भी है कि अपने यहां स्वास्थ्य बीमा का उतना चलन नहीं, जितना आवश्यक है। सरकारें इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकतीं कि अधिक आयु के लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा महंगा होता जाता है और इसके बाद भी उसमें अच्छा-खासा जीएसटी लगता है। आखिर क्यों? अच्छा हो कि सरकारें सेहत के मोर्चे पर और अधिक ध्यान दें।

नशे पर वार

पंजाब सरकार ने बजट में नशे की समस्या पर विशेष ध्यान देकर उचित ही किया है। नशे के सेवन से जहां युवकों की आए दिन मौत हो रही है वहीं, नशीले पदार्थों की आपूर्ति के लिए लूट, झपटमारी के मामले भी सामने आ रहे हैं। ड्रग सेंसस का निर्णय सरकार का बड़ा कदम है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आंकड़ों के आधार पर समाज से इस बुराई को खत्म करने में मदद मिलेगी। यह अच्छा है कि सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल व विकास पर भी जोर दिया है। निश्चित रूप से जब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी और लोग स्वस्थ रहेंगे तो इसका सकारात्मक प्रभाव दिखेगा। खेल के क्षेत्र में पंजाब का कभी उल्लेखनीय स्थान रहता था, लेकिन अब पड़ोसी राज्य हरियाणा उससे आगे निकल गया है। खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने की घोषणा पर यदि अमल होता है तो पंजाब फिर खेलों में आगे निकल सकता है। शहरों में उच्च स्तरीय सड़कों के साथ ही गांवों के विकास पर भी सरकार का ध्यान है। हर विधानसभा क्षेत्र को पांच करोड़ रुपये मिलेंगे तो विकास की गति तेज होगी। बजट में सबसे ज्यादा उम्मीद महिलाओं को थी कि सरकार शायद इस बार 1100 रुपये प्रतिमाह देने के अपने वादे को पूरा कर दे, लेकिन ऐसा लगता है कि आर्थिक संकट के कारण वित्तमंत्री के हाथ बंधे हुए थे। किसी भी सरकार को यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि उसकी आय क्या है और इसी के हिसाब से खर्च भी करना चाहिए।

> राज्य सरकार ने बजट में नशे की समस्या को खत्म करने पर विशेष ध्यान देकर उचित किया है

भाजपा को रोकने के लिए भ्रम की राजनीति

डा. एके वर्मा

स्टालिन केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव बढ़ाकर अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों में राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन परिसीमन और त्रिभाषा फार्मूले को लेकर केंद्र सरकार पर आक्रामक हैं। वह दक्षिणी राज्यों को साथ लेकर मोदी सरकार को घेरना चाहते हैं। वह भ्रम फैला रहे हैं कि परिसीमन से तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटें घट जाएंगी। वे त्रिभाषा फार्मूले को लेकर तमिलनाडु पर हिंदी थोपे जाने का भी आरोप लगा रहे हैं, जो उनकी राजनीतिक बेचैनी को दर्शाता है। तमिलनाडु में 1967 से कांग्रेस का जो पराभव शुरू हुआ, वह दो क्षेत्रीय द्रविड़ दलों- द्रमुक और अन्नाद्रमुक के वर्चस्व के साथ खत्म हुआ। इसकी वजह वहां 1965 से शुरू हिंदी विरोधी आंदोलन था। आज उसी के सहारे स्टालिन आगामी विधानसभा चुनावों में अपनी वापसी का सपना देख रहे हैं। तमिलनाडु में द्रमुक और अन्नाद्रमुक के बीच सत्ता परिवर्तित होती रही है। इस हिसाब से 2026 में अन्नाद्रमुक की बारी दिखती है, लेकिन जयललिता की मृत्यु के बाद वह कमजोर पड़ गई है, जबकि मोदी के नेतृत्व में भाजपा विकल्प के रूप में उभरने की कोशिश कर रही है। भाजपा को पूर्व पुलिस अधिकारी और लोकप्रिय नेता अन्नामलाई का नेतृत्व प्राप्त है। 2024 लोकसभा चुनावों में भाजपा राज्य में 11.3 प्रतिशत वोट पाकर तीसरी शक्ति बनकर उभरी। पार्टी केवल 23 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी और उन सीटों पर उसे 19.6 प्रतिशत वोट मिले। भले ही भाजपा कोई सीट नहीं जीत पाई, पर कन्याकुमारी और कोयंबटूर में दूसरे स्थान पर थी।

स्टालिन को भय है कहीं अन्नाद्रमुक का एक धड़ा भाजपा की ओर न खिसक जाए और 2026 में भाजपा की सरकार न बन जाए। उनका यह भय निराधार नहीं, क्योंकि बीते दिनों अन्नाद्रमुक नेता पलानीसामी ने अमित शाह से मुलाकात की। यह मुलाकात यह भी बताती है कि अन्नाद्रमुक को स्टालिन के हिंदी विरोध में कोई दम नहीं दिखाई देता। स्टालिन ने दो मोर्चे खोल रखे हैं। प्रथम, वे त्रिभाषा फार्मूले को तमिलनाडु पर हिंदी थोपने का प्रयास बता रहे हैं। द्वितीय, परिसीमन पर भ्रम फैला रहे कि इससे तमिलनाडु और दक्षिणी राज्यों की संसद में सीटें घट जाएंगी। ये दोनों वास्तविकता से परे और राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित हैं। त्रिभाषा फार्मूले के तहत छात्रों को पांचवीं तक मातृभाषा में शिक्षा मिलेगी। छह से दस तक तीन भाषाओं अर्थात मातृभाषा, कोई भारतीय भाषा और अंग्रेजी का अध्ययन करना होगा। कक्षा 11 से 12 तक स्कूल चाहे तो कोई विदेशी भाषा जैसे जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश आदि पढ़ने का विकल्प दे सकता है। इसमें कहीं हिंदी पढ़ने की अनिवार्यता नहीं, पर जनता में क्षेत्रीयता-भाषा को आधार बना भ्रम फैलाना आसान है। इसी कारण आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने पूछा है कि पैसा कमाने के लिए तमिल फिल्में हिंदी में क्यों डब की जाती हैं? क्यों वे हिंदी से घृणा करते हैं?

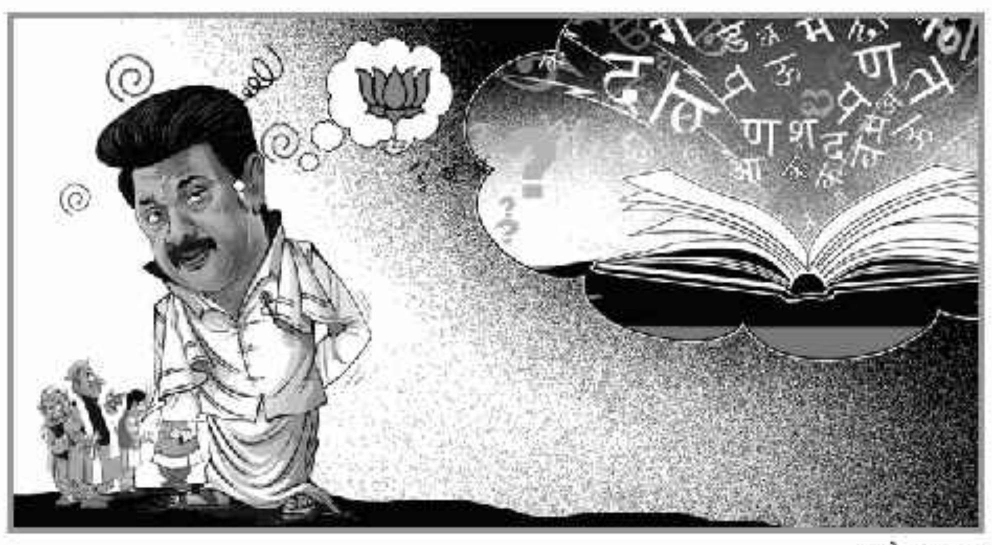

अवधेश राजपूत

परिसीमन पर भी स्टालिन का आरोप भ्रमात्मक है। अभी जनगणना होनी है। उसमें कम से कम एक वर्ष का समय लगेगा और 2026 के अंत तक उसके आंकड़े मिलेंगे। परिसीमन का काम 2027 के पहले शुरू नहीं हो सकेगा। सर्वप्रथम कानून द्वारा पांचवें परिसीमन आयोग का गठन होगा, फिर आयोग अपनी कार्यप्रणाली हेतु नियम बनाएगा। फिर परिसीमन का काम शुरू होगा। इस बार परिसीमन काफी चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि परिसीमन आयोग को लोकसभा की सीटें बढ़ानी हैं, जिससे प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र को एक नया आकार प्रकार मिलेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा और सभी विधानसभाओं की कुल सीटों में एक तिहाई सीटें महिलाओं हेतु आरक्षित करनी पड़ेंगी। विगत 50 वर्षों से पूर्ण परिसीमन नहीं हुआ है, जिससे आज अनेक सांसद लगभग 25-30 लाख जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

संसद को कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है, उन्हें पुरस्कृत करने हेतु कुछ अतिरिक्त सीटें आवंटित की जाएं। यह भी हो सकता है कि लोकसभा के वर्तमान सीट आवंटन को यथावत रखा जाए और परिसीमन से बढ़ी सीटों को नवीनतम जनसंख्या के अनुपात में राज्यों को आवंटित किया जाए। परिसीमन एक विधिक राजनीतिक प्रक्रिया है। इसमें परिसीमन आयोग को कई समझौते करने पड़ते हैं। स्टालिन द्वारा इसे मुद्दा बनाना परिसीमन आयोग पर राजनीतिक दबाव बनाने जैसा है।

प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के बाद तमिलनाडु में भाजपा को सशक्त करने हेतु प्रयासरत हैं। उन्होंने इसके लिए तमिल प्रतीकों का सहारा लिया है। 28 मई, 2023 को उन्होंने नई संसद में तमिल प्रतीक 'सेंगोल' की स्थापना की, जो चोल साम्राज्य में राजसत्ता का प्रतीक माना जाता था। मोदी ने उत्तर और दक्षिण, काशी और तमिल संस्कृति को जोड़ने हेतु दिसंबर 2022 से 'तमिल संगमम' शुरू किया, जिसका तीसरा संस्करण हाल में वाराणसी में हुआ। मोदी सरकार ने ट्रेनों के नाम भी तमिल प्रतीकों पर रखे हैं, जैसे 'सेंगोल एक्सप्रेस।' वह अपने भाषणों में प्रायः तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर और उनकी रचना 'थिरक्कुरल' का उल्लेख करते हैं। मोदी का उद्देश्य देश को एकता के सूत्र में बांधने का है। इसके सह उत्पाद के रूप में भाजपा को उसका राजनीतिक लाभ मिल सकता है।

राष्ट्रीय दल होने के कारण भाजपा को तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, और आंध्र प्रदेश में अपना विस्तार करना ही चाहिए। स्टालिन के डर का यह भी एक कारण है, लेकिन उनका डर निराधार है। त्रिभाषा फार्मूला न तो किसी राज्य पर हिंदी थोपने का प्रयास कर रहा है, न ही परिसीमन से किसी भी राज्य का लोकसभा में प्रतिनिधित्व कम होने जा रहा है। स्टालिन केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव बढ़ाकर अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों में राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन क्या वे ऐसा कर पाएंगे? क्या वह मोदी और भाजपा को तमिलनाडु में रोक पाएंगे? स्पष्ट है कि यह समय ही बताएगा।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं सेंटर फार द स्टडी आफ सोसायटी एंड पालिटिक्स के निदेशक हैं)

response@jagran.com

पाठ्यपुस्तकों में गुम असली नायक

औरंगजेब के महिमामंडन का मामला खत्म भी नहीं हुआ था कि बाबर का उल्लेख कर राणा सांगा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। औरंगजेब का महिमामंडन फिल्म छावा की सफलता के बाद शुरू हुआ था। इस फिल्म में दर्शाई गई औरंगजेब की क्रूरता एवं मजहबी कट्टरता के कारनामों से लोग स्तब्ध रह गए। इस फिल्म में स्वराज्य और स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगाने वाले छत्रपति संभाजी और उन्हें अमानुषिक यातनाएं देने वाले औरंगजेब का चित्रण किया गया है। संभाजी जैसे नायक की वीरता और निःस्वार्थता की कहानी देखकर स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि आखिर किन कारणों से हमारी पाठ्यपुस्तकों में आततायी शासकों एवं विदेशी आक्रांताओं का महिमामंडन किया गया और महानायक सी पात्रता रखने वाले भारतीय योद्धाओं की उपेक्षा की गई? उन्हें मुख्यधारा तो दूर, हाशिए पर भी जगह नहीं दी गई।

छत्रपति संभाजी, पेशवा बाजीराव, लचित बरफुकन, ललितादित्य मुक्तापीड, बप्पा रावल, राणा सांगा, महाराणा कुंभा, सरदार हरि सिंह नलवा जैसे राष्ट्र नायकों की वीरता और सिख गुरुओं एवं उनकी संतानों की बलिदानी परंपरा की तुलना में तुर्कों, अफगानों, मुगलों और अंग्रेज लार्डों के अतिरंजित यशोगायन को भला कैसे उचित एवं तर्कसंगत ठहराया जा सकता है? कैसी विडंबना है कि इतिहास की हमारी पाठ्यपुस्तकों में एक ओर मुगलों की पूरी की पूरी वंशावली रटा दी गई, उन्हें उदार और न्यायप्रिय सिद्ध करने के लिए मिथ्या कहानियां रची गईं तो दूसरी ओर छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, राजा कृष्णदेव राय, राजराजा चोल जैसे अनेक वास्तविक महानायकों को चंद पृष्ठों में समेट दिया गया?

भारत ने अपनी सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा के लिए कितना कुछ भोगा, यह हमें विस्तार से बताया जाना चाहिए था, पर हुआ इसके ठीक विपरीत। हमारे आहत स्वाभिमान और अतीत के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय स्वतंत्र भारत की अधिकांश सरकारों द्वारा उस पर नमक छिड़कने का ही कार्य किया गया। हद तो यह है कि देश में आततायी आक्रांताओं के नाम पर सड़कों, शहरों, चौक-चौराहों एवं सार्वजनिक भवनों आदि के नाम रखे गए और स्वतंत्रता के बाद भी उन्हें यथावत रहने दिया गया। देश के न केवल दूर-दराज के इलाकों, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों के नाम भी आक्रांताओं के नाम पर मिल जाते हैं। उन्हें देखकर वर्तमान पीढ़ी के मन में कैसा भाव जगता होगा? भला कोई देश आक्रमणकारियों का गुणगान कैसे कर सकता है? क्या इंग्लैंड में हिटलर के नाम पर किसी सड़क, भवन या चौक-चौराहे के नाम रखे जाने की कल्पना भी की जा सकती है? इंग्लैंड तो छोड़िए, जर्मनी तक में हिटलर के नामो-निशान नहीं मिलते, परंतु स्वतंत्र भारत में यह सब देखने को मिलता है। बर्बरता की सभी सीमाएं लांघ जाने वाले आक्रांताओं के नाम पर इमारतों-सड़कों-शहरों के न केवल नाम रखे गए, बल्कि उन नामों पर जलसे और जश्न मनाए गए। यदि किसी प्रबुद्ध व्यक्ति अथवा संगठन आदि ने आक्रांताओं द्वारा की गई क्रूरता का विरोध किया तो उलटे उन्हीं पर सांप्रदायिकता का आरोप मढ़ दिया गया।

प्रणय कुमार

> भारत ने अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए कितना कुछ भोगा, यह हमें विस्तार से बताया जाना चाहिए था

राणा सांगा पर सपा सांसद के विवादित बोल। फाइल

मुगलों का महिमामंडन करने वाले बुद्धिजीवी क्या यह नहीं जानते कि मुहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी, मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, तैमूर, नादिर, अब्दाली आदि की तरह मुगल भी विदेशी आक्रांता थे, जिन्हें अपनी पृथक पहचान पर बड़ा गर्व था। उन्होंने भारत से लूटे गए धन का बड़ा हिस्सा समरकंद, खुरासान, दमिश्क, बगदाद जैसे शहरों एवं इस्लामिक खलीफाओं की शानो-शौकत पर खर्च किया। वे स्वयं को तैमूरी नस्ल से जोड़कर देखते थे। जिस तैमूर ने तत्कालीन विश्व की लगभग पांच प्रतिशत आबादी का कत्लेआम किया, जिसने दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक निर्दोष एवं निहत्थे लोगों का अकारण खून बहाया, उससे जुड़े होने में वे गौरव का अनुभव करते रहे।

मुगल शासकों में औरंगजेब तो मजहबी कट्टरता का पर्याय था। नौ अप्रैल, 1669 को उसके द्वारा जारी राज्यादेश उसकी कट्टरता का प्रमाण है। इसमें उसने सभी हिंदू मंदिरों एवं शिक्षा केंद्रों को नष्ट करने के आदेश दिए थे। इस आदेश को काशी-मथुरा समेत उसकी सल्तनत के सभी 21 सूबों में लागू किया गया था। इस आदेश का जिक्र उसके दरबारी लेखक मोहम्मद साफी मुस्तइद खां ने अपनी किताब मआसिर-ए-आलमगीरी में किया है। मजहबी जुनून में उसने गैर इस्लामी त्योहारों एवं धार्मिक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। इस दौरान जजिया लगा, सनातनियों को दोयम दर्जे का नागरिक बनकर जीने को अभिशप्त किया गया तथा सिखों के नौवें गुरु तेगबहादुर और उनके तीन अनुयायियों भाई मतिदास, सतीदास और दयालदास को अत्यंत निर्दयता के साथ मरवा दिया गया।

क्रूर औरंगजेब के बारे में हाल तक एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में यही पढ़ाया जाता रहा कि वह टूटे मंदिरों के निर्माण के लिए दान दिया करता था। क्रूर आक्रांताओं एवं आततायी शासकों में नायकत्व देखने की प्रवृत्ति विभाजन की विषबेल को सींचती और समाज को बांटती है। यह समय की मांग है कि संभाजी या राणा सांगा जैसे योद्धाओं को हमारी पाठ्यपुस्तकों में समुचित स्थान मिले, ताकि कोई आततायियों का गुणगान करने की मूर्खता न कर सके।

(लेखक शिक्षाविद् हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

किंकर्तव्यविमूढ़

प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रायः ऐसी परिस्थितियां आती रहती हैं जिनसे निपटने के लिए उसे जोखिम उठाने की जरूरत रहती है, जिसको लेकर व्यक्ति दुविधा में रहता है। वह समझ नहीं पाता कि उसे जोखिम उठाना चाहिए या नहीं। वास्तव में उसे यह दुविधा प्रतिकूल परिणाम को लेकर मन में बैठी आशंका की वजह से होती है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति के पास चयन के लिए प्रायः दो ही विकल्प होते हैं। पहला कि वह जोखिम उठाए और उस परिस्थिति का सामना डटकर करे और परिणाम की जिम्मेदारी स्वयं ले। दूसरा कि वह कुछ भी न करे और सारी चीजें नियति के भरोसे छोड़ दे। यदि व्यक्ति पहले विकल्प का चयन कर जोखिम उठाता है तब या तो उसे मनोनुकूल परिणाम मिलेंगे या प्रतिकूल। ऐसा करने पर दो बातें हो सकती हैं-या तो वह मनोवांछित परिणाम पाने में सफल हो जाएगा या फिर असफल। सफल होना उसके लिए हर्ष की बात होगी, जबकि असफल होने पर उसे अपने जोखिम भरे प्रयास पर पछतावा होगा कि काश! उसने ऐसा नहीं किया होता। वहीं जिसके मन में असफल होने का भय रहता है वह दूसरे विकल्प का चयन करता है। हालांकि बाद में उसे भी पछतावा होता है कि काश! जोखिम उठाकर कुछ प्रयास किया होता तो शायद परिणाम मनोनुकूल होता। व्यक्ति जोखिम उठाए या नहीं, किंतु उसे पछतावा होना अपरिहार्य है। जोखिम लेने वाले व्यक्ति को अपने प्रयास करने पर पछतावा होता है तो वहीं जोखिम न लेने वाले को अपने प्रयास न करने पर।

निष्कर्षतः किसी भी दुविधा की स्थिति में व्यक्ति को जोखिम अवश्य उठाना चाहिए, क्योंकि कम से कम उसमें सफल होने की संभावना बनी रहती है, वहीं प्रयास न करने पर तो सफल होने की संभावना का ही अंत हो जाता है। अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सारे प्रयास करना, नियति के भरोसे छोड़ने से अधिक श्रेयस्कर है।

क्षितिज उपाध्याय

भारत की खुशहाली का पैमाना

डा. मोनिका राज

हाल में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत को 118वां स्थान दिया गया है, जो देश के करोड़ों नागरिकों के लिए एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक यह है कि नेपाल (92) और पाकिस्तान (109) जैसे देश भी इस सूची में हमसे ऊपर हैं। एक तरफ भारत तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है, दुनिया में उसकी साख बढ़ रही है और तकनीकी विकास में भी वह अग्रणी देशों में शामिल हो रहा है, तो दूसरी तरफ यह रिपोर्ट बताती है कि भारत के लोग अपेक्षाकृत अधिक दुखी हैं। भारत जैसा सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और जीवंत देश वाकई इतना 'अप्रसन्न' है या फिर यह किसी वैश्विक एजेंडे का हिस्सा है?

वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित की जाती है और इसे तैयार करने में कई मानकों को ध्यान में रखा जाता है। इनमें प्रमुख रूप से जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद), जीवन प्रत्याशा, सामाजिक सहयोग, भ्रष्टाचार का स्तर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानसिक स्वास्थ्य शामिल होते हैं। इन आंकड़ों को लेकर विभिन्न देशों के नागरिकों से सर्वेक्षण किया जाता है और फिर उस आधार पर एक सूची तैयार की जाती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सभी पैमाने वास्तव में खुशी को मापने के लिए पर्याप्त हैं? क्या किसी देश के नागरिकों की वास्तविक खुशहाली को मात्र आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर तय किया जा सकता है? भारत जैसे देश, जहां आध्यात्मिकता, पारिवारिक बंधन और सामाजिक ताना-बाना खुशी के अहम कारक होते हैं, क्या उनके मूल्यों को सही तरीके से इस रिपोर्ट में शामिल किया जाता है?

> भारत एक विविधतापूर्ण देश है, जहां हर राज्य, हर समुदाय और हर वर्ग की खुशहाली की परिभाषा अलग हो सकती है

भारत एक विविधतापूर्ण देश है, जहां हर राज्य, हर समुदाय और हर वर्ग की खुशहाली की परिभाषा अलग हो सकती है। पश्चिमी देशों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भौतिक सुख-सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि भारत में परिवार, रिश्ते, आध्यात्मिकता और धार्मिक मान्यताएं खुशी के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। एक पश्चिमी नागरिक के लिए खुशहाली का अर्थ हो सकता है- एक स्थिर नौकरी, निजी घर और साल में कुछ बार विदेश यात्रा। वहीं एक भारतीय व्यक्ति के लिए खुशहाली का अर्थ उसके परिवार के साथ रहना, सामाजिक मेल-जोल और आध्यात्मिक संतोष भी हो सकता है। जब हमारी खुशी के पैमाने ही अलग हैं, तो फिर किसी एक वैश्विक पैमाने से इसे मापा कैसे जा सकता है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत जैसी उभरती हुई शक्ति को निचले स्थान पर रखना उसकी वैश्विक छवि को कमजोर कर सकता है। ऐसे में भारत को अपने नागरिकों के वास्तविक जीवन स्तर को सुधारने और मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारी खुशहाली हमें खुद तय करनी होगी।

(लेखिका शोधार्थी हैं)

मेलबाक्स

हरित और समावेशी शहरी विकास जरूरी

'शहरी विकास का सही तरीका' शीर्षक से लिखे आलेख में हितेश वैध ने भारत में स्थायी और समावेशी शहरी विकास की आवश्यकता पर जोर देते हुए पर्यावरण-अनुकूल, तकनीकी रूप से दक्ष और सामाजिक रूप से संवेदनशील शहरी योजनाकारों के प्रशिक्षण और शिक्षा में सुधार की जरूरत पर प्रकाश डाला है। भारत के आर्थिक विकास की गति जितनी तीव्र हो रही है, शहरीकरण भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन क्या यह शहरी विस्तार पर्यावरणीय संतुलन और सामाजिक समावेशिता को ध्यान में रखकर किया जा रहा है? यदि हमारे शहर अनियोजित और असंतुलित विकास के शिकार होते रहे, तो आर्थिक समृद्धि भी अस्थायी सिद्ध होगी। इसलिए, अब समय आ गया है कि हम शहरी नियोजन को केवल इमारतों, सड़कों और यातायात व्यवस्था तक सीमित न रखकर इसे एक समग्र दृष्टिकोण से देखें, जिसमें पर्यावरणीय अनुकूलता, सामाजिक न्याय और आर्थिक गतिशीलता का संतुलन हो। आज दुनिया भर में 'ग्रीन अर्बनिज्म' और 'स्मार्ट सिटीज' जैसी अवधारणाएं तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं। भारत को भी इन सिद्धांतों को अपनाते हुए अपने शहरों को इस तरह विकसित करना होगा कि वे ऊर्जा-कुशल हों, जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें और हरित आवरण को प्राथमिकता दें। हमें शहरी नियोजन में सौर और पवन ऊर्जा, वर्षा जल संचयन और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी टिकाऊ तकनीकों को अनिवार्य रूप से शामिल करना होगा, ताकि शहर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के बजाय उनके संरक्षण का केंद्र बनें। इसके साथ ही, शहरों को इंसानों के लिए अधिक अनुकूल और रहने योग्य बनाना होगा। पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा और खुली हरित जगहों का विस्तार, ये सब ऐसे कदम हैं, जो शहरों को अधिक समावेशी और पर्यावरण-अनुकूल बनाएंगे। हमें '15-मिनट सिटी' की अवधारणा को अपनाना चाहिए, जहां नागरिकों को अपने लिए सभी बुनियादी सुविधाएं जैसे स्कूल, अस्पताल, बाजार और मनोरंजन केंद्र 15 मिनट के भीतर उपलब्ध हों। इससे यातायात का दबाव कम होगा, प्रदूषण घटेगा और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।

अमन सिंह गौर, छात्र, बीएचयू

ट्रंप की नीतियां भारत के लिए हितकारी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का त्वरित निर्णय विदेशी राजनीति के लिए कड़वा अनुभव हो सकता है, लेकिन अमेरिका के हित में है। पिछले टर्म में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की यात्रा की थी। टैरिफ का आंतरिक मामला है। अमेरिका-भारत की दोस्ती बहुत काम आने वाली है। ट्रंप सरकार रक्षा प्रौद्योगिकी में भारत के सहयोग करने के लिए तैयार है। फिलहाल ट्रंप की नीति भारत विरोधी नहीं है। भारत को अमेरिका से आयात की जितनी आवश्यकता है, उतनी अमेरिका को भी भारत की निर्यात की जरूरत है। अमेरिका की ऊर्जा नीति बेहतर है। ऊर्जा सुरक्षा भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रंप की नीतियां वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए काफी हैं।

कांतिलाल मांडोत, नई दिल्ली

संसद में अमर्यादित आचरण

''सांसदों का आचरण'' शीर्षक से प्रकाशित अग्रलेख पढ़ा। निःसंदेह विगत वर्षों से संसद के दोनों सदनों में चर्चा के स्तर के साथ आपसी व्यवहार में जबरदस्त गिरावट का अनुभव किया जा रहा है। यह सत्य है कि विगत 11 वर्षों में राजनीतिक दलों की भूमिका में बदलाव आया है। सत्ता पक्ष विपक्ष में और विपक्ष सत्ता में बैठा है। संभवतः चर्चा के गिरते स्तर और अमर्यादित आचरण की मुख्य वजह यही है, किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह जनादेश है जिसका सम्मान हर हाल में किया जाना चाहिए। अब बात करें नियम 349 की। इसकी उपधारा-एक सदन के विषय के अलावा अन्य पुस्तक, सामग्री पढ़ने से रोकती है। वहीं उपधारा-दो अमर्यादित अभिव्यक्ति से संबंधित है। सांसदों के अलावा नेता प्रतिपक्ष से यह देश इनके पालन की अपेक्षा करता है। यह अपेक्षा अधिक तो नहीं है।

ओपी चौधरी, अधिवक्ता, रतलाम

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

13 लाख शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए भारतीय बैंक नेटवर्क ने 4,386 करोड़ रुपये से अधिक बचाए हैं। यानी ठगी की घटनाओं को शिकायतकर्ताओं द्वारा तत्काल रिपोर्ट करने की दशा में बड़ी मात्रा में धन को बचाया जा सकता है।

आजकल

लोकमित्र
वरिष्ठ पत्रकार

साइबर ठगों पर प्रभावी अंकुश से ही बनेगी बात

संचार के विभिन्न माध्यमों से साइबर ठगों से सावधान रहने के लिए निरंतर किए जा रहे प्रचार के बावजूद देश में साइबर ठगों पर प्रभावी अंकुश लगता नहीं दिख रहा है। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 तक यानी नौ माह में डिजिटल धोखाधड़ी की 24 लाख घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं, जिनमें ठगों ने लोगों से 4,245 करोड़ रुपये ठग लिए हैं। साइबर धोखाधड़ी के विरुद्ध चलाए जा रहे सजगता अभियान के बावजूद साइबर ठगों के हौसले बुलंद हैं, जिस कारण इतने प्रचार प्रसार के बावजूद इन मामलों पर नियंत्रण मुश्किल होता जा रहा है

प्रतीकात्मक

हमारे देश में साल 2022-23 में जहां कुल 2537 करोड़ रुपये की ठगी हुई थी, वहीं साल 2023-24 में ठगी का आंकड़ा बढ़कर 4403 करोड़ रुपये हो गया। जबकि पिछले दस महीने में अपराधियों द्वारा ठगी गई रकम 4245 करोड़ रुपये हो चुकी है, जो कि साल 2022-23 के मुकाबले 67 प्रतिशत अधिक है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गृह मंत्रालय द्वारा हाल में गठित साइबर प्रकोष्ठ की तमाम सक्रियता के बावजूद अपराधी बेखौफ होकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी निगरानी करने के लिए सेंट्रल पेमेंट्स फ्राड इन्फार्मेशन रजिस्ट्री लागू की है, जिसमें बैंक, नान बैंक प्री पेड पेमेंट, इंस्ट्रूमेंट जारीकर्ता और नान बैंक क्रेडिट कार्ड कार्यकर्ता धोखाधड़ी की घटनाओं की रिपोर्ट करते हैं। इसका उद्देश्य तत्काल रिपोर्टिंग के जरिये ठगों को धन निकालने से रोकना है और अब तक इस प्रयास के जरिये 13 लाख शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करके बैंक नेटवर्क ने 4,386 करोड़ रुपये बचाए भी हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस, जांच एजेंसियों और बैंकों की साझी सतर्कता के बावजूद धोखेबाजों का कहर इन सब पर भारी पड़ रहा है। आरबीआइ ने इस संबंध में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक खास टूल 'म्यूल हंटर डाट एआइ' का सहारा ले रही है।

वहीं दूसरी ओर साइबर ठगों ने पिछले एक साल के भीतर ठगी के अपने तौर-तरीकों में एक हजार से ज्यादा नए तरीकों का इस्तेमाल किया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वास्तव में साइबर अपराधी कितने जुनून और बेखौफ अंदाज में अपनी कारगुजारियों को अंजाम दे रहे हैं। सवाल है कि आखिर हर तरह की कोशिशों और सजगताओं के बावजूद साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं किसी भी कीमत पर रुकने के बजाय आखिर बढ़ती ही क्यों जा रही हैं? दरअसल इसमें बैंकिंग सिस्टम में जो लूप होल्स हैं, वो तो हैं ही, उससे कई गुना ज्यादा आम लोग जो डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, वे बार बार बताने, समझाने के बावजूद लापरवाहियों से बाज नहीं आ रहे। डिजिटल डिवाइस इस्तेमाल करने वाला शायद ही कोई इंसान हो, जो दिन में कम से कम चार बार डिजिटल धोखाधड़ी से सावधान रहने के लिए आह्वान करने वाले विज्ञापनों, सलाहों को न सुनता हो।

लेकिन विभिन्न रिपोर्ट और अनुमान बताते हैं कि अभी भी आनलाइन बैंकिंग या किसी भी तरह के लेन-देन का इस्तेमाल करने वाले 50 प्रतिशत से ज्यादा लोग न केवल अपने आपके ठगे जाने की चिंता से रहित हैं, बल्कि उन्हें इसे जानने, समझने की कोई जरूरत ही नहीं महसूस होती। दिन रात डिजिटल लेनदेन करने वाले कई लोग भी आनलाइन सुरक्षा के प्रति बेहद लापरवाही बरतते हैं और सब कुछ जानने के बावजूद ठगी का शिकार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए आनलाइन अरेस्ट या डिजिटल अरेस्ट अथवा साइबर अरेस्ट जैसे मसले को ही लें, तो पिछले एक साल से इस संबंध में हजारों तरह से आगाह किए जाने की हरसंभव कोशिशें हुई हैं। फोन में कोई काल करने के साथ ही ज्यादातर बार लोगों को यह संदेश बार बार सुनाई देता है, बावजूद इसके सच्चाई यही है कि अधिकांश लोग इस सबको एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं।

ठगी के तरीकों में बदलाव : ठगों द्वारा बार बार ठगी की बदली जा रही तकनीक से भी वह पुलिस और जांच एजेंसियों को गच्चा देने में कामयाब हो रहे हैं। परंतु इससे भी बड़ी बात यह है कि देश में इतने बड़े पैमाने पर डिजिटल जीवनशैली जीने वाले हमारे देश में ज्यादातर लोगों की डिजिटल साक्षरता 50 प्रतिशत भी नहीं है। आम लोगों में से शायद ही किसी ने अपनी आनलाइन गतिविधियों के लिए कहीं से कुछ सीखा हो। आमतौर पर हमारे यहां लोग कोई भी सीख किसी तरह ठोकर खाते हुए सीखने की आदत का शिकार हैं और इस डिजिटल साक्षरता के मामले में भी लोग ऐसा ही उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं, जिस कारण सरकार या संचार माध्यम जितना भी चीख चीखकर लोगों को इस संवेदनशील तकनीक के इस्तेमाल के प्रति आगाह करें, लोग तब तक इस सबके प्रति जरा भी सजग होने की जरूरत नहीं समझते, जब तक कि स्वयं भारी धोखा न उठाएं। यह अकारण नहीं है कि अपने यहां हर घंटे 330 लोग और हर मिनट में करीब 5.5 लोग और लगभग हर 11 सेकंड में कोई न कोई व्यक्ति डिजिटल धोखाधड़ी का शिकार हो रहा है। ठगी की ऐसी भयानक स्थिति तो किसी भी दौर में नहीं रही, यहां तक कि जब कानून व्यवस्था को चाकचौबंद बनाए रखने के लिए जरूरी पुलिस और खुफियां एजेंसियां नहीं थीं, तब भी इतनी तेज रफ्तार से आपराधिक घटनाएं नहीं घटीं।

कोई हैरान करने वाली घटना घटती है और जांच एजेंसियां उसे आधार बनाकर लोगों को आनन फानन ऐसी घटनाओं से बचने की ट्रेनिंग और टिप्स दे रहे होते हैं, उसी दौरान न केवल वैसी ही, बल्कि अगले कुछ दिनों के भीतर ऐसी ही घटनाओं को और भी नए तौर तरीके से चकमा देने वालों की झड़ी लग जाती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस दौर में अपराधी, पुलिस और जांच एजेंसियों के डाल डाल के मुकाबले, केवल पात पात में ही नहीं है, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा तीव्र है। अतः जरूरी है कि देश में डिजिटल धोखेबाजों और अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए केवल सरकारों और पुलिस व जांच एजेंसियों के भरोसे रहना समझदारी नहीं है, नागरिकों को स्वयं भी अपनेआप को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी उठानी होगी तथा आनलाइन धोखेबाजों को सबक सिखाना होगा। (ईआरसी)

शेयर बाजार में गिरावट का आर्थिकी पर असर

शशांक भारद्वाज
आर्थिक मामलों के जानकार

भारतीय शेयर मार्केट विश्वसनीयता के गंभीर संकट के समय में है। मार्केट कैप अपने उच्चतम स्तरों से 110 लाख करोड़ रुपये कम हो चुका है। सैकड़ों शेयर वर्ष के सबसे निचले भावों पर है। इन निचले स्तरों पर भी आक्रामक खरीद नहीं दिख रही। इसका बड़ा कारण यह है कि निवेशकों का विश्वास डिग गया है। उन्हें लग ही नहीं रहा कि शेयरों में इन भावों से भी तेजी आएगी, लाभ होगा। वो इस मनोवृत्ति में दिख रहे कि जो भी भाव मिले, बेच दो। यह एक भयावह स्थिति है। सैकड़ों शेयरों में 70 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आ चुकी है। यानी मार्केट परम निराशा की स्थिति में है। विदेशी निवेशक भी सतत विक्रेता बने हुए हैं।

इन विपरीत परिस्थितियों में वित्त मंत्रालय को मार्केट के प्रोत्साहन के उपाय करने होंगे। सैकड़ों वर्षों के पश्चात भारतीयों के मध्य शेयर मार्केट को लेकर एक अच्छे विश्वास तथा उत्साह का वातावरण बना था। भारत में डीमैट खातों की संख्या बढ़कर 19 करोड़ से अधिक हो गई। कोरोना के बाद से 13 करोड़ नए डीमैट खातों ने शेयर मार्केट को संभाल लिया था, बड़ी तेजी का आधार तैयार किया, उस समय एक आशा के भाव ने मार्केट को उबारने में बड़ी भूमिका निभाई थी, परंतु अभी जैसी निराशा है, उसमें इसके प्रतिकार के लिए करोड़ों डीमैट खाते कहां से खुलेंगे। यह यक्ष प्रश्न है। इतनी बड़ी संख्या में निवेशकों का शेयर मार्केट के प्रति विश्वास डिगना न भारतीय शेयर मार्केट के लिए अच्छा है, न अर्थव्यवस्था के लिए। मूल्यांकन कुछ अधिक हुए थे, परंतु गिरावट के पश्चात भी हालात का निराशाजनक होना तो एक ध्वंस ही है। यदि समय रहते इसका प्रतिकार नहीं किया गया तो इसके घातक दुष्परिणाम हो सकते हैं। सरकार इस पर अविलंब ध्यान दे, उसके हाथ में जो उपाय है उन पर कार्य करना चाहिए। शेयर लाभ पर पूंजीगत कर में बड़ी कटौती करनी चाहिए। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उन्हें छूट प्रदान की जानी चाहिए।

म्यूचुअल फंड (एमएफ) में निवेश आ रहा है, परंतु अब यह भी धीमा हो रहा है। फरवरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड में मात्र 29,303 करोड़ रुपये का निवेश आया। इतनी धनराशि से मार्केट की बहुत सहायता नहीं मिल सकती है। भारत में एक एक कंपनी का मार्केट पूंजीकरण 15 लाख करोड़ रुपये तक है। भारत के मार्केट के आकार को देखते हुआ एक लाख करोड़ रुपये प्रतिमाह एमएफ में निवेश आना चाहिए, ताकि किसी बड़ी बिकवाली को आत्मसात किया जा सके। कई एमएफ में भी 20 से 30 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। इससे इनके निवेशकों का विश्वास भी दुर्बल हो रहा है। कुछ फंड प्रबंधक अत्यंत ऊंची पीई के शेयरों में निवेश करते रहे जो अनुचित था। उनके इस गलत निवेश ने भी एमएफ के प्रदर्शन पर बुरा प्रभाव डाला।

ऐसा नहीं है कि भारत में आर्थिक कारक अच्छे नहीं है। जीडीपी वृद्धि दर अच्छी है, अगली तिमाही और भी अच्छी होने की संभावना है। विश्व की प्रमुख ब्रोकर फर्में बड़ी तेजी की भविष्यवाणी कर रही हैं। कच्चे तेल में गिरावट बनी हुई है। डालर इंडेक्स नीचे है। आवश्यकता मंदी के मनोभाव के प्रतिकार की है। सरकार चेते, सक्रिय हो। अमेरिकी शेयर मार्केट में गिरावट आरंभ हो चुका है। टैरिफ युद्ध वहां नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। नैस्डेक भी 20 हजार के स्तरों से गिरकर 17,300 तक गिर चुका है। भारतीय शेयर मार्केट भी इनसे दुष्प्रभावित हो सकते हैं, रहते भी हैं। इन सबके बीच यह भी समझना होगा कि शेयरों में गिरावट तो आती जाती रहेंगी, आती जाती रहती भी हैं, परंतु विश्वास का संकट नहीं उत्पन्न होना चाहिए। समय आ गया है कि सरकार सक्रिय हो और वह आगे आकर इस विश्वास को कायम रखने का आश्वासन दे।

खरी-खरी

मैं रिटायर हो गया हूं

पूरन सरमा

जब मैं सरकारी सेवा में आया था, उस समय एक महापुरुष ने कहा था, 'नौकरी न कीजिए, घास खोद खाइए', लेकिन मुझे नौकरी की जरूरत थी, सो मैं नौकरी करने लगा। पता ही नहीं चला मैं कब रिटायरमेंट के करीब पहुंच गया, तब एक दिन 'केवल्य' प्राप्त हुआ कि मैं यह तनाव भरा जीवन क्यों जी रहा हूं। शुगर, ब्लड प्रेशर व अन्य रोगों का तोहफा मुझे अलग मिल चुका था। डाक्टरों के चक्कर और दवाओं से घनचक्कर बना मैं घर का रहा, न घाट का। अभी भी सेवा के दो वर्ष रह गए थे। मैंने अपनी पत्नी से एक दिन कहा, 'देखो, अब मैं नौकरी नहीं कर सकता। मेरा शरीर जवाब दे गया है। इसलिए मैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना चाहता हूं।'

पत्नी ने मेरी क्षीण होती काया पर गौर से दृष्टिपात किया और बोली, 'आप वीआरएस ले ही लें। आपने इस घर के लिए इतना किया है कि वह अविस्मरणीय है। हम भले एक टाइम दलिया खाकर टाइम पास कर लेंगे, लेकिन यातना-शिविर से तो आप बाहर निकल जाएंगे।'

पत्नी के आप्त वचन सुनकर मन गदगद हो गया। मोरल सपोर्ट बहुत बड़ी चीज है। फिर जवान बच्चे से पूछा तो वह हकला गया, बोला, 'क्यों पापा, अभी तो दो वर्ष हैं। घर में पड़े-पड़े बोर हो जाओगे। अभी आफिस के बहाने मन बहल जाता है।' मैं बोला, 'तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन नौकरी सिरदर्द बन गई है।' वह बोला, 'फिर आपकी मर्जी।' मैंने कहा, 'बेटा दलिया खा लोगे?'

'दलिया, व्हाट नानसेंस?' यह कहकर वह चला गया, मुझे पता था, यही होने वाला है। मैंने वीआरएस ले लिया और अब सेवानिवृत्ति के सुख के लिए आतुर था। सवाल वहीं आया कि अब दिनभर करें क्या? सक्रिय पथिक की यही बड़ी समस्या होती है। समझ में तो आ रहा था कि आलस्य को अपना लिया जाए तो दिन क्या, वर्षों तक की समस्या हल हो जाएगी। पड़े रहना ही समय पास करने का सबसे सरल और सीधा उपाय है। पत्नी ने कहा कि दोनों वक्त मंदिर चलेंगे। सुबह घूमना आपके लिए आवश्यक है ही। फिर भी, पेंशन के रूप में वेतन से चौथाई मिलने वाली आय से घर चलाना उतना ही मुश्किल था, जितना गठबंधन की सरकार।

X पोस्ट

इन दिनों इंटरनेट मीडिया पर सिर्फ बयानबाजी की जाती है और सड़क पर तमाशा होता है। जबकि होना तो यह चाहिए कि राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी करने वालों को कोर्ट में पेश किया जाए और कानूनी हथौड़ा चलाया जाए। आखिर सड़क पर तोड़फोड़ करके लोगों ने क्या हासिल किया?

मीनाक्षी जोशी@IMinakshiJoshi

आइपीएल में हर दिन विप्रज निगम, दिग्वेश राठी और विग्नेश पुथुर जैसे नवोदित सितारे अपनी चमक बिखेर रहे हैं। देश में गजब की प्रतिभाएं हैं, जो हर अवसर को भुनाने में लगी हैं। इसके लिए आइपीएल एक बढ़िया मंच के रूप में उभरा है।

हर्षा भोगले@bhogleharsha

कुणाल कामरा कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मसीहा नहीं हैं। उनकी प्रस्तुतियां राजनीतिक प्रोपेगंडा का हिस्सा रही हैं, लेकिन यह भी उनका निजी अधिकार है। जिन्हें भी उनकी बातों से आपत्ति है, वे मानहानि का मामला दायर करें। हिंसा किसी भी तरह जायज नहीं ठहराई जा सकती।

संकेत उपाध्याय @sanket

शशिशेखर
संपादकीय प्रभारी, रांची

झारखंड डायरी

खनिजों के प्रदूषण से मिले छुटकारा

खान-खनिज से संपन्न झारखंड का दुर्भाग्य यह है कि खनिज बहुल इलाकों में गरीबी, विस्थापन, प्रदूषण और बीमारी सौगात की तरह आती है। हम गर्व से कहते हैं, झारखंड में देश की 40 प्रतिशत खनिज संपदा है और छोटी-बड़ी हजारों फैक्ट्रियां हैं, लेकिन इन इलाकों में विकास की गति को देखकर महसूस कर सकते हैं कि यहां बड़ी आबादी मूलभूत समस्याओं से ही जूझ रही है।

विकास के लिए खनिज जरूरी है, लेकिन इसकी कीमत फैक्ट्रियों के आसपास के गांव वाले चुकाते हैं। चारो तरफ धुआं, प्रदूषण, धूलकण और तरह-तरह की बीमारियों से लोग परेशान तो होते ही हैं, खेत के साथ नदियां भी प्रदूषित होती हैं। कंपनियों के सीएसआर फंड का भी सही उपयोग नहीं हो पाता है। कंपनियां भी अपनी जिम्मेदारी से भागती रहती हैं।

हाल ही में गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने लोकसभा में इस मामले को सूचना के माध्यम से उठाया है। इसमें उन्होंने अपने क्षेत्र की ही बात की। उन्होंने कहा कि गिरिडीह के गादी श्रीरामपुर, उदनाबाद, मोहनपुर, फुलची आदि पंचायतों में 25 वर्षों से विभिन्न फैक्ट्रियों द्वारा प्रदूषण फैलाया जा रहा है। प्रदूषण से लोग सांस की बीमारियों से जूझ रहे हैं। कृषि भूमि बंजर हो गई है। लोगों में दिव्यांगता बढ़ रही है। फैक्ट्रियों द्वारा नदी में मलबा बहाया जा रहा है, जिससे नदियों के अस्तित्व पर ही संकट आ गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से इसकी जांच की मांग की गई है। हालांकि यह मामला केवल गिरिडीह का ही नहीं है। कुछ दिन पहले रामगढ़ में एक बैठक में हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने भी यही सवाल उठाया कि कंपनियों के प्रदूषण से बच्चों में सांस लेने की बीमारी बढ़ रही है। निमोनिया और टीबी के मरीज भी बढ़ रहे हैं। फैक्ट्री प्रबंधन का उत्तर आता है कि प्रदूषण रोकने के उपाय किए जा रहे हैं।

खनिजों के प्रदूषण से प्रदेश के बड़े इलाके में लोग दुष्प्रभावित हो रहे हैं। फाइल

झारखंड में कोयला एवं अन्य खनिजों के खनन और परिवहन के दौरान उड़ने वाली धूल के प्रदूषण से लोगों का स्वास्थ्य तो दुष्प्रभावित हो ही रहा है, वहीं दूसरी ओर यह पर्यावरण के लिए भी गंभीर संकट पैदा कर रहा है। इस तरह के प्रदूषण के कारण प्रदेश में जलाशय सूख रहे हैं और खेत भी बंजर हो रहे हैं। जहां भी उद्योग लगे हैं, उन जिलों में यह समस्या आम है, लेकिन इसके प्रति न तो सरकार गंभीर दिख रही है, और न ही स्थानीय प्रशासन।

इस तरह की समस्याओं से निपटने तथा खनिज संपदा से भरपूर जिलों के विकास के लिए डीएमएफ फंड (जिला खनिज निधि) की स्थापना की गई थी। झारखंड में इस मद में 13,791.4 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है और आवंटित 10,355.41 में से मात्र 25 प्रतिशत ही खर्च हो पाया है और इस 25 प्रतिशत का बड़ा हिस्सा यानी लगभग 40 प्रतिशत पेयजल और उसके बाद दूसरे मद में खर्च हुआ है, जबकि इस राशि का उपयोग प्रदूषण को दूर करने, प्रभावित लोगों के उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका सुलभ कराने पर खर्च किया जाना है। डीएमएफ फंड एकत्र करने वाले शीर्ष 21 जिलों में से पांच जिले धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा, रामगढ़ और बोकारो झारखंड से हैं। इन पांच जिलों में सर्वाधिक कंपनियां खनन की कार्यरत हैं। डीएमएफ ट्रस्ट 23 राज्यों में कार्यरत है। कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर और अन्य खनिजों से अनिवार्य योगदान से वित्तपोषित फंड ने वर्ष 2015 से अब तक 1,03,242 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए हैं। इस मामले में दुर्भाग्य यह है कि इस मामले में राष्ट्रीय स्तर पर भी लगभग 40 प्रतिशत ही खर्च हुआ है।

'आई फारेस्ट' नामक एक संगठन ने अपने एक हालिया अध्ययन में पाया कि अगले दस साल में यानी वर्ष 2025 से वर्ष 2035 के बीच हम तीन लाग करोड़ रुपये तक संग्रह कर सकते हैं, जिससे हम राज्य का कायाकल्प कर सकते हैं। राशि के सही उपयोग न होने के पीछे बेहतर प्लानिंग का अभाव है। इसके लिए गवर्निंग काउंसिल और मैनेजिंग कमेटी तो पूरे देश में बन गई है, लेकिन दोनों संस्थाओं के प्रमुख डीसी या डीएम ही हैं। इसमें ग्रामसभा को भी शामिल करना है, लेकिन ग्रामसभा को अक्सर बैठकों में शामिल नहीं किया जाता। इस फंड का सही उपयोग करके हम खनन जिलों में गरीबी कम कर सकते हैं। प्रदूषण घटा सकते हैं और खनन क्षेत्रों के विकास के लिए ढांचागत सुविधा प्रदान कर सकते हैं।

कोयला से पूरा देश रोशन होता है, लेकिन अंधेरा झारखंड के हिस्से आता है। कोयला खदानों के आसपास ग्रामीणों की स्थिति देख सकते हैं कि वे किस हाल में रह रहे हैं। हमारे पास फंड की कमी नहीं है, कमी है दृढ़ इच्छाशक्ति और बेहतर कार्ययोजना की।

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या सौगात-ए-मोदी की पहल से अल्पसंख्यकों के बीच भाजपा की पैठ बढ़ेगी?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या राणा सांगा पर अपने बयान के लिए सांसद रामजीलाल सुमन को माफी मांगनी चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

अगले हफ्ते से शुरू होना है नवरात्र,
भर जाएगा प्रेम से अपने मन का पात्र।
अपने मन का पात्र न होगा कोई दंगा,
पा करके 'सौगात' हुआ उनका मन चंगा!
शायद 'ईदी' पाय भाइयों का मन बदले,
निकलें दुर्गा-राम शांति से हफ्ते अगले!!

– ओमप्रकाश तिवारी

मंथन

शुभम केवलिया
असिस्टेंट प्रोफेसर, शहीद भगत सिंह महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय

वैदिक परंपरा के प्राचीन साक्ष्य

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित सिनौली से हाल ही में मिले पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में पहले से ही वैदिक मान्यताओं का अनुसरण करने वाले लोग रहा करते थे और वे इसी क्षेत्र के मूलनिवासी थे

वैदिक काल और आर्य, ये दो ऐसे शब्द हैं जिसने भारत समेत संपूर्ण विश्व के इतिहासकारों व आम जनमानस को 19वीं शताब्दी से आकर्षित करके रखा है। अंग्रेजों के भारत में स्थापित हो जाने के बाद उनके इतिहासकारों ने मजबूती से इस बात को स्थापित करने का प्रयास किया कि आर्य नामक एक जातीय समूह 1500 ईसा पूर्व में मध्य एशिया से चलकर भारत आया। उनके अनुसार, ये वही लोग थे जो भारत में अपने साथ घोड़े व रथ लेकर आए। भारत की परतंत्रता व पुरातात्विक साक्ष्यों की कमी व अनदेखी ने इस मिथक को स्थापित कर दिया कि आर्य नामक एक जाति भारत में मध्य एशिया से आई थी। परंतु, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में हिंडन व यमुना नदी के मध्य में स्थित सिनौली नामक पुरास्थल से वर्ष 2018-19 में मिले पुरावशेषों ने यूरोपीय इतिहासकारों व उनके अनुगामी भारतीय इतिहासकारों द्वारा रचित आर्य आगमन के मिथक को धराशाई करने का कार्य किया है।

कहा जाता था कि 1500 ई. पू. में मध्य एशिया से आए तथाकथित आर्य भारत में रथ लेकर आए, परंतु सिनौली से प्राप्त रथ तो 2000 ई. पू. के हैं तथा 1500 ई. पू. से अधिक प्राचीन हैं। इतना ही नहीं, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में रथों को सूर्य किरणों से आलोकित होने की चर्चा की गई है। सिनौली से मिले काष्ठ निर्मित रथों के पहियों में तांबे से जो जड़ाई का कार्य किया गया है, वह सूर्य के फैलते हुए प्रकाश जैसा ही है। इस प्रकार सिनौली से मिले रथ व ऋग्वेद में वर्णित रथों में साम्यता है। यहां यह बात भी उल्लेखनीय है कि हड़प्पा उत्खनन की विवरणिका (1940) में भी ताम्र निर्मित रथ प्राप्त होने का विवरण उपलब्ध है। दुर्भाग्यवश इस रथ की बात इतिहास की किसी पुस्तक में नहीं की गई है। जहां तक बात घोड़े की है तो सिनौली के उत्खननकर्ता का मानना है कि रथ के वजन व माप के अनुसार यह रथ घोड़े के द्वारा खींचना ही संभव था। इतना ही नहीं, घोड़े के अवशेष सरस्वती सिंधु सभ्यता के विभिन्न पुरास्थल जैसे सुरकोटदा, लोथल, रंगपुर, शिकारपुर आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं।

सिनौली में हुए उत्खनन से हमें योद्धाओं द्वारा पहने जाने वाले ताम्र निर्मित शिरस्त्राण भी मिले हैं। यह शिरस्त्राण मृत शरीर के साथ ही दफनाए गए थे। भारत में इससे पूर्व इस काल के शिरस्त्राण प्राप्त नहीं हुए थे। ऋग्वेद के छठे मंडल में वैदिक देवता मरुतों के द्वारा युद्ध में जाते समय शिरस्त्राण पहने जाने के उल्लेख हैं। यह पुरावशेष भी सिनौली के लोगों में प्रचलित वैदिक परंपरा का ही द्योतक है। सिनौली से ही मिले कई शवाधानों में एक शवाधान में काष्ठ निर्मित एक शवपेटिका ऐसी भी है जिस पर तांबे की नौ मुखाकृतियां बनाई गई हैं। इन मुखाकृतियों ने बैल के सींग युक्त मुकुट पहने हैं। निश्चित तौर पर शवपेटिकाओं पर बनी इन मुखाकृतियों का कोई धार्मिक प्रयोजन है।

ऋग्वेद में इंद्र व अग्नि को बैलों के सींग से युक्त मुकुट पहनाए जाने की चर्चा की गई है। पुरातत्वविदों का ऐसा मत है कि ये मुखाकृतियां वैदिक देवता इंद्र और अग्नि की हैं। भारतीय जनमानस में दीर्घकाल से यह भ्रम रहा है कि उनके समाज में मृत्योपरांत शव को केवल जलाने की ही परंपरा रही है। ऋग्वेद के दसवें मंडल में शवों को दफनाने के कई उल्लेख उपलब्ध हैं। भारतीय समाज में आज भी शवों को जलाने व भू-समाधि देने की परंपरा विद्यमान है।

कई पाश्चात्य विद्वानों ने सिनौली के इन रथों को मध्य एशिया से आने वाले तथाकथित आर्यों से जोड़ने का प्रयत्न किया है। जिन आर्यों के आगमन का समय पूर्व में 1500 ई. पू. बताया जाता था, उसे अब 2000 ई. पू. ले जाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। परंतु ये इतिहासकार यह भूल जाते हैं कि सिनौली के कंकालों का डीएनए व राखीगढ़ी से मिलने वाला 2500 ई. पू. का डीएनए समान है। ऐसे में सिनौली के लोगों को मध्य एशिया से आए आर्य बताना पूर्णतः तथ्यहीन है। इसके साथ ही अमेरिकी मानव विज्ञानी लुकाक्स व कैनेडी के शोध के अनुसार, उत्तर पश्चिम भारत में 800 ई. पू. तक की जनसंख्या में कोई मध्य एशियाई डीएनए उपलब्ध नहीं है। डीएनए पर कुछ ऐसा ही परिणाम हाल ही में हुए शोधकार्यों में भी प्राप्त हुआ है। साथ ही, यदि सिनौली के निवासी पश्चिम दिशा से आए थे तो सिनौली जैसे पुरावशेष उस क्षेत्र से भी प्राप्त होने चाहिए, लेकिन ऐसे कोई पुरावशेष हमें दिखाई नहीं देते।

सिनौली से प्राप्त काष्ठ-ताम्र निर्मित रथ। फाइल

ऋग्वेद में वर्णित शवों को दफनाने की परंपरा, सिनौली से मिलने वाले शवाधान व पुरावशेषों के ऋग्वेद में वर्णित श्लोकों से साम्यता इस बात की ओर इंगित करती हैं कि सिनौली में आज से 4000 वर्ष पूर्व रहने वाले लोग वैदिक परंपरा के अनुयायी थे। इतना ही नहीं, राखीगढ़ी व सिनौली से मिले कंकालों के डीएनए में साम्यता इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि 1500 ई.पू. में आर्य नामक कोई मानव समूह घोड़े युक्त रथों पर सवार हो मध्य एशिया से भारत में नहीं आया। भारत में आज से 4000 वर्ष पूर्व के पहले से ही वैदिक मान्यताओं का अनुसरण करने वाले लोग रहा करते थे और वे यहीं के मूलनिवासी थे।

****

क्विक कामर्स की दो-तिहाई से अधिक हिस्सेदारी

नई दिल्ली : वर्ष, 2024 में सभी ई-किराना आर्डर में से दो-तिहाई से अधिक हिस्सेदारी क्विक कामर्स प्लेटफार्म की रही। यह इस बात को रेखांकित करता है कि कैसे क्विक कामर्स भारत में उपभोक्ताओं की खरीदारी के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। क्विक कामर्स के जरिये की गई खरीदारी (मूल्य के संदर्भ में) ई-कामर्स प्लेटफार्म पर कुल खरीदारी के 10 प्रतिशत के बराबर है। (प्रेट्र)

तमाम वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत का वस्तु एवं सेवा निर्यात 800 अरब डालर के पार जाने के लिए तैयार है।

— संतोष कुमार सारंगी, विदेश व्यापार महानिदेशक

सेंसेक्स	77,606.43	317.93
निफ्टी	23,591.95	105.10
सोना प्रति दस ग्राम	₹91,050	₹365
चांदी प्रति किलोग्राम	₹1,01,700	₹200
डालर	₹85.74	₹0.05
क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$73.62	

एक नजर में

हेलमेट निर्माता स्ट्डस ने जमा किए मसौदा दस्तावेज

नई दिल्ली: हेलमेट निर्माता कंपनी स्ट्डस एसेसरीज ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) के जरिये पैसा जुटाने के लिए सेबी के पास प्रारंभिक दस्तावेज जमा किए हैं। यह पूरा आइपीओ आफर फार सेल पर आधारित होगा और इसमें प्रमोटर 77.9 लाख शेयर बिक्री के लिए पेश करेंगे। बाजारों में सूचीबद्ध होने का यह स्ट्डस का दूसरा प्रयास है।

29-31 मार्च को भी खुलेंगे आयकर कार्यलय

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने कहा है कि साप्ताहिक अवकाश और ईद के बावजूद करदाताओं की सुविधा के लिए उसके देशभर में स्थित कार्यालय 29-31 मार्च तक खुले रहेंगे। आकलन वर्ष 2023-24 के लिए अपडेट आइटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 है। आरबीआइ के सभी कार्यालय भी 31 मार्च को खुलेंगे। (प्रेट्र)

चाय निर्यात में भारत ने श्रीलंका को पीछे छोड़ा

नई दिल्ली : श्रीलंका को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है। कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान भारत ने कुल 25.5 करोड़ किलोग्राम चाय का निर्यात किया है। चाय निर्यात में केन्या शीर्ष पर बना हुआ है। चाय बोर्ड के डाटा के अनुसार, पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान भारत का चाय निर्यात 10 प्रतिशत बढ़ा है। 2023 में भारत ने 23.16 करोड़ किलोग्राम चाय का निर्यात किया था। (आइएएनएस)

अगले वर्ष 6-8 प्रतिशत बढ़ेगा आइटी सेवा क्षेत्र

नई दिल्ली: रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने गुरुवार को ताजा रिपोर्ट में कहा है कि अगले वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारत के आइटी सेवा क्षेत्र में 6-8 प्रतिशत की वृद्धि रहने का अनुमान है। एजेंसी का कहना है कि अमेरिका और यूरोप जैसे प्रमुख बाजारों में उभरी अनिश्चितताओं और व्यापक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत के आइटी सेवा क्षेत्र में वृद्धि जारी रहेगी। (आइएएनएस)

एक जैसे उत्पाद पर हो जीएसटी की एकसमान दर

विवादों के साथ व्यापारियों की लागत में भी आएगी कमी, दरों में कमी करने से सरकार के राजस्व में होगी बढ़ोतरी

जीएसटी की फांस

राजीव कुमार ● जागरण

- राजनीतिक मजबूरियों की वजह से जीएसटी की विसंगतियों पर नहीं हो पाता है कोई फैसला
- जीएसटी स्लैब में बदलाव को लेकर जल्द वित्त मंत्री को रिपोर्ट सौंपेगा मंत्रियों का समूह

नई दिल्ली : अगर आप रेस्तरां में खाना खाते हैं तो पांच प्रतिशत, लेकिन खाने के बाद अगर आपने आइसक्रीम खा ली तो 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। रोटी खाएंगे तो अलग, पराठा खाएंगे तो अलग जीएसटी। कोई ग्राहक एक रोटी और दो पराठा खा ले तो बिल बनाने में दुकानदार परेशान होगा और बिल देखकर ग्राहक भी। रेस्तरां में एसी चल रहा हो या नहीं अगर उसे एसी रेस्तरां का दर्जा प्राप्त है तो किसी भी फूड आइटम पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। कपड़ा खरीदने जाएंगे तो 1000 रुपये से कम वाले पर अलग जीएसटी तो उनसे अधिक वाले पर अलग। फुटवियर में भी यही हाल है। खुले में फूड आइटम पर कोई टैक्स नहीं तो उसे पैक्ड रूप में दे दिया तो टैक्स लग जाएगा। जीएसटी में विसंगतियों के ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। इन भ्रांतियों की वजह से व्यापारी कई बार गलती कर बैठते हैं और उन्हें पेनाल्टी या अन्य रूप में इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है।

ग्राहक भी खुद को ठगा महसूस करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अब जीएसटी की इन विसंगतियों को दूर करने के साथ जीएसटी की दरों में भी कमी लाने की जरूरत है। विशेषज्ञों के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की कुछ बैठकों में इस प्रकार की विसंगतियों को दूर करने को लेकर चर्चाएं तो हुईं, लेकिन जीएसटी कलेक्शन और राजनीतिक मजबूरियों की वजह से कोई फैसला नहीं हो सका। जैसे पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में शामिल करने पर चर्चाएं तो कई बार हुईं, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका। विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक में जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने और कई आइटम की दरों में कमी पर चर्चा शुरू हो सकती है। हालांकि माना जा रहा है कि राज्य राजस्व में कमी की आशंका से दर कम करने पर राजी नहीं होंगे।

पेट्रोल को जीएसटी में लाने के लिए केंद्र को करनी होगी पहल

विशेषज्ञों का कहना है कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में लाने के लिए केंद्र सरकार को पहल करनी होगी। राज्यों के भरोसे छोड़ने पर पेट्रोलियम कभी भी जीएसटी के दायरे में नहीं आ पाएगा। आने वाले महीने में जीएसटी दर बदलाव पर चर्चा शुरू हो सकती है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मुताबिक जीएसटी स्लैब में बदलाव को लेकर बनाए गए मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने अभी अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को नहीं सौंपी है। चौधरी इस जीओएम के अध्यक्ष हैं और उनके मुताबिक जल्द ही वे वित्त मंत्री को रिपोर्ट सौंपने वाले हैं।

जीएसटी दरों को कम करने की जरूरत: टीएस सिंहदेव

कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम तथा बिक्री कर मंत्री टीएस सिंह देव भी मानते हैं कि उपभोक्ताओं के लिए जीएसटी टैक्स की दरों को कम करने की जरूरत है। वह कहते हैं कि चूंकि राज्य अपने राजस्व में कमी से समझौता नहीं करेंगे, इसलिए जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने या स्लैब में बदलाव के दौरान राजस्व व उपभोक्ता के बीच का रास्ता निकालना होगा। जानकार भी कहते हैं कि राजस्व बढ़ने पर राज्यों को वित्तीय रूप से कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि राज्यों को एसजीएसटी के साथ केंद्र के जीएसटी से भी हिस्सेदारी मिलती है।

जीएसटी के लिए सबसे जरूरी चीज है कि सभी खाद्य पदार्थों के लिए एक प्रकार की जीएसटी दर होनी चाहिए व अन्य दरों को भी तार्किक बनाने की जरूरत है। चार स्लैब (5, 12, 18 और 28) की जगह तीन स्लैब होने चाहिए। **-विवेक जौहरी,** पूर्व चेयरमैन, सीबीआइसी

जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने से मुकदमेबाजी में भारी कमी आएगी। जीएसटी स्लैब कम होने से भारत विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। साथ ही, जीएसटी की रिटर्न प्रणाली और इनपुट टैक्स क्रेडिट नीति में भी बदलाव की जरूरत है।

-हरप्रीत सिंह, डेलाइट के पार्टनर (अप्रत्यक्ष कर)

यह सोचना गलत है कि जीएसटी दरों में कमी से राजस्व संग्रह में कमी आएगी। दर कम होने से वस्तुएं सस्ती होंगी जिससे खपत बढ़ेगी। खपत बढ़ने से मैन्यूफैक्चरिंग और रोजगार बढ़ेंगे। जाहिर है इससे राजस्व भी बढ़ेगा।

-एमएस मनी, अप्रत्यक्ष कर विशेषज्ञ

पहली छमाही में आठ लाख करोड़ रुपये का कर्ज लेगी सरकार

नई दिल्ली, प्रेट्र: राजस्व में कमी की भरपाई के लिए केंद्र सरकार अगले वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही के दौरान बाजार से आठ लाख करोड़ रुपये का कर्ज लेने की योजना बना रही है। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि यह राशि डेट सिक्योरिटीज के जरिये जुटाई जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते बजट में राजस्व की भरपाई के लिए बाजार से 14.82 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लेने की घोषणा की थी।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल-सितंबर 2025 के दौरान कर्ज जुटाने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के सावरेन ग्रीन बांड (एसजीबी) भी जारी किए जाएंगे। सरकार ने अगले वित्त वर्ष के दौरान राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। मूल्य के लिहाज से यह 15.68 लाख करोड़ रुपये के करीब होगा। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्व घाटा जीडीपी का 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

ट्रंप के आटो शुल्क से कंपनियों के शेयर टूटे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : ट्रंप ने बुधवार को अप्रैल, 2025 से आटोमोबाइल आयात पर 25 प्रतिशत टैक्स लगाने का एलान किया। विशेषज्ञों का मानना है कि इसका असर भारत से होने वाले आटोमोबाइल निर्यात पर बहुत नहीं होगा, लेकिन शेयर बाजार में आटो कंपनियों के शेयरों ने जिस तरह से गोता लगाया है, वह दूसरी ही आशंका बयां कर रहे हैं। गुरुवार को टाटा मोटर्स के शेयर में 5.5 प्रतिशत और अशोक लीलैंड के शेयर में 2.77 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जबकि आटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों बीएलडब्लू प्रिसिजन फोर्जिंग के शेयरों में 5.89 प्रतिशत, भारत फोर्ज में 4.28 प्रतिशत, सोना बीएलडब्लू में 6.92 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

राष्ट्रपति ट्रंप ने अप्रैल से अमेरिका में आयात होने वाले सभी आटो आयात पर 25 प्रतिशत का सीमा शुल्क लगाया जाएगा। जबकि मई, 2025 से आटो इंजन, ट्रांसमिशन पार्ट्स व पावरट्रेन पार्ट्स, इलेक्ट्रिक वाहनों के कलपुर्जों पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त सीमा शुल्क और लगाया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय कारोबार पर भारत के प्रमुख थिंक टैंक जीटीआरआइ की रिपोर्ट बताती है कि भारत अमेरिका को महज 89 लाख डालर की पैसेंजर कारों का निर्यात करता है, जो भारत के कुल पैसेंजर कार निर्यात का सिर्फ 0.14 प्रतिशत है। इस तरह से अमेरिका के ज्यादा टैक्स का भारत के पैसेंजर कार निर्यात पर बहुत असर नहीं पड़ेगा। वहीं भारत से अमेरिका को 1.25 करोड़ डालर मूल्य के ट्रक का निर्यात किया जाता है जो कुल ट्रक निर्यात का 0.89 प्रतिशत है। यहां थोड़ा असर पड़ने की आशंका है।

- अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस वर्ष अप्रैल से आटोमोबाइल आयात पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स लगाने की घोषणा की
- आर्थिक थिंक टैंक जीटीआरआर ने कहा- भारत का आटो उद्योग रहेगा अप्रभावित, नए अवसर बनने की उम्मीद

89 लाख डालर की कारों का अमेरिका को निर्यात करता है भारत

आटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों पर होगा ज्यादा असर

ट्रंप के फैसले का असल असर भारत में आटोमोबाइल के लिए पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों पर होगा। वर्ष 2024 में कुल 2.2 अरब डालर के कलपुर्जों का भारत ने निर्यात किया था। यह देश के कुल आटो पार्ट्स निर्यात का 29.1 प्रतिशत है। हालांकि यह मैक्सिको, चीन आदि के मुकाबले बहुत ही कम है। अमेरिका ने वर्ष 2024 में कुल 89 अरब डालर के आटो पार्टस का आयात किया था। इसमें मैक्सिको का हिस्सा 36 अरब डालर, चीन का 10 अरब डालर है। इन सभी देशों को ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में यह भारतीय आटोमोबाइल सेक्टर के लिए कुछ नए अवसर भी पैदा कर सकता है। आटो पार्ट्स सेक्टर की भारतीय कंपनियां ज्यादा प्रतिस्पर्द्धी होकर अमेरिका के आटो बाजार में ज्यादा हिस्सेदारी हासिल करने की रणनीति बना सकती हैं।

अप्रैल में 25 आधार अंक घट सकती है रेपो रेट

नई दिल्ली, प्रेट्र: इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (इंड-रा) ने गुरुवार को कहा कि अगले महीने होने वाली आरबीआइ की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती की जा सकती है।

इंड-रा के मुख्य अर्थशास्त्री और सार्वजनिक वित्त प्रमुख देवेंद्र कुमार पंत ने कहा, "हमें उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2024-25 में मुख्य मुद्रास्फीति घटकर 4.7 प्रतिशत रह जाएगी। अगले वित्त वर्ष यानी 2025-26 में रेपो रेट में 75 आधार अंकों की कमी की जा सकती है। हालांकि, अगर अमेरिकी द्वारा लगाए जाने वाले पारस्परिक शुल्क का प्रभाव उम्मीद से अधिक हुआ तो आरबीआइ द्वारा अधिक ढील दी जा सकती है।'

आरबीआइ की अगली एमपीसी बैठक 7-9 अप्रैल को होनी है। रेटिंग एजेंसी ने कहा, ''उच्च और जिद्दी मुद्रास्फीति को काबू में रखने के लिए आरबीआइ ने रेपो रेट में बढ़ोतरी की थी।

7,500 रुपये से ज्यादा किराये के होटल रेस्तरां में 18% जीएसटी

नई दिल्ली, प्रेट्र: एक अप्रैल से होटल के रेस्टोरेंट में खाना महंगा हो गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने गुरुवार को कहा कि किसी भी वित्त वर्ष में किसी भी समय एक कमरे के लिए 7,500 रुपये प्रतिदिन से अधिक किराया लेने वाले होटलों को अगले वित्त वर्ष के लिए 'निर्दिष्ट परिसर' माना जाएगा और ऐसे परिसरों के अंदर प्रदान की जाने वाली रेस्टोरेंट सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

सीबीआइसी की ओर से जारी एफएक्यू (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल) में कहा गया है कि एक अप्रैल 2025 से होटलों के अंदर संचालित होने वाले ऐसे रेस्टोरेंट पर कर की गणना लेन-देन मूल्य के आधार पर होगी। इस मतलब यह है कि पिछले वित्त वर्ष में होटल कमरे के लिए किया गया लेनदेन मूल्य यह निर्धारित करने का आधार होगा कि होटल आवास सेवा प्रदान करने वाला परिसर चालू वित्त वर्ष में अनिवार्य रूप से 'निर्दिष्ट परिसर' की श्रेणी में आता है या नहीं। एफएक्यू के अनुसार, जिन होटलों में कमरे का किराया 7,500 रुपये से कम हैं, वहां बिना जीएसटी पांच प्रतिशत जीएसटी ही लगेगा।

इसके अलावा जो होटल अगले वित्त वर्ष से एक कमरे का एक दिन का किराया 7,500 रुपये से अधिक करना चाहते हैं, उन्हें 31 मार्च 2025 तक जीएसटी प्राधिकरण को इसकी जानकारी देनी होगी। साथ ही नया पंजीकरण चाहने वाले होटलों को 15 दिन के भीतर जानकारी देकर अपने परिसर को निर्दिष्ट घोषित करना होगा।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने जारी किया एफएक्यू, एक अप्रैल 2025 से लागू होंगे नए नियम

ओला-उबर को टक्कर देगी सहकार टैक्सी

नई दिल्ली, आइएएनएस: केंद्र सरकार ने ओला उबर जैसी कंपनियों को टक्कर देने के लिए 'सहकार टैक्सी' सेवा शुरू करने का एलान किया है। यह सेवा बाइक, कैब और आटो जैसी सुविधाएं देगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संसद में इसकी घोषणा की। इसका मकसद ड्राइवरों को ज्यादा फायदा पहुंचाना है। इससे वे कंपनी को लाभ दिए बिना सीधे कमाई कर सकेंगे। सरकार आनलाइन टैक्सी बाजार में ओला, उबर जैसी कंपनियों के दबदबे को कम करने की कोशिश कर रही है। सहकार टैक्सी नाम की इस नई कोआपरेटिव टैक्सी सर्विस में बाइक, कैब और आटो जैसी सुविधाएं मिलेंगी और लोगों के पास परिवहन का एक और विकल्प होगा।

केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संसद में इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सहकार टैक्सी देशभर में दोपहिया टैक्सियों, आटो-रिक्शा और चार पहिया टैक्सियों का पंजीकरण करेगी। शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' नारे का भी जिक्र करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक नारा नहीं है, इसे सच करने के लिए सहकारिता मंत्रालय पिछले साढ़े तीन साल से लगातार काम कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि सहकार टैक्सी सेवा आने वाले कुछ महीनों में शुरू हो जाएगी। अभी इसकी तैयारी चल रही है। जल्द ही लोग इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। मौजूदा समय में ओला और उबर जैसी कंपनियां ड्राइवरों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा ले लेती हैं। सहकार टैक्सी के आने से ड्राइवरों को ज्यादा पैसे मिलेंगे। सरकार समर्थित यह सेवा निजी कंपनियों से अलग होगी। इसमें किसी कंपनी को कमीशन नहीं देना होगा, जिससे ड्राइवर्स की आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

बंगाल में पहले से ही 'यात्री साथी' नाम से एक ऐसी ही सर्विस चल रही है। अब इसका विस्तार सिलीगुड़ी, आसनसोल और दुर्गापुर जैसे शहरों में हो गया है। 'यात्री साथी' नामक यह सेवा त्वरित बुकिंग, स्थानीय भाषा का समर्थन, किफायती किराया और चौबीस घंटे ग्राहक सहायता प्रदान करती है, जिससे यह यात्रियों के बीच एक लोकप्रिय विकल्प बन गया है। 2022 में केरल सरकारी स्वामित्व वाली आनलाइन टैक्सी सेवा 'केरल सवारी' शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया था। हालांकि, बाद में कम उपयोग के कारण इसे बंद कर दिया गया। अब इसे पुनः शुरू करने की योजना है।

अमित शाह ●

- सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संसद में आनलाइन टैक्सी सेवा शुरू करने का किया एलान
- लोगों को मिलेगा परिवहन का विकल्प, कमीशन दिए बगैर सीधे कमाई कर सकेंगे ड्राइवर

सात प्रमुख शहरों में 28 प्रतिशत तक घट सकती है घरों की बिक्री

नई दिल्ली, प्रेट्र: देश के सात प्रमुख शहरों में ऊंची कीमतों और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच जनवरी-मार्च अवधि में मकानों की बिक्री सालाना आधार पर 28 प्रतिशत घटकर 93,280 इकाई रहने का अनुमान है। यह एक साल पहले की समान अवधि में 1,30,170 घर बिके थे।

रियल एस्टेट सलाहकार एनाराक के अनुसार, सात प्रमुख शहरों में से एनसीआर में बिक्री 20 प्रतिशत घटकर 15,650 इकाई से 12,520 इकाई रहने की उम्मीद है। वहीं मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में आवासीय संपत्तियों की बिक्री 26 प्रतिशत घटकर 31,610 इकाई, बेंगलुरु में 16 प्रतिशत घटकर 15,000 इकाई, पुणे में 30 प्रतिशत घटकर 16,100 इकाई, हैदराबाद में 49 प्रतिशत घटकर 10,100 इकाई और चेन्नई में 26 प्रतिशत घटकर 4,050 इकाई और कोलकाता में बिक्री 31 प्रतिशत घटकर 3,900 इकाई रहने का अनुमान है।

देश की एक-तिहाई जीडीपी 284 अरबपतियों के पास

मुंबई, प्रेट्र: देश के 284 अरबपतियों की कुल संपत्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की एक तिहाई है। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार, 'पिछले एक साल के दौरान अदाणी समूह के मुखिया गौतम अदाणी की संपत्ति में सबसे ज्यादा एक लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई। उनकी कुल संपत्ति अब 8.4 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई है।'

सूची में 15 जनवरी तक के आंकड़ों को शामिल किया गया है और इसके मुताबिक, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की संपत्ति में 13 प्रतिशत की गिरावट आई है और यह 8.6 लाख करोड़ रुपये रह गई है। उनकी 100 अरब डालर की संपत्ति ने उन्हें सबसे अमीर एशियाई होने का खिताब हासिल करने में मदद की है। पिछले साल अदाणी की संपत्ति में 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में 284 अरबपति हैं, जिनकी कुल संपत्ति 10 प्रतिशत बढ़कर 98 लाख करोड़ रुपये या देश के सकल घरेलू उत्पाद का एक तिहाई हो गई है। कुछ ही हाथों में संपत्ति के केंद्रीकरण की चिंताओं के बीच सूची में बताया गया है कि प्रत्येक अरबपति के संपत्ति की बात करें तो भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। यहां हर अरबपति की औसत संपत्ति 34,514 करोड़ रुपये है, जबकि चीन में यह 29,027 करोड़ रुपये है। पिछले साल 175 भारतीय अरबपतियों की संपत्ति में बढ़ोतरी हुई है, जबकि 109 की नेटवर्थ में गिरावट आई है।

- गौतम अदाणी की संपत्ति पिछले एक साल में सबसे ज्यादा एक लाख करोड़ रुपये बढ़ी
- 175 भारतीय अरबपतियों की संपत्ति में बढ़ोतरी हुई है, 109 की नेटवर्थ में गिरावट आई

गौतम अदाणी ●

मुकेश अंबानी ●

हेल्थकेयर में सबसे ज्यादा 53 अरबपति

भारत में सबसे ज्यादा 53 अरबपति हेल्थकेयर इंडस्ट्री में हैं। कंज्यूमर गुड्स में 35 और औद्योगिक उत्पादों के क्षेत्र में 32 अरबपति हैं। सूची में कहा गया है कि भारतीय अरबपतियों की औसत आयु 68 वर्ष है, जो वैश्विक अरबपतियों की औसत आयु से दो वर्ष अधिक है। 34 वर्षीय शशांक कुमार और रेजरपे के हर्षिल माथुर सबसे युवा भारतीय अरबपति हैं और कुल संपत्ति 8,643 करोड़ रुपये है।

रोशनी नादर ●

एचसीएल की रोशनी नादर देश की सबसे अमीर महिला

रोशनी नादर 3.5 लाख करोड़ रुपये की नेटवर्थ के साथ सबसे अमीर भारतीय महिला और दुनिया की पांचवीं सबसे अमीर महिला बन गई हैं। उनके पिता शिव नादर ने अपनी कंपनी एचसीएल टेक्नोलाजीज में 47 प्रतिशत हिस्सेदारी अपने बेटी को दी है। देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में 11 नए अरबपति सूची में जुड़े हैं और इस तरह इनकी संख्या 90 हो गई है।

राष्ट्रीय फलक

10 लाख करोड़ खर्च में 25 हजार किमी हाईवे फोरलेन में बदलेंगे : गडकरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में 25,000 किलोमीटर के दो-लेन वाले हाईवे को फोर लेन में परिवर्तित किया जाएगा। इस परियोजना की लागत 10 लाख करोड़ रुपये होगी। इससे सड़क हादसों में कमी आने की उम्मीद है।गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त, 16,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों को छह लेन में बदलने की योजना है और इस पर छह लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा। उन्होंने कहा कि हम इस कार्य को दो वर्षों में पूरा करने की योजना बना रहे हैं।

गडकरी ने बताया कि भारत में हर साल 4,80,000 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इनमें 18 से 45 वर्ष की आयु के 1,88,000 लोग जान गंवाते हैं। सरकार का लक्ष्य 2030 तक सड़क हादसों को 50 प्रतिशत तक कम करना है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी क्षेत्रों में हाईवे विकास को प्राथमिकता दी है।

निर्माणाधीन जोजिला सुरंग एशिया की सबसे लंबी सुरंग होगी : जम्मू-कश्मीर में दो लाख करोड़ रुपये की लागत से सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें 105 सुरंगें बनाई जा रही हैं। उन्होंने जोजिला सुरंग के निर्माण की जानकारी दी जोकि एशिया की सबसे लंबी होगी और शून्य से नीचे के तापमान वाले क्षेत्र में स्थित होगी। उन्होंने कहा कि इसकी लागत का प्रारंभिक अनुमान 12,000 करोड़ था, लेकिन यह लगभग 5,500 करोड़ में पूरा होगा। गडकरी ने बताया कि जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर 36 सुरंगों का बनाई जा रही हैं और इनमें से 22 सुरंगें पूरी हो चुकी हैं। इससे यात्रा का समय वर्तमान सात घंटे से घटकर तीन से साढ़े तीन घंटे रह जाएगा। दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे का कार्य भी प्रगति पर है।

गडकरी बोले, 16,000 किमी हाईवे सिक्स-लेन में बदलेंगे

एम्स ऋषिकेश में सीबीआइ टीम ने खंगाले दस्तावेज

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश: एम्स ऋषिकेश में वर्ष 2017-18 में हुई उपकरणों की खरीद और मेडिकल स्टोर आवंटन में गड़बड़ी मामले की जांच के लिए बुधवार को सीबीआइ की टीम ने एम्स पहुंचकर वहां दस्तावेजों की जांच की। सूत्रों के अनुसार सीबीआइ दस्तावेजों को अपने साथ ले गई। एम्स के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी संदीप कुमार ने सीबीआइ टीम के आने की पुष्टि की। बताया कि पुराने मामले में जांच के लिए टीम आई थी।

बता दें कि एम्स प्रशासन ने वर्ष 2017-18 में अस्पताल परिसर की सड़कों की सफाई के लिए स्वीपिंग मशीन खरीदी थी। जिस कमेटी के माध्यम से खरीद प्रक्रिया पूरी कराई गई, उसमें अनियमितता पाई गई। इसमें करीब 4.41 करोड़ रुपये की गड़बड़ी की गई। इतनी बड़ी लागत से खरीदी गई यह मशीन सिर्फ 124 घंटे ही चल पाई।

****

अमेरिका ने भारत में रद किए दो हजार वीजा अपाइंटमेंट

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत में अमेरिकी दूतावास ने करीब दो हजार वीजा अपाइंटमेंट को रद कर दिया है। वीजा आवेदन में कुछ गड़बड़ियों की शिकायत सामने आई थी। इसी के बाद यह फैसला लिया गया है। दूतावास ने यह भी कहा कि उसकी शेड्यूलिंग नीतियों का उल्लंघन करने वाले एजेंटों और फिक्सरों की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूतावास ने बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए नोटिस में यह जानकारी दी।

दूतावास ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर लिखा, भारतीय वाणिज्य दूतावास की टीम बाट्स द्वारा दिए गए लगभग 2000 वीजा अपाइंटमेंट रद कर रही है। हम उन एजेंटों और फिक्सरों को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे जो हमारी शेड्यूलिंग नीतियों का उल्लंघन करते हैं। टीम ने उन लोगों की पहचान की है जिन्होंने हमारी शेड्यूलिंग नीतियों का उल्लंघन किया। हम तत्काल प्रभाव से इन अपाइंटमेंट को रद कर रहे हैं तथा संबद्ध अकाउंट के शेड्यूलिंग विशेषाधिकारों को निलंबित कर रहे हैं। अमेरिकी वाणिज्य दूतावास टीम ने 2023 में एक लाख 40 हजार से अधिक छात्र वीजा जारी किए हैं - जो किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक है।

- भारत में अमेरिकी दूतावास ने कहा- धोखाधड़ी कतई बर्दाश्त नहीं
- वीजा आवेदन में कुछ गड़बड़ियों की शिकायत के बाद की कार्रवाई

टोरेस घोटाले में ईओडब्ल्यू ने दाखिल किया 27 हजार से ज्यादा चार्जशीट

मिड-डे, मुंबई : महाराष्ट्र के बहुचर्चित टोरेस घोटाले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 27 हजार पन्नों से ज्यादा चार्जशीट दाखिल किए हैं। इसमें सात आरोपित व्यक्तियों और एक फर्म का नाम शामिल है। जांच से पता चला है कि यह सुनियोजित पोंजी स्कीम थी, जिसमें निवेशकों को मैसनेट स्टोन और मैसनेट आधारित चांदी और सोने के आभूषणों की खरीद के जरिए उच्च रिटर्न का वादा करके लुभाया गया था।

ईओडब्ल्यू के अनुसार, राजस्थान से घटिया किस्म के पत्थर 350-500 रुपये में खरीदकर 8,000 रुपये में बेचा गया। वर्ष 2023-25 तक राजस्थान स्थित आपूर्तिकर्ता से 20 करोड़ रुपये मूल्य के पत्थर खरीदे गए थे।

ट्रंप ने आयातित आटो पर लगाया 25 % टैरिफ, कनाडा ने बताया सीधा हमला

व्हाइट हाउस का दावा, यह कदम घरेलू निर्माण को देगा बढ़ावा, कर राजस्व में 100 अरब डालर वृद्धि की उम्मीद

कनाडा के पीएम कार्नी ने कहा, अमेरिकी उपभोक्ताओं का विश्वास पिछले कुछ वर्षों में निचले स्तर पर

वाशिंगटन, एपी: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को आटो उत्पादों के आयात पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की, जो तीन अप्रैल से प्रभावी होगा। साथ ही कहा है कि अगर यूरोपीय यूनियन और कनाडा ने एक साथ मिलकर जवाबी कार्रवाई की तो वह उन पर अधिक टैरिफ लगा सकते हैं। उधर, कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने कहा, ''यह बिल्कुल सीधा हमला है। हम अपने श्रमिकों, अपनी कंपनियों और अपने देश की रक्षा करेंगे।'' साथ ही कहा, ट्रेड वार अमेरिकियों को भी नुकसान पहुंचा रहा है और अमेरिकी उपभोक्ताओं का विश्वास गत कई वर्षों में सबसे कम है। ट्रंप की घोषणा से एशिया, यूरोप और अमेरिका में कई वाहन निर्माताओं के शेयरों की कीमतें गिर गईं, पर विश्लेषकों का कहना है कि एलन मस्क की कंपनी टेस्ला की आपूर्ति व वित्तीय प्रदर्शन प्रभावित नहीं होगा।
ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, ''हम 25 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे और इससे विकास को बढ़ावा मिलेगा।'' जबकि व्हाइट हाउस ने दावा किया कि यह कदम घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देगा। साथ ही उम्मीद जताई कि इस टैरिफ से वार्षिक 100 अरब डालर का राजस्व अर्जित होगा। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि नया टैरिफ तैयार वाहनों और वाहनों में इस्तेमाल पुर्जों दोनों पर लागू होंगे। वे मौजूदा करों के अतिरिक्त होंगे। गौरतलब है कि अमेरिका ने 2024 में 474 अरब डालर के आटोमोटिव उत्पाद आयात किए, जिनमें 220 अरब डालर की यात्री कारें शामिल हैं। अमेरिका के करीबी सहयोगी देश मेक्सिको, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा और जर्मनी इसके सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता थे।
विदेशी नेताओं ने अमेरिकी टैरिफ की आलोचना करने में देर नहीं लगाई। कनाडा ने सख्त प्रतिक्रिया दी, तो यूरोपीय यूनियन ने कहा कि वह टैरिफ वार को टालने की कोशिश करते हुए एक मजबूत जवाब देने की तैयारी कर रहा है। ब्रसेल्स में यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयेन ने यूरोप से आटो निर्यात को निशाना बनाने के अमेरिकी निर्णय पर खेद व्यक्त किया और संकल्प लिया कि यूरोपीय यूनियन अपने उपभोक्ताओं और व्यवसायों की रक्षा करेगा। उन्होंने कहा, 'टैरिफ टैक्स हैं- ये व्यवसायों के लिए बुरे, अमेरिका व यूरोपीय यूनियन में उपभोक्ताओं के लिए समान रूप से बदतर हैं।'' अमेरिका से छूट हासिल करने की कोशिश कर रहे ब्रिटेन ने एलन मस्क की टेस्ला को दी जाने वाली सब्सिडी की समीक्षा करने की धमकी दी है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका का दृष्टिकोण विश्व व्यापार संगठन के नियमों के विरुद्ध है और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को कमजोर करता है।

व्हाइट हाउस के ओवल आफिस में मीडिया से वार्ता करते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। एपी

घोषणा के बाद शेयर गिरे
ट्रंप की घोषणा के बाद जनरल मोटर्स के शेयरों में करीब तीन % की गिरावट आई। हालांकि फोर्ड के शेयरों में मामूली बढ़त दर्ज की गई। जीप व क्रिसलर के मालिक स्टेलेंटिस के शेयरों में लगभग 3.6 % की गिरावट आई।

विश्व नेताओं ने जताई कड़ी प्रतिक्रिया
विदेशी नेताओं ने अमेरिकी टैरिफ की आलोचना करने में देर नहीं लगाई। यह संकेत है कि ट्रंप ट्रेड वार तेज कर सकते हैं। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने कहा, इस क्षेत्र में 1.25 लाख कनाडाई लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है। लगभग पांच लाख संबंधित उद्योगों में कार्यरत हैं। दरअसल, आटो मोबाइल कनाडा का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात वाला क्षेत्र है। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि वह टैरिफ वार टालने की कोशिश करते हुए मजबूत जवाब की तैयारी कर रहा है। ब्रसेल्स में, यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयेन ने कहा, ''टैरिफ टैक्स हैं- ये व्यवसायों के लिए बुरे, अमेरिका व यूरोपीय यूनियन (ईयू) में उपभोक्ताओं के लिए समान रूप से बदतर हैं। ईयू अपने उपभोक्ताओं व व्यवसायों की रक्षा करेगा।'' जर्मनी के वित्त मंत्री राबर्ट हेबेक ने कहा, ''ईयू इन टैरिफ पर सख्त प्रतिक्रिया दे। हम इसे चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेंगे।'' फ्रांस के वित्त मंत्री एरिक लोंबार्ड ने ट्रंप की घोषणा को ''बहुत बुरी खबर'' बताया। कहा, इसका एकमात्र समाधान यह है कि ईयू अपने टैरिफ बढ़ाए। ब्रिटेन ने एलन मस्क की टेस्ला को दी जाने वाली सब्सिडी की समीक्षा की धमकी दी है। चीन ने कहा, अमेरिका का दृष्टिकोण विश्व व्यापार संगठन के नियमों के विरुद्ध है।

इजरायल में न्यायाधीशों की नियुक्ति का विवादित विधेयक पारित

यरुशलम, एपी: इजरायल की संसद ने गुरुवार को वह विवादित विधेयक पारित कर दिया जिसमें सरकार को न्यायाधीशों की नियुक्ति में बड़ा अधिकार मिल जाएगा। न्यायपालिका पर सरकार के कब्जे की कोशिश के विरोध में 2023 में इजरायल में बड़े प्रदर्शन हुए थे। इसे अति दक्षिणपंथी सरकार की न्यायपालिका पर कब्जे की कोशिश माना गया था, पर सात अक्टूबर को हमास के हमले के बाद स्थितियां बदल गईं और पूरा देश युद्ध और गाजा में बंधकों को छुड़वाने की कोशिश में जुट गया।
बंधकों की रिहाई को लेकर नेतन्याहू सरकार के प्रयासों से इजरायली जनता संतुष्ट नहीं हैं। सरकार के प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित विधेयक पारित होने से जन विरोध तेज होने की आशंका है। ताजा विधेयक के पारित होने से न्यायाधीशों की नियुक्ति का निर्णय करने वाली नौ सदस्यीय चयन समिति में सरकार के प्रतिनिधियों को दो अतिरिक्त स्थान मिल जाएंगे, जिससे समिति में बार एसोसिएशन की भागीदारी कम होगी। इससे अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका बढ़ जाएगी, साथ ही नापसंद व्यक्त की नियुक्ति को सरकार रोक सकेगी। न्यायपालिका की नियुक्तियों में सरकारी दखल बढ़ाने का बड़ा कारण पीएम नेतन्याहू पर चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों को कमजोर करना माना जा रहा है। नेतन्याहू पर सत्ता में रहने के दौरान उपहार व अन्य लाभ लेने का आरोप है।

इजरायली सेना के हमले में हमास के प्रवक्ता की मौत

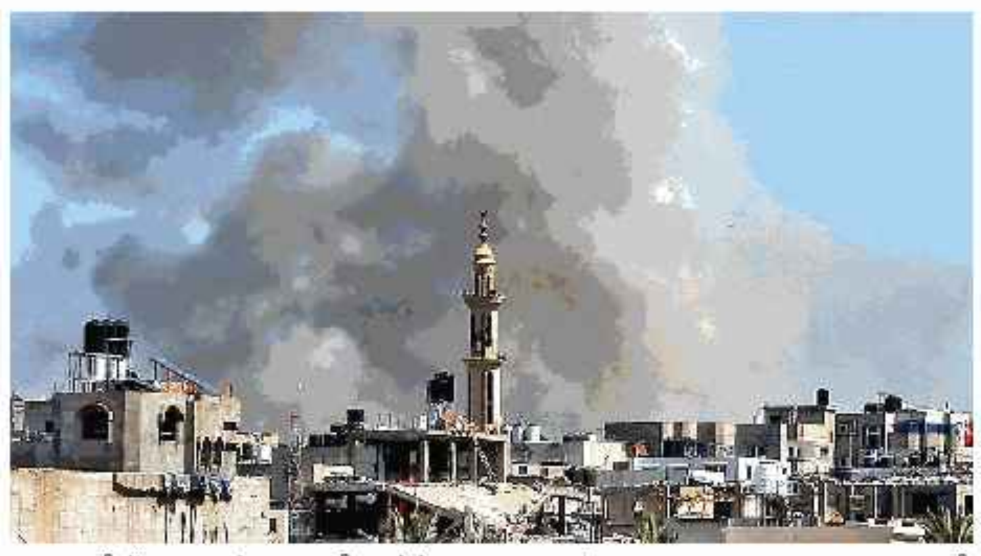
गाजा पट्टी में गुरुवार को इजरायली हमले के बाद उठता धुआं। एएफपी

- हफ्ते भर में मारा गया फलस्तीनी संगठन का तीसरा नेता
- नेतन्याहू ने कहा, बंधक न छूटे तो गाजा में बंद होगी आपूर्ति

यरुशलम, रायटर : गाजा में गुरुवार को इजरायल के हवाई हमले में हमास का प्रवक्ता आब्देल लतीफ अल-कनुआ मारा गया। अल-कनुआ को जबालिया स्थित उसके टेंट में मारा गया। इसके अतिरिक्त एक परिवार के छह अन्य लोग भी मारे गए हैं। हमलों में कई लोग घायल भी हुए हैं। यह जानकारी हमास के मीडिया विंग ने दी है।
इजरायल ने इसी हफ्ते अलग-अलग हमलों में हमास की राजनीतिक शाखा के नेता इस्माइल बरहूम और सलाह अल-बार्दवील को भी मारा था। इजरायल ने दो माह के युद्धविराम को खत्म करते हुए 18 मार्च को गाजा में फिर से हमले शुरू कर दिए हैं, जिनमें अभी तक 830 लोग मारे जा चुके हैं, इनमें से आधी संख्या महिलाओं-बच्चों की है। इजरायल और हमास ने एक-दूसरे पर युद्धविराम की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। हमास के पास बंधक 59 नागरिकों की रिहाई की मांग पूरी न होने पर युद्धविराम टूटा। ये लोग सात अक्टूबर, 2023 से गाजा में बंधक हैं। इनमें से 25 के ही जीवित होने की उम्मीद है।
इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि बंधकों को न छोड़ने पर सेना जल्द ही गाजा को पूरी तरह से घेर लेगी और उसके बाद वहां पर किसी भी वस्तु की आपूर्ति नहीं हो पाएगी।

हमास की हिमायत पर अमेरिका में एक और विदेशी छात्रा पर कार्रवाई

बोस्टन, रायटर: अमेरिकी आव्रजन अधिकारियों ने बोस्टन में टफ्ट्स विश्वविद्यालय की तुर्किये की डाक्टरेट छात्रा रुमेसा ओजतुर्क को हिरासत में लिया। साथ ही उसका वीजा रद कर दिया। उसने गाजा में इजरायली कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाई थी और फलस्तीनियों का समर्थन किया था।
हालांकि, ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि कुछ विरोध यहूदी विरोधी थे और यह अमेरिकी विदेश नीति को कमजोर कर सकते हैं। गिरफ्तारी के वीडियो में नकाबपोश और सादे कपड़ों में एजेंटों को 30 वर्षीय छात्रा रुमेसा ओजतुर्क को मैसाचुसेट्स के सोमरविले में मंगलवार को उसके घर के पास हिरासत में लेते दिखाया गया है।
अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग की प्रवक्ता ट्रिसिया मैकलाघलिन ने कहा कि ओजतुर्क हमास समर्थक गतिविधियों में शामिल थी, जो एक आतंकी संगठन है। कहा, वीजा एक विशेषाधिकार है न कि अधिकार।

क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बांग्लादेश में मजबूत सेना जरूरी : अमेरिका

- हसीना सरकार के पतन के बाद शीर्ष अमेरिकी जनरल का पहला दौरा
- अमेरिका ने बांग्लादेश को सैन्य साजो-सामान देने की जताई है इच्छा

« अमेरिकी सेना के डिप्टी कमांडिंग जनरल जेबी वावेल को ढाका दौरे में स्मृति चिन्ह सौंपते बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वाकर-उज-जमान। प्रेट्र

ढाका, प्रेट्र: बांग्लादेश में गत अगस्त में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद पहली बार किसी शीर्ष अमेरिकी जनरल ने ढाका का दौरा किया है। उन्होंने बांग्लादेशी सेना को अमेरिकी सैन्य साजो-सामान से लैस करने की इच्छा जताई और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए इस देश में मजबूत सेना की जरूरत के महत्व पर जोर दिया। अमेरिकी जनरल का यह दौरा ऐसे समय हुआ है, जब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस चीन दौरे पर हैं। वह शुक्रवार को चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रशांत क्षेत्र के लिए अमेरिकी सेना के डिप्टी कमांडिंग जनरल जेबी वावेल ने 24 घंटे के लिए बांग्लादेश का दौरा किया। अमेरिकी दूतावास ने गुरुवार शाम एक बयान में बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल वावेल ने बांग्लादेश सशस्त्र बल के अपने समकक्ष से मुलाकात की और बांग्लादेशी सेना के साथ अमेरिकी सेना के मजबूत संबंधों को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। वावेल ने बांग्लादेशी सेना की सराहना की है। जबकि सरकारी न्यूज एजेंसी बांग्लादेश संवाद संस्था के अनुसार, अमेरिकी जनरल ने घरेलू सुरक्षा के लिए बांग्लादेशी सेना का समर्थन किया है।

चरमपंथ के बढ़ते उभार पर पूर्व ब्रिटिश सांसद ने जताई चिंता
जेनेवा, एएनआइ : ब्रिटेन के पूर्व सांसद पाल बर्स्टो ने बांग्लादेश में मानवाधिकारों के उल्लंघन व इस्लामी चरमपंथ के उभार पर चिंता जताई है। उन्होंने बुधवार को यहां संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के 58वें सत्र से इतर एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार, राजनीतिक दमन और सुरक्षा बांग्लादेश के लिए गंभीर चुनौतियां हैं, जो इस देश की स्थिरता के लिए खतरा हैं। 'मैं यहां बांग्लादेश के अतीत, वर्तमान या भविष्य की किसी सरकार के बारे में निर्णय देने नहीं आया हूं। बांग्लादेश के दो चहरे हैं, एक अच्छा है। दूसरा पक्ष भ्रष्टाचार है, जो तर्क या दलीलों की जगह कानून को सियासी हथियार के रूप में प्रयोग कर रहा है।' इसी कार्यक्रम में मानवाधिकार कार्यकर्ता फजल उल रहमान अफरीदी ने कहा, इस्लामी चरमपंथ के उभार के कारण बहुलवाद खत्म हो रहा है।

मोदी ने यूनुस को दी बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

- 26 मार्च 1971 को पाक से अलग होकर स्वतंत्र हुआ था बांग्लादेश

नई दिल्ली, प्रेट्र : बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस पर पीएम नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को पड़ोसी देश के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस व सभी नागरिकों को शुभकामनाएं दीं। मोदी ने कहा, यह दिन दोनों देशों के साझा इतिहास और बलिदान का साक्षी है, जिसने द्विपक्षीय साझेदारी की नींव रखी। बांग्लादेश 26 मार्च को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 1971 को इसी दिन इसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी क्योंकि तब तक यह पाकिस्तान का हिस्सा था। यूनुस ने अपने एक्स हैंडल से पीएम का यह संदेश साझा भी किया।
मोदी ने पत्र में लिखा, ''बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम की भावना हमारे संबंधों के लिए मार्गदर्शक है, जो कई क्षेत्रों में फली-फूली है और हमारे नागरिकों को वास्तविक लाभ पहुंचा रही है।'' भारत बांग्लादेश संग साझेदारी आगे बढ़ाने को प्रतिबद्ध है, जो शांति, स्थिरता व समृद्धि की साझा आकांक्षाओं व चिंताओं के प्रति पारस्परिक संवेदनशीलता पर आधारित हो। ज्ञात हो, अगस्त 2024 में तत्कालीन पीएम शेख हसीना के निष्कासन के बाद यूनुस के नेतृत्व में नई अंतरिम सरकार आ गई थी। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की कई घटनाएं हुईं। कट्टरपंथी ताकतों के बारे में भारत की चिंता जताने पर दोनों देशों के संबंधों में खटास आ गई।

पीएम मोदी ने याद दिलाया दोनों देशों का साझा इतिहास और बलिदान

अमेरिकी संसद में अपने सेना प्रमुख पर प्रतिबंध के प्रस्ताव से भड़का पाक

इस्लामाबाद, आइएएनएस: अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसमें कथित मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत देश के कई वरिष्ठ अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। इससे भड़के पाकिस्तान ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया और इसे कुछ लोगों की निजी राय करार दिया है।
अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में 'पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट' नामक विधेयक रिपब्लिकन सांसद जो विल्सन और डेमोक्रेटिक सांसद जिमी पेनेटा ने पेश किया। विधेयक को समीक्षा के लिए सदन की विदेश मामलों व न्यायिक समिति के पास भेज दिया गया। इसमें पूर्व पीएम इमरान खान के कथित मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान सरकार व सेना प्रमुख पर प्रतिबंध की मांग की गई है। अगर पाकिस्तान मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार लाने में विफल रहता है तो बिल में 180 दिनों के अंदर पाबंदी लगाने की बात है।

बलूचिस्तान में बंदूकधारियों ने बस से उतारकर छह लोगों की हत्या की

- बंदूकधारियों ने पहचान पत्र जांचने के बाद यात्रियों को मारी गोली
- यह घटना ग्वादर में बुधवार देर रात ओरमारा राजमार्ग पर हुआ

कराची, प्रेट्र : पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में संदिग्ध विद्रोहियों ने एक यात्री बस से उतारकर पंजाब के छह लोगों को गोली मार दी। पांच यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हफीज बलूच ने कहा, यह ग्वादर जिले में हुआ, जब हथियारबंद लोगों ने बुधवार देर रात ओरमारा राजमार्ग पर कलमात क्षेत्र के पास ग्वादर से कराची जा रही यात्री बस को रोका। बंदूकधारियों ने यात्रियों का पहचान पत्र जांचने के बाद उन्हें गोली मारी और तीन अन्य को अपने साथ ले गए। किसी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, पर अतीत में बलूच विद्रोहियों ने पंजाब के लोगों के खिलाफ ऐसे हमले किए थे।
कड़ी सुरक्षा के बीच जाफर एक्सप्रेस का परिचालन फिर से शुरू : जाफर एक्सप्रेस का परिचालन फिर से शुरू हो गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के लड़ाकों ने 11 मार्च को बोलन में इसे हाईजैक कर लिया था, जिसके बाद सेवा रोक दी गई थी। कड़ी सुरक्षा के बीच गुरुवार को पेशावर कैंट स्टेशन से ट्रेन को क्वेटा के लिए रवाना किया गया। ट्रेन में 280 यात्री सवार थे। जाफर एक्सप्रेस एकमात्र ऐसी ट्रेन है, जो चारों प्रांतों से गुजरती है। क्वेटा से देश के बाकी हिस्सों के लिए सेवाएं शुक्रवार से शुरू होंगी।

क्वेटा में पुलिस वाहन के पास विस्फोट, तीन की मौत
क्वेटा के बारेच मार्केट क्षेत्र में एक पुलिस वाहन के पास बम विस्फोट में तीन की मौत हो गई और 21 अन्य घायल हो गए। बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद ने कहा, एक बाइक में आइईडी रखा गया था। घायलों में चार पुलिसकर्मी शामिल हैं।

« पाकिस्तान के क्वेटा शहर में गुरुवार को विस्फोट के बाद मौके पर जुटे सुरक्षाकर्मी। एएफपी

तुर्किये में विरोध कर रहे छात्रों पर पुलिस ने किया बल प्रयोग

इस्तांबुल, एपी : तुर्किये की राजधानी अंकारा में छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। छात्रों पर पेपर स्प्रे, प्लास्टिक के छर्रे व पानी की बौछार का इस्तेमाल किया गया। इस कारण फिर से तनाव पैदा हो गया है। प्रदर्शन पिछले हफ्ते इस्तांबुल के मेयर एक्रेम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ, जो राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में ट्रायल चलने तक उन्हें जेल भेज दिया गया है।
गुरुवार सुबह छात्रों ने मार्च की कोशिश की और तकनीकी विश्वविद्यालय के गेट के पास जमा हुए। उन्हें हटाने के लिए सुरक्षा बलों ने बल प्रयोग किया। गतिरोध तब शुरू हुआ जब छात्र बैरिकेड के पीछे चले गए, जब तक कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में नहीं ले लिया। रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी के विधायक मेलिह मेरिक ने कहा कि मेरे छात्र मित्र केवल एक प्रेस बयान देना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी।

कनाडा में आगामी चुनाव लड़ने से रोके गए भारतवंशी चंद्र आर्य

- खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाना माना जा रहा कारण

ओटावा, आइएएनएस: कनाडा में लिबरल पार्टी के सांसद चंद्र आर्य को देश में होने वाले आगामी चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। यह माना जा रहा है कि उन्होंने देश में खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है, जिसके कारण पार्टी ने ओटावा नेपियन निर्वाचन क्षेत्र से उनकी दावेदारी को रद कर दिया है। भारतीय मूल के आर्य तीन बार से इस सीट से लिबरल सांसद हैं। वह देश में खालिस्तान समर्थकों को शरण देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के मुखर आलोचक रहे हैं।
चंद्र आर्य ने चुनाव लड़ने से रोके जाने पर कहा, 'लिबरल पार्टी के साथ विवाद का एकमात्र मुद्दा हिंदू कनाडाई लोगों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों की मुखर वकालत करना और खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ मेरा दृढ़ रुख है।' कनाडा के प्रमुख अखबार ग्लोब एंड मेल के अनुसार, लिबरल पार्टी ने आगामी चुनाव के लिए आर्य की दावेदारी को रद कर दिया है। हालांकि पार्टी ने अपने इस निर्णय के लिए कोई कारण नहीं बताया है। भारत-कनाडा के खराब संबंधों के बीच आर्य ने पिछले अगस्त में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की थी। उन्होंने इस दौरे के बारे में कनाडाई सरकार को सूचना नहीं दी थी।

चंद्र आर्य। फाइल

व्हाइट हाउस में बच्चे ने की घुसपैठ

वाशिंगटन, एपी: अमेरिका के राष्ट्रपति निवास व्हाइट हाउस की सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर बुधवार को एक बच्चा चुपके से अंदर घुस गया हालांकि उसे सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों ने पकड़ लिया।
सीक्रेट सर्विस के प्रवक्ता एंथनी गुग्लिल्मी ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट में कहा, यह घटना स्थानीय समयानुसार शाम करीब 6:30 बजे नार्थ लान के पास हुई। अधिकारियों ने तुरंत बच्चे को उसके माता-पिता से मिला दिया। इस दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो में दिख रहा है कि एक सशस्त्र अधिकारी बच्चे को लान में ले जाते हुए दिखाई देता है, तथा फिर बच्चे को दूसरे अधिकारी को सौंप देता है।
व्हाइट हाउस में इस तरह की घुसपैठ पहले भी हो चुकी है। अप्रैल 2023 में एक बच्चा उत्तरी लान में मेटल की बाड़ को पार करके अंदर घुस गया था, और बाद में उसे उसके माता-पिता से मिलवाया गया था।

नेपाल में अमेरिकी महिला का अपहरण करने वाली गिरफ्तार

काठमांडू, प्रेट्र: नेपाल के पोखरा में अमेरिका की एक बुजुर्ग महिला का अपहरण करने के आरोप में नेपाली महिला सरिता लामा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा कि 37 वर्षीया सरिता नुवाकोट जिले के बेल्कोटगाधी नगरपालिका की निवासी है।
नेपाल पुलिस की केंद्रीय जांच ब्यूरो ने हेतौडा उप-महानगरीय शहर से अमेरिकी महिला को मुक्त कराया और सरिता को गिरफ्तार कर लिया। 70 वर्षीया अमेरिकी महिला अपने मित्रों के साथ नेपाल घूमने आई थी और मुक्तिनाथ मंदिर के लिए पोखरा पहुंची थी। पोखरा में लेकसाइड होटल में ठहरी अमेरिकी महिला का सोमवार को अगवा किया गया। पोखरा से अमेरिकी महिला मकवानपुर ले जाई गई जहां उसे बंदी बनाकर रखा गया।
सरिता ने अमेरिकी महिला के लिए 300,000 यूरो (2.77 करोड़ भारतीय रुपये) फिरौती मांगी थी। पीड़ित ने नेपाल में अमेरिकी दूतावास को सूचित किया। दूतावास की सूचना पर पुलिस ने महिला को मुक्त करा लिया।

किम जोंग उन ने नए टोही और हमला करने वाले ड्रोनों का किया निरीक्षण

उत्तर कोरिया द्वारा विकसित नए ड्रोन विभिन्न मिशनों के लिए डिजाइन किए गए हैं
« उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने एक बड़े टोही ड्रोन का निरीक्षण किया। रायटर

सियोल, रायटर : उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने एआइ तकनीक से लैस आत्मघाती ड्रोन के परीक्षण को देखा। कहा, आधुनिक हथियारों के विकास में मानव रहित नियंत्रण व एआइ क्षमता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने नए उन्नत टोही ड्रोन का भी निरीक्षण किया, जो जमीन और समुद्र में सामरिक लक्ष्यों और दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम हैं। उत्तर कोरिया ने पहली बार आधिकारिक तौर पर एक पूर्व चेतावनी विमान का भी अनावरण किया। यह ऐसी क्षमता है जो इसकी पुरानी वायु रक्षा प्रणालियों में सुधार कर सकती है।
कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी द्वारा जारी तस्वीरों में किम को एक बड़े टोही ड्रोन को देखते हुए दिखाया गया है। यह बोइंग के ई-7 वेजटेल एयरबोर्न वार्निंग व कंट्रोल एयरक्राफ्ट जैसा दिख रहा था। अन्य तस्वीरों में लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल सैन्य वाहनों में विस्फोट करने वाले ड्रोन को हमला करते दिखाया गया है। परीक्षण के दौरान टोही ड्रोन की कई लक्ष्यों को ट्रैक करने और जमीन और समुद्र पर सैन्य गतिविधियों की निगरानी करने की क्षमता को भी प्रदर्शित किया। इससे उत्तर कोरिया की खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमता में वृद्धि होगी।

जेलेंस्की का बड़ा दावा– जल्द मरने वाले हैं राष्ट्रपति पुतिन

जेएनएन, नई दिल्ली

- यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक इंटरव्यू के दौरान की बड़ी भविष्यवाणी

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन की तबीयत बिगड़ रही है और वह जल्द मर जाएंगे।
जेलेंस्की ने बुधवार को यूरोविजन न्यूज को दिए साक्षात्कार के दौरान कहा, वह (पुतिन) जल्द ही मर जाएंगे। यह हकीकत है। इसके साथ ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। पुतिन अपनी आखिरी सांस तक सत्ता में बने रहना चाहते हैं। उनकी महात्वाकांक्षाएं केवल यूक्रेन पर कब्जे तक ही सीमित नहीं हैं। वह पश्चिम के साथ सीधा टकराव भी चाहते हैं।
हालांकि, जेलेंस्की ने इसकी जानकारी नहीं दी कि उन्हें ऐसा क्या पता है कि पुतिन की जल्द मौत होने वाली है, पर बीते कुछ वर्षों से रूसी राष्ट्रपति की सेहत को लेकर अटकलों का सिलसिला जारी है। वैसे क्रेमलिन ने ऐसी तमाम रिपोर्टों का खंडन भी किया है।

पुतिन की बिगड़ती सेहत को लेकर पहले भी आ चुकी हैं अफवाहें

बीते अक्टूबर में सैनिकों से हाथ मिलाते समय पुतिन के हाथ में ड्रिप चढ़ने के निशान देखे जाने की बात कही गई थी, जिसके बाद अफवाहें फैली कि वह कैंसर का इलाज करवा रहे हैं।
बता दें कि जेलेंस्की का यह बयान सऊदी अरब में मंगलवार को रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों की अमेरिकी अधिकारियों के साथ वार्ता के बाद आया है, जिसमें युद्धविराम के लिए काला सागर में जहाजों के सुरक्षित आवागमन और ऊर्जा संयंत्रों पर हमले ना किए जाने के समझौते पर सहमति बनी थी।

मिस्र तट पर पर्यटक पनडुब्बी डूबने से छह रूसी नागरिकों की मौत

- सिंदबाद नामक सबमरीन में चालक दल के अलावा 45 रूसी पर्यटक सवार थे
- 39 लोगों को बचा लिया गया, डूबने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है

काहिरा, रायटर: मिस्र के लाल सागर रिसार्ट हर्गहाडा के पास गुरुवार को एक पर्यटक पनडुब्बी के डूबने से छह रूसी नागरिकों की मौत हो गई। 39 विदेशी पर्यटकों को बचा लिया गया। हर्गहाडा में रूसी वाणिज्य दूतावास ने कहा कि सिंदबाद नामक पनडुब्बी में चालक दल के अलावा 45 रूसी पर्यटक सवार थे। गुरुवार सुबह स्थानीय समय 10 बजे यह रवाना हुई थी और तट से करीब एक किलोमीटर दूर डूब गई। यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि पनडुब्बी क्यों डूबी।
रूस के वाणिज्य दूतावास ने कहा कि ज्यादातर लोगों को बचा लिया गया। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। बाकियों को होटल भेज दिया गया। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, पनडुब्बी में बड़े-बड़े पोर्टहोल थे, ताकि यात्री लाल सागर के शानदार कोरल और समुद्री जीवन को देख सकें। यह 25 मीटर की गहराई तक गोता लगाती थी। यह जून 2023 में डूबे टाइटैनिक के पास अटलांटिक के नीचे हजारों मीटर नीचे दुर्घटनाग्रस्त हुए एक्सट्रीम एडवेंचर क्राफ्ट से काफी अलग थी।
उल्लेखनीय है कि लाल सागर मिस्र के पर्यटन उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है, जिसमें रूसी पर्यटक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि पर्यटक नौकाओं के पलटने की कई घटनाएं हुई हैं। पिछले वर्ष जून में ऊंची लहरों से गंभीर क्षति के बाद एक नाव डूब गई थी। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ था। वहीं, नवंबर में सागर में एक पर्यटक नाव पलट गई थी। इस घटना में 11 लोगों की मौत हो गई थी।

****

लखनऊ ने तोड़ा सनराइजर्स का घमंड

सुपरजायंट्स ने पांच विकेट से जीता मुकाबला, पूरन और मार्श ने जड़े अर्धशतक शार्दुल ने झटके चार विकेट

विकेट लेने के बाद रवि बिश्नोई के साथ शार्दुल ठाकुर • एपी

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: राजस्थान रायल्स के विरुद्ध पिछले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के 286 रन बनाने और दिल्ली कैपिटल्स के विरुद्ध लखनऊ सुपरजायंट्स के 210 रन के न बचा पाने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि गुरुवार को हैदराबाद में मेजबान टीम उत्तर प्रदेश की टोली के विरुद्ध 300 रन का रिकार्ड भी बना सकती है, लेकिन मेहमान टीम के गेंदबाजों ने पिछले मैच से सबक लेते हुए हैदराबाद को 190 रनों पर ही रोक दिया। यही नहीं निकोलस पूरन और मिशेल मार्श की तेजतर्रार अर्धशतकीय पारी के दम पर लखनऊ सुपरजायंट्स ने 23 गेंद शेष रहते केवल पांच विकेट पर 193 रन बनाकर लक्ष्य प्राप्त कर लिया।

पूरन-मार्श ने फिर दिखाई क्लास: दिल्ली कैपिटल्स के विरुद्ध लखनऊ सुपरजायंट्स भले ही मुकाबला हार गए हों, परंतु उस मैच में भी टीम को 200 के पार पहुंचाने में पूरन और मार्श का अहम योगदान था। दोनों ने एक बार फिर सनराइजर्स के विरुद्ध अपनी क्लास दिखाई और मैच को पूरी तरह से एकतरफा कर दिया। मैच से पहले सभी को उम्मीद थी कि लखनऊ के गेंदबाजों को सनराइजर्स की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी झेलनी पड़ेगी, लेकिन मैच में बिल्कुल इसके विपरीत देखने को मिला। निकोलस पूरन और मिशेल मार्श ने सनराइजर्स के हर गेंदबाज की क्लास लगाई। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए केवल 43 गेंदों में 116 रन जोड़ दिए। पूरन ने जहां केवल 26 गेंदों में छह चौके और इतने ही छक्के के दम पर 70 रन जोड़े। मार्श ने 31 गेंदों में सात चौके और दो छक्कों की मदद से 52 रन बनाए।

बल्लेबाजी में फिर पंत ने किया निराश: आइपीएल 2025 की नीलामी में सबसे महंगे 27 करोड़ रुपये में बिकने वाले रिषभ पंत अब तक शुरुआती दो मैचों में 27 रन भी नहीं जोड़ सके हैं। पहले मैच में बतौर कप्तान पहली बार शून्य बनाने वाले कप्तान रिषभ पंत ने सनराइजर्स के विरुद्ध खाता तो खोल लिया, परंतु 15 गेंदों की अपनी पारी में 15 रन ही जोड़ सके। इस दौरान उनके बल्ले से केवल एक छक्का निकला। यानी अब तक केवल 21 गेंद खेलने वाले लखनऊ सुपरजायंट्स के कप्तान के बल्ले से केवल 15 रन निकले हैं।

पंत ने ली सीख: पिछले मैच से सबक सीखते हुए कप्तान रिषभ पंत ने टास जीतने के बाद बिना डरे हुए सनराइजर्स के खूंखार बल्लेबाजों को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इसके पीछे उनका मंत्र यह था कि सनराइजर्स जो भी लक्ष्य उन्हें देंगे उनके बल्लेबाज उसे ओस में आसानी से हासिल कर लेंगे, लेकिन पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ की टीम कम स्कोर बनाती है तो दूसरी पारी में सनराइजर्स के लिए लक्ष्य को प्राप्त करना आसान हो जाएगा। गेंदबाजों ने भी सीख लेते हुए सधी हुई गेंदबाजी की। पिछले मैच में चार ओवर में 47 रन लुटाने वाले प्रिंस यादव ने इस बार न केवल 29 रन दिए, बल्कि ट्रेविस हेड का विकेट भी निकाला।

हेड नहीं उठा सके लाभ: पहले मैच में राजस्थान के विरुद्ध अर्धशतक जड़ने वाले हेड को एक बार फिर अच्छी शुरुआत मिली और दो जीवनदान भी मिले, परंतु वह इसका लाभ नहीं उठा सके। रवि बिश्नोई के ओवर की पहली ही गेंद पर हेड जब 35 रन पर थे, निकोलस पूरन ने आसान कैच छोड़कर उन्हें जीवनदान दे दिया। इसके बाद रवि बिश्नोई ने पांचवीं गेंद पर काट एंड बोल्ड का अवसर गंवा दिया, जब वह 42 रन पर थे। हालांकि, हेड इसके बावजूद केवल 47 रन बना सके।

100 विकेट शार्दुल ने आइपीएल में पूरे किए, भारतीय गेंदबाजों में यह कारनामा करने वाले 18वें गेंदबाज बने

स्कोर बोर्ड

हैदराबाद : 190/9 (20 ओवर)

	रन	गेंद	4/6
ट्रैविस हेड बो प्रिंस	47	28	5/3
अभिषेक का. पूरन बो. शार्दुल	06	06	1/0
इशान का. पंत बो. शार्दुल	00	01	0/0
नीतीश बो. बिश्नोई	32	28	2/0
क्लासैन रनआउट	26	17	2/1
अनिकेत का. मिलर बो. दिग्वेश	36	13	0/5
अभिनव का. समद बो. शार्दुल	02	06	0/0
कमिंस का. दिग्वेश बो. आवेश	18	04	0/3
हर्षल अविजित	12	11	0/0
शमी का. बडोनी बो. शार्दुल	01	03	0/0
सिमरजीत अविजित	03	04	0/0

अतिरिक्त: 7, विकेटपतन: 15-1 (अभिषेक, 2.1), 15-2 (इशान, 2.2), 76-3 (हेड, 7.3), 110-4 (क्लासेन, 12), 128-5 (नीतीश, 14.1), 156-6 (अनिकेत, 15.6), 156-7 (अभिनव, 16.2), 176-8 (कमिंस, 17.3), 181-9 (शमी, 18.3), गेंदबाजी: शार्दुल 4-0-34-4, आवेश 4-0-45-1, दिग्वेश 4-0-40-0, बिश्नोई 4-0-42-1, प्रिंस 4-0-29-1

लखनऊ: 193/5 (16.1 ओवर)

	रन	गेंद	4/6
मार्श का. नीतीश बो कमिंस	52	31	7/2
मार्करैम का. कमिंस बो. शमी	01	04	0/0
पूरन एलबीडब्ल्यू कमिंस	70	26	6/6
पंत का. शमी बो. हर्षल	15	15	0/1
बडोनी का. हर्षल बो. जांपा	06	06	1/0
मिलर अविजित	13	07	2/0
समद अविजित	22	08	2/2

अतिरिक्त : 14, विकेटपतन : 4-1 (मार्करैम, 1.3), 120-2 (पूरन, 8.4), 138-3 (मार्श, 10.5), 154-4 (बडोनी, 12.6), 164-5 (पंत, 14.1), गेंदबाजी: अभिषेक 2-0-20-0, शमी 3-0-37-1, सिमरजीत 2-0-28-0, कमिंस 3-0-29-2, जांपा 4-0-46-1, हर्षल 2-0-28-1, इशान 0.1-0-4-0

18 गेंद में अर्धशतक लगाया निकोलस पूरन ने जो आइपीएल 2025 में सबसे तेज है। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स के विरुद्ध मिशेल मार्श ने 24 गेंद में अर्धशतक लगाया था

हैदराबाद में हुआ 'लार्ड' शार्दुल का 'सन राइज'

आइपीएल 2025 की मेगा नीलामी में नहीं बिके मुंबई के आलराउंडर शार्दुल ठाकुर लखनऊ सुपरजायंट्स के सबसे प्रमुख गेंदबाज बन गए हैं। चोटिल मोहसिन खान के पूरे सत्र से बाहर होने के बाद उनके विकल्प के रूप में लखनऊ सुपरजायंट्स के साथ जुड़े शार्दुल ने पहले मैच में दिल्ली की तरह सनराइजर्स के विरुद्ध भी सुपरजायंट्स को शुरुआती सफलता दिला दी। उन्होंने अंत में दो विकेट झटककर सनराइजर्स को 200 के पार जाने से भी वंचित कर दिया। शार्दुल ठाकुर ने अपने दूसरे ही ओवर में पहले ओपनर अभिषेक शर्मा (6) फिर अगली ही गेंद पर इशान किशन (0) को पवेलियन की राह दिखाकर सनराइजर्स को बैकफुट पर भेज दिया। पिछले मैच में भी शार्दुल ने पहले ही ओवर में फ्रेजर मैकगर्क और अभिषेक पोरेल का विकेट ले लिया था, परंतु इसके बावजूद पंत ने दो ओवर रहने के बावजूद उन्हें अंत में गेंदबाजी नहीं दी थी। हालांकि, इस मैच में पंत ने उस गलती को नहीं दोहराया। उन्होंने अंत में फिर शार्दुल का रुख किया, और उन्होंने अभिनव मनोहर (2) और शमी (1) का विकेट झटककर सनराइजर्स को 200 के पार पहुंचने से रोक दिया।

अंक तालिका		मैच	जीत	हार	टाई	नेट रन रेट	अंक
1	आरसीबी	1	1	0	0	+2.200	2
2	लखनऊ	2	1	1	0	+0.963	2
3	पंजाब	1	1	0	0	+0.550	2
4	सीएसके	1	1	0	0	+0.493	2
5	दिल्ली	1	1	0	0	+0.371	2
6	हैदराबाद	2	1	1	0	-0.128	2
7	केकेआर	2	1	1	0	-0.308	2
8	मुंबई	1	0	1	0	-0.493	0
9	गुजरात	1	0	1	0	-0.550	0
10	राजस्थान	2	0	2	0	-1.882	0

इंपैक्ट प्लेयर नियम के न पक्ष में न विरोध में : फिलिप्स

ग्लेन फिलिप्स • एक्स

गुजरात टाइटंस व न्यूजीलैंड के आलराउंडर ने कहा, भविष्य में इस नियम से आलराउंडरों के लिए हो सकती है मुश्किल

नई दिल्ली, प्रेट्र: न्यूजीलैंड और गुजरात टाइटंस के आलराउंडर ग्लेन फिलिप्स का मानना है कि आइपीएल में इंपैक्ट प्लेयर नियम फिलहाल काम कर रहा है लेकिन यह कभी ना कभी आलराउंडर के विकास में समस्याएं खड़ी कर सकता है। इस नियम पर लोगों की राय अलग-अलग है लेकिन बीसीसीआइ ने इसे कम से कम 2027 के सत्र तक लागू किया है।

फिलिप्स ने कहा, मैं ना तो इसके पक्ष में हूं और ना खिलाफ। यह निश्चित रूप से टीम को अलग-अलग चीजें करने की अनुमति देता है। लेकिन मुझे लगता है कि किसी स्तर पर आलराउंडर बाहर हो सकते हैं और इसका स्पष्ट रूप से अंतरराष्ट्रीय मैच, टी-20, वनडे मुकाबले पर असर पड़ सकता है। तो अभी के लिए, यह क्रिकेट का एक बेहतरीन मनोरंजक ब्रांड है। लेकिन मुझे लगता है कि आईपीएल ने जो अच्छा काम किया है, वह है कि नियमों को माहौल के अनुसार बदलना। फिलिप्स ने कहा, बेशक इंपैक्ट प्लेयर नियम इस समय काम कर रहा है लेकिन फिर वे एक और नियम ला सकते हैं और खेल को और मनोरंजक बना सकते हैं। पिछले सत्र में रोहित शर्मा ने कहा था कि वह इंपैक्ट प्लेयर नियम के प्रशंसक नहीं हैं क्योंकि इससे भारतीय आलराउंडर के विकास में बाधा आती है। मौजूदा सत्र से पहले हार्दिक पांड्या ने कहा कि शुरुआती एकादश में उभरते हुए ऑलराउंडर को शामिल करना मुश्किल है जब तक कि कोई उनके जैसा विशुद्ध आलराउंडर नहीं हो।

फिलिप्स ने आइपीएल 2025 से पहले गेंद पर लार लगाने से जुड़े प्रतिबंध को हटाने का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा, इस साल लार का इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे जाहिर तौर पर रिवर्स स्विंग को भी मदद मिलेगी। अगर कोई अतिरिक्त बल्लेबाज खेल रहा है तो गेंदबाजों की मदद के लिए भी कुछ होना चाहिए।

एक नजर में

संधू संयुक्त चौथे स्थान पर सर्वश्रेष्ठ भारतीय

गुरुग्राम : भारत के सात गोल्फरों ने गुरुवार को हीरो इंडियन ओपन के पहले दिन शीर्ष 30 में जगह बनाई जबकि अजितेश संधू संयुक्त चौथे नंबर से सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रहे। संधू (69) और वीर अहलावत (70) क्रमशः संयुक्त चौथे और संयुक्त 10वें स्थान पर थे। दो बार के विजेता एसएसपी चौरसिया, गगनजीत भुल्लर, शिव कपूर, ओम प्रकाश चौहान और रेहान थॉमस ने 72-72 का कार्ड खेला। इंग्लैंड के मार्कस आर्मिटेज शीर्ष पर बने हुए हैं जो चार साल के खिताब के सूखे को समाप्त करने की कोशिश में जुटे हैं। (प्रेट्र)

आइएनए सोलर एलएसजी का एसोसिएट पार्टनर बना

नई दिल्ली : देश की प्रतिष्ठित सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड (आइएनए सोलर) ने आइपीएल 2025-27 के लिए लखनऊ सुपरजायंट्स का एसोसिएट पार्टनर बनने की घोषणा की है। आइएनए सोलर के चेयरमैन मनीष गुप्ता ने कहा, सुपरजायंट्स के साथ साझेदारी प्रधानमंत्री के 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। क्रिकेट देश के हर कोने तक पहुंचता है, और हम इस माध्यम से अक्षय ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इसे अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। प्रबंध निदेशक विकास जैन ने कहा, सुपरजायंट्स जैसे लोकप्रिय ब्रांड के साथ सहयोग हमें व्यापक स्तर पर अक्षय ऊर्जा के संदेश को फैलाने में मदद करेगा। (वि.)

क्वालीफायर में थाइलैंड, मंगोलिया के ग्रुप में भारत

नई दिल्ली : भारत की सीनियर महिला फुटबाल टीम को एएफसी महिला एशियाई कप आस्ट्रेलिया 2026 क्वालीफायर के लिए गुरुवार को ग्रुप बी में थाइलैंड, मंगोलिया, तिमोर लेस्ते और इराक के साथ जगह मिली। टूर्नामेंट का ड्रा कुआलालंपुर में एएफसी हाउस में आयोजित किया गया। थाइलैंड 23 जून से पांच जुलाई के बीच राउंड रोबिन प्रारूप में क्वालीफायर के ग्रुप बी की मेजबानी करेगा। ग्रुप विजेता फाइनल टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करेंगे जिसका आयोजन एक से 26 मार्च 2026 तक होगा। (प्रेट्र)

17 साल से चेपक में चेन्नई सुपरकिंग्स को नहीं हरा सकी है रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आज होगा हाईवोल्टेज मुकाबला

आरसीबी के सामने चेन्नई का किला ढहाने की चुनौती

रुतुराज गायकवाड़ — विराट कोहली

चेन्नई, प्रेट्र: रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) शुक्रवार को आइपीएल मुकाबले में जब चेन्नई सुपरकिंग्स से भिड़ेगी तो टीम की नजरें चेपक में जीत के 17 साल के इंतजार को खत्म करने पर होंगी। आरसीबी ने चेपक में सुपरकिंग्स को सिर्फ एक बार हराया है और वह भी 2008 में टूर्नामेंट के पहले सत्र में। आरसीबी की मौजूदा टीम में सिर्फ स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ही उस मैच का हिस्सा थे और अब वह दूसरी बार सुपरकिंग्स के किले को भेदना चाहेंगे।

चेन्नई के गढ़ चेपक में आरसीबी की राह आसान नहीं होगी। हमेशा की तरह चेन्नई की टीम स्पिनरों की मददगार पिच पर अपने घरेलू मैचों में विरोधी टीमों को कड़ी टक्कर देने को तैयार होगी। टीम के पास अनुभवी रवींद्र जडेजा हैं जो लंबे समय से टीम का हिस्सा हैं जबकि पिछले साल खिलाड़ियों की मेगा नीलामी के जरिए उन्होंने अपने 'पुराने साथी' रविचंद्रन अश्विन को टीम के साथ जोड़ा है। टीम ने अफगानिस्तान के बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर नूर अहमद को भी टीम में शामिल किया है और इस तिकड़ी ने कुछ दिन पहले पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के विरुद्ध अच्छा प्रदर्शन किया था। इस मैच में भी चेन्नई की पारंपरिक पिच देखने को मिलेगी और कोहली की अगुआई में आरसीबी के बल्लेबाजों को अनुभवी गेंदबाजी आक्रमण को मात देने के लिए अपने खेल को बेहतर करना होगा।

आरसीबी के बल्लेबाजी क्रम को सुपरकिंग्स के तीन आयामी स्पिन आक्रमण के विरुद्ध पूरी तरह से आक्रामक होने की जगह अधिक चतुर होना होगा और कोहली को उनका नेतृत्व करना होगा। स्पिन का सामना करना हमेशा से कोहली की बल्लेबाजी का मजबूत पक्ष नहीं रहा है लेकिन पिछले दो वर्षों में उन्होंने इस विभाग में काफी सुधार दिखाया है। कोहली को साथ ही फिल साल्ट, कप्तान रजत पाटीदार, लियाम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा जैसे बल्लेबाजों से समर्थन की जरूर होगी। चेपक की पिच को देखते हुए आरसीबी संभवतः टिम डेविड की जगह जैकब बेथेल को एकादश में शामिल कर सकती है जो बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी का विकल्प भी देते हैं। टीम की नजरें भुवनेश्वर कुमार की फिटनेस पर भी होंगी जो कोलकाता नाइटराइडर्स के विरुद्ध पहले मैच में चोट के कारण नहीं खेल पाए थे और अगर यह अनुभवी तेज गेंदबाज फिट होता है तो उन्हें रसिख सलाम की जगह एकादश में शामिल किया जाएगा।

दूसरी ओर सुपरकिंग्स को मध्यक्रम के फिर से लय में आने की उम्मीद होगी क्योंकि शिवम दुबे, दीपक हुड्डा और सैम कुरेन पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के विरुद्ध प्रभाव नहीं छोड़ पाए थे। उन्हें रचिन रवींद्र और कप्तान रुतुराज गायकवाड़ का अधिक सहयोग करना होगा।

> आरसीबी के लिए चेपक में खेलना बड़ी चुनौती होगी। सुपरकिंग्स की ताकत का मुकाबला करने के लिए आरसीबी को संयोजन में बदलाव करने की जरूरत होगी। लेकिन गलती नहीं करें, चेपक एक किला है। सुपरकिंग्स का पूरा ढांचा चेन्नई में बेहतरीन प्रदर्शन करने के इर्द-गिर्द बना है। **-शेन वाटसन**, पूर्व आलराउंडर, आस्ट्रेलिया

हरियाणा ने दूसरी बार जीती टीम चैंपियनशिप

खेलो इंडिया पैरा गेम्स

34 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 104 पदक हरियाणा ने जीते, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर रहा, उत्तर प्रदेश की टीम तीसरे स्थान पर

चैंपियनशिप ट्राफी के साथ हरियाणा के खिलाड़ी • साई

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का समापन गुरुवार को हुआ जिसमें हरियाणा ने 34 स्वर्ण सहित 104 पदक जीतकर लगातार दूसरी बार टीम चैंपियनशिप अपने नाम की। तमिलनाडु 28 स्वर्ण सहित 74 पदकों के साथ दूसरे और उत्तर प्रदेश 23 स्वर्ण सहित 64 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

नई दिल्ली के तीन स्थानों जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम और कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में हुए इस टूर्नामेंट में 1300 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस दौरान छह खेलों में 18 राष्ट्रीय रिकार्ड भी बने। पैरा पावरलिफ्टिंग में जसप्रीत कौर (पंजाब), मनीष कुमार (हरियाणा), सीमा रानी (पंजाब) और झंडू कुमार (बिहार) ने स्वर्ण जीते। वहीं, 14 एथलीटों ने ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में राष्ट्रीय रिकार्ड बनाए।

खेलो इंडिया पैरा गेम्स के इस संस्करण में कुल 596 पदक वितरित किए गए, जिसमें पुरुषों ने 346 और महिलाओं ने 250 पदक जीते। गुरुवार को गुजरात ने टेबल टेनिस में शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 पदक (चार स्वर्ण) जीते। हरियाणा ने तीन स्वर्ण सहित आठ पदक जीते। टेबल टेनिस के प्रमुख विजेताओं में पुरुषों की क्लास-6 में गुजरात के येजदी अस्पी भामगरा, महिलाओं की क्लास-6 में गुजरात की भाविका कुकड़िया, पुरुषों की क्लास-7 में कर्नाटक के संजीव हम्मनावर और महिलाओं की क्लास-7 में उत्तर प्रदेश की प्राची पांडे ने स्वर्ण पदक जीते।

जैस्मीन और पूजा रानी ने जीते स्वर्ण पदक

खेल डायरी

जीत के बाद जैस्मीन • बीएफआइ

जासं. ग्रेटर नोएडा : राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता जैस्मीन लम्बोरिया और दो बार की एशियाई चैंपियन पूजा रानी ने गुरुवार को आठवीं एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में विपरीत अंदाज में जीत दर्ज करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किए जबकि रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड (आरएसपीबी) ने नौ पदकों के साथ टीम ट्राफी जीती।

जैस्मीन ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए फेदरवेट का ताज अपने नाम किया। जैस्मीन ने आक्रामकता और त्रुटिहीन तकनीक का संयोजन दिखाया और हरियाणा की प्रिया को परास्त किया। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की कांस्य पदक विजेता जैस्मीन ने सर्वसम्मत फैसले में जीत हासिल की। उन्हें टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी चुना गया जिससे उन्हें 50,000 नकद पुरस्कार मिला। जीत के बाद जैस्मीन ने कहा, मैं यहां जीतकर खुश हूं। मैंने कुछ चीजों पर काम किया है और मैंने यहां सुधार देखा है। दूसरी ओर पूर्व एशियाई खेलों की पदक विजेता पूजा को 80 किग्रा के फाइनल में अखिल भारतीय पुलिस की लालफाकमावी राल्ते से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। इसके बाद टोक्यो ओलिंपियन पूजा ने मुकाबला 4-3 से अपने नाम किया। कुल मिलाकर रेलवे ने पांच स्वर्ण और चार कांस्य पदक हासिल किए। हरियाणा दो स्वर्ण, तीन रजत और एक कांस्य के साथ दूसरे स्थान पर रहा। इस बीच अखिल भारतीय पुलिस ने एक स्वर्ण, चार रजत और दो कांस्य जीते। रेलवे के लिए अनामिका हुड्डा ने हरियाणा की तमन्ना पर 5-0 की शानदार जीत के साथ अपने लाइट फ्लाईवेट खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया।

रीतिका हुड्डा पहले स्वर्ण पदक से एक जीत दूर

अम्मान, प्रेट्र : ओलिंपियन रीतिका हुड्डा ने एशियाई चैंपियनशिप के महिला 76 किग्रा वर्ग में दबदबा बनाते हुए बिना कोई अंक गंवाए गुरुवार को यहां फाइनल में जगह बनाई जबकि उनकी तीन अन्य हमवतन भारतीय पहलवान भी कांस्य पदक की दौड़ में हैं। अंडर-23 विश्व चैंपियन बनने वाली भारत की पहली महिला पहलवान और ओलिंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाली सबसे युवा भारतीय पहलवान 22 वर्ष की रीतिका ने फाइनल में जगह बनाने के दौरान जापान की नोडोक यामामोतो और कोरिया की सियोयिओन जियोंग को हराया। रीतिका ने पहले जियोंग को तकनीकी दक्षता से हराया। भारतीय पहलवान ने टेक-डाउन मूव से अंक जुटाए और फिर विरोधी खिलाड़ी के पैर को पकड़कर दो और अंक जुटाए। रीतिका ने इसके बाद कोरियाई खिलाड़ी के पैर पकड़कर अंक जुटाए और मुकाबला अपने नाम किया।

फिलीपींस की खिलाड़ी का सामना अब जेसिका पेगुला से होगा, पुरुषों में दिमित्रोव भी आगे बढ़े

19 साल की इयाला ने किया स्वियातेक का शिकार

मियामी ओपन

एलेक्जेंड्रा इयाला • एएफपी

- फिलीपींस की पहली खिलाड़ी हैं इयाला ऐसा करने वाली
- पेगुला ने ब्रिटेन की एम्मा राडुकानू को दी शिकस्त

मियामी गार्डेंस, एपी: फिलीपींस की वाइल्डकार्ड धारक 19 साल की एलेक्जेंड्रा इयाला ने मियामी ओपन में अपना स्वर्णिम सफर जारी रखते हुए अब पांच बार की ग्रैंडस्लैम चैंपियन व दूसरी वरीयता प्राप्त इगा स्वियातेक को उलटफेर का शिकार बनाया। इयाला ने स्वियातेक को एक घंटे और 37 मिनट में सीधे सेटों में 6-2, 7-5 से हराकर बाहर का रास्ता दिखाया। महिला पेशेवर टूर पर फिलिपींस का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र खिलाड़ी एलेक्सांद्रा को इस डब्ल्यूटीए 1000 प्रतियोगिता के लिए वाइल्ड कार्ड मिला है और वह दुनिया की 140वें नंबर की खिलाड़ी हैं। सेमीफाइनल तक के अपने सफर के दौरान एलेक्सांद्रा ने अब तक तीन ग्रैंडस्लैम विजेताओं को हराया है।

इससे पहले विश्व की 140वें नंबर की खिलाड़ी इयाला ने जेलेना ओस्टापेंको और मेडिसन कीज को हराया था। इयाला ओपन युग में फिलीपींस की पहली खिलाड़ी हैं, जिन्होंने डब्ल्यूटीए टूर प्रतियोगिता में ग्रैंडस्लैम चैंपियन खिलाड़ी को हराया है। 2022 में जूनियर यूएस ओपन खिताब जीतने वाली इयाला ने इससे पहले कभी भी किसी भी टूर्नामेंट में लगातार तीन मैच नहीं जीते थे। सेमीफाइनल में अब इयाला का सामना अमेरिकी खिलाड़ी जेसिका पेगुला से होगा, जिन्होंने ब्रिटेन की एम्मा राडुकानू को कड़े मुकाबले में पराजित किया। चौथी वरीय पेगुला ने दो घंटे और 25 मिनट चले मुकाबले में 6-4, 6-7(3), 6-2 से जीत दर्ज की। पेगुला बीते चार वर्षों में तीसरी बार मियामी ओपन के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। पेगुला और राडुकानू का मुकाबला देर रात समाप्त हुआ, जिसके कारण नोवाक जोकोविक और सेबेस्टियन कोर्डा के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल मुकाबले को रद करना पड़ा।

पुरुष सिंगल्स में करीब तीन घंटे चले मुकाबले में 14वीं वरीयता प्राप्त ग्रिगोर दिमित्रोव ने फ्रांसिस्को सेरुनडोलो 6-7(6), 6-4, 7-6 (3) से हराया। मैच के दौरान दिमित्रोव असहज दिखे और उन्हें मैच के दौरान ही टूर्नामेंट के डाक्टर व एटीपी के फिजियो से उपचार कराना पड़ा। दिमित्रोव करीब 25 मिनट तक कुर्सी पर बैठे रहे और उसके बाद कोर्ट पर लौटे।

****

चर्चा में

सुपरब्वायज आफ मालेगांव में लेखक बने विनीत कुमार सिंह

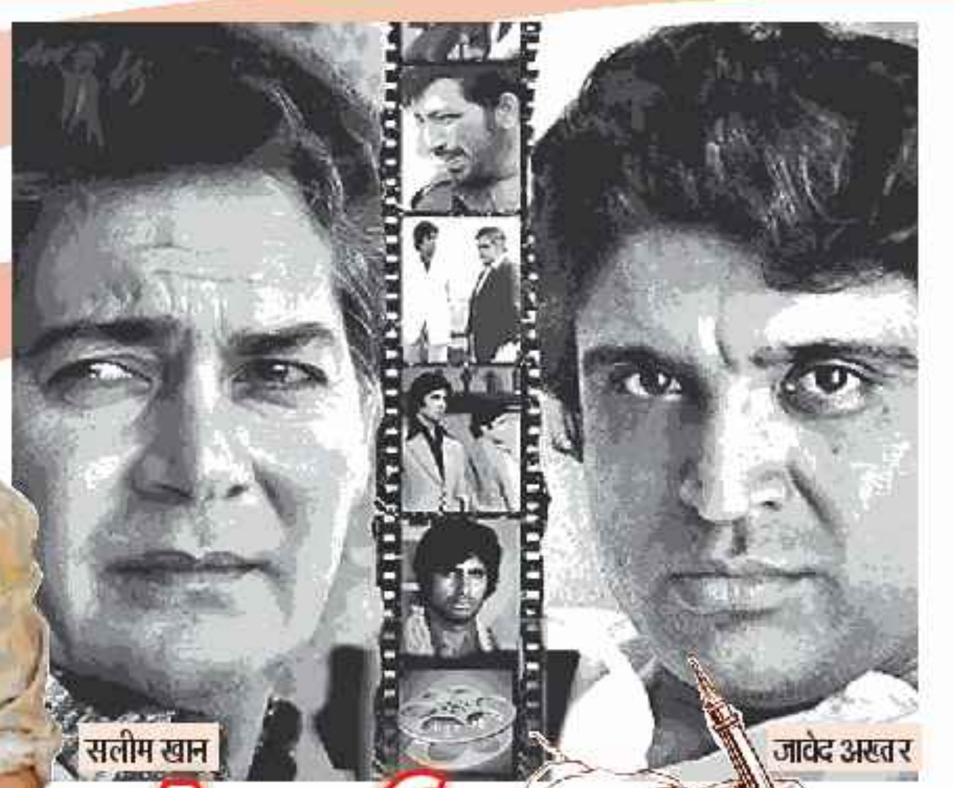

सलीम खान | जावेद अख्तर

● जागरण आर्काइव

नाम के लिए संघर्ष

हाल ही में प्रदर्शित फिल्म सुपरब्वायज आफ मालेगांव में लेखक फरोग (विनीत कुमार सिंह) कहता है, 'लेखक फिल्म का बाप होता है।' इस संवाद के साथ ही उसका दर्द छलक जाता है कि फिल्म को आकार देने में लेखक की आधारभूत भूमिका होती है, लेकिन श्रेय पाने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। इस विषय में लेखक जावेद अख्तर कहते हैं कि किसी लेखक ने फिल्म की कहानी, पटकथा और संवाद तीनों लिखे हैं तो उसकी सफलता श्रेय भी उसे मिलना चाहिए। पिछली सदी के आठवें दशक के दौरान जब लेखकों का नाम फिल्म के पोस्टर पर नहीं आता था तो सलीम (खान)- जावेद (अख्तर) की जोड़ी ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। सलीम पेंटर को पैसे देकर पोस्टर पर अपना नाम लिखवाते थे। लेखकों की इस जोड़ी ने हिंदी सिनेमा का एंग्री यंग मैन यानी अमिताभ बच्चन दिया। समय बदलने के साथ ही एक ओर जहां अब स्टारडम के बजाय कंटेंट अहम हो गया है तो वहीं लेखक भी अपने काम को लेकर मुखर हैं। स्मिता श्रीवास्तव का आलेख...

जानते सब हैं, मानते नहीं

सुपरब्वायज आफ मालेगांव फिल्म निर्माण को लेकर उत्साही युवाओं की कहानी कहती है। लेखक फरोग के पात्र का चर्चित संवाद राइटर बाप होता है, इन दिनों फिल्मों के लेखकों के बीच विमर्श का विषय बना हुआ है। कृष फिल्म और आश्रम 3 वेब सीरीज के लेखक **संजय मासूम** कहते हैं कि जानते सब हैं कि राइटर बाप होता है, लेकिन ऐसा मानते कम ही लोग हैं। हालांकि धीरे-धीरे बदलाव आने लगा है, अब नई कहानियों पर काम हो रहा है। अगर लेखक कोई आइडिया लेकर आ रहा है तो निर्माता-निर्देशक उस पर यकीन करके आगे बढ़ रहे हैं। मैंने राकेश रोशन जैसे निर्देशकों के साथ काम किया। वो लेखकों को बहुत अहमियत देते हैं। वह शूट करने के बाद पहले लेखकों को दिखाते थे ताकि वो बताएं कि जो लिखा था वो स्क्रीन पर आ सका या नहीं।

हर दौर में बनी हैं बेहतरीन फिल्में

लेखक **जावेद अख्तर** कहते हैं कि जिस तरह आर्किटेक्ट किसी इमारत का नक्शा तैयार करता है, उसके बाद इंजीनियर इमारत बनाता है, वैसा ही कुछ है फिल्म के लेखन और निर्माण के साथ। लेखन से ही फिल्म की शुरुआत होती है। कहानी, संवाद और पटकथा लेखन किसी भी फिल्म में सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी लेखक ने फिल्म की कहानी, पटकथा और संवाद तीनों लिखे हैं तो उसे श्रेय के लिए मुखर होना चाहिए, पर अगर ये सब अलग-अलग लोगों ने लिखे हैं, तो श्रेय के लिए अधिकार जताने में थोड़ी समस्या आ सकती है। श्री 420, सुजाता, बंदिनी, मदर इंडिया से लेकर मेरे दौर और वर्तमान में भी बेहतरीन फिल्में बनी हैं, पर उनकी संख्या कम है। अच्छी फिल्में लोगों को याद रह जाती हैं। ये भी सच है है कि जितना मुश्किल अच्छा काम करना है, उतना ही मुश्किल है उसे बेचना। कोई बहुत अच्छी कहानी है, पर ऐसा निर्देशक मिलना जरूरी है, जो उस पर भरोसा जताए। ऐसे कलाकार हों जो उसे कहानी को पर्दे पर जीना चाहें। ये सब भी जरूरी है।

नए लेखकों को आगे बढ़ाना है

द डिप्लोमैट फिल्म के अभिनेता **जान अब्राहम** ने केरल में अपने पार्टनर के साथ लेखकों का रूम बनाया है। जान कहते हैं कि मलयालम सिनेमा बेहतरीन फिल्में बना रहा है। इसलिए सोचा अगर वहां के लेखकों और निर्देशकों के साथ हम काम करें तो फिल्मों के लिए बेहतरीन मौलिक आइडिया मिल सकते हैं। मैंने वहां एक राइटर्स रूम बनाया है, जहां लेखक अपनी कहानियां और विचार रख सकते हैं। हालांकि एक समस्या अभी भी बनी हुई है। अगर हम किसी नए लड़के या लड़की के साथ फिल्म बनाने की सोचते हैं तो स्टूडियो को आइडिया बेचना थोड़ा मुश्किल होगा। नए आइडिया पर काम करने में जोखिम भी होता है। विक्की डोनर जैसी फिल्म दे सकें, जो दर्शकों को पसंद आए तो शायद उस तरह से एक और बना लेंगे।

काम को मिलता है सम्मान

सिकंदर फिल्म के संवाद लेखक और बागी 4 फिल्म के लेखक **रजत अरोड़ा** कहते हैं कि जब सलीम-जावेद साहब लिख रहे थे तो भी बहुत से लेखक लेखन कर रहे थे, लेकिन उनका काम इतना जबरदस्त था कि वह जो इज्जत मांगते थे, उनके सामने बड़े से बड़ा आदमी झुक जाता था। केवल यह कहना कि लेखकों को सम्मान नहीं मिल रहा है, ठीक नहीं है। यह भी देखना जरूरी है कि लेखक उस सम्मान को पाने की दिशा में कितना काम कर रहा है। जिम्मेदारी केवल एक व्यक्ति की नहीं है। सम्मान काम को मिलता है। काम पसंद आएगा तो कौन सम्मान नहीं देगा। सबसे बड़ा साथ दर्शकों का होता है। जहां तक बात है सलीम-जावेद जी की तो आज भी जब भी मैं उदास होता हूं, काम में कहीं अटकता हूं, प्रेरणा की जरूरत होती है तो उनकी फिल्में देख लेता हूं। उनकी बातें सुनकर ही सीखने को मिलता है।

कहानीकार की होती है दुनिया

हिंदी सिनेमा को द लंचबाक्स, मसान, किल जैसी फिल्में देने वाली निर्माता **गुनीत मोंगा** का मानना है कि लेखक की कागज पर लिखी दुनिया को निर्देशक अपने विजन से साकार करता है। वह कहती हैं, 'मैंने तो आज तक कंटेंट वाला सिनेमा ही बनाया है। नवोदित लेखकों और निर्देशकों के साथ काम किया है। दुनियाभर में उन्हें प्रशंसा मिली है, चाहे द लंचबाक्स हो, मसान या किल हो। मुझे तो यही समझ आता है कि फिल्म निर्माण में सबसे अहम लेखक और निर्देशक का काम है। मैंने 20 साल से इसी सोच के साथ काम किया है, आज एक छोटे से कार्नर में दो-तीन आस्कर अवार्ड आ गए हैं तो चमक बढ़ गई है। हम पहले भी वही करते थे, आज भी वही करते हैं। लगकर केवल स्क्रिप्ट पर मेहनत करते हैं। वह दौर कभी गया नहीं था, जाना भी नहीं चाहिए। इसका कारण यह है कि उस दुनिया को कहानीकार रचता है। दुनिया में फिर हम सब अपना काम करते हैं। हम नहीं, बल्कि कहानी हमें चुनती है।

जमाना बदल गया

वर्तमान में लेखकों की चुनौतियों को लेकर रजत अरोड़ा कहते हैं कि वह जमाना अलग था, जब फिल्म निर्माण में चार से पांच लोग हुआ करते थे। निर्माता, निर्देशक, कलाकार, लेखक, एडिटर, संगीत से जुड़े लोगों की टीम हुआ करती थी। यह तो आज भी है, लेकिन आज इसमें स्टूडियो व मार्केटिंग टीम भी जुड़ गई है। निर्माताओं के हाथ में कई चीजें नहीं होती हैं, निर्माता कोई फिल्म बना देता है तो स्टूडियो तय करता है कि मैं फलां का नाम दूंगा या नहीं दूंगा। हर बार नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है। हालांकि यहां कोई निगेटिविटी नहीं है। न ही कोई लड़ाई है। यहां लोग प्यार-मोहब्बत से काम करते हैं। फिल्म चलेगी, काम चलेगा तो आप आगे बढ़ेंगे।

इनपुट : प्रियंका सिंह

रैपिड फायर

रणवीर सिंह संग करना है काम

द आर्चीज और जिगरा फिल्मों के अभिनेता वेदांग रैना का कहना है कि इंडस्ट्री में काम करने के तरीकों को यहां आते ही समझ गए थे, क्योंकि उन्हें सही मार्गदर्शन मिला। वेदांग से झटपट सवालों के चटपट जवाब :

● **फिल्म इंडस्ट्री में किसे अपना गुरु मानते हैं?**
जोया अख्तर, उन्होंने मुझे फिल्मों में सही मौका दिया। अभिनय में आना चाहता था। उन्होंने ऐसी राह पर जाने से बचा लिया, जहां शायद मुझे समझ नहीं आता कि करना क्या है।

● **शुक्रवार का मतलब अभिनेता बनने के बाद कितना बदल गया?**
जब फिल्मों में नहीं आया था तो हम इंतजार करते थे कि कब शुक्रवार आएगा और वीकेंड में मजे करेंगे। अब एहसास होता है कि शुक्रवार को फिल्म प्रदर्शित होने से पहले बतौर कलाकार कितना तनाव होता है।

● **अनुशासन को करियर में किस नंबर पर रखते हैं?**
नंबर एक पर। प्रतिभा से ज्यादा अहम अनुशासन और मेहनत है। यह बात स्कूल में ही सीख गया था।

● **किस कलाकार के साथ स्क्रीन साझा करना है?**
रणवीर सिंह।

● **सबसे अच्छी सलाह क्या मिली है?**
यही है कि जैसे हैं, वैसे ही रहें। पहले इस बारे में सोचता था कि कैसे लोगों के सामने आना है, कैसे दिखाऊं कि मुझमें आत्मविश्वास है। अब मैंने एहसास कर लिया है कि मैं जो हूं, वो हूं। उसे अपनाना ही सही है।

● **अगर तीन लोगों (जीवित या मृत) के लिए एक डिनर पार्टी रखनी हो तो कौन होंगे?**
जीवित में से लियोनेल मेस्सी, उसका बचपन से बड़ा प्रशंसक रहा हूं। विज्ञानी आइजैक न्यूटन, उनके दिमाग से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तीसरे माइकल जैक्सन होंगे।

● **अपने म्यूजिक के लिए कितना समय दे पाते हैं?**
आजकल दे पा रहा हूं, क्योंकि मैं सेट पर नहीं हूं। एहसास हो रहा है कि मेरा जो संगीत के लिए जुनून है, वह बढ़ गया है। संगीत बनाने में मजा आ रहा है।

● **अगर फिल्मों में नहीं आते तो क्या कर रहे होते?**
शायद एमबीए करके नौ से पांच का जाब कर रहा होता, जिससे शायद मुझे नफरत होती। ये लगता कि मैंने गलत निर्णय लिया है। फिर सब कुछ छोड़कर, मैं म्यूजीशियन बनने का प्रयास जरूर करता।

● **जीवन का उद्देश्य क्या रहा है?**
जियो और जीने दो।

प्रियंका सिंह

इस पेज के बारे में अपनी राय और सुझाव भेजें- feature@jagran.com

म्यूजिक कार्नर

सलमान पर जंचती है मेरी गायकी

बुलेया और मन मा इमोशन जागे... जैसे हिट गानों के गायक अमित मिश्रा इन दिनों फिल्म सिकंदर के शीर्षक गीत को लेकर तारीफें बटोर रहे हैं। उनके गाए गाने सिकंदर नाचे नाचे को चार करोड़ से अधिक बार देखा-सुना जा चुका है। उन्होंने साझा की संगीत से जुड़ाव की बातें...

ट्यूबलाइट और रेस 3 फिल्मों के बाद गायक अमित मिश्रा ने अभिनेता सलमान खान के लिए गाना गाया है। सिकंदर के टाइटल सांग को लेकर वह कहते हैं, 'संगीतकार प्रीतम और फिल्म की म्यूजिक टीम ने बताया था कि यह पार्टी नंबर है, इसलिए गायकी में वही ऊर्जा लानी होगी। मैंने गाना रिकार्ड किया, लेकिन उसके बाद गीतकार समीर अनजान सर ने गाने के कुछ बोल बदल दिए। गाने को लेकर टीम के साथ दो सत्र हुए, फिर मैंने पूरी ऊर्जा के साथ यह गाना रिकार्ड किया। इसी दौरान सलमान सर (सलमान खान) से भी मिला। मैं इससे पहले भी उनके लिए गाने गा चुका हूं। इसलिए अंदाजा था कि जो गाना उन पर फिल्माया जाना है, उसे किस अंदाज में गाना चाहिए। यह गाना उन्हें भी काफी पसंद आया।'

अमित गायन के अलावा कई वाद्ययंत्र भी बजा लेते हैं। वह कहते हैं, 'मैंने बचपन से गायन का प्रशिक्षण लिया है। उस समय यूं ही कभी तबला या हारमोनियम वादक से जाकर पूछ लेता था कि उसे कैसे बजाते हैं? पढ़ाई के बाद जब समय मिलता था तो तबला बजाने बैठ जाता था। मुझे लगता है कि किसी संगीतकार को अपनी बात समझानी है तो उसके वाद्य यंत्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद गिटार, ढोल, ड्रम, पियानो और माउथ आर्गन बजाना सीखा। मैंने हाल ही में ग्रांड पियानो खरीदा है, उसे बजाना सीखना है। बेस गिटार भी सीखना है। कुछ नया सीखने का मेरा जुनून वाद्य यंत्रों तक सीमित नहीं रहा। मैंने लाकडाउन के दौरान संगीत की प्रोग्रामिंग तथा अरेंजमेंट करने जैसी टेक्नीकल चीजें सीखीं। कई बार लाइव परफार्मेंस के दौरान वादकों को सिर्फ बोलकर सही लय नहीं समझा पाते हैं, पर अगर वाद्य यंत्र बजाना आता है तो उन्हें बात समझा सकते हैं।'

दीपेश पांडेय

दिल से

गजगामिनी की कहानी

किसी फिल्म या आठ से नौ घंटे की वेब सीरीज में कौन सा दृश्य रील के तौर पर वायरल हो जाएगा, इसका अंदाजा कलाकारों को भी नहीं होता। फिल्मकार संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरामंडी: द डायमंड बाजार करते समय **अदिति राव हैदरी** को भी नहीं लगा था कि पृष्ठभूमि में बजते संगीत पर उनका मोहक अदा के साथ चलने का दृश्य गजगामिनी वाक के नाम से इतना लोकप्रिय हो जाएगा।

संजय लीला भंसाली ने इस सीरीज के दूसरे सीजन की घोषणा भी कर दी है। उसमें अदिति का अवतार क्या होगा, ये तो बाद में सामने आएगा, पर इन दिनों उनके गजगामिनी वाक पर खूब रील बन रही हैं। अदिति कहती हैं कि लोगों को लगता है कि संजय सर बहुत सख्त हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें अपने काम से प्यार है, वह अपने एक्टर्स को बहुत पसंद करते हैं। वह चाहते हैं कि उनके कलाकार अपना सर्वश्रेष्ठ दें। वह तब तक कलाकार को जाने नहीं देते हैं, जब तक उन्हें न लगे कि उस कलाकार ने अपना सौ प्रतिशत दिया है। उनके सामने खड़े होना ही बहुत बड़ी बात है। जहां तक गजगामिनी चाल की बात है तो मैं कथक डांसर नहीं हूं, पर मैंने बेहतर करने की कोशिश की थी। म्यूजिक का एक अंश था, जिस पर मुझे डांस करना था। संजय सर ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि लड़की इस पर घूमे और चलने लग जाए। इतना करना ही बेहद कामुक होगा। संजय सर जो बनाते हैं, उसमें कविता की तरह लय होती है। कोरियोग्राफर ने मेरे उस सीन को बहुत अच्छे से कोरियोग्राफ किया था। संजय सर ने कहा था कि जो भी करना है, थोड़े समयांतराल में करना है, जैसे मेरा चलना, आंखों से कुछ कहना जैसी छोटी-छोटी बारीकियां थीं। मैं खुश हूं कि जो उनके जेहन में था, मैं वह कर पाई। मैं उनकी उस दुनिया में खो गई थी। पता नहीं था कि मेरा चलना गजगामिनी वाक के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा।

स्मिता श्रीवास्तव

आज का भविष्यफल : 28 मार्च, 2025 शुक्रवार

पं. के.ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रहस्थिति : चैत्र मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी
आज का राहुकाल : प्रात : 10 :30 से 12 बजे तक
आज का दिशाशूल : पश्चिम
विशेष : पंचक
आज की भद्रा : प्रात : 09 :30 बजे तक

कल 29 मार्च, 2025 का पंचांग

कल का दिशाशूल : पूर्व
कल का पर्व एवं त्योहार : स्नानदान की अमावस्या
विशेष : विक्रम संवत् 2081 समाप्त, शनि मीन राशि में, पंचक।
विक्रम संवत 2081 शके 1947 उत्तरायण उत्तरगोल बसंत ऋतु चैत्र मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तत्पश्चात प्रतिपदा उत्तरभाद्रपद नक्षत्र तत्पश्चात रेवती नक्षत्र ब्रह्म योग तत्पश्चात ऐंद्र योग मीन में चंद्रमा।

मेष : षटग्रही योग मन अशांत करेगा। आर्थिक या पारिवारिक मामलों में किसी तरह का जोखिम न उठाएं।
वृष : संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में किया गया श्रम सार्थक होगा।
मिथुन : पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होगा।
कर्क : षटग्रही योग पिता या धर्म गुरु से सहयोग देगा। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कुछ नया कार्य प्रारंभ होगा।
सिंह : बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। व्यर्थ की परेशानी या पीड़ा मिल सकती है।
कन्या : दांपत्य जीवन उत्तम रहेगा। रिश्तों में निकटता आएगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी।
तुला : षटग्रही योग संतान के दायित्व की पूर्ति कराएगा। विरोधी परास्त होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।
वृश्चिक : प्रयास फलीभूत होंगे। शासनसत्ता का सहयोग मिलेगा। बुद्धि से किया गया कार्य संपन्न होगा।
धनु : चल या अचल संपत्ति के मामलों में सफलता मिलेगी। पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि या नए अनुबंध की संभावना है।
मकर : किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। धन, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी।
कुंभ : निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। रुका हुआ धन लाभ, व्यावसायिक प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी।
मीन : संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। रिश्तों में निकटता आएगी।

वर्ग पहेली-2937

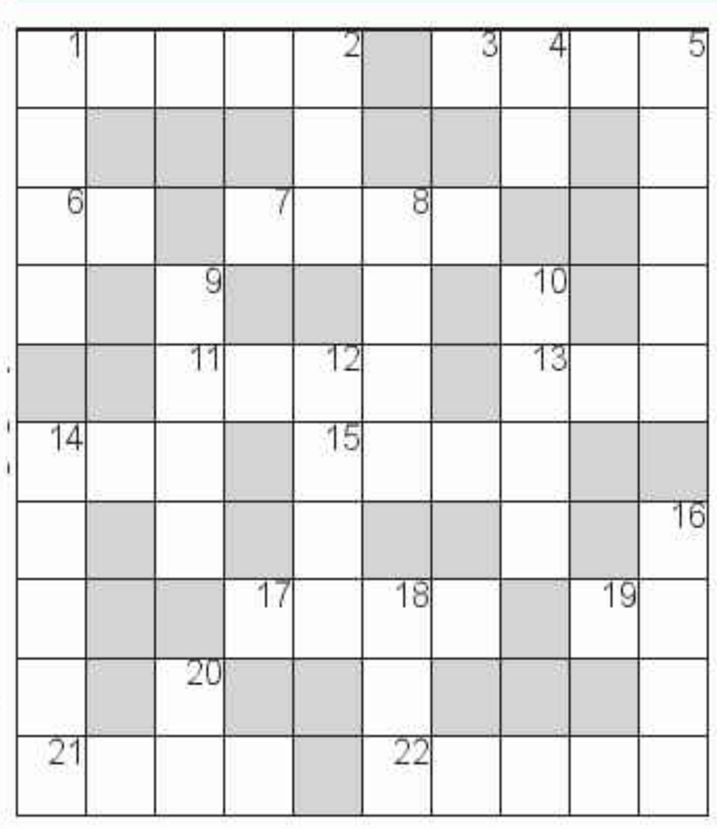

© Bird Features & Writing Agency

बाएं से दाएं
1. तमिलनाडु राज्य का एक प्रसिद्ध नगर (5)।
3. कृष्ण पक्ष की अंतिम रात (4)। 6. देने वाला (2)।
7. नहीं आया हुआ (4)।
11. भगवान का सेवक (4)।
13. हवालात, कैदखाना (3)।
14. एक प्रसिद्ध राजनीतिक दल का मुख पत्र (3)। 15. मान अपमान (4)। 17. मंसूबा (4)।
19. विचार, मत (2)।
21. जो जायज न हो (4)।
22. भागलपुर के शहर में कोयला आधारित विद्युत स्टेशन है (5)।

ऊपर से नीचे
1. विवाह में वर को कन्या देने की रीति (4)। 2. मुग्ध होना, आसक्त होना, प्रेम में पड़ना (3)।
4. हार (2)। 5. वस्तु के विभिन्न अंगों में होने वाला तुलनात्मक संबंध (5)। 8. पार्वती के पुत्र (4)।
9. बिस्मिल्लाह खान बजाते हैं इसे (4)। 10. कहानी का बहुवचन (4)।
12. अवैध माल जमा रखने वाला (4)।
14. हिम्मत हार जाना (3,2)।
16. परिवर्तन, हेर-फेर (4)।
18. नापने का मानदंड (3)।
20. दुख सूचक अव्यय (2)।

कल का हल

मा[1]	ह[2]				ज[3]	प[4]			का[5]
	म[6]	झ	धा	र		ह[7]	ला	ह[8]	ल
	द					चा		ल	
स[9]	म	झ	दा	र[10]		न		च	
ती				ज[11]	मं[12]	ना		ल	
	अ[13]		मुं[14]	नी	म				झाँ[15]
	ज		रा		ता[16]	क	त	ही[17]	न
	ग		द					न	
क[18]	र	मा	पा		प[19]	रा	क	म	
ल			नी[20]	ता				ति[21]	ल

जागरण सुडोकू-2937

8		5		2		3		4
	9						2	
		2	6		7		9	
2				8		4		7
	4		7		5			
7				4			1	6
3			5					1
		4		9		7		
6			8		3			9

कल का हल

8	4	2	9	3	1	6	7	5
3	7	1	2	5	6	8	9	4
9	6	5	4	8	7	1	2	3
7	3	9	6	1	5	4	8	2
5	2	6	8	4	9	3	1	7
4	1	8	3	7	2	9	5	6
2	9	3	5	6	8	7	4	1
1	5	4	7	9	3	2	6	8
6	8	7	1	2	4	5	3	9

राष्ट्रीय फलक

कानूनी जागरूकता कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के दो जज होंगे शामिल

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां इस महीने अरुणाचल प्रदेश में दो दिनों के लिए कानूनी जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

प्राधिकरण ने कहा कि ''कानूनी जागरूकता कार्यक्रम शिविर-सह-सेवा आपके द्वार'' का उद्देश्य पश्चिमी कामेंग जिले के दिरांग तथा बोमडिला और तवांग में आदिवासी समुदायों के बीच कानूनी पहुंच मजबूत करना और जागरूकता को बढ़ाना है। जस्टिस गवई नाल्सा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं।

29 और 30 मार्च को होने वाले इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले जस्टिस गवई और जस्टिस भुइयां तवांग में एक बाल गृह के अलावा एक जेल का भी दौरा करेंगे, जहां वे कुछ संगठनों से मिलकर उनकी कानूनी जरूरतों का आकलन करेंगे और न्याय तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करेंगे।

एअर इंडिया के विमान में खराब सीटों पर बैठने को मजबूर हुए यात्री

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

एयर इंडिया की उड़ान में यात्रियों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। कनाडा जाने वाली एअर इंडिया की उड़ान संख्या एआइ-189 में खराब सीट की शिकायत सामने आई है। बिजनेस क्लास की सीट को आउट आफ सर्विस बताने पर यात्रियों ने आपत्ति जताई तो क्रू ने उनको विमान से उतरने या फिर इकोनामी क्लास की सीट पर बैठने की सलाह दी। आखिर आउट आफ सर्विस सीट पर ही यात्रा करने को मजबूर हुए। इतना ही नहीं, सवा तीन बजे की उड़ान शाम 7.40 बजे टोरंटो के लिए रवाना हुई।

यात्रियों का कहना था कि 14 घंटे का सफर खराब सीट पर बैठकर कैसे पूरा किया जा सकता है। इस पर क्रू ने यात्रियों से कहा कि वे इकोनामी क्लास की सीट पर चले जाएं, लेकिन यात्रियों ने कहा कि बिजनेस क्लास का टिकट लेकर वे इकोनामी क्लास में यात्रा क्यों करें। इस पर क्रू ने कहा कि वे चाहें तो विमान से उतर सकते हैं। किराया का कुछ हिस्सा लौटा दिया जाएगा।

आउट आफ सर्विस लगी सीट। सौ: यात्री

केंद्रीय मंत्री ने भी बयां की थी खराब सीट की पीड़ा : केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से नई दिल्ली के लिए एअर इंडिया की उड़ान एआइ-436 में खराब सीट को लेकर एक्स पर पीड़ा बयां की थी। कनाडा जाने वाली एअर इंडिया की उड़ान एआइ-189 में खराब सीट को लेकर पंजाब के पूर्व मंत्री सिकंदर सिंह मलूका अपनी नाराजगी जता चुके हैं।

यात्री की तबीयत बिगड़ने की वजह से उड़ान में देरी : एअर इंडिया : एअर इंडिया का कहना है कि आमतौर पर खराब सीटें आवंटित नहीं की जाती हैं, लेकिन जब सीट की मांग काफी बढ़ जाती हैं तो कई बार ऐसी सीटें आवंटित हो जाती हैं। इस मसले को क्रू के सदस्यों ने सुलझा लिया है। जहां तक उड़ान में विलंब का प्रश्न है तो इसका कारण एक महिला यात्री की अचानक बिगड़ी तबीयत रही।

उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए 12 भाषाओं में स्वास्थ्य संबंधी एडवाइजरी

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून: उत्तराखंड शासन ने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के दृष्टिगत स्वास्थ्य एडवाइजरी जारी कर दी है। इस बार इसे 12 भाषाओं में जारी किया गया है। इसमें श्रद्धालुओं को यात्रा पर आने से पहले और यात्रा के दौरान उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत के निर्देशों पर इस बार तीर्थयात्रियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को पहले से अधिक बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों से आग्रह किया गया है कि यात्रा से पूर्व स्वास्थ्य जांच और चिकित्सकीय तैयारियों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री जैसे ऊंचे स्थानों पर यात्रियों को कठिन जलवायु एवं मार्ग के अलावा निम्न आक्सीजन स्तर का सामना करना पड़ता है, अतः तीर्थयात्री स्वास्थ्य परीक्षण व आवश्यक तैयारियों के साथ आएं।

महंगी हुई उत्तराखंड में आदि कैलास यात्रा, पंजीकरण शुरू

जागरण संवाददाता, नैनीताल

▸ धारचूला से 40 हजार तो काठगोदाम से देने होंगे प्रति यात्री 50 हजार रुपये

उत्तराखंड में काठगोदाम से आदि कैलास यात्रा पर जाने वाले शिवभक्तों को इस बार जेब आठ से दस हजार रुपये तक अधिक ढीली करनी होगी। साथ ही इस बार टनकपुर (चंपावत) से आदि कैलास का दल नहीं जाएगा। आदि कैलास के लिए काठगोदाम (नैनीताल) व धारचूला (पिथौरागढ़) से जाने वाले दलों के लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम (केएमवीएन) की वेबसाइट में पंजीकरण शुरू हो गए हैं।

केएमवीएन की ओर से आदि कैलास यात्रा का शेड्यूल बुधवार को जारी कर दिया गया है। यात्रा का पहला दल 14 मई को काठगोदाम से रवाना होगा। यह दल यात्रा पूरी कर काठगोदाम में ही रिपोर्ट करेगा। जबकि धारचूला से यात्रा का पहला दल 15 मई को रवाना होगा। काठगोदाम से आठ और धारचूला से पांच दल यात्रा पर जाएंगे। निगम के महाप्रबंधक विजय नाथ शुक्ला ने बताया कि पिछली बार तीन श्रेणी देहरादून से टनकपुर, काठगोदाम व काठगोदाम एक्सप्रेस श्रेणी में दलों के लिए क्रमशः 38 हजार, 40 हजार व 42 हजार की धनराशि तय की गई थी। इस बार केवल एक श्रेणी होगी और प्रत्येक यात्री को 50 हजार की धनराशि देनी होगी। यह धनराशि काठगोदाम से जाने वाले यात्री पर लागू होगी। धारचूला से जाने वाले श्रद्धालु को इस बार 30 हजार की बजाय 40 हजार रुपये चुकाने होंगे।

पर्यटन विकास को भारत-नेपाल सीमा पर खुलेंगे बार्डर कैफे : पिथौरागढ़: भारत-नेपाल-चीन सीमा पर आदि कैलास, ओम पर्वत, पंचाचूली आदि स्थलों में उमड़ रही पर्यटक व श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए अब सीमा क्षेत्र को भी और विकसित करने की तैयारी है।

****

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 28 मार्च, 2025
आजकल
14
www.jagran.com

पहली बार विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ

1891 में आज ही के दिन लंदन में विश्व की पहली भारोत्तोलन चैंपियनशिप आयोजित हुई थी। प्रतियोगिता में छह देशों के सात एथलीटों ने भाग लिया था। इंग्लैंड के एडवर्ड लारेंस पहले चैंपियन बने थे। 1896 में पहले ओलिंपिक में भारोत्तोलन को शामिल किया गया।

आस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा डायनासोर पदचिह्न खोजा गया

2017 में आज ही आस्ट्रेलिया के किंबरली में 5.5 फीट का विशाल डायनासोर पदचिह्न मिला था। इसे दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर पदचिह्न माना जाता है। पदचिह्न एक लंबी गर्दन वाले डायनासोर सारोपोड का था। इस क्षेत्र में कई डायनासोर प्रजातियों के पदचिह्न मिले थे।

टेस्ट में दोहरा शतक जड़ने वाले पहले क्रिकेटर हैं उमरीगर

पाली उमरीगर का जन्म 1926 में आज ही बांबे प्रेसीडेंसी के सोलापुर (अब महाराष्ट्र में) में हुआ था। 18 साल की उम्र में प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया। 1948 में वेस्टइंडीज की एक टीम के खिलाफ संयुक्त विश्वविद्यालयों के लिए शतक जड़कर सुर्खियों में आए। इसी वर्ष टेस्ट में पदार्पण किया। 1955 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में 74 रन देकर छह विकेट लिए। इसी वर्ष न्यूजीलैंड के विरुद्ध टेस्ट में 223 रन बनाकर दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने। वह टेस्ट की एक पारी में शतक बनाने और पांच विकेट लेने वाले क्रिकेटरों में भी शामिल रहे हैं।

कैंसर निदान के लिए संस्थाएं व शख्स हुए सम्मानित

हेल्थकेयर हीरोज समिट एंड अवार्ड्स 2025 ▶ जागरण न्यू मीडिया की हेल्थ वेबसाइट ओनली माय हेल्थ का आयोजन

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और दिल्ली सरकार के मंत्री डा. पंकज कुमार सिंह रहे उपस्थित

जागरण नेटवर्क, नई दिल्ली

जागरण न्यू मीडिया की हेल्थ वेबसाइट ओनली माय हेल्थ ने बुधवार को हेल्थकेयर हीरोज समिट एंड अवार्ड्स 2025 का आयोजन किया। इस वर्ष अवार्ड की थीम 'फाइटिंग कैंसर टुगेदर' था। इसका उद्देश्य कैंसर के खिलाफ एकजुट लड़ाई के लिए समाज, चिकित्सा विशेषज्ञों और नीति-निर्माताओं को एक मंच पर लाना था। यह समिट का पांचवां संस्करण था, जिसमें देशभर से प्रसिद्ध आन्कोलाजिस्ट्स, हेल्थकेयर लीडर्स, पालिसी मेकर्स और कैंसर सर्वाइवर्स शामिल हुए। कार्यक्रम में कैंसर की रोकथाम, समय पर जांच, इलाज और मरीजों की देखभाल को लेकर कई विषयों पर चर्चा हुई।

इस अवसर पर केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास अठावले और दिल्ली में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डा. पंकज कुमार सिंह बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। कैंसर को हरा चुकीं लोकप्रिय टेलीविजन अभिनेत्री हिना खान भी कार्यक्रम में उपस्थित थीं। उन्होंने कैंसर से जंग की कहानी लोगों के साथ शेयर की। इस दौरान उन संस्थाओं और व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने कैंसर निदान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

नई दिल्ली में आयोजित 'हेल्थकेयर हीरोज समिट एंड अवार्ड्स 2025' समारोह को संबोधित करते दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री पंकज सिंह। जागरण

अवार्ड - विजेता

- **एक्सीलेंस इन कैंसर डायग्नास्टिक्स** – स्ट्रैंड लाइफ साइंसेज (बेंगलुरु)
- **आउटस्टैंडिंग आन्कोलाजी ट्रीटमेंट सेंटर** – राजीव गांधी कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट (नई दिल्ली)
- **आउटस्टैंडिंग न्यूट्रिशन सपोर्ट फार कैंसर सर्वाइवर्स** – करुणाकेयर फाउंडेशन (गुजरात)
- **कैम्पेन आफ चेंज** – डीकेएमएस-बीएमएसटी फाउंडेशन इंडिया (बेंगलुरु)
- **हेल्थ स्टार्टअप आफ द ईयर** – खयाल एप (मुंबई)
- **गेम चेंजर्स इन डिजीज डायग्नोसिस (एडिटर्स चाइस)** – एकम्स-हाइड्राक्सी यूरिया ओरल सस्पेंशन फार सिकल सेल डिजीज (नई दिल्ली)
- **बेस्ट मल्टी-स्पेशियलिटी हास्पिटल इन दिल्ली (एडिटर्स चाइस)** – पीएसआरआइ मल्टी-स्पेशियलिटी हास्पिटल (नई दिल्ली)
- **मोस्ट ट्रस्टेड क्लीनिकल साइकोलाजिस्ट (एडिटर्स चाइस)** – डा. काशिका जैन (मेरठ)
- **डिजिटल हेल्थ ट्रेलब्लेजर्स** – डिजिटल डार्विन (नई दिल्ली)
- **डिजिटल हेल्थ ट्रेलब्लेजर्स** – एका केयर (बेंगलुरु)
- **मेंटल वेलनेस चैंपियंस** – आशादीप (नई दिल्ली)
- **गेम चेंजर्स इन डिजीज डायग्नोसिस** – स्मार्ट स्कोप सीएक्स बाय पेरिविंकल टेक्नोलाजीज (पुणे)
- **सेल्फलेस सर्विस इन पब्लिक हेल्थ** – खून (बेंगलुरु)
- **पायनियर्स इन न्यूट्रिशन एजुकेशन** – कडल्स फाउंडेशन (नई दिल्ली)
- **ब्रेकिंग बैरियर्स इन सेक्सुअल हेल्थ** – अर्पण एनजीओ (नई दिल्ली)
- **कम्युनिटी इम्पैक्ट अवार्ड इन कैंसर केयर** – कैनहील (नई दिल्ली)
- **कम्युनिटी इम्पैक्ट अवार्ड इन कैंसर केयर** – समीक्षा फाउंडेशन (बेंगलुरु)
- **मेंटल हेल्थ सपोर्ट फार कैंसर पेशेंट्स** – इंडियन कैंसर सोसाइटी (मुंबई)
- **एमर्जिंग लीडर इन ओटोलैरिंगोलाजी (ईएनटी) अवार्ड** – डा. एस. नम्रता (नई दिल्ली)
- **यंग विजनरी इन गैस्ट्रोएंट्रोलाजी केयर अवार्ड** – डा. टी. रविकिरण (नई दिल्ली)

फिल्म रिव्यू

एम्पुरान (लूसिफर 2)

प्रमुख कलाकार: मोहनलाल, पृथ्वीराज सुकुमारन, मंजू वारियर, अभिमन्यु सिंह, इंद्रजीत, टोविनो थामस
निर्देशक: पृथ्वीराज सुकुमारन
अवधि: दो घंटे 58 मिनट

फिल्म स्टाइलिश, लेकिन विषयवस्तु कमजोर

इस सीक्वल फिल्म में मोहनलाल अपने चिर परिचित अंदाज में हैं।

वर्ष 2019 में आई मलयालम फिल्म लूसिफर के निर्देशक पृथ्वीराज सुकुमारन ने इस फिल्म को तीन भाग में बनाने की बात कही है। फिल्म का दूसरा भाग सिनेमाघरों में एम्पुरान (लूसिफर 2) के नाम से रिलीज हुआ है। मूल कहानी में मुख्यमंत्री पीके रामदास (सचिन खेडेकर) की मृत्यु के बाद उनका दामाद बाबी (विवेक ओबेराय) सत्ता हथियाने की कोशिश करता है। उनके रास्ते का रोड़ा बनता है स्टीफन नेदुम्पल्ली यानी लूसिफर (मोहनलाल)। उनकी मुश्किलों में मदद को तत्पर नजर आते हैं जायद मसूद (पृथ्वीराज सुकुमारन)। अंत में स्टीफन रामदास के बेटे जतिन (टोविनो थामस) को सत्ता सौंपकर विदेश चला जाता है। सीक्वल में कहानी इन्हीं पात्रों की दुनिया को आगे बढ़ाती है।

एम्पुरान में कहानी का आरंभ वर्ष 2002 में सांप्रदायिक हिंसा में किसी तरह जीवित बचे किशोर के साथ होती है। वहां से कहानी वर्तमान में केरल आती है। केरल के मुख्यमंत्री के रूप में जतिन रामदास के निराशाजनक कार्यकाल के पांच साल बाद एक नई राजनीतिक ताकत उभर रही है। वहीं लूसिफर अब कुरैशी अब्राम (मोहनलाल) के तौर पर विदेश में अपना बड़ा नेटवर्क बना चुका है। वह अपने प्रतिद्वंद्वी माफिया सरगना कबुगा को मार देता है और खुद के मारे जाने का षड्यंत्र रचता है। उधर, जतिन अपनी नई पार्टी बनाने की घोषणा करता है और बाबा बजरंगी (अभिमन्यु सिंह) के साथ गठजोड़ करता है। केरल में बिगड़ते राजनीतिक माहौल की खबर मिलने पर लूसिफर वापस लौटता है।

लूसिफर की तुलना में इस फिल्म का स्तर काफी भव्य है, लेकिन लेखक मुरली गोपी सीक्वल को लेकर अपेक्षित गहराई प्रदान करने में असफल रहे हैं।

मोहनलाल की स्टाइलिश एंट्री के बाद कहानी में थोड़ी गति आती है। इस बार जायद मसूद के अतीत को खंगाला गया है, लेकिन उसके लिए गढ़ा गया उसका अतीत और उससे जुड़े पात्र यानी बलराम (अभिमन्यु सिंह) और उसके साथी मुन्ना को समुचित तरीके से गढ़ा नहीं गया है। सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर गोवर्धन (इंद्रजीत) का पात्र भी कमजोर है। फिल्म की अवधि अधिक है। कहानी इराक, फ्रांस, अफ्रीका, लंदन आदि कई देशों में आती-जाती है, कई बार समझना कठिन हो जाता है। हेलिकाप्टर से गोलियां बरसाते और गाड़ियों को उड़ाते दृश्य अच्छे बन पड़े हैं, जिनका श्रेय सिनेमटोग्राफर सुजीत वासुदेव को जाता है। अहम बात यह है कि अगर आपने मूल फिल्म नहीं देखी है तो सीक्वल में पात्रों को समझने में दिक्कत पेश आएगी। मोहनलाल चिरपरिचित अंदाज में हैं। निर्देशक का फोकस कहानी पर कम, हालीवुड स्टाइल पर ज्यादा लग रहा है। मंजू वारियर प्रभाव छोड़ती हैं। टोविनो थामस के पात्र को समुचित तरीके से गढ़ा नहीं गया है। फिल्म के अंत में तीसरे भाग में लूसिफर की पृष्ठभूमि को खंगालने की झलक दे दी गई है। कुल मिलाकर, फिल्म स्टाइल में अव्वल है, लेकिन विषयवस्तु की दृष्टि से कमजोर है।

स्मिता श्रीवास्तव

★★★★★ उत्कृष्ट ★★★★ बहुत अच्छी ★★★ अच्छी ★★ औसत ★ औसत से कम

अपनी राय हमें जरूर बताएं : feature@jagran.com

इधर-उधर की

बिना फ्रिज के अपने आप ठंडी हो जाएगी यह कैन

लंदन, एजेंसी : गर्मी के दिनों में ठंडे पेय की मांग बढ़ जाती है। लंदन स्थित एक स्टार्टअप डेल्टा एच इनोवेशन ने पर्यावरण अनुकूल सेल्फ कूलिंग बेवरेज कैन तकनीक विकसित की है। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया की पहली ठंडी होने वाली कैन है। इसमें सिर्फ एक बटन दबाने पर कैन तरल पदार्थों के तापमान को लगभग 6-7 डिग्री तक कम कर सकती है। यह रिसाइकिल एल्यूमीनियम से बनी है। डिब्बाबंद पेय फ्रिज से बाहर निकालने के बाद गर्म होने लगता है लेकिन यह कैन पेय को 45 मिनट तक ठंडा रख सकती है।

कार्बन उत्सर्जन कम करेगी यह तकनीक। इंटरनेट मीडिया

शुष्क हवा से सांस की नली में सूजन का खतरा

अनुसंधान

ग्लोबल वार्मिंग के कारण शुष्क हवा के संपर्क में आने से सांस की नली में निर्जलीकरण और सूजन का जोखिम बढ़ सकता है। एक अध्ययन में यह जानकारी सामने आया है। वायुमार्ग में सूजन से श्वसन संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है और अस्थमा जैसी स्थिति और भी खराब हो सकती है। अमेरिका के जांस हापकिंस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में बताया कि जैसे-जैसे पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता जा रहा है, सापेक्ष आर्द्रता समान बनी हुई है। पानी के लिए हवा की 'प्यास' का एक माप 'वाष्प दाब घाटा' तेजी से बढ़ सकता है। सापेक्ष आर्द्रता किसी दिए गए तापमान पर हवा में मौजूद नमी की अधिकतम मात्रा है। शोधकर्ताओं ने कहा कि वाष्प दाब घाटा जितना अधिक होगा, हवा की प्यास उतनी ही अधिक होगी और इस प्रकार पानी अधिक तेजी से वाष्पित होगा, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र निर्जलित हो जाएगा।

जांस हापकिंस विश्वविद्यालय में मेडिसिन के सहायक प्रोफेसर और जर्नल कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट में प्रकाशित अध्ययन के मुख्य लेखक डेविड एडवर्ड्स ने कहा, यह समझना है कि शुष्क हवा के संपर्क में आने पर वायुमार्ग कैसे निर्जलित होते हैं, हमें प्रभावी व्यवहार के परिवर्तनों और निवारक या चिकित्सीय हस्तक्षेपों द्वारा निर्जलीकरण के प्रभाव से बचने या उलटने में मदद कर सकता है। लेखकों ने लिखा, पानी का वाष्पीकरण वायुमार्ग की बलगम परतों को पतला करता है और ज्वारीय (आराम से) सांस लेने के दौरान उपकला कोशिकाओं को संकुचित करता है। । उन्होंने पाया कि शुष्क हवा के संपर्क में आने वाली कोशिकाओं में बलगम पतला होता है और कोशिकाओं में सूजन का संकेत देने वाले साइटोकिन्स या प्रोटीन का उच्च स्तर होता है। इसके परिणाम टीम की सैद्धांतिक भविष्यवाणियों के अनुरूप थे कि शुष्क वायु वातावरण के संपर्क में आने पर बलगम पतला हो जाता है, जिससे सूजन को तेज करने के लिए पर्याप्त संपीड़न पैदा होता है। इसके अलावा शोधकर्ताओं ने स्वस्थ चूहों और वायुमार्ग में पहले से मौजूद सूखेपन वाले चूहों को जो आमतौर पर पुरानी श्वसन बीमारियों में देखा जाता है, उन्हें एक सप्ताह तक रुक-रुक कर शुष्क हवा में रखा गया। प्रेट्र

समय के साथ बदल रही है ब्रह्मांड की डार्क एनर्जी

वाशिंगटन, रायटर : लाखों आकाशगंगाओं और चमकदार आकाशगंगा कोर से जुड़े नए डाटा से इस बात के नए प्रमाण मिल रहे हैं कि ब्रह्मांड की डार्क एनर्जी समय के साथ कमजोर हो गई है, न कि स्थिर बनी हुई है। रहस्यमय और अदृश्य ब्रह्मांडीय शक्ति को डार्क एनर्जी कहा जाता है, जो ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार के लिए जिम्मेदार है। शोधकर्ताओं ने एरिजोना में किट पीक नेशनल आब्जर्वेटरी में डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट डीईएसआइ या डेसी द्वारा तीन साल के अवलोकन का विश्लेषण किया।

यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन के नौरलैब में खगोल भौतिकीविद् व डेसी के नौरलैब परियोजना के विज्ञानी अर्जुन डे ने कहा कि डेसी के परिणाम एक विकसित डार्क एनर्जी की ओर इशारा करते हैं। विश्लेषण में लगभग 150 लाख आकाशगंगाओं और क्वासरों के तीन वर्षों के डाटा का उपयोग किया गया है।

स्क्रीन शाट

क्या प्रभास के सिर सजने वाला है शादी का सेहरा?

अनुष्का शेट्टी से रिलेशनशिप को लेकर खबरों में आए थे प्रभास। फाइल

कई कलाकार अपनी व्यक्तिगत जिंदगी से जुड़ी खबरों को इतना रहस्य बनाकर रखते हैं कि पता ही नहीं चलता कि क्या सच्चाई है और क्या अफवाह। विशेषकर शादी और प्रेम संबंधों जैसे विषयों को लेकर। हाल ही में बाहुबली फेम अभिनेता प्रभास की शादी की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी। पहले प्रभास और बाहुबली में देवसेना की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री अनुष्का शेट्टी के रिलेशनशिप की खबरें चर्चा में रही। फिर पिछले दिनों आई खबरों में दावा किया गया कि प्रभाव अनुष्का से नहीं बल्कि हैदराबाद के किसी व्यवसायी की बेटी से शादी रचाने जा रहे हैं। उनकी शादी की तैयारियां भी खूब जोरों से चल रही हैं। हालांकि, उनकी टीम ने आगामी दिनों में शादी जैसे किसी भी घटनाक्रम की संभावना से इन्कार किया है। उनकी टीम ने फिलहाल आ रही प्रभास की शादी से जुड़ी खबरों को अफवाह बताया है। वैसे इससे पहले भी कई सितारों ने पहले तो अपनी शादी की खबरों को अफवाह बताया और फिर शादी के बाद तस्वीरों के साथ शादी की खबर सार्वजनिक की। देखना दिलचस्प होगा प्रभास अपनी जीवनसंगिनी किसे बनाते हैं। प्रभास आगामी दिनों में फिल्म राजा साब 2 में नजर आएंगे।

कई बार अपने पात्रों पर आश्वस्त होना कठिन होता है : आर माधवन

लगातार कोई काम करते रहने के बाद उसमें नयापन लाना कठिन होता है। कलाकारों के लिए भी यह चुनौतीपूर्ण होता है, खासकर जब वह कई पात्र निभा चुके हों। शैतान फिल्म के अभिनेता आर माधवन भी इस बात को मानते हैं। हालांकि उनके पास तरीका भी हैं, जिससे वह पात्र में वास्तविकता ला सकते हैं। चार अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली तमिल फिल्म टेस्ट में माधवन वैज्ञानिक की भूमिका में होंगे, जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में संघर्ष कर रहा है। कई भूमिकाएं कर चुके माधवन के लिए क्या ऐसे रोल चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं? इस पर माधवन कहते हैं कि इतने साल फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के बाद कई बार अपने पात्रों को लेकर आश्वस्त होना कठिन होता है। हम जिस समाज में रहते हैं, जहां पिता, बेटा, पति, कलाकार होने के नाते हमें पता होता है कि लोगों के बीच एक तरह की भावनाएं दिखाते हैं, उससे आगे बढ़कर हम कुछ नहीं दिखाते। इसका दूसरा साइड यह है कि जब जीवन में कोई चुनौती आती है या सफलता मिलती है, तो आप उसमें इतनी गहराई से चल जाते हैं कि आप उन भावनाओं को दिखा जाते हैं, जो कभी लोगों के बीच नहीं दिखाया है। जब ऐसा पात्र आता है, जिसमें कुछ अलग करना होता है, तो आपका वह दूसरा पहलू सामने आता है, जो किसी ने नहीं देखा है।

तमिल फिल्म टेस्ट में वैज्ञानिक की भूमिका में होंगे आर माधवन। फाइल

हंसल मेहता बोले, मैंने फ्लाप लिखे हुए नए टीशर्ट बनवाई हुई है

इन दिनों डिजिटल प्लेटफार्म का माध्यम फिल्मकार हंसल मेहता को भा रहा है। डिजिटल प्लेटफार्म पर कंटेंट को हिट और फ्लाप के तराजू में नहीं तोला जा रहा है। बाक्स आफिस पर फिल्म से जुड़े आंकड़ों को लेकर हंसल कहते हैं कि जब कोई फिल्म सौ करोड़ कमा लेती है, तो लोग कहते हैं कि फिल्म हिट हो गई है। अरे भाई उस फिल्म के हीरो ने ही दो सौ करोड़ ले लिया है, तो हिट कैसी हुई। कई बार वह नकली नंबर और डाटा होते हैं। मैं लगातार इसको लेकर लड़ाई लड़ रहा हूं कि बाक्स आफिस पर नंबर के आधार पर फिल्म की सफलता-असफलता का अंदाजा न लगाया जाए। फिल्में अलग-अलग सोर्सेस से पैसा कमाती हैं। वह इस बिजनेस को बेहतर समझता है, जो इसमें निवेश करता है। शुक्रवार, शनिवार को तय कर लिया जाता है कि फलां फिल्म फ्लाप है। जब लोग किसी फिल्म को फ्लाप कहते हैं, तो जिंदगी भर के लिए उस फिल्म पर वह लेबल लग जाता है। कोई भी चलता- फिरता कह देता है कि तुम तो फ्लाप फिल्में बनाते हो। मैंने फ्लाप लिखे हुए नए टीशर्ट बनवाए हैं। अगर लोग कहेंगे कि मेरी बनाई हुई फिल्म शाहिद फ्लाप है, तो मैं सम्मान से रोज उसे पहनूंगा और हर रोज सुबह उठकर दुनिया और खुद से कहूंगा कि ऐसी और फ्लाप फिल्म बनानी है।

डिजिटल पर काम पसंद आ रहा हंसल को। (@hansalmehta)

सीआईडी में होगी बरबोसा की वापसी

धारावाहिक सीआईडी में फिर बरबोसा की भूमिका में दिखेंगे तिग्मांशु। टीम तिग्मांशु

हासिल और पान सिंह तोमर फिल्मों के निर्देशक तिग्मांशु धूलिया निर्देशन के साथ-साथ अभिनय में भी दिलचस्पी रखते हैं। वह गैंग्स आफ वासेपुर, साहब बीवी और गैंगस्टर तथा जीरो समेत कई फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। बतौर अभिनेता अब वह सोनी चैनल पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक सीआईडी में नजर आने वाले हैं। दरअसल, साल 2018 में बंद होने के छह साल बाद पिछले साल सीआईडी का प्रसारण पुनः शुरू किया गया। 2018 में ही तिग्मांशु शो में आई गैंग के लीडर बरबोसा की भूमिका में नजर आए थे। अब करीब साढ़े छह साल बाद शो में उनकी फिर से बरबोसा की भूमिका में वापसी हो रही हैं। तिग्मांशु ने बुधवार को शूटिंग भी शुरू कर दी है। बरबोसा की वापसी सीआईडी की टीम के लिए नई चुनौतिया खड़ी करेगा। तिग्मांशु का कहना है, 'साढ़े छह साल पहले जब मैं पहली बार सीआईडी में शामिल हुआ था, तो थोड़ा आशंकित था। हालांकि, वह मेरे लिए अविश्वसनीय अनुभव साबित हुआ और दर्शकों ने मेरे पात्र बरबोसा और आई गैंग की सराहना की। अब मुझे वापस बुलाया गया है और मैं इसे लेकर उत्साहित हूं। इस बार मेरा पात्र बरबोसा एक स्पष्ट मिशन और पूरी तैयारी के साथ है। वह पहले से कहीं अधिक गहन, तीव्र और अप्रत्याशित है।

निगेटिव भूमिकाओं में मैं सारी भड़ास निकालता हूं

डोली अरमानों की और कुल्फी कुमार बाजेवाला जैसे धारावाहिकों से लोकप्रियता बटोरने वाले अभिनेता मोहित मलिक अब फिल्मों और डिजिटल प्लेटफार्म पर अच्छे मौके देख रहे हैं। इस साल उन्होंने आजाद से फिल्मों में कदम रखा। अब वह चार अप्रैल से सोनी लिव पर स्ट्रीम होने जा रही वेब सीरीज चमक सीजन 2 में फिर गुरु देओल की भूमिका में नजर आएंगे। उनसे बातचीत के अंश...

सात सवाल

> अगर आपको प्रोडक्ट की तरह काम करते हुए ही पैसे कमाने है, तो आपका सफर सबसे अलग होगा लेकिन अगर क्रिएटिव काम करना है, तो काम के मामले में आपको चुनिंदा बनना पड़ेगा

● टीवी कलाकारों को अक्सर फिल्मों या डिजिटल प्लेटफार्म पर काम खोजते समय वर्गीकृत कर दिया जाता है। चमक के बाद क्या आपको अपने लिए ये बंदिशें टूटती दिख रही हैं?

-मेरे प्रशंसकों के लिए किसी बंदिश के टूटने या बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह मुझे फिल्मों में देखे या ओटीटी पर, उतना ही प्यार देंगे। पेशेवर तौर पर मेरे लिए यह जरूरी है कि मैं ऐसे प्लेटफार्म पर काम करूं, जहां वो लोग मेरा काम देखे। टीवी में आपको आपके प्रशंसक और घर बैठे दर्शक देखते हैं, लेकिन सिनेमा इंडस्ट्री वाले टीवी नहीं देखते हैं। मैं बस चाहता था, इंडस्ट्री के लोग मेरे काम को जाने और पहचाने, ताकि मैं और काम कर सकूं।

● क्या फिल्मों में आने में ज्यादा समय लग गया?

-मेरा ये कभी एजेंडा नहीं था कि फिल्मों में काम करना है। साल 2016-17 से मैंने इस बारे में सोचना शुरू किया था। एक फिल्म करने के बाद अब शेर के मुंह में खून लग गया है।

● डोली अरमानों की धारावाहिक के बाद आजाद में भी खलनायक बने, ऐसी भूमिकाओं से ज्यादा लगाव है?

-ईमानदारी से कहूं तो मुझे निगेटिव भूमिकाएं निभाने में ज्यादा मजा आता है। उन भूमिकाओं में मैं अपनी सारी भड़ास निकालता हूं। मेरे अंदर ऐसी जो भावनाएं होती हैं, जिन्हें हम अंदर ही रखते हैं, निगेटिव भूमिकाएं करते हुए सारी भावनाएं निकल जाती हैं।

● शो के एक संवाद में कलाकार को प्रोडक्ट कहा जाता है, क्या आपने भी कभी इंडस्ट्री में खुद के साथ प्रोडक्ट जैसा व्यवहार होता देखा है?

-कलाकार को प्रोडक्ट के तौर पर देखना किसी-किसी का नजरिया हो सकता है। शो में तो प्रताप देओल का पात्र यह बोल देता है, लेकिन इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से लोग हैं, जो ऐसा सोचते तो हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं। हालांकि, मैंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया है।

● प्रोडक्ट बनने के बाद तो आपको सिर्फ लाभ-हानि और पैसों के नजरिये से देखा जाता है, फिर बतौर कलाकार रचनात्मक संतुष्टि का क्या?

-यह इस पर निर्भर करता है कि आपको कहां और कैसे काम करना है। अगर आपको सिर्फ प्रोडक्ट की तरह काम करते हुए पैसे कमाने है, तो सफर अलग होगा। अगर क्रिएटिव काम करना है, तो काम के मामले में चुनिंदा होना पड़ेगा कि आपको क्या काम और किसके साथ काम करना है।

● पत्नी अदिति संग काम करने का प्रस्ताव आया?

-अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। अगर ऐसा मौका बना तो मैं उनके साथ किसी प्रेम कहानी पर काम करना चाहूंगा।

(दीपेश पांडेय)

जिंदगी रातोंरात बदल सकती है: सारा

गत 16 जनवरी को अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में सैफ और उनकी पहली पत्नी अभिनेत्री अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान की प्रतिक्रिया पहली बार सामने आई है। गुरुवार को एक समारोह में सारा ने अपने पिता पर हुए हमले को लेकर कहा, 'ऐसी चीजें आपको अहसास कराती हैं कि सच में क्या चीजें मायने रखती हैं, जैसे आपकी सांसें, आपकी जिंदगी, आपके पास ऐसे पिता और माता का होना जो आपसे प्यार करते हैं। इन सब चीजों के लिए हमें ऊपरवाले का आभारी होना चाहिए। हमारा पूरा परिवार इसके लिए आभारी है, क्योंकि उस दिन बहुत बुरा हो सकता था।' आगे सारा कहती हैं, 'उस घटना के बाद मुझे अहसास हुआ कि जिंदगी रातोंरात बदल सकती है। इसलिए हमें जिंदगी के हर दिन और हर पल को खुलकर जीना चाहिए।'

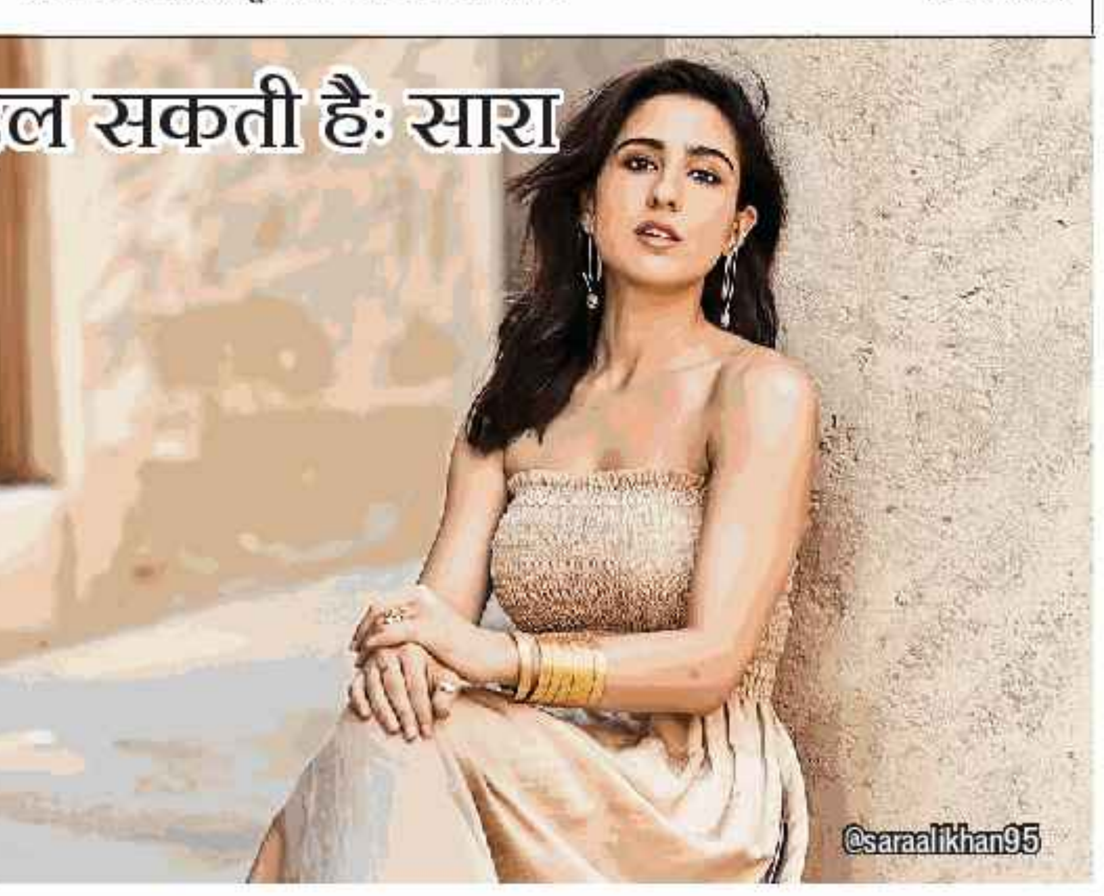

****